

**LOK SABHA
DEBATES**

(Sixth Series)

Vol. XVIII

(August 22 to 31, 1978/Sruvana 21 to Bhadra 9, 1980 (Saka))



Pifth Session, 1978/1980 (Saka)

(Vol. XVIII contains Nos. 21-32)

**LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI**

CONTENTS

No. 30, Tuesday, August 29, 1978/Bhadru 7, 1900 (Saka)

	COLUMNS
Oral Answers to Questions :	
*Starred Questions Nos. 488 to 490 and 492	1-24
Written Answers to Questions :	
Starred Questions Nos. 491 and 494 to 509	24-43
Unstarred Questions Nos. 4739 to 4938	43-208
<i>Re</i> ✓ Short Notice Question on Reported Murder of Two Children in Delhi	209-10
Questions of Privilege against (i) Editor, The National Herald and (ii) Shri Somjibhai Damor, M. P.	211-12
Message from Rajya Sabha	212
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
Reported violent clashes involving naval personnel, workers of Hindustan Shipyard and Bus Workers	212-20
Shri Vijay Kumar Malhotra	212, 214-15
Shri Dhanik Lal Mandal	212-13
Shri Janardhana Poojary	216-17
Shri Ugrasen	218-19
Shri Jagjivan Ram	219, 220
Shri Vasant Sathé	219-20
Estimates Committee—	
Twenty-second Report and Minutes	221
Public Accounts Committee—	
Eighty-third, Eighty-sixth and Ninetieth Reports	221
Matters under Rule 377—	
(i) Reported Research into thermo-nuclear fusion—	
Shri D. D. Desai	221-22

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

(ii)) Need for four-laning of road between Panvel and Dehu Road—	222-23
Shri S. R. Damani	
(iii) Reported Selection of Aircraft for Indian Air Force—	
Shri Raj Narain	223-25
(iv) Public School System—	
Shri Raj Krishna Dawn	225-26
(v) Reported Deaths and Heavy Losses due to Rains in Himachal Pradesh—	
Shri Druga Chand	226
Press Council Bill—	
Motion to consider—	
Shri R. Venkataraman	227-29
Shri Nirmal Chandra Jain	229-31
Shri C. K. Chandrappan	231-33
Shri O. P. Tyagi	233-35
Shri Dhirendranath Basu	235-36
Dr. Ramji Singh	237-39
Shri Ram Kishan	239-42
Shrimati Chandravati	242-44
Chowdhry Balbir Singh	244-45
Shri Amrut Kasar	245-47
Shri Laxmi Narain Nayak	247-48
Prof. P. G. Mavalankar	248-50
Shri Druga Chand	250-52
Shri Chitta Basu	252-54
Shri Purnanarayan Sinha	254-55
Shri B. C. Kamble	255-57
Shri Ajitsinh Dabhi	257-58
Shri A. K. Roy	258-60
Shri L. K. Advani	260-74
Caluses 2 to 5	274-83

Motion *Re.* Increasing Play of Money Power in Elections—

Shri K. P. Unnikrishnan	283—93
Shri Gauri Shankar Rai	294—99
Shri Vasant Sathe	299—302
Shri Samar Mukherjee	302—307
Shri P. K. Deo	307—310
Shri Krishan Kant	311—16
Shri A. Bala Pajanor	316—20
Shri Hari Vishnu Kamath	320—26
Shri C. K. Chandrappan	326—31
Shri Kanwar Lal Gupta	331—36

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, August 29, 1972/Bhadra 7, 1966 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[Mr. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Bharat Singh Chowhan.

SHRI VASANT SATHE : It is such a shocking.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Sathe what is shocking? The Question Hour is not a shocking affair. I am very sorry, Mr. Sathe, you can not just get up and raise any matter you like.

(Interruptions)

SHRI VASANT SATHE : Two children were killed.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, no please Mr. Sathe. There is a way of raising things. You cannot do that here; and you cannot obstruct the Question Hour like this. We have never done this before and I am very sorry I will not allow you. Mr. Bharat Singh Chowhan.

(Interruptions) **

SHRI SAUGATA ROY : Let the whole thing be expunged.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The whole thing is expunged.

SHRI SAUGATA ROY : Thank you very much.

SHRI VAYALAR RAVI : Thank you very much.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Minister. Please take your seats.

(Interruptions).

**Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Ugrasen, please take your seat. Mr. Chowhan, you have put the question.

Yes, Mr. Minister.

निर्वाचित सभ्य के बाद सभ्य भारती रेस्पॉन्सिंग

* 488. श्री भारत तिह चौहान : क्या रेस्पॉन्सिंग नंबरी यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सब है कि बहुत श्री रेस्पॉन्सिंग नंबरी यह बतानी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उकान ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेस्पॉन्सिंग देर से व चौंक, कर्म-चारियों को ग्रासाहन देने की कोई बोधना दैवार की है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी जीरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेस्पॉन्सिंग (श्री यश ईंवर्कर) : (क) भीषण गर्भी के दौरान मर्द 78 महीने में गर्भियों का समय-पालन सन्तोषजनक नहीं था । लेकिन, युवाई में समय-पालन 90-10 प्रतिशत तक ही गया है ।

(घ) ले (क). गर्भियों को समय से बचाना रेस्पॉन्सिंग चारियों की सामाजिक दृष्टी है । फिर भी, गर्भियों के समय-पालन में सुधार लाने के लिए कर्म-चारियों द्वारा किये गये विभिन्न प्रयत्नों के लिए नगद पुरस्कारों, प्रशासित पदों प्राप्ति के रूप में उन्हें कुछ ग्रासाहन दिये जाते हैं ।

श्री भारत तिह चौहान : मैं रेस्पॉन्सिंग श्री से यह जानना चाहता हूँ कि जो गर्भियों लेट बताती है उससे संबंधित अधिकारियों को दण्डित किया जाता है या नहीं ?

श्री यश ईंवर्कर : माननीय, जब गर्भियों लेट आती हैं तो उसके कई कारण होते हैं । जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दातान भैंग पुरिया, छोड़ैंसे अंगीर लौंचने के क्षेत्रिक जनबरी से मई महीने में सब से ज्यादा थे । उसके बाद जून महीने में कम हुए हैं । जब किसी भी कमेचारी की पंकजएलिटी कम होती है तो यह उसके लिए जिम्मेदार होता है तो उसके बारे में अकर एक्शन लिया जाता है । यह पहले भी मैंने बताया था, उसको फिर दोहराना चाहता हूँ ।

श्री भारत तिह चौहान : उपायक महोदय, यह जो कल्पीयुग-प्रबन्ध लाना है, यह धक्कार लेट बताती है और इसको कारन यह है कि पिछले 50 सालों से

इस बादन पर कोई देव रस्तार बाबी नहीं चलावी जाती । इस बाबी में स्टीम इंजन है जो इंजिनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता जबकि और साइनों पर किया गया है ।

व्याख्या व्याख्या : धारा प्रवान पूछिए ।

बी बात तिथि बीहान : देरा स्टेसन पर है कि ब्या उस बादन पर और स्टीम इंजन जबकि किया जाएगा जिससे कि याहियों को तुम्हारा जिसे कर्ताक मह कर्त्ता-दूदा-जन्मनेर बादन बहुत बड़ी बादन है ?

ओ० बच्च बंदबत्ते : बीमन यह बात सही है कि हम बोयों के पास स्टीम इंजनों की तुलना में बीजस इंजन कम है । मैं यानीय सदय को बताना चाहता हूँ कि हावरे पास 8263 स्टीम इंजन, 1903 और स्टीम इंजन और 844 इंजिन लोकोमोटिव हैं । 1971 के बाद से स्टीम लोकोमोटिव बैन्केवर करने का काम हम लोगों ने बना किया है । यारे बात कर बीजस और इंजिन लोकोमोटिव ही रहे । लेकिन जब तक पुराने इंजन हैं, वे जहर कलकारी देते हैं । उन पर मटीनें भी काफी करना पड़ता है । यानीय सदय की यह लिकायत सही है कि जिन कृत्तु पर पुराने स्टीम इंजन हैं, वहाँ काफी तकलीफ रहती है, वहाँ लास बाक एंकवरालिटी भी होता है । लेकिन याहिस्ता याहिस्ता जैसे जैसे स्टीम इंजन कम होते जायेंगे, उमकी बगह पर बीजस इंजन लगाये जाते रहेंगे ।

बी बाब बंदबर बेरवा : उपायक महोदय, मैं यानीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में रेलों के ड्राइवर्स को प्रमोशन दी गयी थी, उनको स्लास ए के कर स्लास थें में कर दिया था, इसके संबंध में जब हमारी निवाले स्टेसन के रेलवे कर्मचारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जो घटका काम करने वाले हैं, उन्हें इनाम नहीं दिया जाता है, और मंत्री महोदय यह कह रहे हैं हम उनको पुरस्कार करते हैं तो इनमें कान सो बात महीं है ? क्या रेलों के कर्मचारियों में बाब बाब में स्लास नहीं है ? क्या इसकी लिकायत आप के पास आयी है ? क्या इसकी लिकायत भी आपके पास आयी है कि जो घटकादावाद में जाती है वह बांदीहुई में जाकर के सेट ही जाती है और उन नमय लेते ही जाती है जबकि सामने से कोई देन नहीं आ रही होती है ?

ओ० बच्च बंदबत्ते : बीमन, मैंने पहले ही बताया है कि जब कोई भी बाबी सेट होती है तो उसके बाब टाइम को बेकायप किया जाता है और घनिम स्टेसन पर वह बाबी ठीक समय पर पहुँचती है । ऐसे ड्राइवरों को हम नकह और बिसेष प्रकार के पुरस्कार देते हैं । इस प्रकार की जर्नी पूरी होने के बाब 15 घण्टे से 25 घण्टे तक हम उनके पुरस्कार में से हैं और यह तक देते हैं जब वे टाइम में आप करते हैं ।

बी डाइरिका नाम तिकारी : क्या यह बात सही है कि थैने बीच के स्टेसनों पर कीची जाती है और तभी बाबी सेट होती तकी है ? क्या यह बात भी सही नहीं है कि जहाँ से बाबी चलती है, या जहाँ से बाबी बोलती

जाती है, बरब उस स्टेसन पर हमको बात बोले तुलना होती है ? किर बब देने विवरत पर बीजों की जाती है तो उसे बहुत बाबा-बाबा बंदा रोकर बोयों सेट किया जाता है ? बोयों महीं पहुँचे से हम बात का ब्यान रखा जाता है कि उस बरब बाबन पर बाबी आने वाली है और उस की कीवर रखा जाए जब वा इस कारणों से भी याहियों सेट नहीं होती है ?

ओ० बच्च बंदबत्ते : याहियों बरब बाबन से पूछा है कि याहियों देदी से खोये कटती है ? उसके बारे में बतला जल्दी है । कह इसतवा जिस सेवकन पर बाबी बालने जाती है उस बर... । लाइन कीवीरें बरब नहीं है, बैच्योटेड कीपेटिटी और लाइन कीपेटिटी बैच्योटाइट है । तो जिस स्टेसन से बाबी बाक करती है वहाँ दिक्कत न होते हुए भी यारे सेवकन में जो दिक्कत है उसको बरह से कही मरंबा काफी दिक्कतें देता होती है । इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ।

बी डाइरिका नाम तिकारी : जब बाबी सेट होती है तो विवरत पर बड़ी करते और लेट कर दी जाती है, इसका क्या जबाब है ?

ओ० बच्च बंदबत्ते : हर स्टेसन की कोई टाइमनल कीपेटिटी होती है । मैंने पहले भी कहा कि कह इसतवा गाबी ठीक समय पर बाती है लेकिन हर स्टेसन की जो टाइमनल कीपेटिटी है वह कभी कभी पूरी घोटका-प्रहर होती है जिससे स्टेसन से बाबी बाब याद नहीं पहुँचे गाबी नियमन के पास रोकी जाती है, और जब स्टेसन लेट-फार्म, से गाबी कीवीर हो जाती है तब बाबी स्टेसन पर बाती है ।

बी बाब बंदबत्ते : इमरजेंसी के समय में एक ही दिन में एक ही बाबार के अनुसार देख के घन्दर सारी याहियों समय पर बलने लगी थीं, क्या यानीय मंत्री नमस्ते है कि यह इमरजेंसी का एक घावीलेट था ? बाब भी सारी याहियों को वक्तव्यली बलाने के लिए धारा एसा बाबार दे सकते हैं या नहीं ?

ओ० बच्च बंदबत्ते : इस सबाल का जबाब मैंने पहले भी दिया था कि इमरजेंसी के दिनों में याहियों की जो पंचवालिटी भी उसके मुकाबले में याहिस्ता याहिस्ता पंचवालिटी बदलती रहे । उसके बाब मई महीने में तबीं में कम हुई थी । जहाँ तक बाब गेज का सबाल है लगातार हर महीने में हमारी कोशिश होने के बाब मई महीने में 1978 के पंचवालिटी बोब गेज पर 82.4 परसेट थी, जून 1978 में 85.1 परसेट हो गई, जुलाई में 90.6 परसेट हो गई और उसके बाब प्रगत महीने में 90.4 परसेट हो गई । भी भी बोडा सा उसमें मुहार हुआ है और कही रहे थे योंत है जहाँ, 85, 96 परसेट भी पंचवालिटी हुई है । तो इमरजेंसी न होते हुए भी हमारी कोशिश होती है कि पंचवालिटी जारी रहे नहीं तो आप मार्ग करते कि इमरजेंसी जाए ।

बी बीबा बाल बंदबत्ते : मैं भी जी से जानना चाहता हूँ कि कह एक पैरसेट देनों में जैसे बैचरा-बड़ीया पर एक ही कोष होते हो एक कोष एक बाब सेट होती भवी जाती है ।

है क्योंकि योग एक ही है। और तुड़ यात्रियों को दें वाहन-कोठे सेवक को बदल देता है क्योंकि की कमी के कारण योगान बेट दर दो यात्रा देते, लेकिन योग यात्रियों बदल देती है या लिवके पास लैवल एक ही बोध है उन यात्रियों को बदलने के बारे में क्या बरकार दीर्घ व्यापारी करती?

श्री० नमू बंडलते : मैंने एक समय सदून में यात्राया था उन यात्रियों के लिये जो टीम इन्हन से बदलती है और इन्हें उनके लिए स्टीम कोक को बदलता है। लेकिन यह कोकल की कमी हो गई तो हमारे सामने प्राविकता का बदलाव था। बादर स्टेसन की स्टीम कोक देना है और ऐसे यात्रियों को देना है। और ऐसे यात्रियों के बारे में लिवर कले के बदल हुन्हें तब किया जाता रायर स्टेसन बदल हो। यात्रे ही ही सब इन्हें उनके लिये भी तकलीफ होती है। हमारे इन्हें इन्हें उनके लिये भी तकलीफ होती है। इसलिये जब स्टीम कम हो जाया 150 परसेंज बाक ट्रेन को हमें कम करना पड़ा। लेकिन ऐसे ऐसे कोवता यात्रियों एक बूढ़ करते, और जो लिवकात मानीय सदृश्य ने रखी है उसकी तरफ बहर ब्यान देते।

श्री चतुर्वेदी : ममी जी ने रेलों की रक्षार बड़ाने और समय पर बहने के लिये बताया जिससे लिये बह बन्धवाद के पात हैं। लेकिन क्या ममी जी यात्रियों कि 30 मई तक कितनी यात्रियों समय पर बड़ी उनका परसेंटेज क्या है, और कितनी यात्रियों समय पर नहीं बड़ी, उनका परसेंटेज क्या है?

श्री० नमू बंडलते : मैंने तो बताया, अभी आपके सामने यो प्राप्त हो गेज के बताए उसमें बताया कि नई 1978 में पंक्षपत्ती 4, 4 परसेंट रही है और भीटर नीटर जेज पर 86, 1 परसेंट रही, और हिंदुस्तान में जो 11,000 यात्रियों बह रही है उसमें 6,000 पैसेंजर ट्रेन हैं इसलिये 6,000 पैसेंजर ट्रेन का हिसाब लगा कर आपके सामने यह परसेंटेज रखा है जाप कियुलेलन कर लीजिए।

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE : Sir, we are informed that the Janata Party train was waiting outside the outer signal. Because of the mediation efforts in which the Railway Minister was also involved. I would like to know whether he will assure the House that the said train will reach the destination in time.

PROF. MADHU DANDAVATE : I welcome the question. It might be true that the Janata Party train might actually be waiting at the outer signal, but in the Emergency the Congress train and democracy were completely derailed. They have actually allowed the derailment.

Railway Station at Sheloo

*489. SHRI D.B. PATIL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is a constant demand for the last 20 years for a railway station at

Sheloo (between Neral and Wangani) on Bombay Poona line;

(b) whether it is a fact that near about 2500 passengers from that area travel by railway;

(c) whether it is also a fact that a station is provided for, if there are more than five hundred passengers travelling daily from a particular spot; and

(d) if so, what are the reasons for not sanctioning and constructing a station at Sheloo?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) :

(a) Yes, Sir. A statement is laid on the table of the House.

(b) About 2200 passengers travel daily from Neral and Wangani stations which are at a distance of 4.87 Kms. and 3.26 Kms. respectively from the proposed site.

(c) There is no such rule.

(d) The proposal was examined in the past but was not found operationally feasible and there was no financial justification also. However, this proposal is being examined afresh in view of the persistent demand from the people in this area.

Statement

Railway Station at Sheloo

The following representations have been received from the public for opening a station at Sheloo since 1958 :—

S. Name of the party from whom Year
No. the representation was received

1	2	3
1	Shri M.J. Dave, Village Sheloo, Taluka Karjat Distt. Kolaba . . .	1958
2	Shri Tukaram Laxman, Sona- vale & others village Sheloo, through the Commissioner, Bombay Division . . .	1959
3	The Collector of Kolaba . . .	1961
4	A joint representation from the residents of Village Bhadwal & Damat, Talu- ka-Karjat (Kolaba) . . .	1961
5	Shri B.N. Dighe, the then M.P., Lok Sabha . . .	1964

1	2	3
6	Sarpanch, Group Grampanchayat, Damat Dahiwali .	1964
7	Sarpanch, Group Gram Panchayat, Shelu, (Distt. Kolabu) . . .	1971
8	Shri Shantaram Rawaji Nimbane, Sarpanch, Group Gram Panchayat, Sheloo ,	1972
9	Shri S.V. Dhamankar, the then M.P. (Lok Sabha) .	1972
10	Shri Yashvant Gopal Patil, Village, Sheloo . .	1973
11	Shri K.B. Tare from Sheloo	1977
12	Shri Vasudev Pitkar, President, Janata Party, Neral.	1978

SHRI D.B. PATIL : It has been admitted that there is a constant demand for the last 20 years and as many as 2,200 passengers travel daily from this particular place. Among those passengers are students and workers going to Bombay, Poona and other industrial areas, and vegetable growers taking the vegetables to Bombay and other industrial areas. In view of the fact that it is necessary and also in view of the fact that you are going to examine this demand, I would like to know from the hon. Minister whether in the near future it is likely to be taken up.

PROF. MADHU DANDAVATE : In 1964 the problem was examined in depth and at that time it was found out that the capital investment that would be required for the introduction of the station would be about Rs. 2 lakhs. To be exact, it would be Rs. 2,36,335. And it was also found out that the recurring losses per year would be of the order of Rs. 69,000. That would be actually Rs. 63,405 per annum. Thirdly, it is found out that since the distance between the existing two stations, Neral and Wangani is 7 kilometres, and within such a short distance, if we try to introduce an additional station, since Bombay to Poona is a highly density traffic route, and the capacity of the section is completely saturated today, running of trains is likely to be disturbed. But in spite of that we have received the latest communication on 23-5-1977 from a prominent person, Mr. K.B. Tare, from that area and I have already decided on 7-7-1977 that that particular problem should be gone through by the Central Railway and only when the problem is thoroughly examined, I will be able to give further information.

SHRI R.K. MHALGI : When would this full examination of the problem be completed?

PROF. MADHU DANDAVATE : I can assure you that within a few months we will be able to see what exactly can be done in the matter. Whether the reply is positive or negative, I will be able to give the information to the Hon'ble Member.

की जलसभी जाई : मंत्री महोदय ने जाई यह बताया कि सर्वे करने के दौरान और इस बाइन के बादू करने में इतना जाई होता : उहांने जाई के बाकी बताये : जेविं बादू ही बाने के बाबू किसने समय के बाद ज्ञा-ज्ञा जुगाड़ होता है, वह नहीं बताया। वह भी उन्हें बताया चाहिए ?

श्रौ. यश दंडवते : मैंने सर्वे का जारी नहीं बताया है, वैनेै कैपिटल एक्सप्रेसिवर बताया है। यार यह नया स्टेशन बनाना होता, तो उसके लिए कितीै पूँजी जानी होती है, वह जाकड़ा है। मैंने 2,36,335 रुपए बताया है। मैंने यह भी बताया है कि स्टेशन बनाने के बाद भी हर साल रेकॉर्ड लात 69,405 रुपए होता।

की जलसभी जाई : मंत्री महोदय ने यह भी बताया है कि आद्य कितीै होती है। उन्होंने जारी बताया है।

श्रौ. यश दंडवते : यार यह स्टेशन बन जाता है, तो इस की कैपिटल कार्स्ट : 2,36,335 रुपए प्रतिवर्ष : 7,446 रुपए, एक्सप्रेसिवर : 76,851 रुपए और इस लिए लात : 49,405 रुपए होता।

Robberies in Running Trains

+

*490. **SHRI K. LAKKAPPA :**
SHRI DURGA CHAND :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to lay a statement showing :

(a) whether Government's attention has been drawn to the serious situation arising out of the activities of robbers in the running trains throughout the country;

(b) if so, the number of train robberies during the last one year, monthwise, together with date and the number of persons arrested;

(c) estimated loss to the passengers in each case and how Government propose to compensate them; and

(d) whether any steps have been taken by Government to minimise the robbery cases in the Railway and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS
(PROF. MADHU DANDAVATE):
(a) to (d). A statement is laid on the
Table of the House.

Statement

(a) Yes.

(b) and (c). Number of robberies and dacoities, monthwise together with the date and the number of persons arrested as well as the value of property lost by the passengers, is indicated in statements 'A', and 'B' laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2730/78] As per the existing rules no compensation is admissible to the victims of such crimes.

(d) The responsibility of ensuring the personal safety of the passengers and the security of their belongings rests with the Government Railway Police which functions under the administrative and disciplinary control of the State Governments. Crime prevention and detection in respect of passenger safety and security of their belongings fall under the category of 'law and order' which is a State subject under the Constitution. However, the Railways render necessary assistance whenever required and close liaison is maintained at all levels with the State Police Agencies. The Railway Protection Force constituted under the R.P.F. Act has preventive and detective powers only in respect of unlawful possession of railway property. The R.P.F. is concerned with the protection of goods entrusted to the Railways for carriage and Railway materials.

Being concerned with the spate of heinous crimes in Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Madhya Pradesh, the Minister of Railways had written to the Chief Ministers of these States requesting them to take such measures to curb crimes in running trains. On 5-8-78, there was a high level meeting between the Minister of Railways and the Chief Minister of Uttar Pradesh at Lucknow in which the problem of crimes on railways was highlighted. The Railway Minister discussed this problem personally with the Chief Minister of Maharashtra at Bombay on August 10, 1978 and by telephone with the Chief Minister of Madhya Pradesh on August 13, 1978.

The response from the State Governments has been encouraging.

Earlier on 16-6-1978 a high level meeting between the officers of the Ministries of Railways and Home Affairs was held. The following firm decisions were taken which have yielded encouraging results :

(1) As the dacoits/robbers were silencing the passengers by show of fire arms and escaping after commission of crime generally by pulling alarm chain under cover of darkness a prompt channel of communication to the armed police guard whenever alarm chain was pulled at night was considered necessary. It was decided that the alarm chain whistle should be sounded repeatedly by the driver. On hearing of this alarm the armed police escort should split themselves in two parts and detrain to apprehend escaping criminals.

(2) The police escort should be accommodated together as far as possible in the centre of the train and they should be equipped with powerful torches.

(3) The police escort party may progressively be equipped with very light pistols which would be useful in lighting up the area on both sides of the train at night.

(4) The Guards and Brakemen should be provided with powerful torch lights in vulnerable trains over affected sections.

(5) There should be a liaison with the States principally affected for stepping up police protection. Chief Security Officers of Eastern, South Eastern, Northern and Central Railways were specifically nominated to maintain close liaison with the State Police authorities of West Bengal, Bihar, U.P., Madhya Pradesh and Maharashtra. The CSOs of other Railways were directed to maintain liaison with above 4 Chief Security Officers. They were directed to indicate to the State Governments the strength of police guard which should be required on vulnerable trains and request the State Police authorities to provide the necessary protection. The requirement of State Governments has been projected to Ministry of Home Affairs.

The Zonal Railways have launched a drive to ensure strict adherence to the following preventive measures in coaches:

(i) Vestibuled doors are kept locked between 22.00 hrs and 06.00 hrs. by the Travelling Ticket Examiners/Coach Attendants.

(ii) Travelling Ticket Examiners and Coach Attendants remain vigilant during night time and prevent entry of intruders, hawkers and unauthorised persons into the coaches.

(iii) In case of non-vestibuled trains, the vestibuled doors are permanently closed or dumnaied.

The above measures formulated are in continuation of the various preventive steps taken by the Govt. Railway Police under the State Governments. The G.R.P. being alive to the problem adopted several regular preventive measures which are given below :

(1) Escorting of important trains at night by armed guards of Govt. Railway Police of the concerned State Government.

(2) Beat patrolling at stations, platforms/ waiting halls.

(3) Surveillance over criminals and known bad characters.

(4) Checking of night trains by Supervisory Officers.

(5) Armed pickets at vulnerable stations.

(6) Special Squads of the C.I.D. of the State Governments take up investigation of important cases to apprehend the gangs responsible for these crimes.

The measures have been intensified by the Government Railway Police.

As a further measures to deal with occurrences of train robberies and dacoities, the Minister of Railways ordered deployment of armed RPF to escort the affected trains running in vulnerable sections. Primarily, they will protect railway property and will also help to instil confidence amongst the travelling public and deter criminals from operating on trains. Over 1400 armed RPF men were put on escort duty on different Railways from the first week of July, 1978. This number has been increased to 2,000 since 16th August, 1978.

SHRI K. LAKKAPPA : The question was held over on that day because the Minister was not furnishing the full facts to this House. I have got great respect for Mr. Dandavate personally. But I do not know why he has failed as a Railway Minister. This question is regarding the spate of robberies in running trains. The answer that has been given is not only unsatisfactory but also not convincing. I do not know what are his powers and controls. He has stated in his reply that as per the existing rules, no compensation is admissible to the victims of such crimes. He has also stated that the responsibility of ensuring personal safety of the passenger is mainly the function of the State Governments and the disciplinary control of the State Governments and that it comes under

the category of law and order which is a State subject under the Constitution. So, he has no control over such things.

In our country about six thousand passenger trains and five thousand goods trains are running every day and twenty thousand CRPF men have been engaged. But still the loss to the exchequer is about Rs. 4 crores. They have not even cared to protect the passengers and the robberies and dacoities are on the increase, and they have not been properly identified because he has no control over the States and the States are not furnishing the correct figures. He has laid a wrong statement on the Table of this House and thus bluffing this House. I do not agree with this. I would like to say that in five months from January to May, there has been an increase in the number of robberies and dacoities. But the statement shows that there is no increase as compared to the position that existed in 1977.

What I would like to arrive at is this. Whether this House has allowed him to make such a wrong statement on the Floor of the House under the Rules of Procedure. Will you kindly tell me about it? That is why I would like to bring to your kind notice.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are asking a question from me... I am asking you to put a question.

SHRI K. LAKKAPPA: With your kind permission, I would like to bring to your kind notice that people are losing faith in travelling trains. On that day, you know probably, there were about 20 commotions specially in the south bound trains. As far as the area of Madhya Pradesh is concerned, I do not know how Madhya Pradesh is famous for dacoities. Whether you have taken any action against this. The hon. Minister has no control over the law and order situation.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Have you put your question?

(*Interruptions*)

SHRI K. LAKKAPPA : He has no control over the law and order situation.

SHRI SURATH BAHADUR SHAH : Can I seek one clarification?

MR. DEPUTY-SPEAKER : No.

SHRI SURATH BAHADUR SHAH : Mr. Lakkappa is using this form for asking useless questions.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Actually, he has over-stepped the mark ; he has not put the question by now.

(*Interruptions*)

SHRI K. LAKKAPPA : Robbery and dacoity are increasing. He has no control over the States because the Constitution will come in the way. There are no rules, at present, to give compensation to the victims.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You cannot make a speech during the Question Hour.

SHRI K. LAKKAPPA : On the basis of the statement, I am putting a supplementary. Then he himself has admitted that there are no laws to give compensation to the victims. Property worth about Rs. 1 lakh has been looted during the last 4-5 months especially in the trains.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are repeating the same thing.

SHRI K. LAKKAPPA : Therefore, in the absence of relevant rules and regulations, how the hon. Minister is going to check effectively this kind of a dacoity and robbery in the running trains ? How would he control the railway police ? In view of these things, will he consider to plug the loopholes and also try to bring legislation to this effect in order to have more control over these railway accidents and save these running trains from being attacked by robbery, murder, dacoity and what not ?

PROF. MADHU DANDAVATE : Mr. Deputy-Speaker, Sir, regarding his inaugural speech while asking the question, I will come to the point proper. Firstly, he has said that I had tried to place a wrong and inadequate information before the House. Sir, on the other hand a very elaborate statement has been laid and you will be pleasantly surprised to find that various annexures which I have provided as a reply to the question contain month-wise the number of accidents, the value of goods that have been lost, the steps that have been taken and how many people have been.....

(*Interruptions*)

I did not interfere when you were asking questions.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You took so many minutes in asking your questions. He has not even started the answer.

PROF. MADHU DANDAVATE : I did not interfere with the question when my hon. friend was asking the question. So, let him have the same patience. He has raised a question as to what exactly is the authority of the railway in dealing with

such crimes. On more than two occasions I said and I will amplify that answer. It is true that general law and order problem on the railways is under the jurisdiction of G.R.P. which is under the jurisdiction of the State Government, but we have also certain machinery like Railway Protection Force whose basic work, no doubt, is for the protection of installations, protections of various types of equipments on the trains and elsewhere. But we have evolved a machinery in cooperation with the State Governments, no matter whatever political complexion of the State administration, and I am happy to say that almost all the States have agreed to give us full cooperation. We have set up a coordination between the State machinery, R.P.F. machinery and the railway machinery also—I mean T.T. and others—and the machinery that we have set up is like this especially those areas which are vulnerable areas for robbery and dacoities. In that area, wherever there are vestibule trains, we have opened out vestibule doors between two coaches; and for every two coaches, we have kept two R.P.F. men.

We are putting one T.T. and two armed R.P.F. I am happy to inform the House that with the help of this arrangement we are able to control the situation though it took some time. Let me come to the dates. Initially there was trouble. There were dacoities—after 11th August when we made this machinery tight not a single case of robbery and dacoity has taken place in Madhya Pradesh. Though efforts were made.....

(*Interruptions*)

Let me complete the answer. (*interruption*) That is before that.

After 11th August, no robberies and dacoities have taken place in Madhya Pradesh. But that does not mean that efforts were not made. Efforts were made by G.R.P. one R.P.F. was able to detect them and we have been able to arrest them. I have given you in the table the number of persons that have been arrested. I, therefore, do not want to repeat it.

SHRI K. LAKKAPPA : I understand, I cannot get a relevant reply. I would like to give the reason why the Railway Ministry is not functioning properly. There is a conspiracy in the Government itself, Mr. Dandavate. The Home Ministry wanted to bring and also throw a muzzle on the Railway Ministry. The Hindi knowing officers are playing tricks and letting this loose in the areas where Jayanti Janta operates, G.T. operates and K.K. express operates. That comes into Madhya

Pradesh daily. All these soups bound trains are being attacked. Same type of people are operating. I will read out.

MR. DEPUTY SPEAKER : I do not want any help from you to deal with the member. I will deal with him myself.

Mr. Lakkappa, please put the question.

SHRI K. LAKKAPPA : Nearly 400 people in the form of a gang again and again are operating in the same place. (Interruptions).

MR. DEPUTY SPEAKER : The more members get up the more time he will be taking.

Mr. Lakkappa, please come to the question.

SHRI K. LAKKAPPA : Such gangs are operating in collusion with these officers who are knowing Hindi and they are purposefully attacking and bringing a bad name to the Railway Ministry. Therefore, I would like to know—because there is an impression already carried in the country specially in the Southern States that the passengers travelling in these trains have no safety—whether such a conspiracy is there? The same gangs are operating several times. What machinery has been engineered to stop all this.

MR. DEPUTY SPEAKER : You keep on repeating.

SHRI K. LAKKAPPA : I have not repeated. You can take action, if even a word has been repeated.

MR. DEPUTY SPEAKER : I will show you. You will yourself know this tomorrow when you go through all this.

PROF. MADHU DANDAVATE : Let me first totally refute the charge that either in the past or at present there is any civil war between the Home Department and the Railway Department. I completely refute that. Then again there is no conspiracy on the basis of language at all. Robbers and dacoits have a language of their own, and that is the language of dacoity and language of robbery..... (Interruptions) I do not want to inject the language issue into the question of dacoity and robbery at all. I had already given a statement of robberies and dacoities state-wise that have taken place and you cannot expect any one particular language group to be responsible for dacoities throughout country, and therefore, I refute that charge altogether. I do not want either the Southern States or the Northern States to be alleged that they are responsible for any type of conspiracy.

But there are certain vulnerable areas where the law and order situation is bad. He made reference to one particular portion of Madhya Pradesh. There we have enforced our machinery and I tell the House very firmly that after the enforcement of that machinery, after 11th of August particularly, in that particular area of Madhya Pradesh, not a single dacoity and robbery has been successful.

श्री लक्ष्मण : जो स्टेटमेंट टेबल पर रखी है उससे यह मालूम होता है कि 1-1-77 से 30-6-78 तक यानी डेंग साल की परवाह में सारे देश में 184 राज्यों और 76 इकाइयों परी हैं और राज्यों में 3,50,000 और इकाइयों में 5,88,000 करीब की सूट हुई है। विहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बैंगलोर में राज्यों और इकाइयों द्वारा परी है। स्टेटमेंट के मालूम होता है कि सर्वे रेलवे द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वे उत्तराखण्ड में हैं और काश्मीर को रोकने में मदद मिली है प्राप्त यह कहा है :

"The Railway Protection Force constituted under the RPF Act has preventive and detective powers only in respect of lawful possession of railway property. The RPF is concerned with the protection of goods entrusted to the Railways for carriage and Railway materials".

इन्हीं दृष्टियों से यह रेलवे प्राप्ती को प्रोटेक्ट करे और इनिवेंट को प्रोटेक्ट करे। ऐसैजर्ज की प्राप्ती और जनको लालू की प्रोटेक्ट करने की उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं समझता हूँ कि रेल वंचालय ऐसैजर्ज की लालू की प्राप्ती को रेल कला हो और राज्य सरकारों से जी विजित तालिकेल की बहात है। मैं जानता चाहूँ हूँ कि यह सरकार ऐसा करने जा रही है?

श्री० मधु दंदावते : यहसे जी हो बार मैं बता चुका हूँ कि बार भी एक की जुलियाई की जिम्मेदारी बहा है। लेकिन हम लोगों का अनुभव यह यह है कि हमेसा बार भी एक के लोगों को जब हम लोगिज में रखते हैं और जी बार भी की जो परार्ज है उसकी तरफ आप न जाए। लेकिन

The very existence of RPF acts as a deterrent.

इकाइयों और राज्यों पर अंकुर लगाने में बदल मिलती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि रेलवे के पान्दर जें यात्रायम होती है, इसकी इनिवेंट होती है उनकी रकम करने के लिए जी के कीविज के अन्दर रह सकते हैं उनकी और जी बार भी का कोलोनियल अंकुर बह रहा है। पूरे रिकॉर्ड में नहीं देता है। लेकिन जितनी इस साल और तिले साल औरियों हैं, उन में प्राप्ती का कितना भाग रिकॉर्ड हुआ वह मैं भागको देना चाहता हूँ। इस साल कितनी प्राप्ती औरी हुई उसका भी सरपरेंट रिकॉर्ड हुआ है जबकि पिछले साल वह पररेंट हुआ था। लेकिन हमें लंबाव नहीं हैं; हम और जी तरफी करना चाहते हैं। लेकिन वह पररेंट के तरफी जीस परसेंट तक हुई है।

SHRI T. A. PAL: Sir, for the last 30 years we never had a situation like this that law and order is given a go-bye and the railway passengers have become victims of robbery and dacoity. It has always been the explanation of the Railway Minister that this is a problem for which the State Governments are responsible. Now, is it the fault of the passenger who travels long distance that the train has to go through so many States and in every State he has to look to the State Government to look after him, or is it the primary responsibility of the Railways who have undertaken to give him this journey, to protect his interests? The Railway Minister has said that the State Governments have agreed to cooperate and prevent such occurrence. But we do not know how far that would be effective. Even if he is able to get all the assistance from the State Governments, will he give an undertaking to the country that the Railway Ministry itself will be responsible if there are losses, and the lives and the property is the responsibility of the Railways? And this is a question which cannot be avoided. Otherwise, I think this explanation will not satisfy anybody and travelling by railways is going to be more and more hazardous.

PROF. MADHU DANDAVATE: The hon. Member himself was fortunately a Railway Minister. I have got with me all the statistics. He has raised very relevant questions. I do not want to attribute any motive to him. He has raised the question: Will the Railways shirk the responsibility and let the entire matter of safety of passengers be left only to the State machinery? I want to assure him that though there are certain jurisdictional problems, sitting together we have already been able to tackle them and without raising this technical issue the recent coordination that we have brought about is able to ensure better safety.

In addition to what I stated earlier, I want to state that in addition to joint patrolling by RPF and GRP men especially in the vulnerable sections where more robberies are taking place, we have taken some additional care. Sometimes when the dacoits commit an act of dacoity and try to run away, the passengers do not know and probably other staff members do not know whether the train has stopped because there is no signal or there is some mischief. When therefore, there is a pulling of the chain, we have set up a certain code whistle by the engine driver. As soon as that is given, all the policemen, GRP men and RPF men on the train divide themselves into two batches, one will go to the left of the train and the other will go to the right of the train and if it is evening or night, we have made special arrangements and put

powerful lights on both sides of the train. Wherever vestibule trains are there, at 10 O'Clock in the night the vestibule doors will be kept closed. Only between two coaches the vestibule door will be open because it has to be protected by RPF and GRP men. For two coaches we have set up this machinery and I can assure the hon. Member that especially after the tightening of this machinery incidence of crime, robbery and dacoity has gone down and therefore, as demanded by the hon. Member, I can assure this House that we shall not shirk the responsibility, but we will undertake the responsibility that has devolved on us.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, I charge the Minister for deliberately misleading the House. On 16th August at 2 O'Clock in the night between Nagpur and Bhopal there was a robbery in the Andhra Express. I was also present there at that time. There is a report in Bhopal. Whatever he said is absolutely wrong. This happened in the air-conditioned chair car. Two brief cases were snatched away and the train was stopped and the robbers went away. The people went to the constable who was sitting in the compartment throughout the night. In spite of the complaint the constable did not take any action. In the morning at 07.30 hrs. all the passengers forced the train to stop at Bhopal for nearly two hours and have a complaint to the police. Unfortunately all your arrangements are not effective. You must think of some more stringent methods which will infuse confidence into the people who travel by train. I request the Minister not to mislead the House, but to take more effective steps and see that nothing happens.

PROF. MADHU DANDAVATE: It is never my intention to mislead the House. I have concretised the various steps that are taken and they are working well. If you have listened to my reply very carefully, I did not say that after 11th August, not a single effort was made by the dacoits and robbers. All that I have said is that they made efforts after 11th of August, but they did not succeed.

(Interruptions)

SHRI A. BALA PAJANOR: I am forced to believe from what the hon. Minister said that nothing has happened for the last 15 days. He wanted that to be on record. But he should not say that. He must admit it.

PROF. MADHU DANDAVATE: I have never tried to mislead this House. I want to make it clear that I used the words.....(Interruptions) Please listen to me. There are three types of things that are happening in the trains, there are sometimes thefts, there are robberies and there are dacoities. Please check up

the records. Sir, you may also check up the records. I did not say that thefts have not taken place in trains. You can check up the records. The hon. Members may laugh. But in my written statement, I had drawn a distinction between minor thefts, robberies and dacoities, where people openly come and indulge in such activities. The particular instance, to which the hon. Member has made a reference, is a theft. You can yourself check the records. In my tabulation also, I have divided the crimes into thefts, robberies and dacoities and I have given separate charts for them. Therefore, minor thefts are taking place and I have never said that there are no thefts. But there are no armed robberies and dacoities in which gangs are coming and successfully doing such things. That is what I have said and I stand by that. As far as this particular theft is concerned, I will try to enquire into the matter and give the details.

Salaries and perquisites of Chairmen and Managing Directors of Union Carbide and other Companies

*492. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have by now taken a decision to slash appropriately the fantastic salaries, allowances, perquisites drawn by the Chairmen/Managing Directors, Executive Directors and other top executives in public limited Companies like Union Carbide and others;

(b) if so, what and if not, the reasons therefor; and

(c) the difficulties which lie in the way of Government in taking necessary action to cut down the very high salaries etc. which have a direct bearing on the prices of consumer articles manufactured by such Companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SATISH AGRAWAL) (a) to (c). The question of the revision of the existing guidelines relating to the remuneration payable to Managing Directors/Whole-time Directors/Managers of Public Limited Companies and Private Companies which are subsidiaries of Public Limited Companies is still under consideration of the Government. It is not possible to give further details.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: In our country, the salary of the first citizen of this country, the President of India is

Rs. 10,000 a month, the salary of the Chief Justice of India is Rs. 5,000 a month and the salary of the Prime Minister, if I am right, is about Rs. 3,000 a month.

Now, this is the information that I have in hand. In Bata, the Managing Director's Annual remuneration is Rs. 2,70,630, for the Products Research & Development Manager Rs. 2,55,395, the Unit Manager Rs. 2,04,162. These are the figures per annum. It comes to roughly Rs. 20,000 a month. In Colgate Palmolive (India) Private Limited, the Managing Director gets Rs. 2,12,424, the Director (manufacturing)—Rs. 2,16,900 and in Cadbury (India) Limited the Managing Director gets Rs. 2,10,460; in Glaxo Laboratories, the Managing Director gets Rs. 2,42,712 and the Director, Technical Division gets Rs. 2,16,521. I have got one or two more examples.

I gather that there is a ceiling of Rs. 7,500 on the basic salary. How is it that in the case of Cadbury (India) Limited, Mr. D.W. McPhie has been given a salary of Rs. 7,700, which exceeds Rs. 7,500 and how is it that in the case of Colgate Palmolives, Mr. H. Rai, an Indian national is given a salary of Rs. 10,000 a month and a total remuneration which exceeds Rs. 2,12,000? In this context, I would like to ask the hon. Minister to give us the break-up of these high salaries that have been paid to the Executives of the different multinational companies and big business houses of India. What is the maximum percentage on profit that you allow as commission to executives of companies?

SHRI SATISH AGRAWAL: So far as the break-up of the remuneration that is permissible under the Company Law is concerned, I may inform the hon. House that for salaries, the maximum limit is Rs. 7,500 per month, which comes to 90,000 per annum.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: How is it that Mr. McPhie is getting more?

SHRI SATISH AGRAWAL: I will come to that later. I am just submitting what is provided under the law. Under the law, there are four items. One is Salaries, the maximum limit of which is Rs. 7,500 per month, which comes to Rs. 90,000 per annum. Then comes, the Commission on profits at the rate of one per cent subject to a maximum of 50 per cent of the salary, i.e., Rs. 45,000 per annum; then, perquisites limited to one-third of salary i.e., house rent, car telephone and club subscription, the maximum ceiling being Rs. 30,000 per annum and that makes a total of Rs. 1,65,000. The fourth category is approximate value of benefits not included

in the third category above, viz., perquisites, i.e., Provident Fund contribution upto ten per cent of the salary, Rs. 9,000 per annum; contribution to pension/superannuation fund upto 15 per cent of the salary, Rs. 13,500 per annum leave travel concession approximately equivalent to one month's salary Rs. 7,500 per annum medical facility Rs. 5,000 per annum; Gratuity at the rate of half month's salary Rs. 3,750 per annum plus reimbursement of actual entertainment expenditure Rs. 6,000 per annum, that makes a total Rs. 44,750 per annum under this head. The total of these four heads come to Rs. 2,09,750 per annum. These are the outside maximum ceiling limits prescribed under the law.

So far as the specific instances are concerned, for the expatriates there is a different limit.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Mr. Rai is an Indian national.

SHRI SATISH AGRAWAL : I do not know about Mr. Rai. You know more than I do about persons. You have been in Parliament for twenty years and I have not been here. So, I do not know about individuals. But I will look into the matter. But these are the maximum limits that have been prescribed under the law. So far as some large houses, about which you were enquiring, are concerned, I may give the details of the position that exists in some of the large houses. For example, in Godrej Soaps Limited, Dr. B.P. Godrej gets a salary of Rs. 7,500 per month plus a commission of Rs. 45,000 per annum. Similarly, in Guest Keen Williams Limited, Shri Sukhendaray gets Rs. 7,500 plus Rs. 45,000 commission; in J.K. Chemicals Limited, Mr. V. Singhania gets Rs. 6,000 per month as salary, in Tata Iron & Steel Company Limited, Mr. R. H. Mody gets Rs. 7,500 as a salary plus Rs. 45,000 as commission; in Greaves Cotton & Co. Mr. Mathrani gets Rs. 7,500 per month as a salary and Rs. 45,000 as commission, in Hoechst Pharmaceuticals Limited, Shri R. Bink gets Rs. 10,000 per month as salary, in this case he may be a repatriate in Dunlop India Limited, Mr. M.W.L. Logan, Whole time Director gets Rs. 7,500 per month as salary and half percent of the profit as commission subject to a maximum of Rs. 30,000 per annum. Of course, in the case of repatriates, the limits are somewhat different. They are decided on the basis of technical knowhow, their requirements, and the administrative ministry makes a recommendation to the Company Law Board and then they give their approval. It may be a different thing. (Interruptions)

MPs are not appointed by the Company Law Board, but they are elected by the people at large. Mr. Patwari cannot be appointed as a whole time director of a company buy the Company Law Board, but he can be elected as a Member of Parliament by the people.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Mr. Agrawal has not replied to my question as to how Mr. H. Rai why is not an expatriate—who is very much an Indian national—of Colgate Palmolive gets a salary and remuneration of Rs. 2,12,424 (Interruptions) which exceeds Rs. 2,10,000; How is it being allowed? Mr. Balidik of Bata, who is only a Commerce graduate and who is not a technocrat gets Rs. 2,70,650. Last year, he has got Rs. 3,10,000. I would like to know how these were allowed and how these are being allowed now. My second question is, he has stated in his reply—this shows the lack of political will on the part of the Government, as it was the case with the previous Government—

"The question of the revision of the existing guidelines relating to the remuneration payable to Managing Directors/Whole-time directors/Managers of Public Limited Companies and Private Companies which are subsidiaries of Public Limited Companies is still under consideration of the Government. It is not possible to give further details."

I would like to ask a specific question here. Since what date this is lying with the Cabinet and why is it that it has been delayed to this extent?

SHRI SATISH AGRAWAL : The decision with regard to the fixation of ceiling for managerial remuneration is pending with the Cabinet. In the month of October '77, Government appointed a study group under the chairmanship of Shri Bhoothalingam and this committee submitted its report somewhere in May, '78. This is being studied. The report of the Sachar Commission is also to be received by the Government. In the light of these two reports the Government is to take a final decision. When the final decision is taken, these things will be considered.

श्री राज विलास गतेश्वर : उपर्युक्त महोदय, एक तरफ इस देश में लोगों की सतता कामबक्ती 250 द० भी नहीं है। लोग जानवर भी तरह जीवन व्यौत्त करते हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट कम्पनियों के प्रबिकारियों को दृढ़ जाता है। सतता विवाह में इस बात पर विचार करेंगे कि इस देश में किसी भी कर्मचारी का, जाहे वह सरकारी कर्मचारी ही नैरसरकारी कर्मचारी हो, किसी का बेतन 500 द० से कम नहीं होता और 2,000 द० ...

श्री एम्. एम्. बटवारी : किसी का बेतन एम्. पी. से ज्यादा न हो।

श्री राम विजय यात्रवाल : मैं पूछता चाहता हूँ कि किसी भी सरकारी या बैर-सरकारी कर्मचारी की जो तमाम तरह की सुविधायें और बेतन हैं उन सब को मिला कर 500 द० से कम नहीं होना चाहिए और 2,000 द० से अधिक न हो ज्यादा इस पर सरकार विचार करें ?

श्री सतीश यात्रवाल : यहीं तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि 500 क० से कम किसी का बेतन, जहाँ और कम सुविधायें नहीं होनी चाहिए और 2,000 द० से अधिक किसी को नहीं मिलना चाहिए, स्वतंत्र और प्राधिकरण नियंत्रित करने के सम्बन्ध में जो उन्होंने प्रश्न किया है, अस्तित्व पर से भी उनकी राय से सहमत हो सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में कभी तक सरकार ने कोई नीति नियंत्रित नहीं की है। इस सम्बन्ध में सरकार के सामने जारा प्रश्न विचाराधीन है और सरकार चाहती है कि मानवादी के स्वतंत्र को बढ़ावा देये, कम किया जाए और कम से कम किया जाए।

SHRI SAUGATA ROY : I do not agree with the Minister when he refers to the Bhoothalingam Committee report which has been totally rejected. (interruptions). In a large number of Indian companies also, salaries beyond Rs. 10,000 per month are being given. The Minister has not replied to Part (c) of the question of Shri Jyotirmoy Bosu as to what are the difficulties being faced by the Government in the question of reducing the salaries, whether the difficulties are that in principle, the Government is opposed to the reduction of the large salaries in private sector undertakings or whether there are other positive legal hurdles in the way of reducing the salaries in the top private sector undertakings.

SHRI SATISH AGRAWAL : There are no legal hurdles in the way of the Government so far as the reduction in the remuneration is concerned. So far as the question of principle is concerned, the Government is not opposed to the idea of limiting or putting a ceiling on the remuneration of the whole-time Directors, Managing Directors and business executives. As I said earlier, the Sachar Committee report is to be received by the Government and one of the terms of reference is this. After studying the report, Government will take a decision very soon in the matter.

श्रीबाबू बतवार तिंह : उपचार महोब्य, यह रिपोर्ट की स्टडी करने का क्या सामन है ? सीधा सा सा याद दंडी से लंडी कोई लिमिट भूकर करने को तैयार है कि किसी मानवीय ज्यादा से ज्यादा किसी मानवी को सामाना मिल सके ? वह रिपोर्ट सो बताती जायेगी, शूलिंगम

कमेटी के समावाह कोई भीर कमेटी बैठ जाएगी यह कांपेस या साथा ज्यादा पर कितनी देर रहेगी ? याप कितनी देर लगायेंगे, जबत के बाबत इसके लिए बहुत भूकर करें। ज्याप यह भी भूकर करें कि ज्यादा से ज्यादा तानवाह पह होगी, इससे कर नहीं होगी ?

श्री सतीश यात्रवाल : कम्पनियों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में निर्णय कर्लैंका बहुत भीष्म सरकार का विचार है, इसमें किसी प्रकार का विलम्ब करने का सरकार का विचार नहीं है और जल्दी से जल्दी इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

प्रतिवेदिक (एकीकायोडिक) व्यावसायों की कमी

* 491. श्री यहानीष किंवद्दन सामन : क्या येटो-लिमिट रेलवान और उर्वरक भंडी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में प्रतिवैधिक घोषणाओं की बहुत कमी है ; और

(ब) यदि हाँ तो सरकार डारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

येटोलिमिट तथा रेलवान और उर्वरक भंडी (ये हेमवती नम्बर बहुगुण) : (क) और (ब), जिन एकीकायोडिक्स कार्मलेजनों के बारे में बेतन के विविध भागों से कमी की रिपोर्ट आज तुम्हें है, वे स्टैटोमाइक्सीन इनजेक्शन और स्ट्रैप्टो वेसिलिन इनजेक्शन हैं। एक वेसिलिन का पायांन उत्पादन होता है लेकिन अन्तर्रिट्रीन बाजार में अपरिवर्त उत्पादन तो कार्यकारी प्राप्ति इनजेक्शन लेजेट के लिए के पहुँचने के परिणाम स्वरूप उपरोक्त कार्मलेजनों की कमी हो गई थी।

स्टेट कैमिकल्स एवं एकीकायोडिक्स कार्मलेजन थाक इंडिया लि. ने इन कार्मलेजनों के उत्पादन के लिए विविध बायारों को जब बहु स्ट्रैटोमाइक्सीन सल्फेट की पर्याप्त जागा की समाप्त कर दी है। परिम-जून, 1978 के दौरान हिन्दुस्तान एकीकायोडिक्स लि. और इंडियन इंजेक्शन इंडस्ट्रीज का उत्पादन भी बोंबे की तुलना में आंतिक रूप से अधिक रहा है।

Earnings from passengers and goods Transportation

*494. SHRI DHARMA VIR VASISHT : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether earnings in the first quarter of the current year from passengers and goods on Railways suffered as compared to the same period last year;

(b) if so, the details of the same month-wise with reasons;

(c) whether working expenses in the same period increased; if so, to what extent; and

(d) whether Government still hope for a sizeable surplus this year, and the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE):

(a) and (b). As compared to the period ending June 1977, there has been an increase of Rs. 12.51 crores under passenger earnings and a shortfall of Rs. 14.57 crores under goods earnings during the quarter ending June 1978. Month-wise details of the earnings under passenger and goods traffic is as under:

(Figures in crores)

Month	Passenger Earnings	Goods Earnings	1977-78	1978-79
April	53.00	56.11	118.85	111.97
May	62.07	64.77	116.02	112.89
June	54.40	61.10	109.42	104.86
Total upto June	169.47	181.98	344.29	329.72

The Railways' gross earnings during April to June, 1978 amounted to Rs. 544.96 crores, which was Rs. 9 lakhs more than the earnings of the corresponding quarter of the last year (Rs. 544.87 crores).

Shortfall under goods earnings has been as a result of a drop in tonnage lifted to the extent of 5.28 million tonnes compared to the budget target for the quarter ending June 1978 and 3.11 million tonnes as compared to the corresponding period of last year.

The various sectors affected include collieries, washeries, steel plants, ore mines and ports. The drop in loading in these sectors was largely due to shortfall in production and other factors.

(c) During the period ending June, '78 there has been an increase of Rs. 29.68 crores under working expenses as compared to the period ending June, 1977.

(d) It is too early to make a forecast as to whether a sizeable surplus will be achieved by the end of the year. Efforts

are continuing to overcome the operational difficulties in respect of goods traffic and if the lost ground in respect of goods traffic can be regained during the remaining months of the year, our expectations regarding achieving a surplus during the year will be fulfilled.

Cases of looting of passengers in South bound trains

*495. SHRIN. SREEKANTAN NAIR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) how many cases of looting of railway passengers have been reported this calendar year in the South bound trains leaving New Delhi/Nizamuddin/Delhi Stations.

(b) what steps have been taken to prevent the mounting looting of railway passengers;

(c) whether the victims of looting had been given compensation by the Railways, if not, whether the Railway will seriously consider such a proposal while intensifying security measures at least in long-distance trains; and

(d) whether the newly introduced alarm system is a success?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE):

(a) During this calendar year, so far, there have been four cases of looting of railway passengers in the South bound trains leaving New Delhi/Nizamuddin/Delhi Stations.

(b) The responsibility of ensuring the personal safety of the passengers and the security of their belongings rests with the Government Railway Police which functions under the administrative and disciplinary control of the State Governments. Crime prevention and detection in respect of passenger safety and security of their belongings fall under the category of 'law and order' which is a State subject under the Constitution. However, the Railways render necessary assistance whenever required and close liaison is maintained at all levels with the State Police Agencies. The Railway Protection Force constituted under the RPF Act has preventive and detective powers only in respect of unlawful possession of railway property. The R.P.F. is concerned with the protection of goods entrusted to the Railways for carriage and Railway materials.

On 16-6-1978 a high level meeting between the officers of the Ministries of Railways and Home Affairs was

held. The following firm decisions were taken which have yielded very encouraging results:

- (1) As the dacoits/robbers were silencing the passengers by show of fire arms and escaping after commission of crime generally by pulling alarm chain under cover of darkness a prompt channel of communication to the armed police guard whenever alarm chain was pulled at night was considered necessary. It was decided that the alarm chain whistle should be sounded repeatedly by the driver. On hearing of this alarm the armed police escort should split themselves in two parts and de-train to apprehend escaping criminals.
- (2) The Police escort should be accommodated together as far as possible in the centre of the train and they should be equipped with powerful torches.
- (3) The police escort party may progressively be equipped with very light pistols which would be useful in lighting up the area on both sides of the train at night.
- (4) The Guard and Brakemen should be provided with powerful torch lights in vulnerable trains over affected sections.
- (5) There should be liaison with the States principally affected for stepping up police protection. Chief Security Officers of Eastern, South Eastern, Northern and Central Railways were specifically nominated to maintain close liaison with the State Police authorities of West Bengal, Bihar, U.P., Madhya Pradesh and Maharashtra. The CSOs of other Railways were directed to maintain liaison with above 4 Chief Security Officers. They were directed to indicate to the State Governments the strength of police guard which should be required on vulnerable trains and request the State Police authorities to provide the necessary protection. The requirements of State Governments have been projected to Ministry of Home Affairs.

The Zonal Railways have launched a drive to ensure strict adherence to the following preventive measures in coaches.

- (i) Vestibuled doors are kept locked between 22.00 hrs. and 06.00 hrs. by the Travelling Ticket Examiners/ Coach Attendants.
- (ii) Travelling Ticket Examiners and Coach Attendants remain vigilant

during night time and prevent entry of intruders, hawkers and unauthorised persons into the coaches.

- (iii) In case of non-vestibuled trains, the vestibuled doors are permanently closed or dummied.

The above measures formulated are in continuation of the various preventive steps taken by the Government Railway Police under the State Governments. The G.R.P. being alive to the problem adopt several regular preventive measures which are given below:

- (1) Escorting of important trains at night by armed guards of Government Railway Police of the concerned State Government.
- (2) Beat patrolling at stations; platforms/ waiting halls.
- (3) Surveillance over criminals and known bad characters.
- (4) Checking of night trains by Supervisory Officers.
- (5) Armed pickets at vulnerable stations.
- (6) Special Squads of the C.I.D. of the State Govts. take up investigation of important cases to apprehend the gangs responsible for these crimes.

These measures have been intensified by the Government Railway Police.

As a further measure to deal with occurrences of train robberies and dacoities, the Minister of Railways ordered deployment of armed RPF to escort the affected trains running in vulnerable sections. Primarily, they will protect railway property and will also help to instil confidence amongst the travelling public and deter criminals from operating on trains. Over 1400 armed RPF men were put on escort duty on different Railways from the first week of July, 1978. Since 16th August over 2000 R.P.F. personnel have been deployed in escorting trains. Being concerned with the spate of heinous crimes in Madhya Pradesh area, Minister of Railways had written to the Chief Minister of Madhya Pradesh requesting him to take special measures to curb crimes in running trains. He had also spoken to him on phone on August 19, 1978. In the affected Divisions viz. Jhansi and Nagpur, 220 RPF personnel are escorting 20 trains of which 16 are long distance trains and 4 short distance trains. 30 GRP personnel are escorting 9 long distance trains. The

South-bound trains escorted are (1) G.T. Express, (2) Dakshin Express, (3) Jayanti Janata Express, (4) Jammu Tawi Express, (5) Tamil Nadu Express, (6) Andhra Pradesh and (7) K.K. Express.

(c) Crimes like robberies, including those committed on trains, is a law and order problem which is a State subject. Under extant rules, no compensation is admissible to the victim of such crimes.

(d) Yes, Sir. On 15-8-1978 while RPF was escorting 131 Down Jayanti Janata Express, its alarm chain was pulled near outer signal of Bhopal. The RPF escort on hearing the code whistle got down and apprehended one person who pulled the chain. He was handed over to G.R.P., Bhopal, for prosecution.

Concession in Railway Freight Charges

*496. SHRI BHARAT SINGH CHOWHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in order to promote country's export trade Government have agreed in principle to help by way of giving concession in railway freight charges;

(b) if so, whether Government will introduce this scheme in respect of all exportable commodities; and

(c) if not, the names of the commodities in respect of which this concession will be given?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) :

(a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

Dacoity in Aligarh-Chandausi Local Train

*497. SHRI YADVENDRA DUTT: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether on 1st July, 1978 Aligarh and Chandausi local train was stopped and more than a dozen armed dacoits entered the train and looted it;

(b) have the criminals been traced and arrested; and

(c) steps to prevent such high rise of crimes on Railways?

THE MINISTER OF RAILWAY (PROF. MADHU DANDAVATE) :

(a) There was no dacoity on 1-7-78 in Aligarh-Chandausi local train. But there

was a dacoity in 355 UP Passenger train (Aligarh-Bareilly) on 29-6-78/26-78 (night). When the train started from Bhojpur station 5 to 6 persons who were already sitting in the compartment threatened Sh. Ajay Bahadur Johri and his friends with country pistol and looted property worth Rs. 700 (Approx.), Government Railway Police, Chandausi registered crime No. 81 dated 4-7-78 under section 395 IPC (Dacoity). The case is pending investigation.

(b) So far, there has been no recovery of property nor has any arrest been made.

(c) The responsibility of ensuring the personal safety of the passengers and the security of their belongings rests with the Government Railway Police which functions under the administrative and disciplinary control of the State Government. Crime prevention and detection in respect of passenger safety and security of their belongings fall under the category of law and order which is a State subject under the Constitution. However, the Railways render necessary assistance whenever required and close liaison is maintained at all levels with the State Police Agencies. The Railway Protection Force constituted under the RPF Act has preventive and detective powers only in respect of unlawful possession of railway property. The RPF is concerned with the protection of goods entrusted to the railways for carriage and railway property, materials and stores.

Being concerned over crimes on Railways, Minister of Railways had drawn attention of Chief Minister of Uttar Pradesh through Demi Official letters. On 5-8-78 there was a high level meeting between Minister of Railways and Chief Minister of U.P. in which problems of crime were highlighted.

On 16-6-1978 a high level meeting between the officers of the Ministries of Railways and Home Affairs was held. The following firm decisions were taken which have yielded very encouraging results:

(1) As the dacoits/robbers were silencing the passengers by show of fire arms and escaping after commission of crime generally by pulling alarm chain under cover of darkness a prompt channel of communication to the armed police guard whenever alarm chain was pulled at night was considered necessary. It was decided that the alarm chain whistle should be sounded repeatedly by the driver. On hearing of this alarm the armed police escort should split themselves

in two parts and de-train to apprehend escaping criminals.

(a) The police escort should be accommodated together as far as possible in the centre of the train and they should be equipped with powerful torches.

(b) The police escort party may progressively be equipped with very light pistols which would be useful in lighting up the area on both sides of the train at night.

(c) The Guards and Brakemen should be provided with powerful torch lights in vulnerable trains over affected sections.

(d) There should be liaison with the States principally affected for stepping up police protection. Chief Security Officers of Eastern, South Eastern, Northern and Central Railways were specifically nominated to maintain close liaison with the State Police authorities of West Bengal, Bihar, U.P., Madhya Pradesh and Maharashtra. The CSOs of other Railways were directed to maintain liaison with above 4 Chief Security Officers. They were directed to indicate to the State Governments the strength of police guard which should be required on vulnerable trains and request the State Police authorities to provide the necessary protection.

The Zonal Railways have launched a drive to ensure strict adherence to the following preventive measures in coaches:—

(i) Vestibuled doors are kept locked between 22.00 hrs. and 06.00 hrs. by the Travelling Ticket Examiners/ Coach Attendants.

(ii) Travelling Ticket Examiners and Coach Attendants remain vigilant during night time and prevent entry of intruders, hawkers and unauthorised persons into the coaches.

(iii) In case of non-vestibuled trains, the vestibuled doors are permanently closed or dummid.

The above measures formulated are in continuation of the various preventive steps taken by the Government Railway Police under the State Governments. The G.R.P. being alive to the problem adopted several regular preventive measures which are given below:

(1) Escorting of important trains at night by armed guards of Government Railway Police of the concerned State Government.

(2) Beat patrolling at stations; platforms/ waiting halls.

(3) Surveillance over criminals and known bad characters.

(4) Checking of night trains by Supervisory Officers.

(5) Armed pickets at vulnerable stations.

(6) Special Squads of the C.I.D. of the State Governments take up investigation of important cases to apprehend the gangs responsible for these crimes.

These measures have been intensified by the Government Railway Police.

As a further measure to deal with occurrences of train robberies and dacoities, the Minister of Railways ordered deployment of armed RPF to escort the affected trains running in vulnerable section. Primarily, they will protect railway property and will also help to instil confidence amongst the travelling public and deter criminals from operating on trains. Over 1400 armed RPF men were put on escort duty on different Railways from the first week of July, 1978. Since 16th August 1978 over 2000 RPF personnel have been deployed in escorting trains.

The following trains are escorted in Aligarh-Chandausi section jointly by Railway Protection Force/Govt. Railway Police:—

	Escort	RPF	G. P.
3 AB Passenger train Bareilly to Aligarh	Bareilly	1-3 Armed	2 both ways.
2 ACM Aligarh-Chandausi Moradabad-Passenger.	Aligarh- Morad- abad	1-3 Armed	2 both ways.
356 Dn. Bareilly-Aligarh.	Both ways 1-3 Armed a		
355 UP Aligarh-Bareilly			

In all 87 passenger trains are being escorted by Railway Protection Force, 206 by GRP, of which 60 trains are jointly escorted by RPF and GRP in U.P.

In these duties 690 RPF and 328 GRP men have been deployed in Uttar Pradesh.

Union Office Bearers Transferred from Delhi to Jodhpur Division

*498. SHRI CHANDRADEO PRA-SAD VERMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some office bearers of recognised Railway Union of Delhi Division were transferred from Delhi Division to Jodhpur Division in April, 1978

(b) whether some departmental enquiry proceedings were instituted against them during emergency for some previous claim cases;

(c) whether all other employees, against whom same or similar proceedings have been instituted, have also been transferred; if not, the reasons thereof;

(d) whether there are policy orders to the effect that office bearers of recognised union cannot be transferred without the consent of the unions, unless it is a case of promotion or a vigilance case is substantiated against such office bearers; if so, whether the trade union officials so transferred to Jodhpur Division come under the above category; and

(e) whether it is also a fact that thirteen Members of Parliament had made the representation in May/June, 1978 against the above mentioned transfers; if so, whether the transfers are being cancelled or pended as a result thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAO): (a) A Chief Parcel Clerk at New Delhi Station, who is also the Vice President of the Uttar Railway Mazdoor Union, New Delhi Branch, was relieved on transfer to Jodhpur Division on 30-4-1978.

(b) Proceedings under the Railway Servants Discipline & Appeal Rules 1969 for imposition of a major penalty were initiated against him in September 1976.

(c) No, Sir. Orders transferring the Chief Parcel Clerk were issued for administrative reasons.

(d) The extent policy orders to provide that the office bearers of recognised unions should not be transferred without the concurrence of the unions. However, the General Managers of the Zonal Railways have special powers to order transfers even without such concurrence, after giving them an opportunity to have their say.

(e) Yes, Sir. Representations have been received from Members of Parliament against the transfer. The case is under consideration.

Delay in Laying Pipelines system from Salaya to Viramgam and Koyali Refinery

*499. Shri D. N. TIWARY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether there has been considerable delay in laying the pipeline system from Salaya to Viramgam and from Viramgam to Koyali refinery;

(b) when the tender was called for and when it was finalised;

(c) the reasons for the delay in the execution of this project; and

(d) losses incurred due to non-laying of this pipeline?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (d). Separate tenders, one for the construction of the Viramgam-Koyali pipeline, and another for the Salaya-Viramgam pipeline were called by Indian Oil Corporation in December, 1975 and March, 1976 and the orders were placed in March, 1976 and July, 1976 respectively. The Viramgam-Koyali section was to be completed by June, 1977 and the Salaya-Viramgam section by October, 1977. The works were, however, actually completed in May, 1978 and June, 1978 and there was thus a delay of 11 months and 8 months respectively beyond the contract dates.

2. The pipeline project is designed to feed crude to the Koyali Refinery in the context of its capacity expansion from 4.3 million tonnes per annum to 7.3 million tonnes per annum.

3. The delay in the completion of the contracts for laying the pipelines as compared to the completion dates mentioned in the contracts is mainly due to (a) delay in arrival of specialised construction equipments from abroad, (b) non-availability of blasting material, (c) failures occurring in the pipes during hydro-static testing of the Viramgam-Koyali pipeline, etc. Particular mention may be made of the numerous failures in the 18" line pipes used in the Viramgam-Koyali pipeline which has contributed mainly to the delay in completion. In fact the pressure rating of the pipeline had to be reduced from 93 kg/cm² as originally specified to 80 kg/cm² in order to successfully complete testing of the pipeline. However, the desired throughput of 5 million tonnes per year will still be achieved.

4. The contracts provide for grant of extension of time for completion as well as for levy of liquidated damages for delays caused beyond the extended time of completion

Disparity in Wage Structures and Allowances of Various Drug and Chemical Undertakings.

*500. SHRI R.K. MHALGI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a great disparity in the wage structure and allowances of the various drug and chemical units/undertakings controlled by Government;

(b) whether Government have any proposals to bring them in line with other firms in private sector and maintain a uniformity in the wage structure and allowances at least among the chemical and drug firms controlled by Government; and

(c) what are the reasons for this delay in implementing the I.L.O. convention of equal pay for equal work?

THE MINISTER OF PETROLEUM & CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Wage structures and allowances vary in the units under the control of Government.

(b) There is no proposal to bring about uniformity with the private sector. As a matter of fact, it cannot be said that there is any degree of uniformity in this regard within the private sector itself.

While approving wage agreements in public sector undertakings, Government take into account among other things, the wage structure prevailing in respect of comparable posts in other similar public sector undertakings, keeping in mind also other relevant factors like regional wage conditions.

(c) The relevant I.L.O. Convention prohibits discrimination in the payment of wages on the ground of sex. It does not provide for the payment of equal wages for the same or similar type of work in different establishments.

महावेबुर—बिहुर रेलवे स्टीमर सेवा

*501. डा० रामजी तिहू : क्या रेल मंत्री यह बताने की रुग्ण करेंगे कि :

(क) बटारो-महावेबुर-बिहुर रेलवे स्टीमर सेवा कितने बर्षों तक चलती रही है और यह यत तीन बर्षों में इतकी बीच बीच में बदल कर रिए जाने के बाबा कारण है;

(ख) क्या रेल मंत्री के सामाजिक सेवा वर्ष वह रेलवे स्टीमर सेवा बदल कर भी रखें है;

(ग) क्या कुछ रेलवे विभागीय तीन बर्षों के प्रयास के पश्चात इह सेवा को बाह्यव्यवस्था बाह्यव्यवस्था में बदल करने में सक्षम हो गए है ताकि प्राइवेट बायपरेटरों की ताक हो सके; और

(घ) उपर्युक्त रेलवे स्टीमर सेवा पुनः क्या बाल होनी चाही रखा क्या इसके प्रयास वर्ष भी बदल रहने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (जी शिव नारायण) :
(क) और (ख). याना बिहुर-महावेबुर बाट रेलवाही सेवा और महावेबुर बाट तबा बारीचाट के बीच स्टीमर सेवाएं 1975 की साताब्दी के प्रसिद्ध दशक से चल रही हैं। 1975 से याना में भारी बाट के कारण भानपुर की प्रवर्षित में सेवाओं में बदलाव हो गई है। इस बर्ष भी बाट के कारण 20-7-78 से सेवा रद्द कर देनी पड़ी थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जैसे ही नदीय पर्सरिस्प्रिलियां अनुकूल होंगी, ये सेवाएं फिर चालू कर दी जायेंगी। प्रयास वर्ष इन बेवालों का चालू रखना प्रथमा इन्हें रद्द करना इन बाबे पर नियंत्र करेगा कि उस समय पर्सरिस्प्रिलियां जैसी रहती रहती हैं।

Rail Finances in a Jam

*502. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state,

(a) whether attention of the Government has been drawn to the news report appearing in the National Herald dated 23rd July, 1978 under the caption "Rail finances in a jam";

(b) if so, what is the reaction of the Government to the various observations made therein;

(c) the facts of the matter; and

(d) details regarding the action taken/proposed to be taken?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Yes, Sir.

(b) The news report refers to the drop in the Railways' goods loading and traffic earnings and to certain factors that have added to the working expenses. The report contains some inaccuracies and has drawn exaggerated conclusions.

(c) The facts are as under:—

(i) *Gross Earnings* :—

The Railways' gross earnings during April to June, 1978 amounted to Rs. 544.96 crores, which was Rs. 9 lakhs more than the earnings of the corresponding quarter of last year (Rs. 544.87 crores) but were short of the budget proportion for the current year (Rs. 568.46 crores) by Rs. 23.50 crores. While the earnings are more than the budget anticipations in respect of Passenger, Parcels and Miscellaneous, there is a drop in total earnings due entirely to a set-back in Goods traffic.

(ii) *Originating Goods Loading* :—

The Revenue goods loading during April to June, 1978, was 49.62 million tonnes as compared to 52.73 million tonnes during the corresponding quarter of last year and the budget proportion of 54.90 million tonnes. The current year's loading, therefore, shows a drop of 3.11 million tonnes as compared to last year and is short of the target by 5.28 million tonnes. The various sectors affected include collieries, washeries, steel plants, ore mines and ports. The drop in goods loadings in these sectors was largely due to shortfall in production and other factors.

(iii) *Working Expenses* :—

The Working Expenses during the first quarter of the current year amount to Rs. 389.18 crores as against Rs. 359.50 crores in the corresponding period of last year. The expenditure during April to June, 1978 is within the budget for the current year.

The allegation that some of the additional expenses to be incurred during the current financial year were deliberately not taken into account at the time of the presentation of the Railway Budget, is not correct. The decisions regarding revision of running allowance, payment to staff as a result of the adjustment of the strike period in May, 1974 with leave due, payment of additional dearness allowance and increase in steel prices, were all post-Railway budget developments, which could not be taken into account while finalising the Railway Budget presented to Parliament on 21.2.1978. The recommendations of the Railway Workers' Classification Tribunal are also under finalisation which will involve additional expenditure.

(iv) *Upgradation/creation of additional posts at the higher level* :—

As per the decision of the Government of India on Third Pay Commission's Recommendation, a review of the Class I Cadres/Services has to be made once in three years. The first review of the Railway cadres was made in 1973-74. The second cadre review has now been taken in hand. It is premature to furnish the details of the proposals at this stage.

(v) *Staff Relations* :—

While it is true that there have been a few agitations in some parts of the railway system, it is an exaggeration to describe "widespread discontent among the staff" as the sole factor responsible for the deterioration in operation. On the other hand, very special attention is being paid to the redressal of staff grievances and to the settlement of various economic demands of the labour. Apart from the announcement regarding the reinstatement and vacation of punishments of all those who have been penalised after the 1974 strike, several measures have been taken to improve the service conditions of Railway employees. Industrial relations on the Railway are very satisfactory now and conducive to efficient working of the system. Minor 'pin-pricks' here and there in a vast organisation like the Railways are inevitable and are not a matter of great concern.

(d) The Railways have been given directions to step up traffic earnings, particularly the performance under Goods, and also to pursue vigorously the measures to control working expenses. As a result of strict monitoring of various operations particularly connected with goods loading and regular coordination between Ministry of Railways, Energy, Industry, Steel & Mines, Labour and Finance, overall performance in July 1978 has improved considerably. The originating loading in June 1978 was 23193 (B.G.) and 5191 (M.G.) wagons per day. In July 1978 it increased to 23803 (B.G.) and 5228 (M.G.) wagons per day.

रेलवे स्टेशनों पर फैटीम और बूक स्टाल

* 503. जी चतुर्वेद : या रेल मंत्री यह बताने की हुए करें कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर कितने फैटीमों और बूक स्टालों के देहे 31 मार्च, 1977 को समाप्त हो गए हैं ;

(ख) उनमें से कितने थे के आगामी बर्तों के लिए पिछले फैटीमों के नाम दिए गए हैं ;

(a) यह सरकार ऐसे ठेके हेते के मामले में इरिजनों और पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेष सुविधाएं और प्राप्तिकर्ता देगी ; और

(b) यदि हाँ, तो ऐसी विशेष सुविधाओं का पूरा व्योंग क्या है ?

ऐसा व्योंग में राज्य बंडी (भी यिल माराफ्ट) ;
(c) के (प).

रेलवे स्टेशनों पर कंटीनों और बूक स्टाल

आनंदनाल और रेलवे टेकों के आवंटन के लिए अनुचित जातियों और अनुचित जनजातियों के व्यक्तियों की तरजीह दी जाती है । जोकिन बड़े स्टेशनों के टेकों के आवंटन में इस प्रकार की काँई तरजीह नहीं दी जाती ।

गाड़ी के निकट बोम्बे लगाने और टोटे-टोटे स्टाल लगाने जैसे छोटे ठेके यद्य प्रवेशन व्यक्तियों और अनुचित जनजातियों के उन्नादवारों को ही प्राप्तिकर्ता किये जा रहे हैं । वह टेकों के मामलों में भी अन्य बातें सामान होने पर अनुचित जाति/अनुचित जनजाति के व्यक्तियों को यद्य प्राप्तिकर्ता क्षमता से तरजीह दी जाती है ।

31-3-77 को ठेके समाप्त हो जाने वाली कंटीनों और बूक स्टालों की संख्या और पिछले ठेकेदारों के नाम में दिए गए ठेकों की संख्या से संबंधित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख ही जाएगी ।

Global Tenders to Import Wheel Sets

*504. SHRI CHITTA BASU : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway Board have recently invited global tenders to import wheelsets;

(b) whether it is also a fact that Durgapur Steel Plant offered to supply such wheelsets; and

(c) if so, why the global tenders have been invited?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Yes, Sir. The following five Global Tenders have recently been invited :

(i) GP-79 for 1280 Nos. Wheelsets for the manufacture of Broad Gauge ICF Type Coaches.

(ii) GP-80 for 3000 Nos. 20-Ton Wheelsets for the manufacture of BOX/RH/CRT Wagons (BG).

(iii) GP-84 for 3200 Nos. 20-Ton Wheelsets for manufacture of BOX/BRH/CRT Wagons (BG).

(iv) GP-82 for 264 Nos. Wheelsets for the manufacture of DC EMU Coaches.

(v) GP-83 for 3340 Nos. 16-Ton Wheelsets for the manufacture of BG Tank Wagons.

(b) The supplies offered by Durgapur Steel Plant are being accepted by the Railways in full; and,

(c) Global Tenders are invited only in those cases where the supplies made by Durgapur Steel Plant or Tata Iron & Steel Company fall short of the requirements of the Railways for meeting the maintenance needs of Coach and Wagon-building Programmes or where the manufacture of certain types of Wheelsets has not been developed by Durgapur Steel Plant and Tata Iron & Steel Company.

Drilling work near Suthri Village, Kutch.

*505. SHRI ANANT DAVE : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether drilling platform for oil is ready near Suthri village in Kutch District;

(b) whether the drilling work is going to start this year;

(c) whether the work has now been entrusted to ONGC; and

(d) if so, what is the progress in this regard and when this work will be completed?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) :

(a) to (d). A location near Suthri was released by the ONGC in September 1978 for exploration of Mesozoic and Tertiary prospects. A foundation on this location for the deployment of rig was also constructed. However, in view of the further geological information obtained by the ONGC in the area, the onland drilling at Suthri has been deferred.

Decline in Freight Earnings

*506. SHRI C. K. JAFFER SHARIFF : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there has been any decline in freight earnings during last six months; and

(b) whether Government have taken steps to meet all outstanding orders for wagons even for movement of low priority items?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE)

(a) Yes, Sir.

(b) Steps have been taken to meet all outstanding demands for wagons, including low priority traffic. As a result, the number of outstanding indents has been brought down by 20% on the B. G. and 30% on the M.G. as on 16th August, 1978 as compared to the demands at the end of June, 1978.

Length of Railway Lines in Bihar Adivasi Areas

*507. SHRI AGHAN SINGH THAKUR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to unstarred question No. 95 on 21-2-1978 regarding length of railway lines in Bihar Adivasi areas and state:

(a) whether any decision has since been taken regarding construction of the lines mentioned as surveyed; and if so, the details thereof, and

(b) if not, the reasons therefor and the time by which a decision will be taken?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) and (b). No decision has so far been taken regarding construction of lines mentioned in the reply given to unstarred question No. 95 on 21-2-1978. The limited funds which are made available are not sufficient even to meet the requirement of projects which are already in hand. The decision regarding construction of these lines would, therefore, depend upon the allocation of funds in the coming years.

रेलवे कारबानों से चोरी गई चतुर्थ

*508. जी बास्तवी जाहि : क्या रेल नंदी यह बताने की क्षमा करें कि :

(क) क्या देश में विभिन्न रेलवे बंकारियों से सम्बन्धित कर्मचारियों की सापराही के कारण ग्रेट बंड लाइन रेल के माल की चोरी होती है जिससे सरकार को भारी हानि होती है ; और

(ब) यदि हाँ, तो उसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल नंदालय में राज्य नंदी (जी शिव नारायण) : (क) आपराधिक गतिविधियों के कारण ग्रेट

बंड बीसलन लखमग 2 लाख रेलवे कारबानों से चोरी बता जाता है ।

(ब) रेलवे कारबानों से रेलों के सामान की ओरी/उडाईपीरी की दोक-बाम के लिए नियमितिवाल निवारक उपाय किये जा रहे हैं :

(1) ग्रनाविहृत प्रबंध प्रबन्ध बिना गेट पास के सामान को बाहर ले जाने को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा दल द्वारा कारबानों के द्वारा पर नियमित बहरा देना ;

(2) कारबानों को नियमित दोवार के बारों प्रोर रेलवे सुरक्षा दल द्वारा गारा लाना ;

(3) खाली माल डिव्हें तथा सभी वाहनों के साथ-साथ कारबानों से बाहर चारे बाहे सभी अग्रिमों की जांच करना ;

(4) रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा साथी पालाक में घरपाल-प्रामूख्यना एकत्र करना तथा सन्वेद्धित्र व्यक्तियों पर कड़ी नियाह रखना ;

(5) नियमित युविल विभाग के साथ निकट समर्पक बनाये रखना ;

(6) कारबानों में लैनात रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी अपनी दृश्यती पर सतर्क रहते हैं और भली प्रकार अपनी दृश्यती नियाहते हैं, इस बात को सुनियनित करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के पर्यावरक कर्मचारियों द्वारा कारबानों में अचानक गवत लगाया जाता है ;

(7) कारबानों में बूल्दान बासी ताले में इच्छा भीर लीन लगाकर रखी जाती है ;

(8) कारबानों में राति के समय यह लगान में कुत्ता दल का उपयोग भी किया जाता है ;

(9) कारबानों में आपराधिक बुनियादी सुरक्षा प्रबन्ध भी किए जाते हैं ।

Accommodation and other Facilities for Judicial Administration

*509. PROF P. G. MAVALANKAR : Will the Minister of LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the judicial administration in the whole country has been suffering for want of proper office and court accommodation, basic facilities and amenities for the judicial officers etc. at many places in various States of the Union;

(b) if so, what concrete and effective steps are being taken by Government to correct and improve the said situation and for how long and at what expenses during the years 1976, 1977, 1978; and

(c) broad outline of the improvements, if any, effected in this regard?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Additional duty to the Managing Directors of Orissa F.C.I.

4739. **SHRI PADMACHARAN SAMANTASINHERA:** Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) is it a fact that the Managing Director of Orissa F.C.I. (Talcher) is given additional duty work other than his own duty;

(b) if so, what is the additional work attached to him and how many days he was absent from Headquarters since last two years upto date; and

(c) for this additional work what is the additional remuneration/T.A. drawn by him since last two years?

THE MINISTER OF PETROLEUM CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) and (b). The position as reported by the company is as follows:

Industrial Licence and capacity	Cost and sources of finances for the project	Position of the project
(i) Nitrile rubber—2000 tonnes per annum.	Project cost Rs. 140.2 lakhs Sources of Finances :— (a) ICICI (b) LIC (c) Internal resources of the company.	Project has been implemented.
(ii) Butadiene Catalyst—60 tonnes per annum.	Project cost Rs. 39.41 lakhs. Entirely financed from internal resources of the company.	Project has been implemented.
(iii) A.B.S.—2000 tonnes per annum	..	Project is under implementation. Industrial licence is valid upto 8-12-1979.

Issue of a Letter of Intent to Colgate-Palmolive India Limited

4741. SHRI P. K. KODIYAN :
SHRI YADVENDRA DUTT :

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether Government have issued a letter of intent to Colgate-Palmolive India Limited to manufacture menthol;

(b) whether it is a fact that the small units engaged in the industry are capable of meeting the entire domestic demand of menthol; and

(c) if so, what are the details and reasons for granting permission to a multi-national to enter into this field?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes, Sir.

(b) The exact demand estimate of menthol has not been made. The present demand of menthol is, however, met by the existing units, both in the organised sector and small-scale sector.

(c) The project which envisages production of menthol from natural Mentha grass was sanctioned on the strong recommendations of the State Government of J & K as this will promote the agricultural economy of the backward area in the State. An export obligation of 60% of the production of menthol has been imposed to protect the interests of small scale units.

मंत्री सेवकों से इन्वेस्टिगेशनों का जनाया जाए

4742. श्री तुरेन्द्र लाल तुमन : क्या देशी लियन, रसायन और चर्चरक मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में कितनी बोगत कर्म नक्की सेवकों तथा छाड़ों में इन्वेस्टिगेशन तथा धरमिकिय दोषियों सज्जाई कर दी गई थी और उनके विषय परा कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या दोषियों में धरमिक दो रोकने हेतु धोषध नियंता कर्मी की अवाकाश बांध करने के लिए कोई योजना बनाय कराये का सरकार का विचार है ?

देशी लियन तथा रसायन और चर्चरक मंत्री (वी हैवानी नाम सहित) : (क) और (ख) दोनों एक्स्ट्री की जा रही है और तभी पटल पर रही जाएगी ।

Representations forwarded by Local M.L.As. and Members of Parliament to the Management of F. C. I., Sindri

4743. SHRI A. K. ROY : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) what is the number of letters of representations forwarded by the local M.L.As. and M.Ps. received by the Management of the Sindri Unit of the F.C.I. and their dates of receipt;

(b) whether it is a fact that despite clear Government instruction to acknowledge such letters immediately and to give a final reply within 21 days most of them have remained unattended and unanswered;

(c) whether it is a fact that the F.C.I. management also adopts discriminatory policy to the C.I.T.U. affiliated F.C. Kamgar Union led by the local M.L.As. and the M.Ps.; and

(d) if so, reason thereof ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) :

(a) to (d). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Inadequate facilities at Ottappalam Station

4744. SHRI K. KUNHAMBU : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that facilities at Ottappalam (Kerala) Railway station are inadequate; and

(b) if so, what are the steps taken to improve the facilities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) The facilities provided at Ottappalam Railway station are considered adequate for the present level of traffic offering at this station.

Movement of Coal and Wheat

4745. SHRI MOHINDER SINGH SAYAN WALA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the task of gearing the railways to perform adequately and efficiently in the revival and growth of the economy did not receive

due attention when it failed to cope up with the right movement of coal and wheat, *inter-alia*; and

(b) if so, what steps are being sought to be taken to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) Does not arise.

Resolution from All India Railway Accounts Employees' Association

4746. SHRI ROBIN SEN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received a resolution passed by the All India Railway Accounts Employees' Association and also by the Danapur Branch, Eastern Railway; and

(b) if so, the demands of the Accounts Staff and steps taken by Government to finalise each demand?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) In the absence of details it has not been possible to identify the resolution referred to. Necessary information is being collected and will be laid on the table of the House.

Action against M/s. Alkali and Chemicals for Illegal Activities

4747. SHRI S. S. DAS : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether in spite of the fact that it has been brought to the notice of the Government that the activities of Alkali and Chemicals are illegal, no action has been taken in the matter; and

(b) why protection is being granted for illegal activities and why the price approvals have not been cancelled?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) and (b). No, Sir. Government have already instructed State Chemicals and Pharmaceuticals Corporation of India Ltd. and M/s. Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited to stop release of canalised raw materials to M/s. Alkali and

Chemical Corporation of India. The company were also asked on 24th May, 1978, to stop the manufacture of such formulations as are presently manufactured by them under loan licence arrangements but are not covered by any Industrial Licence. The company have represented against this decision of the Government. On the prices side, the West Bengal State Drug Controller has been instructed to ensure that the company complies with the revised lower prices for propranolol Hcl. fixed by Government. Thus needed action has been taken in the matter.

Proposal to bring Medical Store Depots under the Ministry

4748. SHRI A. MURUGESAN : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Government Medical Store Depots under Ministry of Health and I.D.P.L. under Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers are performing almost the same work;

(b) if so, whether Government have examined the above and the details thereof; and

(c) the action proposed to be taken to bring the Medical Store Depots under the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) and (b). The primary functions of the Medical Stores Organisation, a Government body under the Ministry of Health and Family Welfare, is to supply on payment, the requirements of hospitals and dispensaries in different States. In particular they handle the supply of bulk of the material required for various National Programmes like Malaria Eradication Programme, T. B. Control Programme, Cholera Control Programme and Family Welfare Programme. Emergency supplies are also arranged by them as relief measures in the case of floods, cyclone and other natural calamities. They function on a no-profit-no-loss basis.

The Medical Stores Depots at Bombay and Madras have factories attached to them which produce about 100 common Pharmaceutical preparations comprising

mainly tinctures, syrups, ointments, tablets and surgical dressings.

I.D.P.L. a public sector undertaking under the Department of Chemicals and Fertilizers are engaged in the manufacture of bulk drugs and formulations consisting of Penicillin, Streptomycin, Tetracycline, oxytetracycline, Griseofulvin, Vitamins, Sulphas, Analgesics, Antipyretics, Tranquillizers, Anti-amoebic, Diuretics, Anti-reheumatics, Anti-tuberculars, Anti-filarials Anthelmintics, hypnotics, Anti-Confulsants, Contraceptive pills and Anti-microbials etc. They also manufacture some fine chemicals. They manufacture various types of Surgical Instruments also. They have marketing organisation to market their products on a commercial basis throughout the country both to Government institutions as well as the trade. R and D activities are also undertaken by them to stabilise and up-date available technologies, improve process know-how and develop new products.

Hence there is no comparison or duplication between the roles of Medical Stores Depots and I.D.P.L.

(c) There is no proposal under consideration at the moment to bring the medical Store Depots under the control of the Ministry.

Use of 'Selson' as Shampoo by M/s. Abbot

4749. SHRI GOVINDA MUNDA - Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. Abbot used 'Selson' as a shampoo to the tune of Rs. 38 lacs in violation of Excise Duty rules;

(b) whether fungus is added to Selson; if so, how it could be a shampoo; and

(c) when did the company remove Selson from their list of shampoos and under what provisions of I (D & F) Act they were allowed to do so ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) :

(a) 'Selson' labelled earlier as 'Dandruff Treatment Shampoo' manufactured by M/s. Abbot, Bombay, is a subject matter of dispute between the Central Excise Department and the manufacturer since 15th of June, 1976. The Government of India have issued a show cause notice dated 18-5-1978 to manufacturer under

Section 35A of the Central Excise and Salt Act, 1944 to review the decision passed by the Collector of Central Excise, Bombay, to continue classifying the product under Tariff Item 14E and the matter is pending decision. If Govt. decides to classify the product on the basis of the above findings under Tariff Item 14E of Central Excise Tariff then the differential central excise duty on clearances of 'Selson' effected from July '75 till May '78 upto about Rs. 3782 lakhs. From June '78 onwards, no clearances have been effected for Selson for home consumption.

(b) Commissioner, Food and Drug Administration, Maharashtra, has confirmed that the preparation of Selson does not contain any fungus.

(c) The matter is under examination.

Proposal to fix selling price of Bulk Drugs

4750. SHRI YASHWANT BOROLE : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether in terms of new Policy common selling price for bulk drugs based on the cost of production of major efficient producers are proposed to be fixed; if so; the basis on which such prices shall be fixed;

(b) how Government will protect new and small scale units who have generally high cost of production; and

(c) whether any representations were received in this regard and if so, Government's reaction to such representation ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) The Pricing Policy which forms a part of the Statement laid on the Table of the Lok Sabha on the 29th March, 1978 containing Government decisions on the report of the Committee on Drugs & Pharmaceuticals Industry (Hathi Committee) envisages that where the indigenous bulk drug is produced by more than one manufacturer, a common selling price for sale to all formulators will be fixed initially on the basis of the average cost of production of relatively more efficient firms which account for a large percentage of the output.

(b) and (c). Representations from the Associations of Drug Manufacturers on the question of providing protection to the new and small scale units in the matter of price

fixation were received. It has been clarified to them that Government may fix a weighted average price with separate retention prices for individual firms in appropriate cases, where there are substantial differences in the cost of production of any bulk drug among the different manufacturers.

Release of canalised bulk Drugs for various Drugs and non-drug Units

4751. DR. VASANT KUMAR PANDIT : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) details regarding name, quantity and date of recommending release of canalised bulk drugs for various drug and non-drug units by his Ministry to the CPC/IDPL during the last 2 years;

(b) provisions of policy under which each of these letters were issued; and

(c) whether through this mechanism certain foreign and Indian companies have been helped and if so, details of unintended benefit in the form of more raw materials obtained by them?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) and (b). Min. of P. C. & F. (Department of C & F) laid down parameters for distribution of canalised bulk drugs within the frame-work of Import Trade Control Policy to Small Scale and DGTD units. Clarifications arising out of the application of the distribution policy were also given as and when sought.

During 1975-76 and 1976-77 action was taken to regulate releases of Methyl Dopa

and the position in this regard has already been indicated in reply to part (b) of Lok Sabha Starred Question No. 503 answered on 20-12-77. Details of instructions issued for release of Methyl Dopa during 1976-77 are given in the attached statement.

In 1977-78, the Deptt. issued allocation orders in respect of L-base to individual units in accordance with the Ministry of Commerce notification No. 42-ITC(PN)/77 dated 2-7-77. Details of these allocations are also indicated in the attached statement.

As regards the circumstances in which CPC were asked to release 1.5 kgs. of Prednisolone in favour of M/s Warner Hindustan Ltd. during 1977-78, the relevant details have already been furnished in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 8802 answered on 2-5-78.

Certain releases of Vit. B 1, Vit. B 2 and Folic Acid were also cleared by the Deptt. in 1977-78 in favour of a few non-drug units. The details of such releases and the circumstances under which these were cleared have already been furnished in reply to Lok Sabha Starred Question No. 341 answered on 8-8-78.

On 29-12-77, CPC were asked to release 16 kgs. of Vit. 'A' in favour of M/s Mysore Snackfoods Ltd., Bangalore who required it for being utilised in the manufacture of extruded ready-to-eat food for use in the mid-day meal programme of the Education Deptt. of Government of Karnataka. It is, however, not known whether the material was actually supplied by the CPC.

(c) As the action taken by the Deptt. was based on well-defined policy and principles, the question of certain foreign and Indian companies deriving unintended benefits does not arise.

Statement

Name of canalised bulk drug/raw-material	Date of recommendation	Name of Company	Quantity (kg.)	1976-77
				1
Methyl Dopa	3-8-76	IDPL	5000	
		Merch Sharp & Dohme	2000	
		Dey's Medical Stores	2000	
		Themis	2000	
		Suneeta Labs.	2000	

1	2	3	4
---	---	---	---

		Gujarat Pharmaceuticals	200
		Jagson Pal & Co.	200
		Unique Chemicals	200
		Cadila Lab.	200
14-9-76		Dolphin Laboratories Pvt. Ltd.	200
26-11-76		G. I. Laboratories	600
28-2-77		Cadila Labs.	50

For 1976-77 &
1977-78

L-Base	19-7-77	Day-Sc-Chem.	45000 (1977-78 only)
	19-8-77	Microbe Labs.	2374 (1977-78 only)
	19-7-77	Trichem Labs.	2968
	19-8-77	Nectrine Pharmacy.	5805 (1977-78 only)
	19-7-77	Vitco Labs.	2691
Do.	Imperial Pharmaceuticals		2242
Do.	Usan Labs.		7514
Do.	Metro Chemicals		575
Do.	Fine Organic		575
Do.	British Pharmaceuticals		2942
Do.	Unique Pharmaceuticals		575
	19-8-77	Jagson Pal & Co.	3951 (1977-78 only)
	28-7-77	Pharmachem	6198 (1977-78 only)
	19-8-77	Pharma Indiana	3348 (1977-78 only)
Do.	Piya Pharma		1365 (1977-78 o n)
	19-7-77	Syntholab	575
	19-8-77	Pure Drug (India)	2340 (1977-78 only)
Do.	Jatin Pharma		1267 (1977-78 only)
	21-9-77	Nirlac Pharmed	1040 (1977-78 only)

1	2	3	4
L. Basc	19-7-77	Allied Chemicals & Pharmaceuticals	575
Do.	Basic Pharma	575	
Do.	Bombay Drug House Pvt. Ltd.	575	
Do.	Gratus Pharma	575	
Do.	Sundeep Drugs Pvt. Ltd.	575	
Do.	Poly Drug Chem.	575	
Do.	Theo Pharma	575	
Do.	Champharma Chemicals & Pharmaceuticals Products	575	
Do.	Intrachem	575	
Do.	Reverie Pharmachem.	575	
Do.	Gufic Pvt. Ltd.	575	
Do.	Suchem Lab.	575	
Do.	Vichem Labs.	575	
Do.	Barichem India Ltd.	575	
Do.	Biomex Remedies	575	
Do.	Orion Chemicals	575	
Do.	Avron Pharmaceuticals	575	
19-8-77	J. K. Pharmaceuticals	250 (1977-78 only)	
27-8-77	Premier Pharmachem.	250 (1977-78 only)	
5-9-78	Pharmayuth Chemicals	1047	
8-9-77	Polydrug Laboratories	575	
Do.	Imphachem Industries	575	
Do.	Santosh Pharmaceuticals	575	
28-9-77	Sunchem Laboratories	250 (1977-78 only)	
20-1-78	Canberra Chemicals	Do.	

Pilferage or Theft of Fertilizers from Fertilizer Factory

from fertilizer factories during the last three years; and

(b) what steps are being taken to prevent such recurring losses due to pilferages?

4752. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) what is the amount of loss suffered by way of pilferage or theft of fertilizers

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) and (b). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Trains for people travelling to New Delhi from neighbouring States

4753. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) what is the approximate number of people who travel daily to New Delhi from neighbouring States;

(b) is it true that the trains by which they travel are frequently behind schedule and the commuter can never be sure of reaching the office or place in time ;

(c) is it also true that such commuters swarm into the reserved compartments and cause great inconvenience to the other passengers; and

(d) if so, what steps are being taken to set the above things right ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) About 25,000.

(b) No. Punctuality performance of local trains in Delhi area is satisfactory.

(c) Cases of commuters entering reserved coaches around Delhi and other important stations, have come to the notice of the Railway Administration.

(d) Staff manning reserved coaches have instructions to ensure that unauthorised passengers do not enter the reserved coaches. At times, however, it becomes difficult to control such passengers. Surprise checks are conducted and unauthorised passengers travelling in those coaches are dealt with as per rules. Cases of deliberate negligence on the part of the staff manning reserved coaches are viewed seriously and appropriate action taken against them.

Discussions with Chairman Indian Oil Corporation by representatives of Refinery Works Union

4754. SHRI AHMED M. PATEL : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether representatives of the Barauni Oil Refinery Works Union met the Chairman of the Indian Oil Corporation recently to resolve the dispute arising out of the 'go slow' tactics launched by the Technical Staff of the refinery ;

(b) if so, the nature of the talks held; and

(c) the reaction of the Government in this regard ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes, Sir.

(b) The major demand made by the various unions and different groups of workers during the talks was a removal of stagnation among the employees. An offer was made to the representatives of the various unions providing stagnation relief to employees of single cadre posts by giving them one scale higher as personal to them without change in their job and designation. This is on the basis of a similar offer made to the recognised union of Gauhati Refinery and accepted by them. However, the Unions at Barauni have made demands for reducing the limit of 12 years to as low as 5 years and have demanded that the scheme should cover categories of employees in posts other than single cadre also.

(c) The matter is under examination.

Vacancies Filled by Promotions and Direct Recruitment

4755. SHRI SHIV SAMPATI RAM : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of vacancies filled by promotions and direct recruitment in each class/category and grade over Allahabad, Bikaner, Delhi, Firozpur, Jodhpur, Lucknow, Moradabad and railway electrification of Northern Railway and how many among them were from SC/ST and how many of them were belonging to Non-SC/ST in the year 1977 ;

(b) the number of vacancies in each class, category and grade which had come to the share of SC/ST as reserved quota including carry forward vacancies ;

(c) whether the entire vacancies in reserved quota were fully subscribed (give details); and

(d) if not, whether any special steps are being taken to a secure adequate representations of SC/ST and wipe out the back-log ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (d) . Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

प्राक्त के परिवहन से लिए रेलगाड़ियाँ

4756. श्री वर्षभूत लाल घेट : क्या रेल बंदी यह बताने की हुया करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सोराष्ट्र लोक के राजकोट जिले में भावावारा, धोरावी, शीर उपजोड़ा द्वेषी,

आवानगर जिसे में जाम-बोधपुर और जालपुर स्टेशनों, जूलाह जिसे में बेराबल और कोइर स्टेशनों और आवानगर जिसे में महुआ भावि स्टेशनों की (स्टेशन-वार) 16 मई से 31 जुलाई, 1978 तक और जामरी से जूलाई, 1978 तक बलांग-बलग किसी बैचन पायाज के परिवहन के लिए धार्यदित किये गये;

(क) क्या पायाज के लकड़ान हेतु बहु बैचनों की कमी की ओर रहि है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पायाज नष्ट होने वाली वस्तु है और रहि हो, तो क्या पायाज के लिए बैचनों की समाई हेतु इस वर्ष कोई समय-न्यूनी तैयार की गई है और क्या इनसे वर्ष के लिए भी इस प्रयोगन हेतु कोई उल्लं तूंची तैयार करने का प्रस्ताव है?

रेल अंतर्राष्ट्रीय में राष्ट्र अंतरी (भी लिख यातायात);

(क) कंबल विवरण में व्योता दिया हुआ है।

(ग) इस यातायात की निकासी न्याय-धिक क्षण से साव-साय होती रही है। लेकिन,

जब इसी बढ़ी हुई बांगों की पूर्ति के लिए बाल दिव्यांगों की बचाई हुआई बढ़ी लोंगे दैवांगों पर बांग पर रह कर दिये जाएं।

(ग) पायाज यातायात एक कमी उम्मी अनुदूषी के अनुसारे नहीं किया जा सकता है क्योंकि पायाज के लिए जालदिव्यांगों की बांग बहुत से स्टेशनों के लिए हासी है और वे जांगे न्यायिक अनुदूषी कर की जाती है जितका सबूत यह है कि यातायात के समाई कर देने पर उनके लिए बांगल (इंडेट) बढ़ी लातार में रह कर दिये जाते हैं। परं भी, यह अनुदूषित करने के लिए कठबूत उठाये जा रहे हैं कि यातायात कोई अनुदूषी नहीं यात बही है, तो भी जहां तक सम्भव होता है, पायाज यातायात को भाल दिल्ला आंदोलन के लिए अधिकाहत उच्च प्रावधारिकता दे कर बचावी धार्य-मान्य यातायात अनुदूषी के प्रत्यर्थी 'ब' प्राविनिकादा लेकर, पायाज से लड़े भाल दिल्लों के दृष्टिकोण पर कही नजर रख कर तथा भांवरीनी परियांग दिल्लों धार्य को दूर करने के लिए उनकी मानीदारिंग करके जल्दी से जल्दी भेज दिया जाये।

विवरण

स्टेशन	पायाज से लादे गये माल-दिव्यांगों की संख्या		31-7-78 को बकाया पंचीकरण	मांग-देवों का रह करना देना
	15-6-78	31-7-78		
1	2	3	4	5
आवानगर	.	214	953	16 1187
धोरांगी	.	87	356	28 581
उण्लेटा	.	65	250	5 301
जाम-बोधपुर	.	18	92	.. 259
जालपुर	.	4	7	1 3
बेराबल	.	230	823	2 1375
कोइर	.	7	42	6 154
महुआ	.	8	586	147 600
आवानगर	.	..	683	.. 359

Survey of lines during 1978-79.

4757. SHRI GIRIDHAR GO—MANGO : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the names of the lines included for survey for the year 1978-79 and in the Sixth Plan in the State of Orissa to convert into B.G. lines;

(b) the reasons for non-inclusion of Naupada-Gunupur N.G. line for survey; and

(c) progress of the work and programmes for the new lines to be included?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (c). A reconnaissance engineering-cum-traffic survey for the conversion of Rupsa-Talband narrow gauge line into broad gauge and its extension up to Gorumanisani / Chakulia has been taken up during the current financial year.

Surveys have also been taken up on the request of the Government of Orissa for construction of two new railway lines from Talcher to Sambalpur and from Koraput to Salur/Parvatipuram. Construction of the first phase of the Jakhapura

Banspani line from Jakhpura to Daitari is in progress. It is not proposed to consider conversion of Naupada-Gunupur narrow gauge line into broad gauge at present due to constraint of resources.

The list of new lines and conversion projects to be included in the Sixth Plan has not yet been finalised.

Demand for halt of Nava Jeevan Express at Raichur

4758. SHRI RAJSHEKHAR KOLUR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a demand from a wide section of the people to provide a halt of Nava Jeevan Express at Raichur Railway Station in Karnataka ;

(b) if so, whether a decision has been taken to provide a halt; and

(c) if not, the reasons for such decision?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes, several representations have been received.

(b) and (c) 145/146 Ahmedabad-Madras Nava Jeevan Express provides fast service between these two cities. Provision of additional stoppages will slow down the train to the inconvenience of through passengers who have been representing for reduction in journey time.

Pilferage on Railways

4759. SHRI MADHAVRAO SGINDIA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the financial year 1977-78, the pilferage on Indian Railways was more than what it was in the previous years;

(b) if so, comparative figures for the last three years;

(c) whether as a result the railways had to pay a huge sum in the form of compensation; and

(d) if so, total amount paid during the last three years separately ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (d). The cases of pilferage during 1977-78 were 82,926 as compared to 86,985 during 1976-77, i.e. a decrease of 4,059.

The statistics of the number of cases and the amount of compensation paid in these cases of pilferage during the last three years are :

Year	Number of cases of pilferage	Amount of compensation paid	(in crores of rupees)	
			1975-76	1976-77
1975-76.	1,56,181	7.22		
1976-77.	86,985	5.46		
1977-78.	82,926	5.47		

Procurement of Oxytetracycline by M/s. Pfizer from IDPL

4760. SHRI BALWANT SINGH RAMOOHALIA : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1275 regarding manufacture of Oxytetracycline by M/s. Pfizer dated 25th July, 1978 and state :

(a) was the entitlement and actual release of Oxytetracycline effected in favour of M/s. Pfizer on the basis of policy parameters as indicated in reply to the said question ;

(b) how M/s. Pfizer were entitled for release of Oxytetracycline from IDPL when they themselves are licenced to produce this drug ; and

(c) whether M/s. Pfizer are still procuring Oxytetracycline from IDPL and if so, quantity supplied by IDPL during current year to M/s. Pfizer and whether IDPL have met the demand of other users of Oxytetracycline in full before supplying to Pfizer, under what provisions of policy these supplies have been effected ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Upto the year 1976-77, the releases of Oxytetracycline were made by IDPL as per demand received from various units because this drug was banned for import upto that year.

Oxytetracycline was canalised for the first time in 1977-78. M/s. Pfizer were entitled to a release of more than 20 tonnes during 1977-78, both in terms of the old policy regarding supply of canalised raw

materials and the revised policy announced in October, 1977, but they were actually supplied a quantity of 5'00 tonnes by IDPL.

(b) There are no guidelines or instructions that drug manufacturing units licensed for production of a particular bulk drug are debarred from obtaining supplies thereof from other manufacturers/suppliers' of the same drug.

(c) Yes, Sir. Oxytetracycline has been declassified and put on the banned list for the year 1978-79. For 1978-79, M/s. Pfizer registered a total quantity of 27 tonnes with IDPL with delivery schedule of 9 tonnes in the first quarter and 6 tonnes in each of the remaining three quarters. While IDPL have so far released a quantity of 15 tonnes of Oxytetracycline to M/s. Pfizer against the delivery schedule for the first two quarters, they have met the demand from other units also in full.

पूर्वोत्तर रेलवे से मान्यता आपत संघ

4761. की हुकम बन्द कल्पादाता : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की हुपा करेंगे कि :

(a) इस समय पूर्वोत्तर रेलवे में मान्यता आपत संघ का नाम क्या है;

(b) क्या किसी संघ ने मान्यता के लिए अपने दावे को प्राप्तिकारी भी है; और

(c) यदि हाँ, तो उसका नाम क्या है और इसे तदनुसार मान्यता न देने के क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्रालय के राज्य भंडी (की रिपब्लिक आरामधन) : (क) इस समय पूर्वोत्तर रेलवे पर नियन्त्रित हो यूनियनों को मान्यता प्रिसी हुई है :—

(i) एन० ६० रेलवे एम्प्लाइ यूनियन— यह भाल इंडिया रेलवे मंत्र के फेरेजन का साथ सम्बद्ध है।

(ii) एन० ६० रेलवे एम्प्लाइ यूनियन (पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ) — यह नेशनल फेरेजन आफ इंडियन रेलवे देने के साथ सम्बद्ध है।

(ब) और (ग) पूर्वोत्तर रेलवे अमिक संघ, जोकि एक मान्यता रहित यूनियन है, ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक को एक पत्र लिखा है जिसमें मान्यता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

मई 1977 में हुए लिपसीय मजदूर सम्मेलन के बाद कम मंत्रालय ने एक लिपसीय समिति स्थापित की थी जो अन्य बातों के साथ-साथ यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के मानदण्डों पर भारे में सिफारिश करेगी। सरकार ने योग्यताग्रन्थीक सम्बन्धों के बिना के बारे में उनकी रिपोर्ट पर विचार

कर रही है। यह तक इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली सामान्य नीति पर निर्भय नहीं लिया जाता तब तक ऐसे प्रकारतों द्वारा किसी नई दूसरी बात की मान्यता प्रदान नहीं की जा रही।

Progress of complete take over of Swadeshi Cotton Mills

4762. SHRI MOHAN LAL PIPIL : Will the minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to reply given to Starred Question No. 761 on 18th April, 1978 regarding Swadeshi Cotton Mills and state :

(a) the progress so far made by the National Textile Corporation in taking over complete management of Swadeshi Cotton Mills Company Ltd., Kanpur and its 5 units alongwith assets investments share, land, subsidiary company owning two sugar units etc; and

(b) why not other civil and criminal action/proceedings are taken against erring erstwhile management?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) Possession of six textile undertakings of Swadeshi Cotton Mills Company Limited, Kanpur, was taken by the National Textile Corporation Limited immediately after the issue of the Notification dated 13-4-1978 in terms of Section 18AA of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951. The question of take-over of other industries of the Company did not arise since such take-over would not have merited action under the said Act. Meanwhile, in terms of the arrangements approved by the Delhi High Court, National Textile Corporation is also in possession of certain portions of the premises of the Company.

(b) The Ministry of Industry which is concerned in the matter has informed that there is no move for any such action. As far as this Department is concerned, action under section 408 of the Companies Act, 1956 had already been taken but the matter is subjudice.

Representation from Sangli Municipal Council

4763. SHRI ANNASAHEB GOT KHINDE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether at the time of his visit on the 15th June, 1978, to Sangli, Maharashtra State, the President of the Sangli Municipal Council had made some representation to him regarding the amount of more than Rs. 13 lakhs paid by the said

council to the Railways as the price of the Railway land sold to the Council;

(b) if so, taking into consideration the fact that such blocking of funds has resulted in seriously affecting the developmental activities of the said council, whether Government will take a decision at an early date in the matter;

(c) if so, the probable date when the decision is likely to be taken;

(d) whether till then the Government will stay the demand of the remaining amount of about Rs. 5 1/2 lakh raised against the said council; and

(e) if not, the reasons for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) and (c). The land in question was handed over to the Municipal Council and other parties last year, but in view of the subsequent proposal for restoring Miraj-Sangli branch line, the Municipal Council and other parties to whom the railway land between Sangli and Miraj was handed over have been requested not to make any construction thereon. In case, it is ultimately decided to restore the branch line, the land will be taken back, otherwise it will be permitted to be used by the Municipal Council. It will however, take some time more before a decision is taken.

(d) Yes.

(e) In view of (d) above the question does not arise.

Promotion to Loyal Workers

4764. SHRI R. L. KUREEL : SHRI SUBHASH AHUJA :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 6514 on 11th April 1978 regarding promotion of coaching clerks as Commercial Apprentices at New Delhi Station and State further:

(a) whether such like promotions have been given to other loyal workers in Indian Railways;

(b) if not, reasons for giving preferential treatment to these employees;

(c) whether these employees were deputed by the Administration to work against the Railway Strike in 1974;

(d) if so, reasons for making them absent from their duty from 8th May, 1974 to

19th May, 1974 and declaring them loyal;

(e) if so, number of other employees given this type of preferential benefits to promotions in Northern Railway; and

(f) if so, the further redressal actions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No. There were no other such cases.

(b) As indicated in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 9638 answered on 9-5-78, there was only one solitary case. It was a case of fresh appointment as Commercial Apprentice against 20% quota for wards of Railway employees on the basis of service rendered by his father. There was no question of giving any preferential treatment in this particular case.

(c) to (f). Do not arise as there were no other employees similarly treated.

Change of name from Dumex to Pfizer

4765. SHRI MOHAN SINGH TUR : Will the Minister of PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) when it became known for the first time to his Ministry that Pfizer have purchased Dumex in India.

(b) when was the request for change of name from Dumex to Pfizer received by Government and what were the details furnished by Pfizer for seeking transfer of independent licence/approvals possessed by M/s. Dumex in their name; and

(c) when was the approval of Government granted for such change in name and on what basis and under what provisions was this change in name allowed by Government?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) to (c) M/s. East Asiatic Company, a Denmark based international Corporation were marketing, since 1946, Pharmaceutical products bearing the name of "Dumex" manufactured by a combine of six drug manufacturing firms known as Danish United Medical Export. On 21st November, 1950 this was organised as a Private Limited Company in the name of Dumex Limited, as a subsidiary of the Danish firm—East Asiatic Company.

In May, 1958, M/s. Dumex submitted an application for the issue of capital of Rs. 30 lakhs as preference capital of M/s. East Asiatic & Co. India Limited and Rs. 30 lakhs as equity capital to M/s. Pfizer,

Panama. They stated, as justification therefore, the fact that M/s. Pfizer proposed to invest and would also furnish technical know how etc. for the manufacture of antibiotics in India from the basic stage. This application was considered by the Govt. in 1958 and was agreed to with the approval of the then Minister of Industry.

On 10th June, 1960 Govt. agreed to the issue of shares worth Rs. 25.10 lakhs to M/s. Pfizer Corporation, Panama by M/s. Dumex Limited, Bombay for the establishment of a plant in Chandigarh for the manufacture of Oxytetracycline and Tetracycline.

In July, 1960 the East Asiatic Company (I) Pvt. Ltd. intimated that 15,000 preference shares out of c. 10,000 preference shares held by them in M/s. Dumex Limited were redeemed out of the accumulated profits, on the 3rd June, 1960. Hence, the East Asiatic Company (I) Pvt. Ltd. were left with only 15,000 preference shares with a value of Rs. 15 lakhs only. Thus M/s. Pfizer acquired controlling interest in M/s. Dumex Limited.

Later in 1960, a proposal was made by East Asiatic Co. (I) Pvt. Ltd. and East Asiatic Co. Ltd., Denmark wanting to sell all their shares in Dumex Limited amounting to Rs. 9.9 lakhs of the face value of Rs. 100 per share to M/s. Pfizer at Rs. 200 per share.

This proposal was agreed to in consultation with the then Ministry of Commerce and Industry and Department of Company Law Administration. The Department of Company Law Administration considered the price of Rs. 200 as fair and reasonable. The procedure at that time regarding consulting the concerned Administrative Ministry about association of foreign equity and the Department of Company Law Administration to check up the reasonableness of the price at which the shares would be transferred was duly observed in this case. Hence by the end of 1960 M/s. Pfizer acquired the entire shareholding of M/s. Dumex. As a result, M/s. Dumex Pvt. Ltd. ceased to exist as a separate Company in India, on its re-incorporation as M/s. Pfizer. The name of M/s. Dumex Pvt. Ltd. was subsequently changed to M/s. Pfizer and Industrial Licences and Registration Certificate held in the name of Dumex were also endorsed in the name of M/s. Pfizer in July, 1961.

Time taken by train from Udaipur to Jodhpur

4766. SHRI R. D. GATTANI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a time of more than 15 hours is taken by the train for reaching Udaipur from Jodhpur which is a distance of 301 Kms.; and

(b) if so, whether efforts would be made to bring down this time to a reasonable limit?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) 221 UP Jodhpur-Udaipur Passenger takes 12 hours 50 minutes from Jodhpur to Udaipur.

(b) Speeding up of this train is not operationally feasible under the present conditions of track and traction and the need to maintain connections enroute.

Strength of Assistant Officers

4767. SHRI KISHORE LAL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) What was the strength of Assistant Officers, Senior Scale Officers, Junior Administrative Officers and Principal Officers, department wise, in each zone in the Indian Railways in April, 1974 and in April, 1978; and

(b) What percentage of upgradation has been done in the case of officers grade wise and Class III and IV employees since 1974 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2731/78].

(b) Number of gazetted posts upgraded after 1-4-1974 305

J.A. to S.A. Grade	51	}
S.S. to J.A. Grade	163	
JS/Cl. II to Sr. Scale	91	

Number of Class III posts upgraded to Class II 506

Number of Class III posts upgraded 24297

Number of Class IV posts upgraded 11538

Upgradations are done only on the basis of worth of charge and responsibilities and not on percentage basis.

Representation regarding Work Done by ONGC in Tripura

4768. SHRI SACHINDRALAL SINGHA : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether he had received any representation either from any M.P. or from

the workers representatives of ONGC working in Tripura regarding the delay of work in the State :

(b) if so, the details of the representation/representations; and

(c) the details of action taken on the basis of representation/representations.

THE MINISTER OF PETROLEUM & CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA) : (a) to (c) The General Secretary, ONGC Workers' Union, Tripura Project, Agartala and General Secretary, ONGC Workmen Association, Calcutta jointly submitted a Memorandum dated 8-4-76 through Shri Saman Mukherjee, M.P. vide, his letter dt. 11-5-77 Para 1 of his Memorandum which refers to the alleged mis-management and unplanned drilling in Tripura Project, besides West Bengal Project reads as under :-

"Drilling Aspects :

Drilling is being carried out at West Bengal and Tripura since last 12 years but so far practically is nil. Although there are so many reasons behind it still our 12 years practical experience does not permit that a major portion of the reasons cannot be avoided, viz., regular stuck up in the wells due to unplanned drilling operation and mere negligence of the management, indecision in releasing of drilling point, frequent changing of decision in all respects, which spoils the man power, material, money and time etc. Therefore, it is expected that you will probe into the matter to put this vital organisation to a sound footing."

The matter was examined and comments were called for from the ONGC. In regard to West Bengal I had already supplied the reply in answer to Question No. 2192 in the Lok Sabha on 1-8-1978, which may be referred to. In so far as the drilling work in Tripura is concerned the apparent slow pace of exploration by the ONGC in Tripura has been mainly due to the remoteness of the area, difficult sub-surface conditions and the high pressures encountered in the drilling of the wells in that State. However, notwithstanding these difficulties, further drilling in Tripura is being continued by the ONGC more vigorously.

Geological and Geophysical Survey by ONGC in North Eastern Region and Eastern Region.

4769. SHRI SUDHIR GHOSAL : Will the MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the name of the area in North Eastern Region and Eastern Region where

ONGC conducted geological and geophysical survey up-to-date, period-wise ;

(b) the names of the scientists participated in these survey work areawise ;

(c) the details of the Report submitted by each of the survey team ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, & CHEMICALS AND FERTILIZERS : (SHRI H.N. BAHUGUNA) : (a) to (c) The necessary information is being obtained from the ONGC and will be laid on the table of the Sabha.

Petrochemicals Complex at Haldia

4770. DR. BIJOY MONDAL : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether West Bengal Government have given any proposal for a petrochemicals complex at Haldia ;

(b) if so, details of the proposal of the State Government ; and

(c) the action taken up-to-date in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM & CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA) : (a) to (c) A letter of intent was issued to the West Bengal Industrial Development Corporation Limited, in November, 1977, for the setting up of a petrochemical complex upto the capacities specified below :

Items of manufacture	Annual capacities/tonnes
(1) Ethylene	54,000
(2) Propylene	30,000
(3) Prolysis Gasoline	46,000
(4) Butadiene	8,000
(5) Benzene	8,000
(6) Ethylene Oxide	3,000
(7) Ethylene Glycol	10,000
(8) Diethylene Glycol	1,500
(9) Ethyl Hexanol	21,000
(10) Isobutanol	8,100
(11) N-Butanol	3,100
(12) HDPE	20,000
(13) P.V.C. . . .	45,000

The Corporation have yet to come up with the feasibility reports.

मंदालय में हरिजनों के लिए विशेष सेव

4771. श्री मही लाल : क्या ऐडोलियम रत्नालय और उर्बरक मंदीर यह बताने की हुआ करेंगे कि :

(क) क्या उनका व्यापार दिनांक 25 जूलाई, 1978 के 'बवाहार टाइम' और 'जनयग' में उनके मंदालय में हरिजनों के लिए दो विशेष सेव बनाये जाने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दो विशेष मैल उपरोक्त समाचार पत्र में उल्लिखित नियमों, विशेष रूप से भारतीय तेज नियम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए बनाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इन सेवों के सदस्यों का व्यापार क्या है और क्या अनुसूचित जातियों के अधिकारी/कर्मचारी इन सेवों का व्यापक नियम किये जायेगा क्योंकि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की समस्याएं अचूकी तरह से समझ सकते और उन्हें बेहतर हल कर सकते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

ऐडोलियम तथा रत्नालय और उर्बरक मंदीर (श्री हैमवती नवन बहुमुखी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) इस मंदालय के नियंत्रण-धीन सार्वजनिक सेव के व्यवसायिक उद्यमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवहन प्रणिनिधियों को युनिवेंशन करने हेतु प्रशासनिक कदमों की गुणवत्ता करने के लिए दो प्रकारों स्थापिन करने का नियंत्रण किया गया है। ऐडोलियम विभाग में खाले गये मेल का संचालन ईडियन आपैरेशन द्वारा किया जायेगा और रत्नालय तथा उर्बरक विभाग में स्थापिन करने (प्रकारों) का संचालन भारतीय उर्बरक नियम द्वारा किया जायेगा। इन प्रकारों का स्वरूप प्रशासनिक इकाइयों जैसा होगा और ये प्रकारों कुल मिला कर इस मंदालय की देवरेख में ग्रान्ट घरपर उपवर्मों के भाग के हप में काम करेंगे। ईडियन आपैरेशन नवा भारतीय उर्बरक नियम से प्रदूषित किया गया है कि वे इन प्रकारों का गठन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। इन प्रकारों को प्रशासी बनाने से सर्वानुषित सुझावों पर विचार किया जायेगा ।

टाटा आवरण एवं स्टील कम्पनी के लिए इसका सोहा का परिवहन

4772. श्री रामवेद तिथि : क्या रेल मंदीर यह बताने की हुआ करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा नगर इस्पात संबंध के लिए इलावा सोहा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और

अन्य राज्यों से टाटा नगर (जमशेदपुर) को बैगों द्वारा भेजा जाता है ;

(ख) क्या टाटा प्रोजेक्ट के अधिकारियों की साठ-गांठ से रेल अधिकारी इन बैगों को बापती याका के मवय लानी दणते हैं जब कि वे बस्तुतः टाटा स्टील के उत्पादों से भरे होते हैं जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को भारी नुकसान होता है ;

(ग) क्या इन वारे में गवर्नरेंट रेलवे गुलिस (जी० आर० पी०) के पास कोई प्रथम सूचा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और इस मामले की जांच चल रही है ;

(घ) क्या बिहार के जी० आर० पी० अधिकारियों ने इस मामले को दबाने के लिए जांच रोक दी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस वारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की जा रही है ?

रेल मंदालय में राज्य मंदीर (क्षी लिपि नारायण) :

(क) जो नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Sanctioned Strength of House Surgeons in Northern Railway.

4773. SHRI NATHU SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the present sanctioned strength of House Surgeons in Northern Railway Hospital, New Delhi and the existing working strength in that Hospital ; and

(b) if the working strength is not commensurate with the sanctioned strength when the remaining vacancies are likely to be filled up ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) The maximum permissible number of House Surgeons that could be appointed in the Central Hospital, New Delhi is 10. At present 7 House Surgeons are working Action is being processed to fill the remaining three posts.

Maintenance of Rake

4774. SHRI BALDEV SINGH JASROTIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the instructions existing on the Railways each rake should get primary maintenance after a run of approximately 1000 kms. and secondary maintenance after a run of 500 kms.;

(b) whether it is also a fact that 63 UP/64⁴ Lucknow Agra Express has been extended upto Kota without any secondary maintenance at Kota though the one side run is more than 600 kms.; and]

(c) what remedial measures are proposed by the Government to avoid the violation of rules which endangers safety?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No. Normally Primary maintenance is given at the originating Station and secondary maintenance at the terminating Station depending on the Rake links. No kilometrage targets have been laid down for this purpose.

(b) Yes, 63 UP/64⁴ Lucknow-Agra Express has been extended upto Kota. The Primary Maintenance of this train is based at Lucknow, the originating Station, and Safe-to-run examination at Kota, the terminating Station. After the Safe-to-run examination the train is fit to run for its return journey.

(c) Does not arise, as no Safety rules have been violated. ■ ■ ■

अखण्ड-बन्धई एक्सप्रेस और सावरमती एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में क्विक भीड़-माड़

4775. श्री राधवली: क्या रेल मंत्री पह बताने की हुया करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जात है कि अखण्ड-बन्धई एक्सप्रेस और सावरमती एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में हमेशा भीड़-माड़ रहती है तथा इसके परिवाम-स्वरूप भारी भीड़ के दिनों में यात्री इन रेलगाड़ियों में नहीं बह पाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन रेलगाड़ियों की बोगियों की संख्या बढ़ाने और इनको डीजल इंजनों से चलाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसा कब तक किया जायेगा?

* रेल बंद्रावलय में राज्य बंद्री (श्री विष्व नारायण):
(क) 115/116 बन्धई-बन्धक एक्सप्रेस प्राप्ते 165/166 सावरमती एक्सप्रेस गाड़ियों में, कुछ बहानों पर भीड़-माड़ देखी गई है।

(ख) और (ग). गुंजाइश न होने के कारण इन गाड़ियों में भारतीय डिवे नहीं लगाये जा सकते। लंबी दूरी की यात्री गाड़ियों के डीजली-करण का काम ज्यानात्मक भास्यार पर किया जा रहा है परन्तु यह डीजल इंजनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है जो प्राथमिक रूप से माल यानायात की निकासी के लिए उपलब्ध है। फिर भी, जब भलिक्षण डीजल रेल इंजन उत्तराञ्चल हांग, अब गाड़ियों के साथ-साथ इन गाड़ियों के डीजलीकरण के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

बीटर गेज स्टेशन, स्वार्डी भास्यापुर के पीछे बाली घड़ी भूमि

4776. श्री भीठा बाली भूमि: क्या रेल और यह बताने की हुया करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्वार्डी भास्यापुर जंक्शन (कोटा परिवहन रेलवे) में बीटर गेज स्टेशन और मनटाइन भास्यारिया दुकानों के पीछे रेलवे भूमि का बहुत बड़ा लोक बाली पड़ा हुआ है और यदि हाँ, तो भूमि का किनारा लोक बाली पड़ा हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि इस लोक में पानी जमा हा या है और कई बांधों में रुका हुआ पानी सड़कों फैला रहा है जोकि इस पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वहाँ पर प्रायः भीमारियां फैलती हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस पानी की निकासी और इस स्थान की साफ रखने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है और यदि हाँ, तो तमस्वर्णी भीमा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस स्थान को कब तक साफ कराया जायेगा?

रेल बंद्रावलय में राज्य बंद्री (श्री विष्व नारायण): (क) से (ग). स्वार्डी भास्यापुर रेलवे भूमि की लोक रेलवे भूमि की सामान्य विवादास्पद है। रेलवे सीमा के साथ-साथ बहुत सी दुकानें/होटल भाड़ बन गये हैं। इन दुकानों/होटलों का पानी रेलवे लोक में स्थित कुछ लिखे जाने वें जमा हो जाता है। भूमि-सीमा के बारे में विचार का निपटारा करने और साथ ही उस लोक से पानी के निकास की समस्या के समाधान के लिए स्वार्डी भास्यापुर नोटिकाइट एरिया कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था। रेलवे सीमा के साथ-साथ पानी की निकासी के लिए प्रकल्पी नामों की व्यवस्था करने के समान्य में एक प्रस्ताव पर नोटिकाइट एरिया कमेटी के साथ बात-चीत की जा रही है।

Consumer Price of L.P. Gas

4777. SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the consumer price of L.P. (cooking gas) produced and marketed by

the Government owned oil companies is statutorily or otherwise fixed by the Government ;

(b) if so, the formula on which the consumer price is fixed both in the case of direct marketing by Indian Oil and Burmah Shell through their retail agents and in the case of Hindustan Petroleum through their wholesale distributors like M/s. Kosan Gas Co. and East Coast Gas Pvt. Ltd., and Domestic Gas Pvt. Ltd. ;

(c) whether it is a fact that wholesale distributors like M/s. Kosan Gas Co., Bombay and East Coast Gas Co., Visakhapatnam, while showing in their costings to Ministry as if they are allowing Rs. 3.37 p. as retail agents margin are actually paying Rs. 2.75 p. only per cylinder ; and

(d) the reasons for the delay in implementing the decision of the Government for the take over of M/s. Kosan Gas Co. as announced on the Floor of the Lok Sabha on 4th September, 1977 by the Hon'ble Minister?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) The consumer price of domestic cooking gas for all marketing companies is fixed by Government—but not statutorily.

(b) and (c). The formula on which the price to the consumer is fixed takes into account the various elements of cost, cylinder filling charges, marketing and distribution charges, margins, dealer's commission, local taxes, etc. It includes a commission of Rs. 3.37/ cylinder. While the formula applies to all the marketing companies, the commission of Rs. 3.37/ cylinder is applicable to a full-fledged agent with complete facilities/services to customers. Kosan Gas (one of the concessionaires of Hindustan Petroleum Corporation), has one main agent and some agents and sub-agents. The commission is shared between the concessionaires and their agents/sub-agents in proportion to the services/facilities provided by them. Agents are given commission ranging from Rs. 2.75 to Rs. 3.37 per cylinder and the sub-agents from Rs. 1.25 to Rs. 1.75 per cylinder depending on the services performed by them. As per arrangement reached by East Coast Gas Co./Domestic Gas Co. Pvt. Ltd., (which are the concessionaires of the Vishakh Marketing Unit of HPC—the erstwhile CORIL) with their agents directly, an amount of Rs. 2.75/ cylinder is given to their agents as against Rs. 3.37/ cylinder pro ided in the price build-up.

(d) Steps in this regard have already been initiated.

Consideration of Hathi Committee Report

4778. **SHRI OM PRAKASH TYAGI :** Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether Government have considered the report of Hathi Committee ;

(b) if so, the details of the major recommendations thereof accepted by Government ;

(c) whether Government have also accepted the recommendations made in the Hathi Committee report about multi-national Drug Companies ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) to (d). Government have taken comprehensive decisions on the recommendations of the Hathi Committee and a *Statement* reflecting the New Drug Policy has already been laid on the Table of the House on 29th March, 1978. The said *Statement* contains *inter alia*, Government's decisions on the regulation of activities of multi-national drug companies and summarises the recommendation of the Hathi Committee on the role of foreign companies vis-a-vis Government decisions thereon.

दिल्ली में बुर्किंग गैस के लिए पंजीकरण

4779. **श्री राजकेश्वर तिथि :** क्या देशीयम, रसायन और उर्वरक भंडी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सभी गैस ग्योमियों में गैस के कनेक्शनों के लिए पंजीकरण काफी समय से बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन के क्या कारण हैं और सरकार का पंजीकरण ग्राम्य करने के लिए कब आदेश जारी करने का विचार है ?

पंजीकरण तथा रसायन और उर्वरक भंडी (श्री हेमचंद्रे नवन बृहणी) : (क) जाना पकाने की गैस को मांग की घरेलू इस उत्पाद की नायातर कमी को देखते हुए तेल क्षेत्रियों द्वारा (दिल्ली सहित) कुछ लोकों में तेल देशीयम गैस (जाना पकाने की गैस) के कनेक्शन प्रदान करने के लिए नामों के पंजीकरण को निरुत्थानित किया गया था ।

(ख) तेल क्षेत्रियों को वर्ष 1980 से जब जाना पकाने की गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती आरम्भ हो जायेगी, जहां कहीं भी जड़की होगा एक विशिष्ट जैमाने पर नये प्राकृकों को व्यापार में रखते हुए नया पंजीकरण ग्राम्य करने की सलाह भी गयी है ।

Contractors engaged for construction of Mathura Refinery

4780. SHRI PIUS TIRKEY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3236 re: contracts for construction of Mathura Refinery on 8-8-1978 and to state:

(a) the names and addresses of the Indian and Foreign Contractors/Firms engaged for the construction/erection of the Mathura Refinery ; and

(b) what is the nature, magnitude and value of work to be executed under the contract by each contractor?

THE MINISTER OF PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). A statement giving the required information is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2732/78].

मेरठ, देहरादून और आगरा में कृकिंग गैस को एंजेसियों का आवंटन

4781. व्यी नवाब तिह बौहान: क्या देट्रोलियम रसायन और उत्तरक मंत्री यह बताने की हुपा करेंगे कि :

(क) मेरठ, देहरादून और आगरा में कृकिंग गैस को कितनी एंजेसियों आवंटित करने का निर्णय किया गया है ;

(ल) उन के आवंटन के मामले में कितने सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा ;

(ग) उन में घनसूचित जातियों और घनसूचित जनजातियों तथा प्रथ्य बताने के लिए क्या कोटा निर्धारित किया गया है ; और

(घ) इन संबंध में कि तने प्रावेदन पद प्राप्त हो चुके हैं तथा उन पर कब तक निर्णय किये जाने की संधानना है ?

देट्रोलियम रसायन और उत्तरक और व्यी नवाब तिह बौहान (प्रतिवाक्य): (क) इंडियन फायल कार्पोरेशन ने एक मेरठ में, एक देहरादून में और दो आगरा में कृकिंग गैस की वितरण एंजेसी खोलने का नियमन किया है ।

(घ) बहुमान मार्गादारी स्परेक्सियों के घनसूच, आवेदन पदों को मामलित करने के लिए विकापन प्रकाशित करने परेंगे और वाणिज्यिक महत्व की व्याप में उत्कर वितरण एंजेसी दी जायेगी, बास्तविक उत्तरोक्त साहकारी संसाधनियों और हृषि उत्थोग नियमों को प्रावधिकता दी जा रही है ।

(ग) सरकार द्वारा जारी की गई मार्गादारी स्परेक्सियों के घनसूच आवंटनिक जेट की कम्पनियों

देट्रोलियम, तरल एंट्रोलियम गैस (बाला पकाने की गैस) एस्टो के ३०० एस्टो ३०० को भी एंजेसियों द्वारा विनियमित आधार पर देती है ।

(i) घनसूचित जाति/घनसूचित जनजाति के लोगों को 25 प्रतिशत ;

(ii) आरीरिक क्षम से विकलांग लोगों के लिए 2 प्रतिशत ; और

(iii) जेट को वाणिज्यिक आधार पर, जिन में बास्तविक उत्तरोक्त सारकारी सोसाइटियों और हृषि उत्थोग नियमों को प्रावधिकता दी जा रही है ।

दिनांक 15-5-1978 को लोक सभा में दिये गये विवरण के घनसूच द्वारा घनसूचित जाति/घनसूचित जनजाति लोगों के लिए ८७० में से २४ नवी कृकिंग गैस की वितरण एंजेसियों द्वारा जायेगी । इन २४ स्थानों में मेरठ, देहरादून और आगरा की सामिन नहीं किया गया है ।

(घ) देहरादून और आगरा में वितरण एंजेसी के लिए प्रावेदन पदों को मामले के लिए प्रेस विकापन घमी हाल ही में प्रकाशित किए गए हैं और प्रावेदन पदों को प्राप्त करने की घनसूच घमी समाप्त नहीं है । इसलिए कुल जितने प्रावेदन पद प्राप्त हुए हैं इन संबंध में इतना जीघ बताना कठिन होगा । साधारणतः जयन करने और नियुक्ति के संबंध में पद जारी करने में ३ से ४ महीने तक लग जाते हैं ।

Paying of rent by I.D.P.L.

4782. SHRI KACHARULAL HEM-RAJ JAIN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that I.D.P.L. is paying rent 20 per cent more to the landlords in addition to that a penalty of Rs. 45,000 has been imposed by D.D.A. ; and

(b) if so, the reasons therefor and whether it is proposed to inquire into the matter?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited have been paying 20% of the rent per month as composition fee to Delhi Development Authority only with effect from 1-7-1977. They deposited with Delhi Development Authority a sum of Rs. 40,000 as security money which has since been adjusted against the composition fee due.

(b) This arrangement was entered into with the Delhi Development Authority

as shifting to alternative accommodation would have proved more costly, apart from the fact that suitable alternative accommodation was just not available. The Company propose to shift to their own office building, which is under construction.

मेहसाना रेलवे स्टेशन के दोनों ओर राल्से का होना 4783. यो योटीचाई बार० खालीरी : क्या दूसरे बालीय यह बताने की क्षमा करते हैं :

(क) क्या मेहसाना रेलवे स्टेशन से मेहसाना कर्म्मे तक स्टेशन के दोनों ओर रेलवे के नाले हैं;

(ख) क्या ये नाले बहुत लोडे हैं और भरप्रेसिन चैम्पाइंग के न होने के कारण वहां पर प्रायः दुर्घटनायें होती हैं और क्या हाल ही की एक दुर्घटना में दो व्यक्तियां मारे गये थे और क्या इस कारण मेहसाना नगर-पालिका ने इन नालों को बोटा करने के बारे में मांग प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस प्रापरियार्य मांग को पूरा किये जाने का प्रस्ताव है ; यदि हाँ तो कब और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

रेल नियंत्रणमें राजक वकी (श्री लिल नारायण) : (क) मेहसाना बाईं में दो रेल पुल (नं० 962 और 963) हैं। इनका नियंत्रण केवल स्थानीय नालों की जलस्रोतों को पूरा करने के लिए किया गया था त कि नियंत्रण सहक पुल के लए भैं उत्पयोग के लिए।

(ख) नालों के बहाव के प्रयोजन के लिए इन पुलों की चैम्पाइंग पर्याप्त है। इन पुलों के नीचे यातायात के कारण दुर्घटनाओं की रेसों को आनकारी नहीं है। इन पुलों को बोटा करने के लिए मेहसाना नगरपालिका ने रेल विभाग के साथ कोई प्रत-व्यवहार नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठा।

Composition of Board of Directors of Khandelwal Ferro Alloys Limited

4784. SHRI M.A. HANNAN ALHAJ: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the composition of Board of Directors of the Khandelwal Ferro Alloys Limited, Bombay, and the names of its allied units;

(b) whether there are reports of mismanagement in this group of companies and its directors are drawing heavy salaries and perquisites; if so, full details thereof; and

(c) what action Government have taken to check mismanagement in this group of companies and whether any inquiry has been made thereto?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) The composition of Board of Directors of M/s. Khandelwal Ferro Alloys Limited, Bombay as

per the annual return of the company made upto 13-4-1978 is as under :—

(i) Shri Madan Mohan R. Ruia, Chairman.

(ii) Shri K.R.K. Menon

(iii) Shri Jasvantlal Matubhai

(iv) Shri K. Sadagopan

(v) Shri Shreenath R. Khandelwal

(vi) Shri Premnath R. Khandelwal

(vii) Shri O.K. Shah

(viii) Shri L.N. Jadhavani (Nominated by IFC of India).

According to the Annual Report for the Year 1977, the company has got two units namely,

(i) FERRO MANGANESE UNIT

(ii) TUBE MILL UNIT

(b) Certain complaints were received from a shareholder of the company making allegations regarding (i) the management set up of the company since the abolition of the Managing Agency system, (ii) drawal of excess perquisites by the Directors and (iii) sale of steel tubes to Khandelwal Private Limited to derive substantial profits for Khandelwal Directors.

(c) Enquiries were made into these allegations and it was found that there was no substance in these allegations.

Removal of Chairman and Director of Belapur Sugar and Allied Industries

4785. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news published in the Financial Express of 27th June, 1976, regarding resolution for the removal of the Chairman and Director of Belapur Sugar and Allied Industries;

(b) if so, whether there is any pressure direct or indirect on the Government for changing the management; and

(c) what are the views of Government on the existing management which is nominated by the Government?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

1. (c) S/Shri H. B. Dhondy and R.R. Desai were appointed as Government Directors under section 408 of the Companies, 1956 for a period of two years with effect from 28-3-1973 and their tenure expired on 27-3-1975. There are no Government nominated Directors on the Board of the company after 27-3-1975.

Memorandum from Employees Union of Eastern Gas Power Company and its Associated Concerns.

4786. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of PETROLEUM CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have received a memorandum from the Eastern Gas Power Company and its associated concern's employees union expressing apprehension, the sizeable section of the employees may be rendered surplus and retrenched as a result of the Centre's reported decision for restructuring of the present system of distributorship;

(b) if so, whether Government have taken steps to alleviate the fear expressed by the employees' union; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c): As already indicated in the Statement made in the Lok Sabha on 15-5-1978, restructuring of the cooking gas distributorships has been decided upon to ensure that such distributorships do not become or continue to be too big and thus deprive others from the opportunity of running such distributorships. While the restructuring may result in certain employees being rendered surplus at certain points, it may at the same time generate better employment opportunities at the new points. Oil companies may also persuade the new distributors to explore the possibility of engaging employees retrenched by big distributors.

Shifting of Main Office of Bongaigaon Refinery Petro-Chemicals Ltd

4787. SHRI PURNANARAYAN SINHA: Will the Minister of PETROLEUM CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) if it is a fact that Chairman and Managing Director, Bongaigaon Refinery and Petro-Chemicals Limited promised to shift the main office of Project to Bon-

gaigaon while answering to some agitators in Assam;

(b) is it a fact that the office of the undertaking has failed to implement his promise and he still maintains his office in New Delhi and still following the policy of denying employment to local people in emplacement and allotment of contracts; and

(c) if so, action Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (c): The Managing Director had promised to shift his office to Bongaigaon by the 1st June, 1978, and his office has been shifted to Bongaigaon with effect from 1st June, 1978.

The company is having at present a liaison office and some other staff in New Delhi. The purpose of having this office is to maintain contact with the company's consultants, whose head offices are located in Delhi, and also the administrative Ministry.

The employment policy of the Company is governed by the Government's guidelines issued from time to time.

Contracts are awarded by the Company on the basis of tenders and strictly in accordance with the normal tender procedures.

**न्यायालयों और धार्य स्थानों पर नियुक्ति
एडवोकेट**

4788. श्री हुकम सेह नारायण यादव: क्या विधि, न्याय और कानूनी कार्य मंडी यह बताने की हुकम करेंगे कि कोर्टीय सरकार ने हरिजनों, आदिवासियों, महिलाओं, मुसलमानों और पिछड़ वर्गों के किनने एडवोकेटों को न्यायालयों, धार्यों व न्यायालयों में नियुक्त की जाए और उन न्यायालयों, धार्यों व न्यायालयों के नाम क्या हैं जिनमें उन की नियुक्ति की गई है और सरकार ने कूल किनने एडवोकेटों की नियुक्ति की?

विधि, न्याय और कानूनी कार्य मंडी (श्री शाहि चतुर्वेद): जानकारी हड्डी की जा रही है और सबन के पटल पर रख दी जाएगी।

पहुँच, 1974 की हड्डी के पश्चात् राज्यपरिषित पदों का बोलाया जाना।

4789. श्री हरप्रीत सर्व: क्या ऐसे मंडी यह बताने की हुकम करेंगे कि:

(क) मई, 1974 की रेलवे हड्डी के पश्चात् किनने राज्यपरिषित पद बनाये गये और किनने राज्यपरिषित धर्मिकारियों को पदोंपर किया गया;

(क) यदि हां, तो क्या उन्हें उच्च बेतन मान दिये गये थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार 1974 से पहले की स्थिति बहाल करने हेतु कोई कार्यवाही करेंगी; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य बंडो (श्री शिव नारायण) :

(क) से (घ). बड़े हुए कार्य भार को मम्मानन और नियानन अल्पकालिक नियानन कार्य के लिए 1974 की रेल हड्डाल के बाद आज तक विभिन्न कंपनियों पर लगभग 1265 राजपत्रित पद संचित किये गये। ऐसे कई पद उस काम के पराहोने पर जिस के लिए वे पद सुनित किये गये थे, बाद में, अधिकारियों के द्वारा नियानन कर दिये गये। इस प्रवृत्ति अनुकालिक प्रबन्धन के पारणामस्तकप, (लगभग, 1947 अधिकारी उच्चतर ब्रेडों में पदान्तर किये गये और वे सामान्य नियमों के प्रधीन उपयुक्त बेतनमानों में लगा दिये गये)। चकिं ऐसा हड्डाल के कारण नहीं किया गया था, इसलिए हड्डाल के पूर्ण की स्थिति को बहाल करने का प्रयत्न ही नहीं उठता।

Permission letters issued to Drug Units without Seal of the Ministry

4790. SHRI UGRASEN : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Industrial licences, their clarifications and other letters issued under I (D & R) Act possess the seal of the issuing Ministry;

(b) whether it is a fact that Permission Letters which were granted to drug manufacturing units don't possess any seal and were issued by officers in excess of their powers, violating provisions of I (D & R) Act and rules made thereunder; give details of officers involved in the issue of Permission letters; details of permission letters issued product wise, whether before issuing each and every such Permission Letter, application for industrial licence was received or not; and

(c) how many applications of Indian firms for such formulations were rejected at the same time; details of such applications and reasons for rejection?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) :

(a) All Industrial Licences issued under the Industries (Development & Regulation) Act or any amendments made to the Industrial Licence under this Act bear the Seal of the Ministry of Industry.

(b) Consequent on the coming into force of the I (D & R) Act in 1951, firms which were in existence before the Act came into force were entitled to Registration under the Act for their existing range of production as well as such items where the parties had taken effective steps to manufacture them.

Various Companies approached the Govt. from time to time subsequently, seeking authorisation for the manufacture of articles which could be produced by them without adding to their existing plant and machinery. The Licensing Committee at their meeting held on 23-11-1955, examined this issue in the context of the implications of the term "new article" and held that a broad view of the definition of "new article" was reasonable and should be taken. The Committee felt that, where no new Trade Mark or new Patent was involved and the product was covered within the ambit of the same item in Schedule I of the I (D & R) Act, 1951, for which the concerned company held a Registration/Industrial approvals, then such product would not be a "new article" and there should be no objection to the Company manufacturing it.

Based on this decision, and with a view to enabling Companies already holding valid authorisation to fully utilise the existing machinery, without adding to either royalty burden or plant and machinery or seeking any additional concessions for import of raw materials in relaxation of the general import policy, Permission Letters were issued to such Companies.

Generally, these letters were issued without any seal of the issuing Ministry because they were in the nature of a clarification as to the meaning of "new article" and elaborated the authorisations for manufacture available to the party, namely, Registration Certificates and Licence, thereby explaining to them that they were authorised to manufacture these additional items without a separate licence, provided the following 4 main conditions were satisfied:

(i) No additional plant and machinery will be required for the purpose;

(ii) No royalty will be payable;

(iii) The products would be marketed under trade marks already in use and no new patent was involved.

(iv) No special concession in regard to the import of basic raw materials and ingredients would be made in relaxation of the general Import Policy in force from time to time.

Details of Permission Letters are furnished in Annexure II of Chapter V of the

Hathi Committee Report, which has already been laid on the Table of the House.

(c) Since the Permission Letters were issued in the fifties, it is not possible to state if Indian Companies had been refused the manufacture of any such item covered by Permission Letters issued to Foreign Companies.

Reduction in cost of production of Fertilizers

4791. DR. SAROJINI MAHISHI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) in view of the fact that more than Rs. 50 crores are given by way of subsidies to indigenous phosphatic fertilizers, what concrete steps are being taken by Government to reduce the cost of production of these fertilizers; and

(b) what is the total quantity of phosphatic fertilizers imported in the past three years?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) About 60 to 70 per cent of the cost of production of phosphatic fertilizers is accounted for by the cost of basic inputs like imported phosphatic acid, rock-phosphate, bulk of which is imported, and potash and sulphur, both of which are also imported. As the inputs are mainly imported, we have little control over their cost. However, it has been the constant endeavour of Government to reduce the cost of production and make fertilizers available to the farmers at reasonable prices. With this in view, measures such as reduction in import duty on phosphoric acid, reduction in excise duty on super-phosphate and reduction in the price of imported potash were taken in the past in order to reduce the cost of production and thereby, the price to the farmers. Since, however, these measures were not adequate to bring about significant reduction in the prices of phosphatic fertilizers, the scheme of price support was introduced with a view to bringing down the prices.

(b) The quantity of imports of phosphatic fertilizers in terms of nutrient is furnished below:—

Year	Quantity in lakh tonnes of P 205
1975-76	3.37
1976-77	0.23
1977-78	1.64

Lay off in M/s. Dharanghdra Chemical Works and M/s. Plastics Resins Limited, Sahupuram Arumuganeri and Tirunelveli

4792. SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was lay off in Messrs Dharanghdra Chemicals Works, Sahupuram and Messrs Plastics Resins Limited, Sahupuram, Arumuganeri Tirunelveli District Tamilnadu State during the current year as well as last year;

(b) if so, what is the reason therefor;

(c) whether Government are aware that a number of small scale industries depending upon the raw material Resins, will be affected if M/s. Plastics Resins were to stop production; and

(d) if so, whether the Government would take over the management of this Unit in the interest of the small scale industries or whether the alternative entrust the management with its sister Unit viz., Dharanghdra Chemical Works Ltd., Sahupuram for its management?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). There was no lay off in M/s. Dharanghdra Chemicals Works during the current year or during the last year. M/s. Plastic Resins and Chemicals Limited was closed from 11th November to 24th November, '77 and during this period the workers were laid off. The factory again closed down on 15th February, '78 due to uneconomic operations and the lay off of the workers continues since then.

(c) and (d). The problems of this Company were discussed in an inter-Ministerial Meeting and the matter is under examination.

In the meantime, import of PVC resins is being allowed to meet the gap between the demand and the indigenous availability.

Sale of Non-Canalised bulk drugs to IDPL on high-sea basis

4793. SHRI RAMJILAL SUMAN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) details of non-canalised bulk drugs sold to IDPL on high-sea basis during the last three years, year-wise;

(b) under what authority were these high-sea sales were also effected in favour of any other authority; if so, details thereof; if not, why; and

(c) whether for allowing high-sea sales and making delivery of non-canalised bulk drugs it was ascertained that IDPL hold necessary independent licence for manufacture of formulations covered; if not, under what authority were non-canalised items released to IDPL on high-sea basis?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Details of non-canalised bulk drugs sold by CPC to IDPL on high sea sales basis during the last three years are indicated below:

	1975-76	1976-77	1977-78
Vitamin A	..	7.175	MMU
Procaine			
Penicillin	—	3000 BU (By air)	1000 BU

(b) The import of Vit. A which was a banned item for import during 1976-77, was authorised at the instance of Ministry of Health and Family Welfare in favour of IDPL to meet a specific requirement in respect of the Family Planning Programme. This import was necessitated due to shortage of this drug in the indigenous market and it was an *ad hoc* arrangement.

As regards Procaine Penicillin the material was imported by CPC to meet IDPL's requirements for an export order from Afghanistan and the import was authorised against an advance licence issued in favour of IDPL by the Office of CCI&E.

In the case of canalised raw materials, IDPL share with CPC the responsibility for distribution of such raw materials and in this capacity take delivery of materials on high sea sales basis from the latter. On the same analogy, in the instant cases also, the material was transferred on high sea sales basis by the CPC.

If the reference in the words 'any other authority' is to an 'Actual User', the Ministry has no knowledge whether any other actual user made a similar request to CPC for supply of non-canalised raw materials on high sea sales basis.

(c) No, Sir. The basis on which non-canalised items were released to IDPL on high sea sales basis, has been explained in (b) above.

Cost price of urea

4794. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what is the present units cost price of urea produced in the country; and

(b) what is the present unit cost price of urea which is being imported from abroad and the reasons for the difference in costs?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). The cost of production of urea in the country varies from plant to plant depending upon such factors as the capital cost, feedstock used, vintage, process adopted, location, cost of utilities etc. The price of imported urea does not depend on its cost of production in the exporting countries but on the international market forces. Data in respect of the cost of production of urea in other countries is not available in a form that makes comparison with the cost of production of indigenous urea possible.

Money collected by Ms. Bharat (P) Ltd. from Cement Stockists

4795. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a huge amount have been collected by M/s. Bharat (P) Ltd. from the Cement Stockists in the form of advances, security loans, etc. and misappropriated; and

(b) if so, what action has been taken by Government against the Ex-Executive Directors of the Company?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) and (b). Presumably the question refers to M/s. Bharat Overseas Private Limited. This company was acting as sole selling agents of M/s. Jaipur Udyog Limited, and had taken large sums of money from cement dealers. The precise position in this regard is not known, since the company has not filed any balance sheet after March 31, 1974.

Due to complaints received about non-supply of cement and/or non-refund of the advances, action is being taken to conduct an inspection of the books of accounts etc., of the company under section 209A of the Companies Act, 1956 to get a clear idea of the irregularities committed, if

any, and to take such action as may be called for.

वीत वडे शौकोगिक गृहों के परिस्तायन का समाचार

4796. श्री आर्द्धीन प्रसाद मासूर : क्या विधि, स्थायी और कम्पनी कार्य भंडी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का व्यायान 8 अनु, के 'दि इक्षियन एक्सेम' में 'गवर्नेंट आर हिटरिंग्ड ट लिंकिंहटे' 20 विं शार्ट सिलिंज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ब) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, स्थायी और कम्पनी कार्य भंडी (श्री शाति श्रवण) : (क) हां, शामान जी ।

(ब) 23 दिसंबर, 1977 को संसद में रखे गये शौकोगिक नीति विवाद में सरकार ने बड़े गृहों के सम्बन्ध में अपनी पहुंच की स्पष्ट व्योपणी की है। इस नीति को, नारसेन नीति सीमा और एकाधिक कार एवं नियंत्रणकारी आपात प्रश्न अधिनियम का दृष्टा से लागू करने के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि हाथों में प्रार्थिक व्यक्ति संकेन्द्र पर विस्तीर्ण एवं स्पष्ट प्रबन्ध पर आते विचार किया है और इस सरकार के संकेन्द्र को प्रभावी रूप से बगान करने के प्रस्तावों की अभी परीक्षा की जा रही है।

Drug to control Tuberculosis

4797. SHRI AMRSINH V. RATHAWA: SHRI SUKHENDRA SINGH:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar has achieved a break-through in preparing a drug from a seaweed to control tuberculosis;

(b) if so, the progressive results achieved so far in this direction; and

(c) the time by which the drug is likely to be put in commercial production?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आयुर्वेदिक शौकिक कारबानों की स्थापना

4798. श्री लक्ष्मीनारायण नाथक : क्या लेट्रोलियम, रसायन और उर्बरक भंडी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राजवार उन स्थानों का शौकर क्या है जहां सरकारी आयुर्वेदिक शौकिक कारबाने की विधि है;

(ख) आयुर्वेदिक शौकिक के उपयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से बनेमान जनना पार्टी सरकार ने सत्ता सम्बालने के बाद अब तक कितने नये आयुर्वेदिक शौकिक कारबाने स्थापित किये हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे कारबाने स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में ऐसे कारबानों की स्थापना करने की है जहां अमररक्टन काटक और अन्य जंगली जड़ी बूटियां बहुतायत से उपलब्ध हैं?

लेट्रोलियम तथा रसायन और उर्बरक भंडी (श्री हेमतराम बहुगुणा) : (क) सं. (ग) सं. (ग) : रासायन और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अपेक्षित सूचना उमके ढारा एकत्र की जा रही है और सभा पट्टन पर प्रस्तुत नी जायेगी।

Request for shifting of Mathura Refinery

4799. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether twelve eminent personalities of the country have written to him requesting him to intervene and shift the site of Mathura Refinery to a less risky site to save Taj Mahal and Agra city from pollution; and

(b) if so, what action he proposes to take in the matter?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Appointment of Managing Director of Jeypore Sugar Company Orissa

4800. SHRI M.R. LAKSHMI NARAYANAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the answer given to Starred Question No. 1017 on 8th May, 1978 regarding Jeypore Sugar Co. Ltd. and state :

(a) whether the Jeypore Sugar Company Orissa, has now made an application for

approval of Mrs. Rajeshwari Ramakrishnan as Managing Director if so, whether Government propose that she will not be given approval ;

(b) whether it is true that the Management of Jeypore Sugar Company consisting of one family also is in the management of K.C.P. Ltd., Madras ; if so, what are the family members ; and

(c) whether it is a fact that representations were made by shareholders of K.C.P. Limited more than a year ago for appointing Government Directors ; if so, what action has been taken so far on these representations ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) Yes, Sir. The proposal of the company for the re-appointment of Shrimati RAJESHWARI RAMAKRISHNAN as the Managing Director of the company for a period of five years with effect from 3-9-1977 on her existing remuneration has since been received, and is under consideration.

(b) The following five directors of the Jeypore Sugar Company Limited are also the directors of M/s. K.C.P. Ltd.

- (i) Shri V.L. Dutt (Managing Director)
- (ii) Mrs. V.R. Dhurghamal
- (iii) Shri M.A. Krishnamachari
- (iv) Shri R. Prabhu
- (v) Shri P.R. Ramakrishnan

(c) A representation from Shri K. Rajendra Chowdhary, Advocate has been received on behalf of some shareholders of the company for the appointment of Government Directors on the Board of M/s. K.C.P. Ltd. The same is under consideration of the Government.

Selection of Station Masters

4801. SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI :

SHRI DAYA RAM SHAKYA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that All India Station Masters Association, Delhi Division boycotted selection of Station Masters Grade Rs. 455-700 on 11th June, 1978 and 16th July, 1978 ;

(b) whether the boycott was due to serious allegations of anomalies and favouritism in the oral test which have been totally ignored by the administration of Delhi Division in the emergency time ;

(c) whether the same procedure of selection in Grade Rs. 455-700 for S. Ms. and A.SMs is held in All Railways, if not, the reason thereof ; and

(d) what action the Railway administration took for the favouritism given to juniormost persons under the cover of emergency ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Yes; the post of ASMs/SMs in grade Rs. 455-700 (Rs) are selection posts on all Indian Railways.

(d) Does not arise.

शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे

4802. श्री कैलाल प्रकाश : क्या रेल मंत्री यह बताने की हुया करेंगे कि :

(क) शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के स्थान पर बड़ी रेल लाइन बनाने की योजना कब तक पूरी हो जायेगी;

(ख) इसके निर्माण के लिये यदा वागिन लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, और

(ग) क्या इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि इस समय रेल यात्रा की बोर्डिंगप्लेट उपलब्ध नहीं है जो गहले उपलब्ध थी, निर्माण कार्य में लेजी लाने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) शाहदरा-सहारनपुर बड़ी लाइन को पूरा करने के काम को पहले ही उच्च प्रारम्भिकता दी गयी है। शाहदरा से बागपत रोड तक का बहु यातायात के लिए खोला भी जा चका है। बागपत रोड से शामली तक के ध्रगाने बरण को चानू वर्ष में और समूर्ध वरियोजना को मार्च, 1980 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मध्य प्रदेश में शौचालय तथा रसायन संयंत्र की स्थापना

4803. श्री मुहम्मद तिहू : क्या बेटोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बनाने की हुया करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में मरकारी लेव में शौचालय तथा रसायन संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तामस्मन्दी औरा क्या है ?

बेटोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हैमवती मम्मन बहागुणा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में एक संयुक्त लेवीय पामूलेशन एक स्थारित कर

के लिये इहियन इस एवं कार्माचिकित्स लिंग एक सकारी उपकरण तकीकी भाषिक संयाप्ता रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।

निम्नलिखित मर्दों का निराण करने के लिये मध्य प्रदेश के शाब्दिक जिले में मेशनर नामक स्थान पर एक नया एक स्थापित करने के लिये मेंसें एम पी एयो मांगरडी कलिङ्गसे लिंग को मार्च, 1978 में एक आग्रण पत्र जारी किया गया है।

(i) मल्फूरिक एमिड 1,40,000 टन प्रतिवर्ष

(ii) काल्पोरिक एमिड 50,000 टन प्रतिवर्ष

(iii) मोनो एमोनियम फारफेट 73,600 टन प्रतिवर्ष इस प्रायोजना को एम० पी० एयो इंडिस्ट्रीज इकायमेंट ग्राहणरेण द्वारा मैमर्स घर्मसी मांगरडी केलीकल्प कम्पनी के महोगी में मंगूत क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है।

निम्न थेणी लिपिकों को बरिटना-मूची

4804. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या रेल थेणी यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के महायकों और उच्च थेणी निपिकों की बरिटना मूचीयां तैयार की गई हैं ;

(ख) रेलवे बोर्ड के निम्न थेणी लिपिकों की बरिटना मूची पिल्ली बार लिम वर्ष तैयार की गई थी ;

(ग) यदि नहीं, तो निम्न थेणी लिपिकों की बरिटना-मूची बर तक तैयार न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यह मूची कब तक तैयार होने की मांगवाना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य थेणी (श्री शिव मारायण) :

(क) जी हा।

(ख) 1978

(ग) और (ख). प्रश्न नहीं उठता ।

Inclusion of Representatives of RPF in Staff Council

1805. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1327 on 25th July, 1978 regarding All India R.P.F. Association and state :

(a) whether representatives of the All India R.P.F. Association will also be included in the Staff Council (Karamchari Parishad) and if so, the number thereof; and

(b) the justification for including a representative and C.S.O. of the Zonal Railway Protection Force Association in the Staff Council when the Zonal Railway Protection Force Association is recognised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) The presence of Chief Security Officer on Staff Council is considered necessary on account of the following :—

(1) Chief Security Officer is the head of the Force on the Zonal Railway as such is conversant with the various problems of the Force. (2) Zonal Railways' Associations do not represent the entire Force and as such the CSO's presence will take care of the interest of the other staff who are not members of the Association. (3) The attendance of CSO will help ultimately to accelerate the follow-up on decisions taken which is in the ultimate interest of the Railway Protection Force.

बम्बा-पार थेणे के निपिकाइंग के लिए परिवहन सुविधाओं में मुद्दार की योजना

4806. श्री फल बन वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमनालाल थेणे के नामांग निपिकाइंगों के लिए परिवहन जन सुविधाओं में मुद्दार की उन के मदालय की कोई योजना है ; और

(ख) क्या यानालाल को भीड़ और कठिनाइयों को दैवत हुए सरकार हापुड़-जालन गाड़ी को नई दिल्ली की ओर मार्दाने का प्रयाप करेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य थेणी (श्री शिव मारायण) :

(क) नयी दिल्ली दिल्ली और गाजियाबाद के बीच यात्रा करने के लिए बहुत सी गाड़ियां उपलब्ध हैं। यांग-बही लालन थमता पर अतिरिक्त दिवाव होने तक दिल्ली/नयी दिल्ली में प्रवाहित टर्मिनल सुविधाओं के कारण कोई प्रतिरक्त गाड़ी बनाना परिवानानिक दृष्टि से अवाहारिक नहीं है।

(ख) । पन्न० पच० के जल्ल गाड़ी दिल्ली शाहदरा, दिल्ली नवा नयी दिल्ली के गार्ड बूर्जा। हापुड़ और हजरत निजामुद्दीन के बीच पहल से ही चल रही है और इस गाड़ी का मार्ग बदलकर, दिल्ली शाहिं जा परिवहर करते हुए, नये मुमुन पुल, तिलक लिंग के गार्ड बनाये जाने को इस गाड़ी के वर्तमान उपयोगकर्ता परमद नहीं करेंगे।

Broad Gauge Line from Guntakal to Hospet

4807. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the broad gauge line from Guntakal to Hospet is in

Guntakal Division and metre gauge track from Guntakal to Hospet is in Hubli Division;

(b) whether it is a fact that there are administrative difficulties and waste of man-power in regard to inspection of track and other assets ; and

(c) in view of the above facts whether Government are willing to transfer the metre gauge line also to Guntakal Division?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes. The Broad Gauge line from Guntakal to Hospet falls in Guntakal Division and the metre gauge line from Guntakal (excluding) to Hospet in Hubli Division of South Central Railway.

(b) and (c). No specific administrative or operational difficulties and waste of man-power in regard to the inspection of track and other assets have so far come to light, arising out of the existing arrangement. As such the question of transfer of the section from Hubli to Guntakal Division is not under consideration of this Ministry.

Transfer of Name in respect of L.P.G. Connection of Indian Oil

4808. **SHRI R.L.P. VERMA :** Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that L.P.G. connections of Indian Oil cannot be transferred from the name of a dependent father of his son ; and if so, the reasons therefor;

(b) whether Government have received such requests for transfer and if so, the action taken by Government in this behalf;

(c) whether Government will consider transfer of gas connections from dependent parents over 60 years of age ; and

(d) what is the procedure for transfer of a gas connection to the next ofkins in case of death of parents?

THE MINISTER OF PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA) : (a) to (d). As per present practice, normally gas connections are non-transferable. The Indian Oil Corporation has no system of transferring a gas connection from one name to another. However, in exceptional circumstances involving death etc., as and when a connection has to be transferred at the request of a close blood relation, at the Corporation's instance, IOC's distributor first prepares a Termination

Voucher in the name of original subscriber and then issues a new gas connection in lieu of the said Termination Voucher (with a changed name). In such cases, security deposit for the gas cylinder and pressure regulator is collected at the prevailing rates.

During the period from 1-1-78 to 31-7-78 no such request was received in this Ministry.

वसा में लोकल रेलवे

4809. **श्री हिंदूर लोहरी :** वसा रेल लंबी वहाँ रेलवे की कृपा करेंगे कि :

(a) वसा बंदालय को पता है कि वसा (बिहार) में लोकल रेल गाड़ी में बहुत परिवर्ती भीड़ गयी है ;

(b) वसा बरकार को वसा के लोगों में इन बारे में जिकायें दियी हैं ;

(c) वसा बरकार का विचार रिली-हायर का बम्ब बड़न पीर उत्तर वार्ड वसा में होकर चलाने का है ; और

(d) वसा बरकार का विचार आवश्यों वाले बाली विकल्प एक्स्प्रेस का वार्ड वसा में होकर करने का है ?

रेल लंबालय में राज्य लंबी (जी विल लार्क्स) :

(e) राज्य-वसा बरक एवं वहाँ रेली वसा मार्गी वार्ड मार्गी वार्ड में कूल भीड़-भाड़ देखी गयी है ।

(f) जी हाँ :

(g) जी (f). जी, नहीं ।

Aeromagnetic Survey of Mahanandi Basin

4810. **SHRI JANARDHANA POOJARY :** Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether the Aeromagnetic Survey of Mahanandi Basin has been completed; and

(b) if so, the results thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA) : (a) Yes, Sir.

(b) The results will be known after the data is analysed by the National Geophysical Research Institute of India at their laboratory and research centre at Hyderabad.

मालगाड़ियों द्वारा ले जाये गये दौरों की संख्या

4811. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान माल गाड़ियों द्वारा कितने दौरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया और उन से कितनी आय हुई ;

(ख) क्या उन को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सम्बन्धित अधिकारी इन दौरों को ले जाने के लिए 50 रुपए प्रति बैगन के हिसाब से अतिरिक्त धन-राशि ले रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कायवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :

(क) रेल द्वारा दोये गये मवेशियों की संख्या के अंकड़े नहीं रखे जाते हैं । लेकिन, वर्ष 1977-78 के दौरान भारतीय रेलों की बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन के स्टेशनों से चौपहियों के हिसाब से 98,848 माल डिव्हॉर्म में मवेशी लादे गये थे । यद्यपि जेबों को अंतिम रूप दिया जाना है, अभी शेष है । फिर भी उन से 6.85 करोड़ रुपये की आमदनी (अनन्तिम) होने का अनुमान है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Bogies and Buses set on fire in Marathwada

4812. SHRI AMAR ROYPRADHAN:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some rail bogies and buses were set on fire in Marathwada on the 27th July, 1978 ; and

(b) if so, what are the details in this regard and the reaction of Government there-to ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) : The violent agitation launched in the Marathwada region affected the Railways from 28th July, 1978 onwards and as such there was no incident of burning of bogies on the 27th July, 1978. There were 4 instances of arson—all on 28th July, 1978 involving 11 coaches in all. Out of 11 coaches 9 were completely burnt and two slightly burnt. Two cases as Crime No. 36 & 37/78 of GRP/Jalana u/s. 147/148/149/426,323-324-335-337-427-431 IPC read with Section 127 and 128 IRA were registered in connection with the incident which took place at Saini Railway Station where 7 bogies were burnt. In another incident which took place at Boker Railway

Station, involving 3 coaches, GRP/Purna registered a case under crime No. B-44/78 u/s. 100-B, IRA. Similarly, in another incident which took place at Chudawa Railway Station involving one coach, GRP/Purna registered case under Crime No. B-40/78 u/s. 100-B IRA. 26 agitators were arrested.

The information regarding burning of buses in Marathwada region is not available.

Statewise Production of Crude Oil, Chemicals and Fertilizers

4813. SHRI AHSAN JAFRI : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) what is the State-wise production of crude oil, chemicals and fertilizers in India during the last three years;

(b) what is the State-wise refining capacity ; and

(c) whether Gujarat is getting its due share in the allocation of funds and other benefits ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA) : (a) and (b) : A statement giving information in respect of production of crude oil and refining capacity is attached. Information regarding chemicals and fertilizers is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(c) Allocation of funds to projects in various States including Gujarat is made according to the Annual Plans.

Statement

‘ooo’ Tonnes

Crude Production	Oil	1975	1976	1977
Assam . .	4189	4267	4510	
Gujarat . .	4094	4164	4237	
Off-shore . .	Nil	228	1438	
Tot21 . .	8283	8659	10185	

Refining Capacity	Mn. Tonnes per Ann- um	
Andhra Pradesh	1.55	
Assam	1.25	
Bihar	3.30	
Gujarat	4.30	
Kerala	3.30	
Maharashtra	8.75	
Tamil Nadu	2.50	
West Bengal	2.50	
Total	27.45	

Raids on Petrol pumps for adulteration in North India

4814. SHRI RAGHBIR SINGH : Will the Minister of PETROLEUM CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether Government of India conducted any raids on the Petrol Pumps in Northern India during the last three years ;

(b) if so, the names of such Petrol Pumps on which raids were made for adulteration of Petrol and Diesel ;

(c) the names of petrol pumps whose petrol and diesel was found adulterated ; and

(d) whether any action was taken against them and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) to (d) : No raids have been conducted by the Government of India on petrol pumps in Northern India during the last three years.

State Governments have been requested to ensure periodical sample checks of petrol sold from retail outlets (petrol pumps) and take appropriate action against those indulging in adulteration.

According to the information available with this Ministry, in the case of two retail outlets (petrol pumps) of Hindustan Petroleum Corporation Limited (Visakh Marketing Unit), raids were carried out during May '78 by the State Governments'

Civil Supplies Authorities. The details thereof are as under :—

(i) *At M/s. Modern Auto, Lucknow* : The raid was based on a complaint of a scooterist. Petrol sample was drawn by the Civil Supplies Department, but, so far, no advice has been received by the oil company from them regarding adulteration of the product. The representative of the oil company had carried out the filter-paper test at the site and he did not find evidence of adulteration.

(ii) *At Lakshmi Motors, Jaipur* : Petrol sample was drawn by the District Supply Officer, Jaipur, on the basis of a complaint by a scooterist. The oil company has tested a sample of the product which was found to be on specification.

Pending receipt of advice from the concerned State Authorities no action has been taken by the oil company in these two cases. Besides, in one case at Ballabhgarh (Hariana) a retail outlet of Bharat Petroleum Corporation Ltd., (BPC) owned by M/s. Tara Chand Saluja & Sons, was inspected by the Police on receipt of complaint about the alleged adulteration of petrol and high speed diesel oil. As per BPC's report, the analysis showed that while the high speed diesel samples were found to be on specifications, the petrol samples failed on two counts namely, octane number and the final boiling point. The petrol appeared to be contaminated to the extent of approximately 10% with product like kerosene and mineral turpentine oil. BPC had conveyed the test reports to the Police authorities and simultaneously wrote to the dealer asking for his explanation. The dealer had replied saying that no adulteration had taken place at his site. As further investigations in this regard are being carried out both by the oil company and the Police authorities the question of taking action against the dealer, at this stage, does not arise.

Study group on salary structure of executives of Private sector

4815. SHRI SARATKAR : Will the Minister of LAW, JUSTICE and COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government has constituted any study Group of ranking officials to look into the salary structures of private sector companies ;

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) what is the constitution of the Group and by which date it has been asked to submit its report?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) (a) to (c) : No such Study Group has been constituted by the Government recently. However, the Bhothalingsam Study Group on Wages, Incomes and Prices, which was set up in October, 1977, has already submitted its report. The report, besides other things, deals with the remuneration structure of managerial personnel of private sector Companies and is under examination of the Government.

कोयले पर आधारित नया उर्वरक संयंत्र

4816. श्री मोर्चित्व राम निरी :

श्री लक्ष्मीनारायण :

श्री ग्राम तिह ठाकुर :

श्री कल्पलक्ष्म देवराज जी :

क्या ऐटोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृता करेंगे कि :

(क) क्या कोरका उर्वरक संयंत्र के प्रतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य में उपलब्ध कायेते के प्रचुर मंडारों पर आधारित कोई अन्य नया उर्वरक संयंत्र स्वापित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस स्थान पर संगाया जायेगा?

ऐटोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मेम्बरी नवन बहुमुण्डा) : (क) नाही (ख) : जी, नहीं। पर्यावरण वाले में इनके उपलब्धी को इयान में रखते हुए प्रतिरिक्त उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए गैस के प्रयोग को फोटो-टाक के रूप में प्रयोगिकता भी जा रही है। गैस के रूप में फोटो-टाक पर प्राप्तिरिक्त प्रतिरिक्त संयंत्र की परियोजना तात्कार और रसायन के कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के बन्दूमध्यों के प्रसात ही भारत की कायेंगी।

Manufacture of Chloramphenicol by M/s. MAC Laboratories Pvt. Ltd.,

4817. SHRI GAURI SHANKAR RAI : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) what is the total licensed capacity of M/s. Mac Laboratories Pvt. Ltd., to manufacture Chloramphenicol from basic stage;

(b) what is the total quantity of various intermediates they can import during the current Import Trade Control Policy on the basis of past consumption; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) The total licensed capacity of M/s. Mac Laboratories Pvt. Ltd., for the basic manufacture of Chloramphenicol is 25 Tonnes per annum.

(b) and (c). The intermediates allowed for imports which are required for the manufacture of Chloramphenicol figure either in Appendix 5 of the 1978-79 Import Policy (Restricted Items) or in the OGL list. As far as the OGL items are concerned, the import will be governed by para 23 of the 1978-79 Import Policy. As far as Appendix 5 items are concerned, the import will be according to policy set out in paras 24 to 36 of the Import Policy.

Linking of Shravanabelagola by Railway

4818. SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) are Government aware of the fact that in the year 1981 there is going to be a big celebration of 'Mahamastikabhisheka' of Gommateshwara, the world famous 1000 year old statue situated at Shravanabelagola in the State of Karnataka for which at least 1 crore people are likely to reach there;

(b) do Government not feel their duty to see that for providing them with suitable transport facilities, it is necessary to link that place by Railway; and

(c) will Government provide such a facility?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (c), Government are aware of the need for construction of new railway lines in the areas where transport facilities are lacking, or are inadequate to meet the demands of the area, but have not been able to take up the construction of more such lines on account of constraint of resources.

Registrar of the Court of Judicial Commissioner of Goa, Daman & Diu

4819. SHRI AMRUT KASAR : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Registrar of the Court of the Judicial Commissioner of Goa, Daman and Diu was not in services of the Judiciary from June 1966 to April, 1968.

(b) whether he was attending law classes at the R. L. Law College Belgaum

during the above period but regularly drew payments from the Government treasury; and

(c) if so, what action has been taken against the Registrar of the Court of the Judicial Commissioner for cheating the Government?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) According to the Government of Goa, Daman & Diu, the present Registrar of the Court of Judicial Commissioner of Goa, Daman and Diu was Superintendent in the District and Sessions Court during the period June 1966 to April, 1968.

(b) and (c). According to the information furnished by the Judicial Commissioner the Registrar had attended service regularly and was paid during the above period on the basis of his attendance. The Judicial Commissioner has also intimated that the information regarding his attendance of Law classes at the Law College Belgaum is not available, but that there has been no cheating and therefore there is no question of taking action against him.

Complaints Regarding Air Pollution due to Chemical Plants

4820. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints regarding air pollution from localities where major chemicals plants in the public and private sectors are located; and

(b) if so, what are the details thereof and the steps Government have taken to redress their grievances?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). Government have received complaints of air pollution caused by the operation of the following plants:

(a) Caustic Soda unit of M/s. Jayshree Chemicals at Ganjam (Orissa).

(b) Trombay unit of Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited at Trombay (Maharashtra).

2. In the case of M/s. Jayshree Chemicals, the Government decided that grant of letter of intent and licence (both fresh ones and renewals) and other pending matters relating to this firm should

be deferred till the firm has taken all steps to check pollution of air and water in and around Ganjam town. All administrative Ministries/Departments have been requested to give effect to this decision.

3. The Trombay unit of the Rashtriya Chemicals & Fertilizers is implementing anti-pollution measures costing Rs. 677 lakhs. The air pollution from this plant will be substantially reduced when it starts using low-sulphur gas from Bombay High in place of Naphtha in December, 1978.

Exchange of Railway Expertise between Australia and India

4821. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) Whether the Australian Parliamentary Delegation which visited India recently mentioned about wide scope for exchange of expertise between the two countries in the field of railways; and

(b) if so, Government's reaction thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). The Ministry of Railways have no information in the matter.

लखनऊ और वाराणसी के बीच नई गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

4822. श्री गंगा चत्ता तिहू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ और वाराणसी के बीच कृष्णनगर के गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही हैं; और

(ब) यदि हाँ, तो वे कब तक चलाई जायेंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य बंडी (श्री निवारण): (क) और (ब). जी, नहीं। तथापि, वाराणसी और लखनऊ के रास्ते हावड़ा और जन्मनगर के बीच सप्ताह में दो बार चलाने वाली एक ट्रेन गाड़ी भव्यतावर 1978 के मात्र मास चलाये जाने का प्रस्ताव है।

Shortage of Judges of High Courts in West Bengal

4823. SHRI K. B. GHETTRI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of West Bengal is facing a great

difficulty in High Courts because of the shortage of Judges;

(b) whether the Government of West Bengal have urged the Central Government to sanction eight posts of Judges recently; and

(c) if so, what is the reaction of the Central Government.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) to (c). The Government of West Bengal have pointed out the heavy arrears that have accumulated in the High Court of Calcutta and have proposed the creation of eight more posts of Additional Judges. They have been requested to obtain and send to the Central Government the views of the Chief Justice of the Calcutta High Court, before a final decision is taken in the matter.

पिकोल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर का समान पेड़

4824. श्री राम नरेश कुमाराहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाराणसी डिबीजन में पिकोल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर का पेड़ समान है;

(ख) यदि हाँ, तो स्टेशन मास्टर के पद का दर्जा न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस स्टेशन पर विजली नहीं है; और

(घ) इस स्टेशन की दशा में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सिंह नारायण) :

(क) जी, हाँ।

(ख) विभिन्न पेड़ों के लिए प्रतिशत पर माध्यात्म स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के संबंधों के अन्तर्गत के आधार पर मेड़ों को ऊंचा किया गया है।

(ग) स्टेशन पर विजली नहीं लगी है।

(घ) उमित लायत पर विभिन्न उपलब्ध होने और उपलब्ध लिपि के भीतर रेल उपयोगकर्ता मुख्यमात्रा समिति द्वारा सिफारिश किये जाने के बाद इस स्टेशन पर विजली लगाने का कार्यक्रम बनाया जायेगा।

भारतीय रेल नियम द्वारा घोषित साम

4825. श्री छित्रकाही वासित : क्या ऐट्रोलियम रेलवन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह वर्ष भारतीय रेल नियम द्वारा पिलो सभी वर्षों से अधिक लाभ प्राप्ति किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो मूल्यों में बढ़ि के परिणाम-स्वरूप कितना लाभ प्राप्ति किया गया था; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मूल्य ढांचे पर पुनर्विचार करने का है?

ऐट्रोलियम तथा रेलवन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नवन बहुगुण) : (क) जी, हाँ। इतिहास आयल कार्पोरेशन का युद्ध लाभ पिलो सभी वर्षों की अपेक्षा वर्ष 1977-78 के दौरान अधिक था। वर्ष 1977-78 के दौरान युद्ध लाभ लगभग 49.24 करोड़ रुपये का था जब कि वर्ष 1976-77 में युद्ध लाभ 48.41 करोड़ रु. था। वर्ष 1977-78 में युद्ध लाभ आयकर प्रधिनियम के अन्तर्गत कर का दायित्व कम होने के कारण अधिक हुआ था।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रमाण नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐट्रोलियम उत्पादों का मूल्य कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Oil Prospecting in Contai and Tamluk, West Bengal

4826. PROF. SAMAR GUHA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have any project to undertake prospecting of oil in the Contai and Tamluk sub-divisions of West Bengal;

(b) whether according to the report of the preliminary survey oil is likely to be found in that area, and along the off-shore areas of Contai;

(c) whether Government will also undertake off-shore drilling project along the coastal area of Contai sub-division of West Bengal; and

(d) if so, facts about the replies related to the above questions?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BHAGUNA): (a) to (d). The necessary information is being collected from the ONGC and will be laid on the Table of the Sabha

विश्व बैंक से सहायता

4827. डा० सरलीनारायण दादेय : क्या रेल नंती यह बताने की हुआ करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक से अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी भारतीय रेलों के विकास के लिए बैंक द्वारा पर वित्तीय सहायता देने के लिए दीवार है; और

(क) यदि हाँ, तो क्या उसके लिए परिवर्तनाएँ योजनायें बनाई गई हैं अथवा इस बारे में क्या घोरा है?

रेल अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंध में राज्य नंती (वी शिव नारायण) :

(क) और (क) भारतीय रेलों द्वारा पर विकास एजेंसी द्वारा अंग को पूर्या करने के लिए विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंध की सहायता प्राप्त करती रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंध जो विश्व बैंक से सम्बद्ध है, ने हाल ही में प्रस्तावित रेल आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण परियोजना के लिए 1900 लाख रुपये का एक और छह देने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। प्रस्तावित रुपये में गामिल वर्दों का घोरा और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंध द्वारा उनके लिए महसूत सहायता की राशि नीचे बढ़ाई गई है:—

मद	(लाख रुपये में)
(i) गारवाना आधुनिकीकरण विरोधान्वयन	1250
(ii) पहिया एवं मुरा संयंत्र	380
(iii) पहियों, टायरों और मुरों का आयात	150
(iv) विकास सहायता	120
जोड़	1900

माजारा स्टेशन पर रेलगाड़ी के पटरी से डाल जाने से सम्बन्धित दस्तावेजों का गुम होना

4828. वी शिव नारा राही : क्या रेल नंती यह बताने की हुआ करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के माजारा स्टेशन पर दिनांक 10 जून, 1977 को रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने की जांच से सम्बन्धित दस्तावेज गुम हो गये हैं; और

(क) यदि हाँ, तो उसके लिए कौन व्यक्ति दोषी पाये गये थे तथा उनके विषय क्या कार्यवाही की गई है?

रेल अन्तर्राष्ट्रीय में राज्य नंती (वी शिव नारायण) :

(क) वी नहीं।

(क) प्रश्न नहीं उठता।

Persons Coming to Delhi by Suburban Trains

4829. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that thousands of central government employees and workers daily come to Delhi/New Delhi by suburban trains and they have to reach their offices before 10 A.M.;

(b) whether keeping in view the large number of Government servants who come to their offices from far-away places, Government would ensure punctuality of suburban trains especially trains coming from Ghaziabad and Faridabad like Meerut shuttle etc.;

(c) the number of times when Meerut shuttle reached New Delhi station late during the last six months month-wise;

(d) whether Government would attach Diesel Engine to Meerut Shuttle for its speedy operation and if so, by what time and if not, the reasons therefor; and

(e) whether Government propose to introduce at least two more electric trains between New Ghaziabad to New Delhi/Delhi via Indraprastha rail bridge to avoid congestion in Meerut shuttle; if so, by what time and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) Yes. Every endeavour is being made to run suburban trains in time.

(c) During the period from January to June 1978, 2NM Meerut City-New Delhi shuttle arrived New Delhi late on three days each in January and February, six in March, two in April, three in May and one day in June.

(d) Dieselsisation of this train is not feasible for want of spare diesel locomotives.

(e) Introduction of any new train between Ghaziabad and New Delhi/Delhi is at present not operationally feasible for want of necessary terminal facilities at Delhi/New Delhi.

Manufacture of Synthetic Menthol

4830. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to allow a large scale unit to Manufacture Synthetic Menthol;

(b) if so, whether this large scale unit is under Public Sector or Private sector and if it is a Private sector unit the name of the company;

(c) whether Government are aware that by this decision nearly 200 small scale units engaged in menthol production will be badly affected and more than 35 thousand employees will lose their jobs; and

(d) in view of the production of menthol by small scale units is enough to meet the internal requirements will Government reconsider to allow large scale unit in this field of Industry?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). Yes, Sir. Shri Jayant S. Dalal has been granted a Letter of Intent on 28-10-1975 for the manufacture of 200 tonnes of L-Menthol etc. (through Synthetic route). The letter of Intent has been issued, apart from other conditions, subject to an export obligation of 25% of the annual production of Menthol.

An application for the import of Capital Goods by M/s. Camphor & Allied Products Limited, Bombay for the manufacture of Menthol and Thymol has also been approved on 19-8-1978 subject to an export obligation of 60% of the annual production and the party advised to apply to DGTD for registration of capacity.

(c) and (d). No precise demand estimate for this item has yet been made. The present demand of Menthol, is however, met by the existing units, both in the organised sector as well as in the small scale sector. With a view to protect the interests of small scale sector, a suitable export obligation is imposed by Government in the case of large scale units.

सरकारी बकील

4831. श्री भारती चत्तारी : क्या विधि, व्यापक और कम्पनी कार्य-भंडी पर बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 में कितने सरकारी बकील नियुक्त किये गये;

(ब) उच्चतम व्यायालय में बंधकालिक बकारी बकील व्यापक प्रबंधकालिक बॉर्ड-बॉर्ड से सरकारी बकील नियुक्त किये गये और उनके नाम और पते क्या हैं ; और

(ग) उनमें से पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान व्यापार स्थिति में नियुक्त किये गये सरकारी बकीलों के नाम और पते क्या हैं ?

विधि, व्यापक और कम्पनी कार्य-भंडी (श्री चात्ती चत्तारी) : (क) 274।

(ब) भारत के उच्चतम व्यायालय में नियुक्त सरकारी बॉर्डों की सूची लाग पट्ट पर एक ही गई है। [व्यायालय में रक्त व्यापक बॉर्ड संघर्ष एल-टी-2733/78]

(ग) व्यापार स्थिति के दौरान नियमित व्यापकतादारों को सरकारी बॉर्डों के रूप में नियुक्त किया गया था :

भारत का उच्चतम व्यायालय

श्री बार० बी० दातार और कुमारी मुख्यमान्द्र (श्रीमती सुषमा कंवर) :

विलीनी उच्च व्यायालय
श्री ए० एन० गोस्वामी

वित्त व्यायालय, विलीनी
श्री दीक्षित राम शुक्ता

मुख्य उच्च व्यायालय

सर्वेश्वरी सोराब, श्री० विमादासल, के० के० सिंहचंद्री, श्री० पार० बालूक और श्री० बी० टिप्पणीस

कलकत्ता उच्च व्यायालय

सर्वेश्वरी एस० एम० हाजरा, ए० पी० राय, श्री० गण० चोरी, विद्यास बनजी, श्री० क० नाहा, एम० वी० भवर्गी, हरिमंहन धर, प्रदीप मलिक, विवरेन्द्र शेषाल, एस० पाल, मधुसूदन बनजी और विलीन कुमार बोस।

इन व्यापकतादारों के पास उनके घपने घपने व्यायालयों की मार्फत हैं।

Restriction on Profit of Essential Drug Formulations

4832. SHRI S. S. SOMANI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) is it a fact that margin on essential drug formulations in the category I and II will be restricted to 40 and 55 per cent respectively;

(b) has there been any representation from the Industry on the ground

that this would make their production uneconomical and will badly hit their profitability; and

(c) have Government given an assurance to the Industry that formulations in category III and IV will enable them to maintain their profitability while reducing the prices of essential drug;

(d) how would this help units which are predominantly producing formulations in Category I & II only; and

(e) will Government allow such units, as listed in (d) above, to diversify their formulations activity to category III and IV drugs as long as they are within the ratio of 1:5 or 1:10 as the case may be.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Yes, Sir. The new Pricing Policy contained in the Statement laid on the Table of the Lok Sabha on the 29th March, 1978 envisages a mark up (including the distribution costs, outward freight, promotional expenses, manufacturers' margin and trade commission) of 40 per cent and 55 per cent respectively on Category I and II formulations.

(b) Yes, Sir. Representations were received from the drug industry on this point.

(c) to (e). It has been clarified to the Industry that in order to make their overall operations economically viable, with lower mark ups in Category I and Category II, Government would consider their diversification into the formulations falling in Category III and Category IV. Such a diversification would be considered keeping in view the provisions of paragraph 14, 17, 20, 22, 25 of the Statement referred to in (a) above.

Import of Crude Oil

4833. SHRI G. NARSIMHA REDDY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what is the total quantity of crude oil being imported and what is the quantity available in our country;

(b) within how many years we can be self-sufficient; and

(c) after becoming self-sufficient whether there is any possibility of reducing the prices of petrol, kerosene, diesel etc.?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) A quantity of 15 million tonnes of crude oil is expected to be imported during 1978-79. Indigenous crude oil availability during this period is expected to aggregate to 12.14 million tonnes.

(b) While all attempts are being made to intensify our exploration activities, and while plans are being made for the exploitation of our established reserves, keeping in view the need to conserve this non-renewable source of energy, it is difficult to hold out any promise of self-sufficiency in crude oil. Our exploration policy will be pursued vigorously with a view to making an inventory of our hydrocarbon resources.

(c) Does not arise in view of (b) above.

पेट्रोल का उत्पादन बढ़ाया जाना

4834. बोर्डरी राम गोपाल तिथः क्या पेट्रोलियम, रासायन और उर्बरक मंडी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह वर्ष के पेट्रोल के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष इसके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है और आगामी वर्ष में इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) क्या पेट्रोल के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए उपरोक्ताओं को राहत देने के लिए इसका मूल्य कम करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम तथा रासायन और उर्बरक मंडी (बोर्डरी नगर बहुगुणी) : (क) वर्ष 1978 के प्रथम छ. महीनों के दौरान पेट्रोल के उत्पादन में (मोटर स्प्रिट) वर्ष 1977 की तदनुस्पृष्ट अवधि के 691,000 बी० टन उत्पादन की तुलना में 768,000 बी० टन वृद्धि हुई। अगले वर्ष मोटर स्प्रिट के उत्पादन में वृद्धि मार्ग में वृद्धि पर नियंत्रकरणीय जिमका इस समय 5 प्रतिशत अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग). आगामी काले तेल के ऊपरोक्त मूल्यों के कारण पेट्रोल के मूल्य को कम करना संभव नहीं होगा।

कोरोबंडल एक्सप्रेस का गोदावरी के जिलों तक बढ़ाया जाना

4835. की कसुम हाय्याकूति : क्या ऐसे भंडी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरोबंडल एक्सप्रेस की सुविधाओं का, जो भंडा में एकमात्र एक्सप्रेस गाड़ी है, आनंद प्रदेश में गोदावरी के जिलों तक विस्तार किया जा सकता है; और

(ब) यदि नहीं, तो तमिनानाडु एक्सप्रेस शीर के १०० एक्सप्रेस गाड़ियों को समय पर तिमाने के लिए विवरणात्मक में गोवावरी के लियों के लागों के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

रेल वंचालय में राज्य भंडी (बी शिव नारायण):
(क) यी नहीं।

(ब) शीर (ग). गोदावरी लियों से मदास शीर विलों की तरफ यात्रा करने वाले अब गाड़ियों की सुविधा के लिए 121/122 तमिन नाडु एक्सप्रेस शीर 125/126 के एक्सप्रेस गाड़ियों विवरणात्मक में 45/46 हवड़ा-गुटर कोस्ट एक्सप्रेस 4 मदास-हवड़ा भंडी शीर 79 पुरी-तिलसित एक्सप्रेस के साथ उपयोग का सेवा है।

Different rate of Wages in different Drug Units

4836. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what are the reasons for having different rates of wages in two different drug and chemicals units managed by Government;

(b) whether the discrimination is resulting in dissatisfaction among the workers; and

(c) whether this has affected production of drugs and chemicals?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA):
(a) Presumably, the Hon'ble Member is referring to M/s. Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd. and Bengal Immunity & Company Ltd, whose management has been taken over by Government recently under the Industries (Development & Regulation) Act. Since Government has only taken over the management of these companies, the wage structures that existed while they were under private management, continue. Any revision of such wage structures is possible only after the future status of these companies is decided.

(b) and (c). The different rates of wages, as far as the Government is aware, has not led to any dissatisfaction among the workers, nor has it affected production.

Railway Line from Khamgaon to Jaina

4837. SHRI D. G. GAWAI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether a decision was taken to lay a railway line from Khamgaon to

Jaina in Buldana district in Maharashtra;

(b) the expenditure incurred by Government on laying this line in 1935 and 1936 and the reasons for stopping the construction works on this railway line later on; and

(c) whether Government propose to complete this railway line and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). A survey for Khamgaon-Chikli-Jaina line was carried out in 1900 and the earthwork for the same was also taken up as famine relief measure. The work was subsequently abandoned. Several surveys for the line have been carried out since then. The project was sanctioned in July 1931, but the construction of the line was postponed due to lack of funds. The project was again reviewed in the year 1933 and a Traffic Survey was carried out in 1933-34. It was abandoned in 1935 on account of its unremunerative character. Information regarding the expenditure incurred on the line at different stages is not available. No investigations have been made for the project in the recent past. In view of very limited availability of resources which are not sufficient even for meeting the commitments already made, the project may have to await better times for consideration.

Amritsar Railway Station

4838. DR. BALDEV PRAKASH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the work to provide entry to Railway Station, Amritsar from the Gole Bagh side has started;

(b) is it a fact that provision has been made in the current year's budget for this work; and

(c) how long it will take to complete the work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). The work of providing an entry from Gole Bagh side to Amritsar Railway station has been included in the Railway's Works Programme for the current year. Designs and Drawings are being prepared. It is expected that this work will be completed in about 3 years time. k

Petro-Chemical Complex at Cochin

4899. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the Kerala State Government have submitted its projects for a petro-chemical complex at Cochin; and

(b) if so, what are the details of the projects and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Proposals have been received from the State Government of Kerala from time to time for setting up a Petrochemical complex at Cochin.

(b) The initial proposals were with regard to a petrochemical complex based on a naphtha cracker, whereas the latest proposals envisage production of aromatics.

A number of studies are under way to work out the details of the new petrochemical projects which need to be set up during the Sixth Five Year Plan. A final decision regarding the projects to be taken up for implementation, including their locations, will be taken on receipt of the reports of the studies. If and when it is decided to set up any new petrochemical project the proposal of the Kerala Government would also be kept in view.

Reduction of Capital under FERA

4840. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the Indian Chemicals Industry has been asked to reduce its capital under the FERA;

(b) if so, whether the shares are sold only to the Kiroloskars; and

(c) if so, the steps taken to distribute the shares to Public?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) No company under the name and style of Indian Chemicals Industry has been directed to dilute the foreign holdings under the provisions of FERA, 1973.

(b) and (c) Does not arise.

Shortage of Life Savings Drugs

4841. SHRI F. P. GAEKWAD: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that recently there has been acute shortage of life savings drugs, not to speak of other vital medicines;

(b) whether Government are aware that these drugs can be procured only at exorbitant prices; and

(c) if so, whether Government will consider chalking out a dynamic strategy to meet social demands of the consumers who are not immediately concerned whether multinationals or Indian industry behave well within the bounds of National Law?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA):

(a) A close watch is maintained over the availability of essential drugs. The supply position of drugs and pharmaceuticals is by and large satisfactory. Occasionally reports of shortages of patent or proprietary products are received but in these cases equivalent substitutes of other producers are available. Recently reports about the non-availability of both proprietary and non-proprietary substitutes in respect of the following formulations have been received :

- (1) Dapsone Tablets
- (2) Adrenaline in Oil Injection
- (3) Neocaprine Tablets
- (4) Cinegestrol Injection & Tablets
- (5) Gas-Gangrene Anti-Toxin
- (6) Insulin Lente
- (7) Ethyl Chloride Spray
- (8) Mycostatin Tablets.

Suitable action to relieve the shortages has been taken in consultation with the manufacturers concerned.

(b) The prices of drugs and medicines are controlled under the provisions of Drugs (Prices Control) Order, 1970. Prior approval of the Government is necessary to effect any increase in price.

Any violation of the provisions of the Drug (Price Control) Order 1970 is punishable under the Essential Commodities Act, 1955.

(c) The following data relating to overall production of drugs and pharmaceuticals in respect of the last two years would reveal that the availability of drugs in the country is increasing :

Rs. Crores

Year	Availability of drugs*	Availability of formulations*
1976-77	150	700
1977-78	164	900

*Indigenous Production+Imports-Exports.

379 शाउन पलबल-दिल्ली बाटल रेलगाड़ी का तिलक लिंग, नई दिल्ली में बनता

4842. जी राम बंदर बेरवा : क्या रेल मंत्री मह बताने की हुया करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 379 शाउन पलबल दिल्ली बाटल रेलगाड़ी तिलक लिंग के बाहरी सिंगल पर प्रतिविन 10-15 मिनट रहती है क्योंकि एच ० एन ० फैटे बर्ल बाटल (जो नए यमुना युग्म से पूर्वर्ती है) प्रतिविन तिलक लिंग से पहुँचती है जिसके कारण पलबल और फरीदाबाद से आने वाले हजारों सरकारी कर्मचारियों को इसे रखना पड़ता है और वे अपने कार्यालय बिलबल से पहुँचते हैं;

(ब) क्या सरकार उन हवारों सरकारी कर्मचारियों के प्रति सहानुप्रिति रखती है जिन्हें तिलक लिंग स्टेनिंग पर रेलगाड़ी से पहुँचने के कारण देरी हो जाती है ताका क्या उनके विद्युत धनुषालानामक कार्यवाही की जा सकती है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार 379 शाउन रेलगाड़ी को तिलक लिंग पर इसके निवार्फरित समय यथा सुबह नी बजकर बालीस मिनट पर रोकने के लिए अधिकारियों को निवेदन देती, और यदि नहीं, तो इन दोनों रेलगाड़ीयों को साथ-साथ तिलक लिंग पर रोकने के लिए क्या वैत्यनिक उपाय किए हैं ताकि इन रेलगाड़ीयों में याता करने वाले सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय समय पर पहुँच सकें?

ऐसे संक्षालय में राज्य मंत्री (जी राम नारायण) :

(क) से (ग) जब कि 2 एन एम बेर्ल-नई दिल्ली बाटल बेरल सिंटी से ग्रातः आने वाली एक नायर ईंटिक बाली गाड़ी है, पलबल की तरफ से आने वाले ईंटिक बाली 367 शाउन यात्रा 379 शाउन पलबल-दिल्ली बाटल गाड़ीयों से ०९. ५० बजे या १०. २० बजे दिल्ली पहुँच सकते हैं। केवल कुछ यात्राओं पर, जब कि 2 एन एम बेर्ल बाटल विलबल से बच रही थी, लेटकार्ड सम्बन्धी क्लिनिकों के कारण 379 शाउन को तिलक लिंग के बाहरी सिंगल पर रोका गया। 379 शाउन पलबल-दिल्ली बाटल का समय पालन संतोष जनक रहा है।

Assistance by Bulgaria for setting up of Chemicals and Pharmaceutical Unit

4843. SHRI TRUN GOGOI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased state:

(a) whether Bulgaria will help India to set up chemicals and pharmaceutical units and agro-industrial complexes in various parts of the country;

(b) whether the assistance will also include training programme by the Bulgarian Technocrats and experts in various fields; and

(c) if so, how soon the aid would be forthcoming and the extent of it?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) :

(a) to (c) At the Fourth Meeting of the Indo-Bulgarian Joint Session for Economic, Scientific and Technical Cooperation held recently, Bulgaria has offered technical assistance for setting up chemical and agro-industrial complexes in various parts of India. The assistance offered includes training of Indian personnel.

The offer of assistance by Bulgaria is being studied.

Availability of Imported Life-Savings Drugs

4844. SHRI S. R. REDDY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that certain imported life-saving drugs for cancer and other fatal diseases are not available in the country; and

(b) if so, what steps Government propose to take to ensure adequate supply of these drugs?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) :

(a) and (b) Anti-cancer formulations in respect of which complaints about shortages have been reported recently are Clinestrol tablets and Injections. Shortages of other life saving drugs for cancer and other fatal diseases have not been reported.

The main reason for the shortage of Clinestrol tablets and Injections is that M/s. Glaxo Laboratories (India) Ltd.,

who were manufacturing these preparations, have stopped production due to very low demand. Other firms are marketing these tablets under the name of Stilboestrol tablets and they are available in the country.

The import policy for the year 1978-79 provides for liberalised import of anti-cancer drugs and other life-saving and essential medicines; and the consumers can import the same under the Open General Licence.

रेल माल डिब्बों की कमी

4845. श्री अवनतराम जायसवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या मह मच है कि रेल माल डिब्बों की कमी के कारण ग्रोवोरिंग उत्पादन पर दुरा प्रभाव पड़ा है :

(ग्र) यदि हाँ, तो 1977 में किनने रेल माल डिब्बों का उत्पादन हुआ तथा 1976 में उत्पादित माल डिब्बों की संख्या से उनकी संख्या कितनी अधिक थी ;

(ग) रेल विभाग द्वारा पर्यात संख्या में माल डिब्बे सप्लाई न किया जाने के क्या कारण हैं तथा क्या मह कमी उत्पादन में कार्यक्रमान्वयन के कारण प्रभाव पर्यात संख्या में माल डिब्बे न उत्पादित करने के कारण उत्पन्न हुई है; और

(घ) रेल माल डिब्बों की कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) रेलवे के माल डिब्बों की कमी के कारण ग्रोवोरिंग उत्पादन पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का ब्योरा इस मंत्रालय को ज्ञात नहीं है। किन्तु उत्कर्षकों और सीमेंट के अधिक आवाहन के कारण रेलों पर भारतगोदावरी यातायात के परिवर्तनाकृष्ण रेलों को लम्बी दूरी काले यातायात की हुआई करने को कहा गया है जिसके कारण माल डिब्बों के फेरों पर प्रतिकूल समय लाने लगा। माल को लाने, उत्पादने यादि के लिए होने वाले विकल्प के कारण भी माल डिब्बों के फेरो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके कारण माल डिब्बों की सप्लाई में मासूमी सी नियरेट आयी और कुछ लेबों से इस बारे में विकायते मिलें।

1976 में बनाये गये माल डिब्बों की संख्या चौपहियों के द्वितीय से 11284 और 1977 में 12669 थी। इस प्रकार 1977 में उत्पादन में 1385 माल डिब्बों की बढ़ि हो गई। माल डिब्बों की उपलब्धता में कमी के कारण उत्पादन में अनुशासन नहीं कहा जा सकता क्योंकि 1975-76 और 1976-77 के दौरान योजना में निर्धारित स्फरण से अतिकृत उत्पादन हुआ था। सरकार ने नियंत्रण किया है कि 1978-79 के बजाए में चौपहियों

के हिसाब से 10,000 माल डिब्बों का आवंशक होने का लिए इस तरह रखा गया है जबकि 12,000 माल डिब्बे कर दिया जाय जिसे दोर बढ़ा कर 13,000 तक कर देने की सम्भावना हो सकती है।

Wagon Shortage in Guntakal Division

4846. SHRI K. OBUL REDDY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether he is aware of the acute shortage of wagons in Guntakal Division after its merger into South Central Railway;

(b) what action Government are going to take for the supply of nearly 1000 pending demands for wagons in Cuddapah and Kodur stations of Guntakal Division;

(c) what action Government propose to take to meet the future demands of wagons for export of huge quantities of Baryts to various countries abroad from Cuddapah and Kodur Stations of Guntakal Division;

(d) whether Government propose to run a Baryts goods special to Madras Harbour from these stations to meet the heavy Baryts traffic for export; and

(e) whether Government are aware that nearly 50,000 tonnes of Baryts Powder has to be moved to North West and North Eastern parts of the country for the drilling requirement of O.N.G.C. in closed wagons and whether the Govt. will take action for supply of closed wagons for O.N.G.C. and for export of Baryts Powder?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b) Wagons are being supplied for clearing demands at Cuddapah and Koduru depending upon the availability of suitable stock. At the end of July only 585 demands were outstanding at Cuddapah and Koduru stations of Guntakal Division.

(c) and (d) One box rake has been formed and put into close circuit between Koduru and Madras Harbour for loading Baryts. In addition, block specials with open wagons are planned to run from Cuddapah and Koduru to Madras Harbour and available covered wagons are secured to load Baryts Powder.

(e) Yes. Supply of covered wagons for clearing demands of Baryts Powder from Koduru on O.N.G.C. account will be arranged depending on the availability of covered stock.

Conversion of Sholapur-Gadag Line

4847 SHRI K. B. CHOUDHARI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to convert Sholapur-Gadag Railway line from metre gauge to broad gauge ; and

(b) if so, when the conversion job is going to be undertaken ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) No; in view of the severe constraint on the availability of resources, it will not be possible to undertake the conversion of Sholapur-Gadag line at present.

Shortage of drugs for T.B. Treatment

4848. SHRI D. AMAT : Will the Minister of PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of drugs for the treatment of T.B. cases in the country ; and

(b) if so, what are the reasons and what steps are being taken to remedy the situation ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) and (b) : The only anti-T.B. formulation whose shortages have been reported from different areas of the country, from time to time, is Streptomycin Injection. The main reason for the shortage of this drug is late arrival of imported material due to inadequate availability of bulk drug Streptomycin Sulphate in the international market.

Apart from arranging for the needed imports, the following steps were also taken to deal with the situation :—

(i) The State Drug Controllers/Associations of Drug Manufacturers were requested to ask the Streptomycin viallers to curtail their production of Streptomycin-Penicillin in order to increase

the availability of Streptomycin Injections. Major viallers were also separately requested to do so.

(ii) IDPL and HAL, both public sector enterprises, were requested to augment their production of bulk Streptomycin Sulphate.

GPC have since released adequate quantities of bulk Streptomycin Sulphate among various viallers who are lifting the material and the supply of Streptomycin vials is improving.

Private Railway Companies

4849. SHRI AHMED HUSSAIN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the name and number of private Railway companies operating in N.E. region with State-wise break-up of Kilometers, liabilities and payments made to and received from Government;

(b) how and by when Government propose to take over them ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) There are Two Light Railway Companies viz., the Chaparmukh-Silghat Light Railway Company and Katakhali-Lalazar Light Railway Company which are privately owned but worked by the N.E. Railway in the State of Assam. The statement attached gives the details.

(b) and (c) : In case of both the railways the Govt. have the right to exercise its option once every ten years to purchase the Railways. The last option to purchase fell on 31-3-78 for Chaparmukh-Silghat Light Railway Co. and on 31-3-74 or Katakhali-Lalazar Light Railway Co. It was decided not to purchase these lines, because the purchase was not considered financially viable. The general policy of the Govt. in regard to purchase of privately owned railways has been to conserve resources for acquisition of new assets rather than to purchase old and worn-out ones.

Statement

	Chaparmukh-Silghat	Katakhal-Lalabazar
1. Length	81 Kms.	38 Kms.
2. Liabilities as on 31-3-77	(i) Subscribed capital, 31,60,000 Subscribed capital (ii) Balance on Reserves & Surplus Acc- ounts. 1,63,890 Reserves & Surplus Accounts: 60,633 (iii) Loan from Govt. for capital expendi- ture. 1,13,633 Debentures. 6,50,000 (iv) Advance to the Co. 1,50,000 .. (v) Misc. 2,51,982 Misc. 1,20,368	8,91,100 60,633 6,50,000 .. 1,20,368
3. (i) Payment made to the Company during 1976-77.	Rs. 3,74,293	Rs. 1,42,555
(ii) Payment* received from the company during 1976-77.	Rs. 94,210/-	Rs. 6,505/-

*This does not take into account the actual expenditure incurred by the N.E. Railway in running the lines.

Cost of construction of pavilion at Exhibitions arranged by A. I. Congress Party

4850. SHRI BHAGAT RAM : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the total cost (for construction) of pavilion or stalls paid to contractors in the exhibitions arranged by All India Congress Party on the eve of Session of All India Congress Committee.

(b) in case these were constructed departmentally, the cost debited to these works may be given separately for each work;

(c) the fee, rent or any other charges paid by railways to the organizers of the exhibitions showing details of such payments;

(d) cost on the maintenance of the aforesaid pavilions or stalls;

(e) cost of dismantling these pavilions or stalls after the exhibitions were over; and

(f) under whose order or recommendations these exhibitions were held and the details of the orders or recommendations thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) A sum of Rs. 2,99,900 was paid by the Railways to the contractors for construction of railway pavilions in the various exhibitions arranged by the AICC on the eve of AICC Sessions.

(b) Rs. 48,720 was incurred for departmental construction of pavilions, out of which Rs. 41,000 was spent on erection of stalls, floorings, etc. and Rs. 7,720/- as miscellaneous charges including T.A./D.A. paid to the staff employed at stalls, electrical work, etc.

(c) Rs. 1,01,360 as rent.
(d) Rs. 17,278/-.
(e) Rs. 21,380/-.

(f) The Railways' participation in these exhibitions was decided upon by the Ministry of Railways (Railway Board) vide details in the enclosed Statement :

Statement

Exhibitions held during A.I.C.C. Session and participated in by the Zonal Railways

NORTHERN RAILWAY :

A.I.C.C. Session at Kamagatamaru Nagar, Chandigarh, held in December, '75/Jan., '76.

NORTH-EAST FRONTIER RAILWAY:

A.I.C.C. Session at Gauhati held in November/December, '76.

EASTERN RAILWAY:

(1) A.I.C.C. Session, 1965 at Durgapur.

(2) A.I.C.C. Session, 1972 at Bidhan Nagar, Calcutta.

Sale of Books and Agencies
Railway Stations

4851. SHRI ARJUN SINGH BHADOURIA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 4619 on 28th March, 1978 regarding sale of books and Agencies at Railway stations and state :—

(a) whether the said information has been collected; and

(b) if so, what are the details of the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHLOK NARAIN) : (a) and (b). The Implementation Report containing the required information has already been laid on the Table of the House by the Department of Parliamentary Affairs, on 27-7-1978.

Subjects for Diploma Courses in
Company Secretaryship

4852. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 9633 on 9th May, 1978 regarding syllabus of Diploma in Company Secretaryship of Delhi and state :—

(a) whether the syllabus of the Post-Diploma in Company Secretaryship and the correspondence course of the Institute does not contain the subjects like Project Report/Dissertation and experienced trained employed persons in the field are admitted in the course;

(b) whether persons who have already passed the full-fledged two years Delhi State Course of Company Secretaryship are required to again appear in the examinations conducted by the All India Institute of Company Secretaryship; if so, reasons thereof; and

(c) whether Government propose to recognise the Post-Diploma in Company Secretaryship under Rule 2(a) of Companies (Secretary's Qualifications) Rules, 1975 or to refer the matter to the Expert

Committee on Company Law, already appointed by the Government?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) As per syllabus of the correspondence course of the Institute of Company Secretaries of India and the Post Diploma in Company Secretaryship of Delhi Administration, the position is as under :—

Corres- pondence Course of the Insti- tute	Post- Diploma in Com- pany Secre- taryship
(i) whether Project Report/Dissertation is included in the course.	No Yes
(ii) whether experienced, trained persons in the field are admitted.	No Yes
(b) Yes, Sir. Under rule 2(a) of the Companies (Secretary's Qualifications) Rules, 1975, a person in order to be eligible to be qualified as Secretary of a company having paid up share capital of Rs. 25 lakhs and above, is required to have the membership of the Institute of Company Secretaries of India, New Delhi.	
(c) There is no such proposal at present.	

बिहार में स्टेशनों को नया रथ देना

4853. श्री राम सेथक हड्डारी : नया रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नया दक्षिण मध्य रेलवे में स्टेशनों पर सफाई रखनाव और सुन्दर बनाने के बारे में किये गये कार्यों के परिणामस्वरूप उक्त रेलवे का कार्य घर सुचारूपण ढंग से हो रहा है;

(ख) नया बिहार में हसनपुर रोड, नया नगर, कोसरा, फिलानपुर तथा मुसाइपुर स्टेशनों पर सफाई, रखनाव और सुन्दर बनाने के लिए भी इसी प्रकार के कार्य किये जाने हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में व्योरा नया है ?

रेल मंत्रालय में राय शंको (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग). रेल प्रशासन का नियन्त्रण यह प्रयास रहता है कि स्टेशनों को साफ़-सुधरा रखा जाये और उनका रखरखाव ठीक तरह से किया जाये।

दलिल-नम्बर रेलवे पर कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों के डार्बे में परिवर्तन/नवीकरण किया गया है। जब ऐसे काम प्रावधान होते हैं तब तक कार्यक्रम के आधार पर उन्हें किया जाता है बशर्ते सेवीय रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति उनका भनुमोदन कर दे और धन उपलब्ध हो।

इस समय दूरवास्तर रेलवे के हसनपुर रोड, नवानगर, रुसेडा घाट, किशनपुर और मुक्तापुर रेलवे स्टेशनों के डार्बे में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Hindi Medium in Railway Schools, Dahod

4854. SHRI SOMJIBHAI DAMOR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) is there any proposal to extend educational facilities from 1st to IV Class in Hindi Medium in Railway Schools, Western Railway, Dahod ;

(b) if so, please give full details thereof ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) whether Central Government are pressing Gujarat Government to open a primary school of Hindi Medium ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) There already exists one Railway Primary (Hindi Medium) School at Dahod in addition to two Hindi Medium Schools run by railwaymen.

(d) No.

Short Payment of Wages to Labourers performing Parcel Handling Work at Allahabad

4855. SHRI N. K. SHEJWALKAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to reply given to Unstated Question No. 312 on the 18th July, 1978 regarding short payment of wages to labourers performing Parcel handling work at Allahabad and state :

(a) whether it is the policy of Government to encourage Society by way of giving them extensions beyond the contractual term who were/are systematically and continuously cheating poor and innocent workers by way of making short payments to the tune of several lakhs of rupees during a short period of few years ;

(b) what action has been taken by the Government to recover short payment of Rs. 1,23,53/- provisionally worked out against the Society;

(c) whether officers of Headquarters Office, Northern Railway are interfering with the Divisional Superintendent, Allahabad, in the matter of recovery of amount from the Society; and

(d) if so, what remedial action is proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) Recoveries are being effected from the bill of the Society commencing from the month of April, 1978.

(c) No.

(d) Does not arise.

Booking of Low Rated Goods Traffic

4856. SHRI G.M. BANATWALLA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the railways have recently completely closed or suspended booking of low rated goods traffic ;

(b) if so, since when and what are the reasons therefor ; and

(c) in view of the inconvenience and losses to small dealers particularly when is the said booking expected to recommence ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Trains Running between Mysore and Chamarajanagar

4857. SHRI B. RACHAIAH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the trains are running between Mysore and Chamarajanagar;

(b) if so, from what date; and

(c) what are the imminent causes for cancelling the running of these trains started by M.S.R. belonging to former Indian State ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) and (c). Out of 8 pairs of passenger trains running on Mysore-Chamarajanagar section 3 pairs of trains were cancelled on 22nd and 23rd July, '78. One

pair of trains was restored on 24-7-78 and another pair on 26-7-78. At present only one pair of trains remains cancelled. This will be restored as and when the steam coal position becomes satisfactory.

Regularisation of services of Casual Workers

4858. SHRI T. S. NEGI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the services of casual workers with six months service are regularised by Government;

(b) whether there are employees in the catering department of the Railways who have rendered more than three years service but have not been made regular;

(c) if so, the reasons therefor; and whether Government proposed to regularise the services of these casual workers;

(d) whether an interview was held in January, 1978 for the regularisation of services of casual workers working in the canteens in Parliament House and its Annex;

(e) if so, how many workers were made regular as a result thereof indicating the length of their service ; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS : (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Casual workers with over 120 days of service are eligible for screening but their regularisation will depend on vacancies being available.

(b) Yes.

(c) As stated in reply to part (a) of the Question, regularisation of services of casual workers depends on the availability of regular vacancies. The screened candidates are listed and absorbed in regular vacancies as and when the same occur.

(d) to (f) A sitting of the Screening Committee was held in January 1978 but the screening of all the casual labour could not be finalised as the eligibility of some of them was under examination. The screening will be finalised shortly.

Trains Originating from and terminating at Allahabad

4859. SHRI DHIRENDRANATH BASU : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of mail, express and passenger trains originating and terminating from and to Allahabad and through mail, express and passenger trains including parcels express with stoppage at Allahabad during the financial years 1960-61, 1961-62, 1975-76, 1976-77 and 1977-78.

(b) the number of parcels packages handled at Allahabad including packages in sealed vans during the financial years 1960-61, 1961-62, 1975-76, 1976-77 and 1977-78 ; and

(c) the assessed number of parcel porters required to exclusively handle parcels traffic at Allahabad upon which monthly lump-sum rate payable to handling contractors was fixed by Railways during the financial years 1960-61, 1961-62, 1975-76, 1976-77 and 1977-78 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) The number of trains originating and terminating and passing through Allahabad including Parcel Express and COD shuttle were 46 in 1960-61, 46 in 1961-62, 66 in 1975-76, 74 in 1976-77 and during 1977-78 were 74.

(b) and (c). A statement is attached.

Statement

(b) Yearwise comparative figures of packages booked, received and handled at parcel transit at Allahabad are as under :

Year	No. of Packages Booked	No. of Packages received	transit Packages handled	Total No. of packages dealt with
1960-61				
1961-62				
1975-76	288791	971125	549660	1209576
1976-77	327812	420738	567210	1325760
1977-78	345917	410972	569184	1326073

(c) The number of porters required to perform parcels handling work and other miscellaneous items of work was assessed at 110.

Train Accidents

4860. SHRI V. M. SUDHEERAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the increasing number of train accidents ;

(b) whether Government received any report on this rail accident at Valachive near Kottayam ;

(c) the details of the damages ; and

(d) the steps taken therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) During July, 1978, there were 75 train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains on the Indian Government Railways against 95 and 88 train accidents in May, 1978 and June, 1978 respectively.

(b) Presumably, the reference is to the derailment of 47 Up Trivandrum-Cannanore Express between Kunjappuram and Piravam Road stations of Southern Railway on 1-8-1978. The report of the Additional Commissioner of Railways Safety, who inquired into this accident, has not yet been received.

(c) The cost of damage to railway property involved in this accident has been estimated at approximately Rs. 80,000/-.

(d) Since human failure is the largest single factor responsible for accidents, Safety Organisations on the Railways have been engaged in a relentless campaign to create greater safety consciousness amongst the staff connected with the running of trains and to ensure that staff do not violate rules or indulge in short-cut methods that may lead to accidents. In order to reduce dependence on human element, various sophisticated aids like ultrasonic flaw detectors for wheels, axles and rails, track-circuiting, axle counters, automatic warning system, etc. are being introduced progressively. It has been decided to complete track-circuiting on run-through lines on all the stations on trunk routes by 1981. In addition, track-circuiting of 100 vulnerable stations from fouling mark to Advanced Starter will be completed by 30-9-1979.

तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करना

4861. श्री शारद एम् रकेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने का है जो सकाम अधिकारियों द्वारा नियुक्त किये गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे बोर्ड के लिये III के उन तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के अपनी तर्फ आवेदन आरी न किए जाने के कारण है जो वर्ष 1975-76 में सकाम अधिकारियों द्वारा नियुक्त किये गये थे ;

(ग) क्या उनके द्वारा 11-6-77 की सकाम समां में घोषित बहनीत वर्ष 1975-76 में सकाम अधिकारियों द्वारा नियुक्त रेलवे बोर्ड के तदर्थ कर्मचारियों पर सारूप नहीं होती कि सकाम अधिकारियों द्वारा नियुक्त तदर्थ कर्मचारियों को नियमित कर दिया जायेगा ;

(घ) यदि हाँ, तो उनके कब तक नियमित किया जायगा और यदि नहीं, तो उन के सम्बन्ध में यह नीति सारूप क्यों नहीं की गई है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार [उनको लेकीय रेलवे में घोषित रेलवे सेवा आयोग में बदलन का है और यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य भंडी (श्री शिव नारायण) : (क) जी हैं।

(ख) से (य). 1976 में जो विशेष कर्मचारी तदर्थ घाघार पर नियुक्त किये गये थे वे हिन्दी टाइप जानने वाले बल्की की कमी की पूरा करने के लिए थे। उनकी नियमित विशेष क्षमता से बोधी अवधि के लिए इस बते के घाघार पर की गई थी कि जब वे नियमों में की गई यद्यवक्ता के घनसार निर्धारित स्रोत से घर्हता-प्राप्त कर्मचारी उपलब्ध हो जायेगे इन्हें हटा दिया जायेगा।

इन सभी तदर्थ कर्मचारियों की सेवाओं को तब तक नियमित नहीं किया जा सकता जब सकाम आयोग द्वारा जी जाने वाली परीक्षा पास नहीं कर लेते और कार्मिक विभाग द्वारा नामित नहीं किये जाते।

(इ) इन कर्मचारियों को लेकीय रेलवे में समर्पित करने के प्रस्ताव पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक ये सोने रेल सेवा आयोग द्वारा जी जाने वाली परीक्षा पास नहीं कर लेते और उनके द्वारा नामित नहीं किये जाते।

स्टेनल सुपरिलेन्डेन्टों की संख्या

4862. जी रेलवे प्रताप सिंह : यदा रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) परिवहन-पूर्व और दक्षिण रेलवे में देन सुपरिलेन्डेन्टों की अंकूरण संख्या कितनी है ;

(ब) उनमें से कितने पद रेलवे केंटरिंग विभाग में हैं, रेलवे-जार, और गये ;

(ग) क्या दक्षिण रेलवे के उपरीकत पर पर केवल अन्य विभागों के कर्मचारी लेने का नियंत्रण किया गया है ;

(द) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(इ) क्या सकारात्मक विभाग के कर्मचारियों में से इस पद को अर्हता का है जिससे परिवहनों की विभागीय भूमि भाँति हो सके ?

रेल अंतर्राज्य में राज्य भंडी (जी शिव नारायण) :

(क) परिवहन रेलवे	एक
पूर्व रेलवे	एक
दक्षिण रेलवे	25
(ख) परिवहन रेलवे	एक
पूर्व रेलवे	एक
दक्षिण रेलवे	11

(ग) जहाँ तक परिवहन और पूर्व रेलवे का सम्बन्ध है, प्रत्येक रेलवे पर केवल एक-एक पद है और उस पर, फिलहाल, बानपान विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी ही लगा हुआ है। जहाँ तक दक्षिण रेलवे का सम्बन्ध है, रेल प्राप्तानन ने, बानपानापात्र थामक संगठनों के साथ विभाग-विभागीय करने के बाद, स्थानीय तौर पर यह विभिन्नवाले किया है कि इन पदों को भरने के लिए बानपान विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ बाणीय और विभाग विभागों के कर्मचारियों के उन कर्मचारियों पर भी विभाग विभागीय काम करने का सम्पर्क का अनुभव प्राप्त है।

(च) यारी भाँधीक का काम केवल बानपान प्रबन्धी का पर्यावरण करना ही नहीं है। उससे यारी की जाती है कि वह विभिन्न शासकीयों के कर्मचारियों का काम म सम्बन्ध एवं पर्यावरण की स्वयंस्वा करे और यारी में जिन विविध सुविधाओं की स्वयंस्वा की हुई है उनके उचित स्पष्ट से काम करने की सुनिश्चित करे।

(इ) यारी (ग) और (च) के उत्तरों को देखते हुए, इसका प्रमाण नहीं उठता।

Wagons supplied to Hindustan Steel Stockyard at Bhubaneswar

4863. SHRI SIVAJI PATNAIK : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that wagons supplied to the Hindustan

Steel Stockyard at Bhubaneswar deliberately returned by the contractor caused a great loss to the revenue of the railways ;

(b) if so, what action Government have taken against this; and

(c) whether Government are also aware that officials are involved to manipulate demurrage charges for the interest of the contractor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) The Railways do not deal with any contractor but only with the Branch Manager of Hindustan Steel Ltd. Stockyard, Bhubaneswar. Any request for diversion or removal of wagons is generally made by the Depot Superintendent of the Stockyard.

(b) Does not arise.

(c) Since the Railways have no dealings with any contractor, the question of officials involved in manipulating demurrage charges in favour of the contractor does not arise.

Loss detected in investigation against Deputy Chief Engineer, N.E. Railways in 1961

4864. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a loss of Rs. 32,500/- was detected in an investigation done by the Chief Vigilance Commissioner and his staff against a Deputy Chief Engineer (presently promoted as General Manager) on the N.E. Railway in the year 1961 ;

(b) is it a fact that the then Chief Vigilance Commissioner instead of recommending recovery of the loss of public money directed an oral warning to be administered to the officer; and

(c) how many such cases were investigated by the Commission from 1966 upto 1977 and what was the amount of public money written off ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b). In 1961, tenders were invited by the North Eastern Railway for the construction of 31 units type I, 10 units type II, 3 units type III and 3 units type IV quarters for medical staff at Gorakhpur and while the tenders received were under scrutiny, a decision was taken to change the side in respect of 31 units type I quarters. The Change of site necessitated extra plinth involving extra earth work and brick work. The contractor, whose tender was

the lowest with respect to quantities of work at originally proposed site, was awarded the contract. His rates for the additional work for the new site were higher than those quoted by other contractors. The C.B.I. investigation showed that the value of the contract became higher by Rs. 32,500 as compared to next higher tender taking into consideration the quantities at the new site. The Central Vigilance Commission to whom the case was referred, as per extant procedure, advised that no malafides had been established against the Officer and that it would be enough if he was administered a warning to be careful in future, which was done.

The case was investigated by the Central Bureau of Investigation and not by the Central Vigilance Commission. (There is no post like Chief Vigilance Commissioner.)

(c) The Central Vigilance Commission has advised that no record is available to show the number of such cases investigated by the Commission. Such statistical record is not maintained by the Commission.

Increase in Price of Urea

4865. SHRI CHHITUBHAI GAMIT: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the Gujarat State Fertilizers Company Limited has demanded increase of 40 to 50 per cent in the price of urea fertilizer; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) and (b). Yes, Sir. The Gujarat State Fertilizer Company Limited have made a representation for increase in their retention price of urea from Rs. 1006 to Rs. 1557 per metric tonne. While a part of the increase has been sought on account of increase in cost of packing material, catalysts, consumable stores and repairs and maintenance, bulk of the increase claimed by the company is on the ground that the basic parameters of pricing like consumption norms, level of capacity utilisation and the working of net worth adopted in fixation of retention prices should be relaxed and related to their actual experience.

Expansion of Capacity by Synthetics and Chemicals Limited

4866. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what is the rated plant capacity of Synthetics and Chemicals Limited and

how much rubber every year this factory has manufactured year-wise for the last three years and what was its value in terms of money year-wise; and

(b) whether the Government have any idea of allowing this industry to expand its capacity even when its production costs are extremely high, huge wastage of money prevails and additional quantities cannot be given to this industry of alcohol which will be consumed in other precious industries?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) The licensed capacity of SRR and Nitrile rubber plants is 30,000 M.T. and 2,000 M.T. respectively. Production and value of these rubbers during the last three years as reported by the company is as follows:

	1975	1976	1977
Production	22,712 M.T.	23,264 M.T.	27,328 M.T.
Value	Rs. 19.25 crores	Rs. 21.67 crores	Rs. 27.09 crores

(b) No such proposal is under consideration.

Setting up an Antibiotic unit in Nagpur

4867. SHRI R.K. MHALGI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government and the State Government of Maharashtra have proposals under consideration to start antibiotic unit in Nagpur area;

(b) if so, at what stage the said proposals stand; and when it is likely to be commissioned; and

(c) what is the total outlay of each of the projects and the break-up of the share of Centre and the State Government?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) and (b). Government have approved on 3rd August, 1978 the setting up of a joint venture formulation unit near Nagpur in Maharashtra State, by Hindustan Antibiotics Ltd., and the State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra. This project is expected to be completed by August 1980.

(c) The project involves a total capital outlay of about Rs. 2.84 crores with equity of Rs. 114 lakhs. The contribution of Hindustan Antibiotics Ltd., and the State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra to the equity would be 51% and 49% respectively.

Railway Platforms in Kerala

4868. SHRI K. KUNHAMBU : SHRI VAYALAR RAVI :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Railway Platforms in Kerala are not in accordance with climatic conditions ;

(b) whether these uncovered platforms are very inconvenient and troublesome to the passengers during rainy seasons ; and

(c) do Government propose to make provision of covered platforms in major stations in Kerala ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (c). Covers on Railway Platforms including those in Kerala are being provided according to their relative needs, on a programmed basis, in consultation with Railway Users Amenities Committee and subject to availability of funds.

Trains between Ferozepur and Chandigarh

4869. SHRI MOHINDER SINGH SAYIAN WALA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a train between Ferozepur and Chandigarh via Abhor & Malout has been routed through Suratgarh and Bhatinda ;

(b) if so, the reasons for the same ; and

(c) whether in the interest of better political and social link of Chandigarh with Ferozepur than Suratgarh the old link will be restored ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (c). No. 87/88 Kalka-Bhatinda-Chandigarh Express has been extended to Suratgarh with effect from 15-5-78. Two through coaches continue to run on this train between Firozepur and Chandigarh/Kalka.

Persons arrested for Sabotage on Railways

4870. SHRI MOHINDER SINGH SAYIAN WALA : Will the Minister of

RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 3768 on 21-3-78 regarding persons arrested for sabotage on Railways and state :

(a) whether the information regarding the number of persons arrested for sabotage on railways has since been collected ;

(b) whether these culprits belonged to certain political party or any cult otherwise ; and

(c) action taken against them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes. Twenty persons were arrested in one case of sabotage on Central Railway between Mana and Murtizapur in Akola District.

(b) No complicity or collaboration of any political party or cult has been proved in the course of investigation.

(c) Charge-sheets have been filed against eleven persons. The case is pending trial.

Distribution of Fertilizers imported from U. K.

4871. SHRI MOHINDER SINGH SAYIAN WALA : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5482 regarding distribution of fertilizers imported from U. K. on the 4th April, 1978 and state :

(a) whether details for distribution of fertilizers imported from U. K. have since been finalised ;

(b) if not, the reason for the same ; and

(c) whether some supplies have been received from U. K. ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) to (c). The details of the Fertilizer Educational Project to be financed from U. K. Aid Funds are being discussed with the concerned Ministries with a view to obtaining the necessary approval of Government.

No supply of fertilizers has so far been received from U. K. under this scheme. However, an order has been placed by Fertilizer Corporation of India for supply of 25,000 tonnes of Urea from U. K. which is expected to arrive during the current financial year.

Section Officers in Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway

4872. SHRI ROBIN SEN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Section Officers working in the Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway at Delhi are not transferable and the Section Officers working on Vadodra, Ratlam, Kota, Rajkot and Bhavnagar Divisions are transferable ; and

(b) if so, steps taken by the Government to bring at par all the Section Officers in the matter of transfer ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No. The posts of Section Officers (Accounts) are selection posts. Their seniority is maintained on whole railway basis and they are liable for transfer anywhere on Western Railway.

(b) Does not arise.

Demonstrations at gate of Foreign Traffic Accounts Officer

4873. SHRI ROBIN SEN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that series of Demonstrations were held at the gate of the Foreign Traffic Accounts Officer, Western Railway at Delhi from 1st May, 1978 to 31st July, 1978 ; and

(b) if so, the demand of the employees and steps taken by Government to finalise each demand ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) There were 5 demonstrations during the period.

(b) The demands are :

- (1) Inter-section transfers.
- (2) Refund of CDS (Other than annual).
- (3) House Building Advance and Flood Advance.
- (4) Shortage of Staff.
- (5) Delay in disposal of staff representations.
- (6) Out of turn allotment of Quarters.
- (7) Construction of more Quarters.

(8) Matters pertaining to passes and establishment claims.

In accordance with Government's policy staff demands received from any source are given due consideration and necessary action is taken. The demands of all categories of staff are considered and solved through the various tiers of the Permanent Negotiating Machinery and the Joint Consultative Machinery.

Cash Award to Staff of Asansol Division

4874. SHRI ROBIN SEN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) how much amount has so far been spent towards payment of cash award to staff of Asansol Division with effect from April, 1977 and onwards (month-wise) ;

(b) what are the basic principles/conditions of considering grant of cash award to staff ;

(c) how much staff has been granted cash award on more than one occasion from April, 1977 and onwards ;

(d) whether there is any improvement in Railway working in Asansol Division after payment of Cash Award to staff ; and

(e) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) The details are as under :—

Month/Year	Amount	Rs.
April '77	12,025	
July '77	1,300	
August '77	1,550	
October '77	8,750	
January '78	1,100	
February '78	2,850	
March '78	5,975	
April '78	23,750	
May '78	400	

(b) Awards are given in recognition of exemplary and extraordinary work done by the staff.

(c) 33

(d) and (e). It would not be possible to correlate improvements in Railway working with the grant of individual cash awards as the railway working is dependent on a variety of factors. However, speaking in general, following improvements have been elected in the Asansol Division :—

- (i) Disposal of Pension and P.F. settlement cases.
- (ii) Clearance of Deposit P. F. items.
- (iii) Recoveries effected from assorted staff Bills by intensified Internal Audit.
- (iv) Closure of Audit references.
- (v) Recoveries of dues from non-Railway parties.
- (vi) Timely calculation of electric charges bills.
- (vii) Dealing with direct purchase of store bills.
- (viii) Weeding out the time expired records, etc.

Number of staff working in Asansol Division

4875. SHRI ROBIN SEN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :—

(a) the strength of staff working in Asansol Division of Eastern Railway in respect of the following categories :—

- (i) Officers ; (ii) Supervisors
- (iii) Artisans ; (iv) Semi-skilled ;
- (v) Un-skilled and (vi) Ministerial ;

(b) the number out of the above who have been granted cash Award from April, 1977 and onwards ; and

(c) the figures may please be shown category-wise as mentioned above ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (c) :

Category	No. of staff	No. of staff granted cash Award
Officers . .	92	1
Supervisors . .	1026	81
Artisans . .	3648	41
Semi-skilled . .	940	10
Un-skilled . .	8862	17
Ministerial . .	1151	158
	15,719	308

Award of Contract to Union Carbide

4876. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :—

(a) have Government seen the report of Hindustan Times dated the 31st July, 1978 'Multinational bags big dairy Board deal' if so, what is the reaction of the Government ;

(b) is it a fact that in preference to the Indo-Burma Petroleum Company (I.B.P.) a public sector Co. the contract has been given to Union Carbide ;

(c) is it that the Union Carbide quoted the highest unit price ; and

(d) will Government enquire into this and stay this apparently deal ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI B. N. BAHUGUNA) : (a) Yes, Sir ; but the press report is not correct.

(b) No, Sir.

(c) and (d). The bids made by the various parties in response to the global tender are under processing by the National Dairy Development Board.

रेल कर्मचारियों का 6 सूची मांग पत्र

4877. डा० रामजी तिथि : या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या सरकार रेल कर्मचारियों द्वारा 1974 में दिए गए 6 सूची मांग पत्र की वैधता तथा अधिकारी को स्वीकार करती है; यदि हाँ, तो उन पर अब तक कार्यवाही की गई है; और यह नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ब) इस समय सभी रेलवे में नियमित अधिकारी को कुल संख्या कितनी है और वे कितनी प्रवधि से कार्य कर रहे हैं ;

(ग) उन्हें नियमित नीकरी देने के सम्बन्ध में जनता सरकार ने क्या कार्यवाही की है और करने का विचार है ;

(घ) या सरकार रेल कर्मचारियों को उन्हें प्रत्यक्ष केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से भलप करके बोनस देने का जोश्वर से सहली है; यदि हाँ, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क), (ग) और (घ). इन मंत्रीों के बारे में स्थिति हल्लन विवरण में दी गई है।

(क)	4 महीने से कम	114294
	4 महीने से 3 वर्ष तक	74674
	3 वर्ष से 5 वर्ष तक	26664
	5 वर्ष से 10 वर्ष तक	23110

विवरण

10 वर्ष से अधिक	3455
जोड़	2,42197

कम संख्या

मांग

तत्सम्बन्धी स्थिति

(1) (i) देश विभिन्न के समस्त अधिकारों सहित, जिसमें बार्ता का अधिकार भी सामिल हो, सभी रेल कर्मचारियों को भौतिक अधिक मात्रा जाये।

(ii) रेल कर्मचारियों के कार्य बढ़ाए बढ़ा कर 8 घण्टे प्रतिदिन कर दिए जायें।

(iii) भौतिक पद्धति द्वारा सभी रेल कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करके कम से कम बेतन पाने वाले कर्मचारी की अवसरों पर अधिकृत मूल्यांकन बेतन के अनुसार उनका पुनर्वर्गीकरण तथा रिप्रोडेशन किया जायेगा।

2. कार्य मूल्यांकन तथा पुनर्वर्गीकरण पूरा होने तक ऐसे कर्मचारियों के बेतन की तरकार केन्द्रीय सरकार के उपकरणों के कर्मचारियों के बराबर बनाया।

(1) (i) रेल कर्मचारी पहले से ही भौतिक विवाद विभिन्न के उपकरणों के अनुसार प्राप्त होते हैं। तबापि, देश की बातों के अनुसार परिवहनरूप से उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाता है, जबोकि प्रकृति के अनुसार रेल, बूल कप से सार्वजनिक देश है तथा भवने सामिल एवं सामरिट महत्व के कारण सरकार द्वारा सीधे बाईं जाती है।

(ii) विभिन्न स्थितियों में काम करने वाले रेल कर्मचारियों के सभी बातों के लिए उनके कार्य भार पर विचार किये जिनमें विभिन्न 8 घण्टे की एक समान कार्य बढ़ावों की मांग स्थीकार नहीं की जा सकती। किन्तु, रेल कर्मचारियों के कार्य बढ़ावों के सम्बन्ध में विभागीय अधिकरण के निर्णय को 1-8-1974 से स्थीकार कर दिया गया है।

(iii) और (2) मई, 1974 की हड़ताल से पूर्व अधिकारों के साथ ही बातें जिसमें यह सहमति हुई थी कि कार्य मूल्यांकन तीसरे बेतन जायेगा की विभागियों के अनुसार ही किया जायेगा, के फलस्वरूप सरकार द्वारा नियमित बदलाव दिये गये हैं:—

(क) कारवाला कर्मचारियों के पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विधिकरण बनाया गया है जिसमें भाव्यता प्राप्त हो फेरियां द्वारा मनोनीत अधिकारों के दो प्रतिविधि तथा दो सरकारी संस्थाओं सहित एक नियम घटाया गया है।

(ख) वहाँ तक चाल साइन कर्मचारियों का सम्बन्ध है, एवं नियोन्टिव स्टाफ कालज, तिकड़बराबाद में एक अध्ययन बोर्ड ने अपना प्रविष्टि पूरा कर दिया है। विस्तृत कार्य-मूल्यांकन प्रारम्भ करने से पूर्व स्वतन्त्र हृषि से एक मार्गदर्शी अध्ययन करने के प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा। वहाँ तक बेतन में समानता लाने का प्रयत्न है, तीसरे बेतन जायेगा कि यह मत वा नियोन्टिव सार्वजनिक बोर्ड के साथ बेतन की उचित समानता को रेल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बेतन स्तर को नियोन्टिव करने के लिए

मात्र	तत्त्वमत्त्वी स्थिति
	ठोस भास्तर के रूप में नहीं माना जा सकता। जो भी हो, यह एक ऐसा भास्तर है जिससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी समूहों रूप के प्रभावित होते हैं तथा जहां तक ऐसे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ऐसे भ्रातालय द्वारा भी एकत्रणा कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यह बेतन, आय तथा शूल नीति से भी जुड़ा दृष्टा है और इस पर सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त भूतालियम अध्ययन दल द्वारा उत्तर में गहराई से अध्ययन कर लिये जाने के बाद ही विचार किया जायेगा।
3. वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिए एक माह के बेतन की दर पर जांच।	3. यह बेतन, आय और कीमतों की नीति के प्रश्न के साथ बनियाल रूप से जुड़ा है और सरकार द्वारा भूतालियम अध्ययन दल की ट्रिपोर्ट पर विचार कर लिये जाने के बाद इस बारे में विचार किया जायगा।
4. सभी नैमित्तिक रेस कर्मचारियों को नियमित करता तथा पूर्व-न्यायित लाग सहित उनका सभी लाभों के साथ सेवाओं में स्थानकरण।	4. यात्रिय पूर्ण रूप से नियमित करने की आवश्यकता की नैमित्तिक व्यापकों को नियमित नहीं करी देने में काफी प्रतिकूल है। नियमित नियमितों की कमी के कारण जिन नैमित्तिक व्यापकों को नैमित्तिक व्यापकों के रूप में लगे रहना पड़ा है, उनकी विकायतों को दूर करने के उपाय भी किये गये हैं।
5. विभागीय दौर पर चालाकी यदी दुकानों के मालामल से पर्याप्त एवं रियावती दरों पर आवाजाओं तथा आन्य आवश्यक पत्तुओं की सज्जाई।	5. उठाये गये मुद्रे पर रेल भ्रातालय द्वारा अकेले नहीं माने जा सकता क्योंकि इसमें सरकार को सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में नियंत्रण करने हैं।
6. उत्तीर्ण के सभी मालसे बापस लिये जायें।	6. उत्तीर्ण के बहुत से कवित मालसे हाल ही में सरकार के नौकरियों में लाये गये थे और उनकी जांच कराई गयी है और प्रत्येक मालसे में गृह-दोष के भास्तर पर आवश्यक तथा व्यावहारिक कार्रवाई की गयी है।

Products Manufactured by M/s.
Sandoz (India) Ltd.

4878. SHRI S. S. DAS : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) what are the products manufactured by M/s. Sandoz (India) Ltd. under authorisation of May, 1969; detailed composition of each product;

(b) is the podophyllum project shelved and if so, why the company have not been asked to return the licence; and

(c) what was the investment made on podophyllum project alone, source of

funds and how this investment have been utilized?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) (a) and (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Apart from active principals of Podophyllum (Glycoside/Aglycone Fractions), Industrial Licence No. L/22/166/63-Cu. III dated 21-8-69 granted to M/s. Sandoz also includes the following items, added subsequently in the said licence on 16-5-67 :—

1. Active Principals of Senna
2. Active Principals of Belladone

3. Synthesis of O-Nitrophenol and Nitrophenol

4. Synthesis of O-Aminophenol

5. Synthesis of 3-hydroxyquinoline

6. Synthesis of 8-hydroxyquinaldine

M/s. Sanidz are manufacturing certain items out of those added subsequently. The question of asking them to return the licence, therefore, does not arise. However, this aspect would be looked into at the time of issue of a consolidated licence to them.

Pending Industrial Licences Applications of Foreign Drug Firms

1879. SHRI S. S. DAS : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) details regarding date, name of the product, capacity etc. of the pending industrial licence applications of the foreign companies as on date and the reasons for delay in disposing of such applications;

(b) how many applications of Indian companies for similar product are pending; and

(c) whether this delay in disposing of applications is helping certain foreign companies?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) The requisite details in respect of foreign drug companies having direct foreign equity exceeding 40% are indicated in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library See No. LT-2734/78.]

The processing of Industrial Licence applications received from foreign companies was kept in abeyance pending Government's decision on the recommendations of Hathi Committee on Drugs and Pharmaceuticals Industry. The New Drug Policy has been announced recently and all such pending applications are now being processed in the light of that. Some of these applications have already been processed by this Ministry and cases forwarded to the Licensing Committee/LC-cum-MRTP Committee for their consideration.

(b) and (c), 5 (five) applications from Indian companies for certain similar products, out of which 4 (four) have been received very recently, are under consideration of the Government. It cannot

therefore, be said that there is delay and that it is helping foreign companies.

Approval of prices for New Products by M/s. Warner Hindustan, Limited

1880. SHRI S. S. DAS : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) names of the new products for which price approvals have been granted to M/s. Warner Hindustan Limited.

(b) how many new products are indicated in the price list of this company now as compared to the year 1975, and

(c) if this company have introduced the products without price approval why action has not been taken against them?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) :

(a) and (b). M/s. Warner Hindustan Limited, were granted price approval for the following new products between the years 1975 to 1977 :—

(1) Agarol M Emulsion

(2) Tedral C Tablets.

Since price list for the year 1975 is not available, price list effective from 1st January, 1974, has been compared with price list effective from 28th March, 1978. It is noticed that the above two products are the only products appearing in the later price list, compared to the former price list.

(c) As the Company introduced these products with prior price approval of the Government, the question of taking any action against them does not arise.

Guest houses maintained by synthetics and chemicals limited

1881. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) how many guest houses Synthetics & Chemicals Ltd. has been maintaining at various places in the country for the last three years and how much expenses are being incurred on each guest house every year;

(b) for what sort of guest such guest houses have been kept at company's expenses; and

(c) do employees also stay in these guest houses during their official duties?

(THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) to (c) : M/s. Synthetics and Chemicals Limited has furnished the following information :—

The company is maintaining one guest house at 69 Golf Links, New Delhi and two guest houses at its plant at Bhitaura, Bareilly. The expenditure incurred at Delhi guest house and Bareilly guest houses during the last 3 years is given below :

	New Delhi	Bareilly
	Rs.	Rs.
1975	40,299	95,057
1976	36,506	1,31,166
1977	31,996	1,32,478

The guest house at Delhi is rented by the company and those at Bareilly are owned by the company.

The guest house at Delhi is maintained for the use of directors of the company for business purposes or on their way to Bareilly/Lucknow and for discussions and meetings. One of the guest houses at Bhitaura, Bareilly is located within the housing colony near the factory and is maintained for the use of the directors as there is no accommodation available nearby. The other guest house at Bhitaura is maintained within the housing colony for the staff of the company on official visit. This facility is also extended to the representatives of the suppliers, auditors who visit factory for the purpose of business of the company and to the government officials on official visits.

The expenditure is less than one per cent. of the total revenue of the company and hence it has not been shown separately in the published accounts and is grouped under miscellaneous expenses.

Finances paid by Synthetics and Chemicals Limited to Distillers Trading Corporation

4882. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) How much finances from time to time Synthetics and Chemicals Limited have paid to Distillers Trading Corporation Limited for rendering various services,

(b) what is the justification of these payments to Distillers Trading Corporation limited; and
(c) is Distillers Trading Corporation as sister concern of Synthetics and Chemicals Limited ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) and (b) : M/s. Synthetics and Chemicals Limited had appointed M/s. Distillers Trading Corporation Limited as agents for handling storage and transport of alcohol at Kandla at mutually agreed rates. The precise amount of payment made by the Synthetics and Chemicals Limited to M/s. Distillers Trading Corporation Limited is not available with this Department at present. An Investigation into the affairs of the company has been ordered and is in progress.

(c) The Distillers Trading Corporation has registered itself as an inter-connected undertaking of M/s. Synthetics and Chemicals Limited under M.R.T.P. Act.

Rise in prices of canalised items due to loading of pricing by CPC.

4883. SHRI GOVINDA MUNDA : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) why canalised items of drugs have not been kept open for REP import licences ;

(b) whether it is a fact that consumer prices of canalised items have gone up in Indian Market due to loading of pricing by CPC ; if not, how ; and

(c) formulations of canalised items whose consumer prices have not gone up/have gone down during the last three years, year-wise ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) It is not a fact that, under the 1978-79 Import Policy, canalised bulk drugs cannot be imported under REP import licences. The Policy provides that wherever the product exported contains a canalised bulk drug, the same can be imported under REP entitlement upto a certain percentage.

(b) During 1977-78, the prices of formulation of canalised bulk drugs like the anti-malarial chloroquin phosphate, the anti-TB streptomycin sulphate etc. which are required by the masses have been held at levels lower than those entitled by the landed cost of these bulk drugs, through the instrument of loading

the pooled prices of newer antibiotics canalised bulk drugs like ampicillin, chloramphenicol etc. where the demand is more selective. During 1978-79, there have been no increases in prices of formulations based on canalised bulk drugs.

(c) Formulations based on canalised bulk drugs run into large numbers and time and effort involved in compiling information regarding increase/decrease in the price of formulations during the last three years would not be commensurate with the results likely to be achieved.

Issue of COB Licences

4884. SHRI YASHWANT BOROLE: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILISERS be pleased to state :—

(a) details of COB licences granted during the last three years year-wise, with name of the company, products granted, production before the grant of COB and after the grant of COB;

(b) whether Government have recognised installed capacity as one of the criteria for grant of COB and if so, would it not benefit the foreign companies; and

(c) full details of amendments made to the COB licences during the said period and whether such amendments confirm to the basis followed in the past, if not reasons for deviation *vis-a-vis* New policy ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILISERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) A Statement furnishing the requisite details in regard to the drugs and pharmaceuticals industry to the extent available, is attached.

(b) The uniform criteria both Indian and foreign companies for fixing annual capacities in the COB Licence are as under :—

(i) Where production has been established and reported for a period of more than one year or to the specified date, the capacity is fixed at the level corresponding to the highest annual production, subject to a minimum economic capacity to be determined in respect of the concerned industries/products, whichever is higher. However, where it is not practicable to fix a minimum economic capacity, the capacity is fixed provisionally on the basis of peak production in any of the previous years.

(ii) Where production had commenced within less than one year before the specified date or the Undertaking has not yet gone into production, the capacity is provisionally determined on the basis of the minimum economic capacity. But in cases where it is not practicable to fix the minimum economic capacity, the capacity is provisionally determined on the basis of the capacity claimed or the computation based on plant and equipment installed.

(iii) Where a minimum economic capacity or a provisional capacity is fixed, this capacity is fixed finally on the basis of the highest annual production, after the unit has been in production for a period of 3 years.

(c) The details of amendments made to the COB Licences mentioned in the Statement referred to in part (a) above are as under :—

(i) COB Licences granted to *M/s. Roussel Pharmaceuticals Ltd.*, & (ii) *M/s. Tamil Nadu Dadha Pharmaceuticals Ltd.*

Their COB Licences were amended to include certain items which were earlier left out in the COB Licence inadvertently.

(iii) COB Licence granted to *M/s. Cadila Lab.*

Initially, *M/s. Cadila Lab* were granted a COB Licence for the manufacture of certain drug formulations where the annual capacities for various types of formulations were fixed category-wise on the basis of maximum production achieved by them for each item during the preceding 3 years from the date of submission of COB Licence application by them. After obtaining the said COB Licence, this party represented against the annual capacities fixed the COB Licence on the ground that, since it was by the virtue of installation of additional machinery which made them change over from being a small scale unit to a DGTD unit, their annual capacities should be fixed on a provisional basis upto the level of additional installed capacities, in addition to the capacities already granted to them in the COB Licence. With the approval of the Licensing Committee, the party's request was acceded to and their COB Licence was amended accordingly on 28-11-77.

The above amendments to the COB Licence are in conformity with the policy indicated at (b) above.

Statement

Sl. No.	Name of the party	No. & date of COB Licence	Item of manufacture and annual Capacity equivalent to the higher production achieved during the last 3 years preceding the year of submission of application for COB licence.	
1	2	3	4	
1.	M/s. Roussel Pharm. Ltd.,	IL : 551 (75) dt. 27-12-75	1. Tablets 2. Ointments 3. Liquid Orals 4. Vials 5. Ampoules 6. Sofratulla	475.36 lakhs p.a. 25.377 kgs. per annum. 22,680 Ltrs p.a. 11.98 lakhs p.a. 7.19 lakhs p.a. 1000 units p.a.
2.	M/s. Uni-UCB Pvt. Limited.	IL : 25/76 dt. 23-2-76	V. spiritus Tablets	5.2 Million Nos. per annum.
3.	M/s. Tamil Nadu Diddha Pharma. Ltd.	IL : 53/76 dt. 8-4-76	1. Tablets 2. Ampoules 3. Vials 4. Capsules 5. Ointment 6. Liquids	89 Million Nos. per annum. 18355 Ltrs. p.a. 692 " " 7.7 Million nos. per annum. 7000 kgs. 4550 litres
4.	M/s. Cadila Labs	IL : 134 (76) dt. 6-10-76	1. Tablets 2. Liquids 3. Capsules 4. Granules & Dry Syrup 5. Ointments 6. Injections	986 lakh Nos. 317.20 litres 135.28 lakh Nos. 17075 kgs. 4960 kgs. 22.25 litres
5.	M/s. Kerala State Drugs & Pharm. Ltd.,	IL : 15 (77) dt. 24-1-77	1. Tablets 2. Capsules 3. Liquid (Bottles) 4. Parenteral 5. Lakhs Nos (Ampoules)	630 lakhs Nos. 110 lakhs Nos. 70,000 litres.
6.	M/s. East (I) Pharm. Works Ltd.	IL : 3 (77) dt. 11-1-77	1. Tetracycline Capsules (250mg). Tablets (500 mg.) 2. Chloramphenicol Capsules (250 mg). 3. Chloramphenicol Streptomycin Caps. (125 mg. + 125 mg.)	1. Million Nos. One Million Nos. One Million Nos.
7.	M/s. German Remedies Ltd.	IL : 21 (77) dt. 1-2-77	1. Hydroxy Progesterone Caproate 2. Bisacodyl B.P. 3. Hydroxy Ethyl Theophylline 4. Tablets & Dragees 5. Ampoules 6. Liquids 7. Suppositories 8. Ointment	— 3 kgs. — 126 kgs. — 3828 kgs. — 1335 lakh Nos. 53 lakh Nos. 98,000 litres. 5 lakh Nos. 7360 kgs.

1	2	3	4
8. M/s. Hoechst Pharm. Ltd.	IL : 92/77 dt. 27-6-77	1. Catilan Capsules 2. Vitahext 3. Hostacortin 'H' 10 ml.	11.1 million Nos. 3.1 lakh Litres 77,000 vials
9. M/s. Haffkine Bio-Pharmaceuticals Ltd.	IL : 140 (77) dt. 8-12-77	1. Diphtheria Tetanus Vaccine	6.40 lakhs doses
10. M/s. Amrutanjan Ltd.	IL : 36 (78) dt. 14-6-78	1. Amrutanjan Pain Balm (5-25 gms.) 2. Do. (12 gms.) 3. Do. (24 gms.) 4. Dermal Ointment (16 gms.) 5. Cetomix Cough Mixture (60 ml.)	21,65,000 Nos. 20.57 Million Nos. 2,60,000 Nos. 1,80,000 Nos. 20,000 Nos.

Rise in prices of Antibiotics

4885. SHRI YASHWANT BOROLE : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that prices of two antibiotics formulations viz. Ampicillin and Chloramphenicol have gone up substantially during last one year;

(b) if so the reasons for the same and percentage increase in prices ; and

(c) what steps have been taken to ensure their availability at cheap prices ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA) :

(a) During the last one year, there have been some increases in Ampicillin and Chloramphenicol formulation prices.

(b) The price increases have followed increases in the prices at which Ampicillin and Chloramphenicol, which are canalised bulk drugs, were made available to the formulators. The prices of these new antibiotics were increased so as to enable drugs like the anti-malarial chloroquine phosphate and the anti-TB streptomycin sulphate to be distributed at low prices.

The increase in the prices of Ampicillin formulations allowed after 1-8-1977 varied from 1.70 per cent to 19.90 per cent and in the case of Chloramphenicol formulations, the increases allowed after the same

date varied from 0.60 per cent to 10.70 per cent.

(c) The pooled price of Chloramphenicol powder has since been reduced from Rs. 586 kg. to Rs. 460/Kg. Consequential reductions in the price of formulations of this drug would be notified in due course.

Forums Associated by Government for Fixation of Prices of Bulk Drugs.

4886. SHRI YASHWANT BOROLE : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) what forums have been associated by Government for fixation of prices of bulk drugs during the last three years ;

(b) what was the categorisation for placing the cost of production of different bulk drugs for discussion at different forums and who decided for discussion at a particular forum ; and

(c) how it was ensured that no discrimination was exercised in fixing the prices full history of price fixation of Indomethacin, Phenothiazine, Ethisymycin Streat, Griseofulvin, Phthalyl Sulphathiazole, Tetracycline and Metronidazole may be given ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA) :

(a) The Prices of bulk drugs have been fixed by the Government on the advice

of Drug Prices Review Committee/High Level Group on Inter-Ministerial Coordination in the field of Drugs and Pharmaceuticals.

(b) Broadly, the High Level Group dealt with the price fixation of essential bulk drugs listed in Schedule I of the DPCO, 1970 and bulk drugs cost examined by the Working Group set up in 1974 under the Chairmanship of Chairman, BICP. The DPRC dealt with the price fixation of other bulk drugs.

(c) The composition of DPRC and of the High Level Group was broad-based and it included representatives from the concerned Ministries and Departments of Government including the Ministry of Health & FW, Ministry of Commerce and DGTB; the conclusions of these groups would, therefore be objective. Details regarding the price fixation of Indomethacin, Phenothiazine, Erythromycin Streate, Griseofulvin, Pithalyal Sulphathiazole, Tetracycline and Metronidazole are given in the attached Statement.

Statement

S. No.	Name of the Drug	Name of the Manufacturer	Price as prevailing from time to time	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Indometacin	Themis Organon Chemicals	22-1-1977 (Rs. 1268.50/kg. declared by the Co.)	The Company have since intimard that they are no longer producing this drug.
		Marmaid Chemicals	13-10-1977 Rs. 1400/kg (Do.)	
2.	Phenothiazine Fine veterinary Phenothiazine Fine Dispersible Powder.	Alkali and Chemical Corporation of India Ltd.	1.1878.00/tonne (declared by the Co. in 1970) Rs. 12480.00/tonnes (Do.)	Both bulk drugs are for veterinary use. The present prices of formulations are based on a price of Rs. 128,400 per tonne for Phenothiazine, Fine dispersible powder.
3.	Erythromycin Stearate	Themis Pharmaceuticals	4-9-1976 Rs. 1300/kg. (fixed on the recommendations of the High Level Group).	The Company have declared a price of Rs. 1642.56/kg. in Sept. 1975. They supplied the drug at a price of Rs. 1112.50/- up to March, 1976 through GPC. On the 4th Sept., 1976, the price was fixed at Rs. 1300/kg.
Do. 4.	Atenic Chemical Works Co., Ltd.		20-4-1976 Rs. 1700/kg. for Capital use Rs. 1785.00/kg. for sale to others (Fixed on the recommendations of DPRC after cost examination).	The company is producing from basic stage as compared to Themis who produce from intermediate stage.
4.	Griseofulvin	I. D. P. L.	19-11-77 Rs. 4925/kg. (declared by IDPL)	A pooled price covering indigenous production and imports was fixed at Rs. 1471/kg. on 31-1-1978.
5.	Phthalyl Sulphathiazole	Cadila Chemicals IDPL	3-5-1978 Rs. 129.00/kg. (Do.) May, 1977 Rs. 173.00/kg. (Do.)	A pooled price based on IDPL's indigenous production and imports was fixed at Rs. 159.40/kg. on 30-9-1977.

5

4

3

2

1

6. Tetracycline HCl.

IDPL
Cyanamid
Pfizer
Symbiotics

1970 Rs. 1000/kg. (declared)
May, 1970 Rs. 850/kg. (Notified in the Official Gazette)
September, 1976 Rs. 650/- (do.)

The price was notified on the recommendations of the High Level Group.

7. Metronidazole

May & Baker
Unilever
Cipla
Unilever
I.D.P.L.

1970 Rs. 794.53 (declared by the co.)
1977 Rs. 619.00 (do.)
1977 Rs. 460.00 (do.)
1977 Rs. 460.00 (do.)
1977 Rs. 465.00 (do.)

Working of the New Drug Policy

4887. DR. VASANT KUMAR PANDIT : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) how the new drug policy ensures that only efficient units are encouraged to produce bulk drugs in the country;

(b) are any changes in the new drug policy expected in the near future and if so, what main provisions are proposed to be changed are under review ; and

(c) is there any re-thinking on loan licences and scheme of registration with D.G.T.D.?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA) : (a) The new drug policy aims at achieving self-reliance and self-sufficiency in the drugs and pharmaceuticals industry. Different areas of responsibilities have been earmarked for the "Public Sector", "Indian Sector" and "Open for all Sectors". Besides, while considering proposals for licensing the manufacture of bulk drugs, Government keep in view various relevant factors like economy of scale, technology and pricing of products. A cardinal feature of the new drug Pricing Policy is that the prices of bulk drugs will ordinarily be based on the average cost of relatively more efficient manufacturers who account for a large percentage of the production of such bulk drugs.

(b) and (c). Government have received representations from Drug Manufacturers' Associations on various decisions of the Government contained in the New Drug Policy including decisions on loan licensing and abolition of Scheme of Registration with DGTD. These are under consideration of Government. Drug manufacturing units have also been asked to workout their profitability profiles based on the norms contained in the Policy.

Supply of Bulk Drugs by CPC to IDPL and HAL on high Sea Sale Basis

4888. DR. VASANT KUMAR PANDIT : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) what non-canalised bulk drugs were supplied by the CPC to IDPL and HAL on High Sea Sale basis ;

(b) what was the landed cost of such drugs to IDPL and HAL and what prices for such bulk drugs were allowed in the formulations ; and

(c) whether IDPL have enjoyed any unintended benefit on this account and if so, under what authority were such sales allowed without adjusting prices?

THE MINISTER OF PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA) : (a) Non-canalised bulk drug was supplied by CPC to HAL on high sea sales basis. The details of non-canalised drugs supplied by CPC to IDPL on high sea sales basis are as under :—

1975-76 1976-77 1977-78

Vit. A	7.175	..
			MMU	

Procaine Penicillin	3000	1000
			BU	BU

(b) and (c) : The average landed cost of the supplies of Vit. A and Procaine Penicillin to IDPL referred to in (a) above, works out as under :

1976-77

Vit. A	Rs. 2,64.112	MMU
--------	----	----	--------------	-----

Procaine Penicillin	Rs. 533.48	Per BU
---------------------	----	----	------------	--------

1977-78

Procaine Penicillin	Rs. 427.36	Per BU
---------------------	----	----	------------	--------

Vi A was utilised by IDPL for meeting the requirements of Family Planning Programme and Procaine Penicillin for meeting an export order from Afghanistan. The prices of formulations are not fixed with reference to the cost of procurement of individual consignments.

Distribution of Canalised Raw Materials under New Policy

4889. DR. VASANT KUMAR PANDIT : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) Salient features of the restrictions placed on the organised sector units in regard to the release of canalised raw materials in the new policy ;

(b) what liberalisations have been announced for the small scale and Indian units in the new policy ; and

(c) what is the sanctity of the new policy of distribution what are the penalties for its violation and how of that it has been violated by the CPC after its announcement ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) and (b) : Salient features of old and new policies for release of canalised raw materials in favour of drug manufacturing units in the organised and the small scale sector have already been furnished in reply Lok Sabha Unstarred Question No. 1354 answered on 25-7-78.

In the case of DGTD units, under the new policy the release of canalised raw materials shall be determined with reference to either the releases of same items obtained in 1976-77 or the entitlement as per licensed capacities of individual drug formulations where such capacities are specified and the units concerned choose to claim releases on this basis. This is in line with Government's decision relating to the regularisation of excess production, because the criterion for regularisation of production... in excess of licensed capacity or capacity based on COB licences, permission letters, registration certificates, no objection certificates etc. with the highest production actually achieved in any year during the three years period ending March 31, 1977. The policy is liberal to the extent that DGTD units can claim raw materials as per licensed capacity entitlement or releases obtained in 1976-77, whereas previously such units were obtaining canalised raw materials to the extent of best of consumption during any of the two previous years or the quantity recommended by the State Drug controllers whichever was less.

In the case of Small Scale Units, it is expected that under the new policy they will get higher allocations of canalised raw materials as compared with their entitlements under the old policy. Moreover, they can exercise their choice in the selection of canalised raw materials within the overall quantity ceiling applicable to them, which can enable them to adjust their product mix as per requirements of the market.

(c) The new policy guidelines for release of canalised raw materials have been prescribed under the authority derived from the provisions of Import Policy, 1978-79, whereby the Ministry of P.C & F are required to lay down the connected policy in respect of import, price and distribution of raw materials in Appendix 9.

No specific instance where C.P.C. have violated the guidelines has so far come to the notice of Government.

Car Shed at Kalwa

4890. SHRI R.K. MHALGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that because of new car-shed of Central Railway being built at Kalwa near Thana (Maharashtra), at Chinchapada Zopadipatti for about 160 poor families have reached a dangerous situation ; and

(b) what steps Railway Administration propose to take to avert the danger to the said Zopadipatti in this rainy season?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) Does not arise.

Bangkok Meeting of ESCAP

4891. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state what decisions were taken at the meeting of the Inter-Government Railway group of the Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) held recently at Bangkok ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : The Inter-Governmental Railway Group of ESCAP, at their meeting held at Bangkok on 12th June, 1978, considered various issues connected with the promotion of economic and technical co-operation among developing countries, sharing of knowledge of railway research and new railway techniques. The Group, being a recommendatory body of ESCAP, by its nature and functioning, made recommendations to ESCAP on various aspects of railway operations and training of personnel.

Trains running on uneconomic Routes.

4892. SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE ALLURI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether any railway trains are being run at present on uneconomic routes, if so, what are the numbers of such trains ; and

(b) whether there is any scheme under Government's consideration to make these trains economically viable; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) About 380 pairs of passenger carrying trains are running on uneconomic lines.

(b) No.

Availability of Wagons for Movement of Salt from Western Coast

4893. SHRI AHMED M. PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is fact that due to non-availability of wagons a heavy set back has been done to the movement of edible salt from Western Coast to the Northern States;

(b) if so, the quantity of salt accumulated on salt belt ; and

(c) the measures taken by Government to allot adequate number of wagons to clear the accumulated salt ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) and (c) : Do not arise.

Reservation in Service for SC/ST Employees

4894. SHRI SHIV SAMPATI RAM : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have examined the implications of the decision of the Allahabad High Court, interpreting the Railway Board's directive, relating to reservations in service for SC/ST employees and restricting scope of reservation of posts and not of vacancies ;

(b) whether Government have taken a step to nullify its effect of this decision by suitably modifying Railway Board's directive ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (c) As the judgement of the Allahabad High Court disputes the policy of the Government in regard to reservation for Sch. Castes/Sch. Tribes in services an application has been filed in the Supreme Court for grant of special leave to appeal to that Court against the judgement of the Allahabad High Court. The application is pending consideration before the Supreme Court.

Representations regarding Halt and Speed of Somnath Mail

4895. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many persons have sent a representation to the General Manager, Western Railway, Bombay and the Ministry on 29-5-1978 regarding halting, crossing, and speed of Somnath Mail and Saurashtra Mail at Jetpur city in Rajkot district of Saurashtra region in Gujarat ;

(b) if so, the nature of demands contained therein ; and

(c) the details of action taken so far by Government or Railway Board in regard to each of these demands or if the action is proposed to be taken, when it will be taken and the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No representation appears to have been received.

(b) and (c) Does not arise.

4896. श्री उमर्सिंह भाई वडेल : क्या देहोलियन, रताबल और चर्चरक मंडी यह बताने की हुए करते हैं :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार की इस नीति का विरोध किया है कि दहराई हाई टेल बोरों की गत की विजली बरों के लिए हैथन के रूप में उपयोग न किया जाये तथा यह माना की है कि इस गैस पर सांसारित की बड़े विजली बरों की स्वापना की जाये और यदि हाई, तो क्या ;

(ख) इन दो बोरों का ब्लैरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार की इन दोनों बोरों को स्वीकार कर लिया है और यदि हाई, दो क्या तथा इसका ब्लैरा क्या है और यदि नहीं, दो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) गुजरात सरकार की इन दोनों को क्या तथा किस प्रकार स्वीकार किया जावेगा ?

देहोलियन तथा रताबल और चर्चरक मंडी (श्री हेमवती नवल बहुलाल) : (क) के (न) देहोलियन के रूप में दहराई हाई गैस सरकार ब्लैरा जहां इनके लिए लकड़ी वर लकड़ियां बनाई जाएं तथा लकड़ियां को बोरे विकिट प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है, वहीं पर गुजरात सरकार ने कुछ दरों में गुजरात में सुपर विजली वर

की स्वापन करने और सोनाराष्ट्र में विजली उत्पादन करने के लिए तात्परी नहीं की उपयोगिता का क्षेत्र उत्तेजित किया है।

जहां तक बम्बई हाई की अपतटीय रैस का सम्बन्ध है, इस का उपासनाव उर्वरक के संभवन अंडार के रूप में उपयोग किया जायेगा। यह वह रैस, जिसका उपयोग नव तक नहीं किया जा सकता है, वह तक कि उर्वरक यन्हि इसे लेने की विधि में न हो, उसे तथा किसी प्रकार की अतिरिक्त रैस को विजली उत्पादन के एक आनंदरिक उपाय के रूप में बूझाने में उपयोग किया जाना चाहिए। तात्परी रैस को उपयोग करने के प्रावृत्ति पर विचार करना अपनी समय के अनुकूल नहीं है क्योंकि इन संरचनाओं का मनुष्यित रूप से मूल्यांकन करने और उन्हें वाणिज्यिक रूप से उपयोग घोषित करने के पश्चात् ही तात्परी रैस के सम्प्रयोगन और परिवहन संबंधी नियंत्रण करना संभव होगा।

गुजरात में अपतटीय रैस की अनुकूलतम उपयोगिता का व्याप्तिकरण करने के लिए निम्न कार्यकारी एवं भी सिफारिशें आप बातों के साथ साथ निम्नलिखित विचारादाराओं के आधार पर यहीः—

“जिस मात्रा में प्राकृतिक रैस के उपलब्ध होने की संभावना प्रतीत होती है वह एक इनी महावृष्टि क्षेत्री सामग्री के बाहर है कि इसका उर्वरक का उत्पादन करने जैसे उच्च महावृष्टि प्रायोगिकता प्राप्त प्रयोगों में उपयोग करने का हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए, जहां पर रैस की अवधार कीमत नेपाल की अवधार कीमत से वह जाती है और यह मध्य ईंधित तेल के अवधार मूल्य से कहीं अधिक बढ़ जाती है, जिसमें भट्टी का तेल, एच० एस० एस०, एस० एस० एस० एस०, आर० एक० थो० आदि तेल सम्मिलित हैं। (रैस के प्रयोग में यह सम्मिलितता बहुत सकती है यदि रैस की उपलब्ध मात्रा में अधार घटनाएँ डर्जी भीति की संभाल करने के आधार पर पर्याप्त बढ़ावदारी हो जाती है)।”

इसको व्याप में रखते हुए उत्तर एवं न अतिरिक्त विजली का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक रैस की भागी स्पाई पर कोई विचार नहीं किया।

इस एवं में गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि भी जामिल था। भोटे होर पर इस की सिफारिशें सरकार द्वारा मात्र भी गई हैं।

गुजरात और महाराष्ट्र में अपतटीय रैस की उपयोगिता के लिए कार्यकारी दलों की सिफारिशों पर विचार करते समय, इस आपाव का भी नियंत्रण किया गया था कि योजना आयोगों को परिवहनी प्रबंध में छठी योजना प्रबंध के द्वारा विजली की संसाधी मांग के प्रावृत्ति का और मांग को पूरा करने के विभिन्न प्रायिकियों/संसाधनों का भी आध्ययन करना चाहिए।

Cases pending in Gujarat High Court

4897. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of cases pending in the Gujarat High Court as on the 31st July, 1978; and number of cases of each category among them;

(b) the reasons why these cases are pending and the time by which they are likely to be disposed of;

(c) the number of posts indicating the nature thereof which are lying vacant in the Gujarat High Court at present and the reasons therefor; and

(d) the time by which these are likely to be filled :

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Information as on 31st July, 1978 is not available. A statement containing the requisite information as on 30th June, 1978 is given in the attached statement.

(b) No time limit can be fixed for the disposal of these cases. The main reasons for the pendency indicated by the High Court are :—

(i) Disposal of some cases is linked with decision of cases filed in Supreme Court or the High Court on similar or like question of law.

(ii) Difficulty in serving notices on heirs and legal representatives of parties consequent upon their death and on parties residing in foreign countries.

(iii) Some vacancies of Judges are unfilled.

(c) and (d). Two posts of Permanent Judges and four posts of additional judges in the High Court are vacant and steps are being taken to fill them up.

Statement

Cases pending in the Gujarat High Court as on 30th June, 1978.

Civil Suits	13
Testamentary Petitions	1
Liquidation Cases	51
Company Petitions	61
Company Applications	145

Income Tax References	778
Income Tax Applications	19
Sales Tax References	68
Estate Duty References	37
Estate Duty Applications	1
Gift Tax Applications	8
Wealth Tax References	47
Wealth Tax Applications	4
Stamp References	12
Civil Applications (Original)	5
Original Side Appeals	3
Miscellaneous Petitions	1
Miscellaneous Applications	22
Criminal Contempt under the Contempt of Court Act	1
Letters Patent Appeals	180
First Appeals	3524
Second Appeals	1142
Miscellaneous First & Second Appeals	212
Civil Revision Applications	924
Miscellaneous Civil Applications	91
Civil Applications (Appellate)	811
Civil References	2
<i>Special Civil Applications</i>	
Service Matters	523
Land Reforms including land ceiling	827
Labour Laws	44
Others	987
<i>Criminal Appeals</i>	
By person convicted	370
By Government from judgement of acquittal	841
By Complaint u/s. 378(4) of Cr. P.C.	67
Criminal Revision Applications	242
References	2
Criminal Miscellaneous Petitions.	180
<i>Writ Petitions</i>	
(i) Special Criminal Applications u/Article 226 and 227	28
(ii) Special Criminal Applications u/Article 227	31
Transfer Applications	11
Criminal Cases	4

12,320

Rail Coordination Directorate at Bhubaneswar

4898. SHRI GIRIDHAR GCMANGO : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether his Ministry has received a proposal from the Government of Orissa to set up Rail Coordination Directorate at Bhubaneswar ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the steps taken by the Ministry so far, in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) The Government of Orissa has proposed to set up Rail Coordination Directorate at Bhubaneswar with a view to bridging the communication gap between the State Government and the South-Eastern Railway on the one hand and between the local press, trade and commercial interest and the Railways on the other hand.

(c) The Government of Orissa has been advised that the Rail Coordination Directorate may be created as a part of State Government establishment for liaison purposes with the Railways at Bhubaneswar. In order to make the Directorate effective, it has also been suggested to the State Government that the Directorate be manned by Senior Railway Officials to be spared by the Railways on deputation basis if the State Government so desires.

Total Length of Narrow Gauge Lines

4899. SHRI DURGA CHAND : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) what is the total route kilometres of narrow-gauge, line-wise in the country;

(b) what is the total amount required for conversion of narrow gauge into metre-gauge ;

(c) what is the route kilometres of narrow gauge proposed to be converted into metre-gauge during the Sixth Five Year Plan ;

(d) whether Pathankot-Joginder Nagar narrow-gauge is proposed to be undertaken during the Sixth Plan ;

(e) if not, what are the reasons therefor, and

(f) what is the expenditure
the conversion of this line?

**THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI
SHEO NARAIN):** (a) The total length
of narrow gauge lines in the country is
4280 Kms.

(b) Under the present policy existing
narrow gauge and metre gauge lines if
taken up for conversion are to be converted
to broad gauge in order to have uniform
gauge throughout the country in the long
run. The total cost of conversion of the
narrow gauge lines excluding hill railways
into broad gauge would be about Rs. 700
crores, while in the case of hill railways it
would be prohibitive.

(c) and (d). The list of narrow gauge
lines to be converted into broad gauge
during the Sixth Five Year Plan has not yet
been finalised.

(e) It is not proposed to consider con-
version of Pathankot-Joginder Nagar
narrow gauge line into broad gauge
due to its high cost and constraint of
resources.

(f) No investigations have been made
for the conversion of Pathankot-Joginder
Nagar line so far. On an approximate
basis the cost of the conversion of Pathan-
kot-Joginder Nagar NG line (164 Kms.)
into BG would be about Rs. 80 crores.

**Excursion Tours for Domestic and
Foreign Tourists**

4900. SHRI DURGA CHAND : Will
the Minister of RAILWAYS be pleased to
state :

(a) whether Railway Administration in
collaboration with India Tourism Develop-
ment Corporation is contemplating to
start excursion tours for domestic and
foreign tourists;

(b) if so, what are the details thereof;
and

(c) what are the details of the present
excursion tours undertaken by the Rail-
ways and with what results?

**THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI
SHEO NARAIN):** (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Railways do not as such sponsor or
conduct any excursion tours, but only
provide passenger coaches and special
trains to anybody asking for it on fulfil-
ment of the prescribed conditions and on
payment of normal tariff charges.

**Restructuring of Fertiliser Corpora-
tion Limited**

4901. SHRI VASANT SATHE : Will
the Minister of PETROLEUM, CHEMI-
CALS AND FERTILIZERS be pleased
to state :

(a) whether Government have taken a
decision for restructuring of Fertilisers
Corporation of India and details thereof;

(b) at what stage of implementation
the decision stands;

(c) whether Government have received
representation/memorandum from the
employees Association and other organisa-
tions details thereof; and

(d) what steps have been taken to en-
sure that the interest of the employees
does not get effected, on this account?

**THE MINISTER OF PETROLEUM
AND CHEMICALS AND FERTILIZERS
(SHRI H.N. BAHUGUNA):** (a) and (b).
The Fertilizers Corporation of India
and the National Fertilizers Limited have
been reorganised into the following 5
companies w.e.f. 1st April, 1978 :—

Name of the Company	Units/Divisions
1. Fertilizer Corpora- tion of India Limit- ed.	Sindri (including Sindri Modernisa- tion and Sindri Rationalisation), Gorakhpur, Tal- cher, Ramagun- dam and Korba.
2. National Fertilizers Ltd.	Nangal, Bhatinda and Panipat.
3. Hindustan Fertiliz- er Corporation Limited.	Namrup, Haldia, Barauni and Duga- pur.
4. Rashtriya Chemi- cals and Fertilizers Limited.	All units of Trombay and the gas based plants in the South of Bombay.
5. Fertilizer (Plann- ing and Develop- ment) India Ltd.	P & D Division of the FCI.

(c) and (d). When the reorganisation
proposals were under consideration, some
representations were received from Emp-
loyees' Associations etc., stating *inter
alia* that the proposed reorganisation had
caused apprehensions in the minds of the
officers and staff about their future. In
order to safeguard the career prospects of

personnel in the new companies, it has been decided that promotion to the posts in the corporate cadre should be made on the basis of an Inter-Company Promotion Committee to be set up for this purpose.

Zone-wise Catering Staff

4902. SHRI VASANT SATHE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) what is the number of casual/temporary catering staff zone-wise engaged on the Railways ;

(b) whether the Government have received representation from the Union of these staff members ;

(c) if so, what are the important contents of the memorandum ; and

(d) the decision taken by the Government recently to improve service/working conditions of these staff members ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a)

Railway	Number
Central	470
Eastern	42
Northern	172
North Eastern	23
Northeast Frontier	54
Southern	191
South Central	121
South Eastern	124
Western	549
	1746

(b) Yes.

(c) The main demands are as under :—

(i) Allotment of revised pay scales to casual labour.

(ii) Betterment of their service conditions like permanent absorption in regular posts.

(iii) All temporary posts in the departmental catering should be made permanent.

(d) The recent decision is in regard to absorption of Commission bearers as regular Class IV employees in a phased manner based on the length of their service. However, casual labour working in the Catering department are already being considered for regular absorption after screening as per extant rules. Temporary staff are confirmed in their turn as and when permanent posts become available.

Loss to Railways during recent floods

4903. SHRI VASANT SATHE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) what is the estimated loss caused to the Indian Railways due to recent floods in various parts of the country, zone-wise ;

(b) how does it compare with the loss incurred by Railway during the previous year ;

(c) whether Government propose to take specific measures to avert threat of floods to rail lines on a permanent basis, in selected flood-prone tracts to avoid recurrence of high expenditure on maintaining the rail tracks ; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) The loss caused to Indian Railways due to recent floods during the period 1-5-78 to 31-7-78 zone-wise is as under :—

S.No.	Railway	Approximate estimated loss (Figures in lakhs of Rs.)
1.	Central	2.17
2.	Eastern	nil
3.	Northern	0.27
4.	North Eastern	1.50
5.	Northeast Frontier	0.20
6.	Southern	nil
7.	South Central	2.40
8.	South Eastern	nil
9.	Western	10.50
	Total	17.04

(b) The loss incurred this year during the period 1-5-78 to 31-7-78 is very much less as compared to the loss suffered by the

Railways during the corresponding period of the previous year.

(c) and (d). A statement is attached.

Statement

Steps taken to avoid flooding and damaging of Railway lines due to floods.

All Railway lines and bridges are designed and constructed so as to be safe against normal floods. At the time of construction of new railway lines, careful study is made of the terrain, rainfall, drainage and flood records in the area, in order to ensure that the new line is not affected by the ravages of floods. The alignment is selected carefully, the formation level of the track is kept above the flood level in the area and bridges with adequate waterway are provided to let the flood waters of the rivers flow unhampered, so that safety of the railway line is not endangered. Special attention is given to bridges, which are normally designed for a flood frequency of 50 years, after a careful consideration of hydrology and past history of floods. Their foundations are designed to withstand heavier floods than those of 50 years frequency.

2. The following steps are taken to prevent flooding and flood damage on the existing lines:

1. All bridges are carefully inspected every year and repairs to substructures, flooring, guide-bunds, pitching etc. carried out as necessary.

2. Waterways of all bridges are cleaned before the monsoons so that there is no obstruction to the flow of water.

3. Bridge cells review the adequacy of waterway of important and vulnerable bridges. Some bridges may be widened, raised, rafted or additional bridge constructed as a result thereof. Vulnerable bridges are kept under watch.

4. Wherever justified and otherwise feasible, the formation may be raised and/or strengthened, pitched with stones or diverted away from the flood affected area. Training works such as groynes, bunds, pitching of river banks, guide bunds, etc. are provided for rivers where necessary.

Despite all the measures mentioned above, certain amount of flood damage on the vast railway system is unavoidable.

5. In order to ensure safety of trains, keyman of the permanent way gang examines the track in his beat every day. During monsoons, night patrolling of track is introduced on sections likely to be damaged by breaches/floods. Stationary watch-

men are posted at vulnerable spots and bridges. In addition, in the case of severe storms, the man on his own initiative organises patrolling of track, irrespective of any other patrolling that may be in force. Immediate action is taken to protect the trains in case anything dangerous is observed.

तेल तथा प्राकृतिक वैत आवेग हारा दिये गये भू-प्रकाशन तथा भू-प्राकृतिकीय सर्वेक्षण

4904. जी चुरेज जा तुमन : क्या घेउलियन, रासायन और उर्बरक मंडी यह बताने की हुया कर्दै कि :

(क) यह तीन बचों में तेल तथा प्राकृतिक ही आवेग ने देश के दिन स्थानों पर भू-प्रकाशनिक तथा भू-प्राकृतिकीय सर्वेक्षण किये तथा उनके क्या परिणाम मिले; और

(ब) इस घब्बिय में सर्वेक्षण कार्य पर कितनी जनराति कर्दै की गई?

घेउलियन तथा रसायन और उर्बरक मंडी (जी घेउलियी नम्बर बहुमुण्डा) : (क) यह 1975-76 से 1977-78 के चिले लोग बचों की घब्बिय के द्वारा तेल तथा प्राकृतिक ही आवेग ने अचू-कालीन, राजस्वान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड प्रदेश, तमिलनाडु, उडीसा, झार, नारायणीय, लिपुरा, घर्यांगास, प्रदेश, परिषद्यम बंकाल, गुजरात, महाराष्ट्र और प्रदेश निकोहर द्वारा समूह के विभिन्न भागों में तेल तथा हीस की संशोधनाओं का पता लगाने के लिए घावेई सर्वेक्षण किये।

अपरादीय लोगों में ये कार्य संबंधित बन्धव हाई कोरो मण्डल समुद्रीतट, भरत तापर के सौराष्ट्र अपात, दिल्ली बहीन संरक्षण, दिल्ली बहीन संरक्षण के विभिन्न, बहीन रसायन, घंगरिया समूह टट, रत्न गिर, बंगलोर, बंगलोर बोर्डीन, बन्धव रसायनिरी उत्तर बहीन के उत्तर बन्धव हाई के उत्तर पूर्व, करायकल, पांडिचेरी, लिंबेन्न के पक्के मर्म, कोहीन के उत्तर परिषद्यम, परिषद्यम बन्धव के गहरे महादीपीय बम्बाट, बंगलोर निकोहर द्वारा द्वीप समूह के मण्डलट, लेल, और कुण्डा बोर्डीन टट बहीन के लोगों में प्रायोगित किये गये थे।

इन लोगों में विभिन्न किस्म के सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए अनेक फील्ड दलों को सामाया गया था। भू-गर्भीय दलों ने विस्तृत आयोजित हारा 1105 वर्ष किलो ग्रीटर, घर्यांगरेवर आयोजित हारा 10,055 वर्ष किलो ग्रीटर, लिंबेन्न के जारियत हारा 1798 लाइन किलो ग्रीटर, लेली सर्वेक्षण के जारियत हारा 8915 किलो ग्रीटर-द्वीप, घंगरिया किलान और मन्द-मान्दु बाल-विलों हारा 144,900 किलो ग्रीटर के लोग में सर्वेक्षण कर लिया। भू-कम्पीय सर्वेक्षण करने वाले दलों ने भी 1000 वर्षीय 10 सर्वेक्षण हारा 6445 लाइन किलो ग्रीटर, प्रतिविवित सर्वेक्षणों हारा 509

लाइन किसी भी दूर, और परवरणात अतिविविष्ट सर्वेक्षणों द्वारा 5721 लाइन किसी भी दूर लेन में सर्वेक्षण आयोगित किए। गुरुवर-बुधवारीय लेन में सर्वेक्षण करने वाले दूसों ने 20309 केन्द्रों से इन घाकड़ों का परिवाप किया। अरटटीय लेनों में भू-भीतिकीय सर्वेक्षण करने वाले दूसों ने पिछले दीन वालों में कुल 50,077 लाइन किसी भी दूर लेन का सर्वेक्षण किया।

(ब) पिछले दीन वालों में तेस तथा प्रारंभिक नीति आयोग द्वारा वन्यजीव सर्वेक्षणों पर निम्नलिखित वर्च किया गया था :

वर्ष	किया गया वर्च
(रपए लाखों में)	
1975-76	832.30
1976-77	704.14
1977-78	785.67 (अस्थाई)

विहार में दुर्भिक्षण गैर एजेंसियों का आवंटन

4905. भी दुर्भिक्षण गा. कुलन : क्या वेत्तेलिकम, रसायन और उर्बारक नीति यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विहार राज्य के विभिन्न जाहरों में किन ने व्यक्तियों को कुकिंग गैर की एजेंसियों दी गई है और किनमें व्यक्ति अपनी इन एजेंसियों में प्रावृद्धन की प्रतीका भूमी में है;

(ब) उन्हें एजेंसियों देने के लिए क्या शीति निर्धारित की गई है जबकि निर्धारित की जा रही है; और

(ग) प्रतीका भूमी वाले व्यक्तियों को एजेंसियां आवंटित करने के लिए नियंत्रण कब तक किया जायेगा।

वेत्तेलिकम तथा रसायन और उर्बारक नीति (भी हेल्पली नाम से जाना जाता है) : (क) से (ग) विहार राज्य में विभिन्न जाहरों में इस समय 34 कुकिंग गैर वितरक (एक उप-वितरक को नियाकर) हैं।

सरकार द्वारा जारी की गई मार्गदर्शी कप रेलवेरों के अनुसार सार्वजनिक लेन की तेल कार्य-नियों की सभी प्रकार की एजेंसियों अनुदृष्टि जाति / अनुदृष्टि व्यवसायि के लाइनों के लिए 25 प्रतिशत और आरटीरिक लेन से विभिन्न व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत आरटीरिक भवितव्य की जाती है और जो वे 73 प्रतिशत व्याख्यिक भवितव्य को ज्ञान में रख कर की जायेंगी, जिसमें वास्तविक उपलोक्ता लक्षकारी सोसाइटियों और एशो इंडस्ट्रीज कारोबारिक को प्राप्तिकरता दी जाती है। सभी विवृतियां

सर्वेक्षण लेन के समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्र आवंटित करके की जाती है।

एजेंसियों का प्रावृद्धन करने के लिए वे जो व्यक्तियों नहीं रखी जाती हैं। एंजेंसी के लिए व्यक्तियों द्वारा दिये गये आवेदन पत्र लेन कार्यनियों द्वारा ऐसी एजेंसियों के लिए जारी किये गये विज्ञापन के उत्तर में दिए जाते हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे में नीतिलिपक अधिक

4906. भी दुर्भिक्षण गा. कुलन : क्या रेल नीति यह बताने की कृपा करने कि :

(क) इस समय पूर्वोत्तर रेलवे में, विशीजन-वार, कुल कितने नीतिलिपक अधिक हैं और उनमें इस वर्च से अधिक समय से काम करने वाले अधिकारों की संख्या क्या है;

(ब) उनमें से अनुदृष्टि जातियों और अनुदृष्टि जनजातियों के अधिकारों की प्रतिशतताता क्या है; और

(ग) क्या इन नीतिलिपक अधिकारों की हेल्पली को नियाकर करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

रेल नीतिलिपक में राज्य नीति (भी विवरण)

(क)

नीति	जोड़	एक वर्च से अधिक सेवा
इंडियनपर	1167	574
लकड़क	2683	873
बाराणसी	1855	1855
समस्तीपुर	5603	3000
गोरखपुर	7974	3572
जोड़	19,282	9,874

(व) दूसरा इकलौटी की जा रही है और इस पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आकर्तिक अधिकारों की सेवाएं नियमित करने के लिए नीतिलिपित विवरण है —

(i) 1970 के बाद से बहुर्व व्यक्ति में सामान्य जाति बन कर ही रही है और समस्या सभी विवित व्याख्यिक अधिकारों की जांच-प्रबोल करके भरी जाती है।

(ii) इस आवधि के अन्तर्वेदन दिए गए हैं कि कारबाहों, भोकी लेडों, वाही-रीतानी

इष्टपत्ताप्राप्ति, सवारी और माल दिल्ला डिप्युटी, यात्री और स्टेजरों जैसी कुछ जगहों में माल बहाने-दरवाजे तथा विविध इंजीनियरों, लिंगनल और पुरुष अनुसंधान के प्राविधिक कामों को ढाक कर, कार्ड प्राक-सिक प्रतिक नियमित नहीं किये जायें। लिंगनल इंजीनियरों, लिंगनल तथा पुरुष अनुसंधान की निरीक्षाओं की स्थानान्तरी सहित इन सभी जगहों में समय-समय पर रेल प्रशासनों को संबंध समीक्षा करनी होती है और प्राविधिकतानुसार नियमित पदों का लूजन करना होता है।

(iii) रेल प्रशासनों को यह सुनियमित करने के लिए भी अनुदेश दिया गया है कि रेल पथ जैसे वे जहाँ रेल पथ अनुरूपण की यांत्रिक तथा धार्य प्राविधिक प्रतिकार्य नहीं की जायें वहाँ जितने कर्मचारी मजूर किए गए हों वे सभी नियमित प्राविधिक पर रखे जायें। दूसरे जगहों में जहाँ रेल पथ के अनुरूपण के प्राविधिक दरोंके लाग किये जाने के कारण गैंग के कर्मचारियों की संख्या प्रत्येक वाहनों के गण-दोष के प्राविधिक पर नियमित की जानी होती है वहाँ अपेक्षित वह नियमित प्राविधिक पर भरे जाने चाहिए।

(iv) जिन स्थानों पर प्राक-सिक प्रतिक नहीं रखने होते और वहाँ जांच-पहलास किये गये या उन्हें गये उन्मीदारों के समावेश के कारण अवाकाश किये और कारण से नियमित रूप में रिक्तियों जगता समझ न हो तो ऐसी रिक्तियों पर लगाये गये प्रतिक्रियत व्यक्तियों को बेतत की प्राप्तिक दर पर एक्जियों के रूप में नियुक्त किया जायेगा जो कि ईमिक दरों पर प्राक-सिक प्रतिकों के रूप में।

उत्तर बिहार तथा दिल्ली के बीच बल्लै बाली जनता जाता जाती

4907. श्री दुर्गेन्द्र ज्ञा तुम्हारा क्या रेल मंत्री यह बातों की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता जनता बाड़ी उत्तर बिहार और दिल्ली के बीच लौटी बल्लै बाली एकमात्र गाड़ी है जोकि सप्ताह में दो बार बल्लै है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि गाड़ियों की कमी के कारण वालियों को बड़ी कठिनाई हो रही है और क्या भूमालाय की जनतों जनता गाड़ी को प्रतिक्रियत बलाने के लिए लोगों से अमरोद प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल अनुसंधान में राज्य मंत्री (श्री लिल नारायण) : (क) सप्ताह में दो बार बल्लै बाली 153/154 जनती जनता एक्सप्रेस के बल्लै, 3 घंटे सप्ताह द्वितीय प्रतिविवर नहीं दिल्ली और मुजफ्फर-पुर के बीच 85/86 बासम बेस में बल्लै है।

(ख) अन्य

(व) और (ग). सप्ताह में दो बार बल्लै बाली 153/154 मुजफ्फर-पुर—दिल्ली जनती जनता एक्सप्रेस की बारंबारता में बड़ी कठिनता या इस मार्ग पर एक यांत्रिक एक्सप्रेस गाड़ी का बल्लै जाना भावित बल्लै में लाइन जनता के प्रभाव और दिल्ली-बोल्ड में पर्यावरणीयों की कमी के कारण, स समय परिवालिक पूर्णित के व्यवहारिक नहीं है।

Procedure for issue of Priority letters for Gas Connections

4908. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the present procedure being adopted for issue of priority letters to general public for domestic gas connections in urban as well as rural areas throughout the country;

(b) whether in the absence of proper procedure, the consumers wanting new connections are not able to register their demands with the dealers or with Indian Oil Corporation directly;

(c) if so, what steps are being taken to modify the existing procedure so as to enable consumers wanting new connections to register their names with authorities concerned?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA) : (a) to (c). Applications for cooking gas connections are required to be registered with the cooking gas distributors of the oil companies. The gas connections are released by the distributors from amongst those who are registered on a 'first-come, first-served' basis, and a waiting list is maintained. Some connections are being released by the distributors on priority basis on the advice of the oil companies. Advice is also being given to oil companies by the Ministry for issue of such priority connections.

Generally gas connections are given on priority to Members of Parliament and State

Legislatures, other VIPs, foreign dignitaries, cases of hardships, commercial contacts, Government Organisations / Institutions etc.

According to oil companies, the registration of names for granting Liquefied Petroleum Gas (cooking gas) connections had been discouraged in certain areas by them in view of the continued shortages of the product compared to its demand.

The oil companies have been advised to start fresh registrations, wherever necessary, keeping in view the possibilities of enrolment of new customers on a significant scale from about 1980, when substantial quantities of cooking gas will start becoming available.

Efforts to find Oil off The Kerala Coast

4909. SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether a proposal to intensify efforts to find out oil off the Kerala Coast is under consideration of the Government in near future ; and

(b) if so, details therein and steps that have already been taken or proposed to be taken in this regard during the coming year?

THE MINISTER OF PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA) : (a) and (b). ONGC had drilled an exploratory well 60 Kms. north-west of Cochin during April-May, 1978. This well was drilled to a depth of 1755 metres. However, as no oil or gas was found, the drilling was suspended.

Further exploration programme in the area will depend upon the interpretation of the data obtained from this well and the seismic data of the area collected earlier.

Removal of Dr. R.R. Jaipuria from Management of Swadeshi Cotton Mills

4910. SHRI K. MALLANNA : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Mr. R.R. Jaipuria who is responsible for mismanagement of Swadeshi Cotton Mills Company Limited has since been removed from that post ;

(b) if so, what are the details and since when he ceased to be Managing Director; and

(c) what Government propose to do to save Swadeshi Mining and Manufacturing Company Limited (having two sugar Mills) a subsidiary of Swadeshi Cotton Mills Co. Ltd., from onslaughts of mismanagement of Dr. R.R. Jaipuria?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) and (b). The company's proposal under section 269 of the Companies Act, 1956 for the re-appointment of Dr. R.R. Jaipuria as Managing Director of the company for the period from 1-7-1977 to 31-8-1980 has been rejected by Department in May, 1978. He ceased to be the Managing Director of the Company with effect from 1-9-1977. A representation has been filed by the company against the said rejection which is pending.

(c) The Government has no material to indicate any acts of mismanagement by Dr. R.R. Jaipuria who is the non-executive Chairman of Swadeshi Mining and Manufacturing Company Limited.

Complaints regarding Production of Oxytetracycline

4911. SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the nature of complaints received during past three years from various Members of Parliament about Oxytetracycline and its excess profits, addressed to the Minister and the former Prime Minister with details ;

(b) what action was proposed by the former regime and what action has been taken in this regard so far ; and

(c) if no action has yet been taken, reasons therefor ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA) : (a) to (c). The following points were raised in the main by certain members of Parliament in their letters addressed to the Minister (PC&F) and the former Prime Minister during the last 3 years, about manufacture of Oxytetracycline and excess profits thereof by M/s. Pfizer Ltd.

(i) Regularisation of their excess production of Oxytetracycline ;

(ii) Non-execution of Export Bond by M/s. Pfizer.

(iii) Substantial profits on unauthorised production of Oxytetracycline and its formulations since there was no price fixation based on cost examination of Oxytetracycline.

(iv) Suit in USA against M/s. Pfizer of USA charging them with violation of Anti-trust laws in the manufacture of and sale of a group of broad spectrum antibiotics.

2. The present position on each of the above points is as under :—

(i) Regularisation of excess production of Oxytetracycline beyond the licensed capacity of M/s. Pfizer will be considered in the light of the New Drug Policy.

(ii) The position in regard to non-execution of Export Bond has already been explained in reply to Lok Sabha Starred Question No. 236 answered on 1-8-78.

(iii) In 1970, when Drug Prices (Control) Order, 1970 came into force, M/s. Pfizer declared the price of Oxytetracycline Hcl. at Rs. 960/kg. as they were entitled to, since this item was not included in Schedule I to the said Order. The prices of formulations of Oxytetracycline are allowed based on the above price. BICP conducted cost-cum-technical examination for Oxytetracycline and submitted their report to the Government in the year 1975. Based on the report of the BICP, Govt. reduced the price of Oxytetracycline from Rs. 960/kg. to Rs. 725/kg. for captive use and Rs. 749/kg. for sale to other non-associated formulators. The prices of formulations based on the reduced price of Oxytetracycline have already given effect to the reduced prices.

(iv) Government of India filed a suit on 11-10-74 against six US Drug Manufacturing Companies, including Pfizer for allegedly having entered into a conspiracy for concerted price fixation and over-charging on domestic as well as overseas sales of Broad Spectrum Antibiotics in violation of the US Anti-Trust Laws. The Anti-Trust Laws provide that "any person who shall be injured in his business or property by reason of anything forbidden in the Anti Trust Laws may sue therefor in any District Court of the United States.....and shall recover three-fold the damages by him sustained and the cost of suit, including a reasonable Attorney's fee."

The defendant Companies had contended before the US Supreme Court that a "foreign nation" was not a "person" as defined in the Clayton Act (Anti-Trust Statute) and was, therefore, no eligible to sue them in US Courts.

The US Supreme Court in its judgement delivered on 11-1-1978 has, however, ruled against the defendant companies and held that foreign Governments may sue them in US Courts for "treble damages". The claims are now being processed further.

News regarding Government Nominees on Board of Directors of private Companies

4912. **SRHI SURENDRA BIKRAM:** Will the Minister of LAW, JUSTICE, AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the 'Economic Times' dated 22nd June, 1978 under the Caption 'Directors on Private Companies';

(b) if so, under what special circumstances the Government will place its nominees on the private sector companies; and

(c) in case of defalcations of funds and frauds, how minority shareholders will be able to save their interest and insist on placement of Government nominees on the Boards of Private Companies?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Yes, Sir.

(b) In order to prevent the affairs of the company being conducted in a manner oppressive to any members of the company or in a manner which is prejudicial to the interests of the company or to public interest, Government nominees are appointed in public and private limited companies under Section 408 of the Companies Act, 1956. As and when such cases come to the notice of the Central Government, appropriate action as per provisions of the Companies Act, 1956 will be taken.

(c) In case of defalcation of funds and frauds, the minority shareholders may bring the matter to the notice of Government. If Government is satisfied after inspection or investigation into the affairs of the company that the charges are substantiated, it will take action to appoint Government directors in the Board of the Company under Section 408 of the Companies Act, 1956.

Release of canalised bulk drugs to M/s. Pfizer, Sandoz and Hoechst

4913. **SHRI RAMDEO SINGH:** Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that M/s Pfizer, Sandoz and Hoechst have been granted canalised bulk drug in 1977-78 substantially in excess of the quantities released to them in 1974-75 and 1975-76;

(b) if so, under what provisions of ITG policy and rules laid down by the Ministry these releases were affected; and

(c) details of bulk drugs released in favour of these companies, each bulk-drug wise along with licensed capacity and what action is proposed to be taken against the officers for flouting statutory conditions?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA).
(a) A statement showing the releases of canalised bulk drugs actually made by IDPL and CPC to M/s Pfizer, Sandoz and Hoechst during 1975-76, 1976-77 and 1977-78 is attached. These releases were made in accordance with the parameters prescribed for distribution of canalised raw materials from time to time.

(b) All the three companies mentioned above are DGTD units. Policy regarding distribution of canalised bulk drugs to DGTD units during the last three years has already been indicated in reply to Lok Sabha Starred Question No. 339 answered on 8-8-78. This policy is in line with the provisions in the I.T.C. Policies of last three years whereunder DGTD units were allowed import of raw materials by way of replenishment of such raw materials consumed in any

of the previous two years, whichever is advantageous.

(c) Details of canalised bulk drugs released to the three companies have been indicated in the attached statement. These releases were not linked to requirements as per licensed capacities for individual formulations being produced by them. From the total releases of various items of canalised bulk drugs, DGTD units could manufacture their range of formulations to the extent of market demand. In view of this, it was possible for such units to have produced certain formulations in excess of their approved capacities.

The policy relating to regularisation or otherwise of production in excess of licensed capacity is contained in the Statement laid on the Table of the House on 29-3-78 containing decisions of Govt. on the recommendations made by the (Hathi) Committee on Drug Industry. In terms of the new drug policy it has also been decided in such cases to issue consolidated industrial licences to drug manufacturing units indicating therein, *inter alia*, the capacities of formulations in terms of bulk drugs to be consumed. Once this is done, the release of canalised bulk drugs to DGTD units would get linked to their licensed capacities.

Statement

(Figs. in Kgs.)

Name of the Company	Canalised bulk drug	QTY released in		
		1975-76	1976-77	1977-78
I	2	3	4	5
<i>CPC items</i>				
M/s. Hoechst Pharmaceuticals Ltd.	Chloroquin Phosphate	230	..	175
	Prenylamine Lactate	170	435	435
	Prednisolone	19.5
	Vitamin B6	150	65	170
	Caffeine	645
	Chloramphenicol Powder	N.A.	3137	3015
<i>IDPL items</i>				
	Tetracycline Hcl.	14710	14180	14180
	Tetracycline Base	745	1000	1000
	Streptomycin Sulphate	5025	5930	5930
	Vit. B1 oral	66	66	140

	1	2	3	4	5	6
	Vit. B2	.	.	98	90	70
	Analgin	.	.	125000	131175	128970
M/s Sandoz (I) Ltd.	<i>CPC Items</i>					
	Chloroquin Phosphate	.	.	185	100	100
	Vit. B6	.	.	240	200	20
	Caffeine	520
	Chloramphenicol Powder	.	.	N.A.	900	1875
	Chloramphenicol Palmitate	.	.	250	265	165
	Vit. 'C' Plain	.	.	3465	3720	4725
	Vit. 'C' Coated	.	.	2340	2940	385
	<i>IDPL Items</i>					
	Tetracycline Hcl	.	.	3235	3050	3050
	Vit. B1-Mono	.	.	215	410	480
	Folic Acid	.	.	38.7	49.5	48
	Vit. B2	.	.	59	112	180
	Phenobarbitone	.	.	1312	1975	1975
	Amidopyrine	.	.	890	1385	1050
						(upto III quarter)
	Tetracycline Base	900	1250
M/s Pfizer Ltd.	<i>IDPL Items</i>					
	Streptomycin Sulphate	.	.	27695	12000	2000
	Sulphadimidine	.	.	11050	11150	10000
	Piperazine Hexa-Hydrate	5000	13185
	Oxytetracycline Hcl	5000
	Vitamin B1 Hcl.	150
	Vitamin B1 Amp.	.	.	129	100	90
	Vitamin B1 Mono	.	.	5579	6124	8800
	Vitamin B2	.	.	2736	2998	3550
	Folic Acid	.	.	226	236	250
	Vitamin B2-5-Phos	.	.	93
	<i>CPC Items</i>					
	Vitamin B6	.	.	1205	880	1505
	Chloroquin Phosphate	.	.	465	550	775
	Calcium-D-Pantothenate	.	.	3175	3445	3821
	D-Panthenol	.	.	80	78	75
	Vitamin C	.	.	38755	40575	45430
	Citric Acid	.	.	worth Rs. 40337	worth Rs. 34778	..
	Tartaric Acid	.	.	worth Rs. 37905	worth Rs. 411970	worth Rs. 39273
	Prednisolone	265	203.5

*Quantity released against 'Release Orders' within their values.

लौराट्टु में कुछ उद्दोगों की वैश्वन सम्बन्धी बातें

4914. भी जर्नल तित जाही बदेस : सभा रेल नंगी यह बताने की रुपा करते हैं :

(क) 16 मई, 1978 से 15 जुलाई, 1978 तक पोर्टबॉर्ड, राणाकाश, बोरबी, उपर्जटा, माणाव-दर में उद्दोगों की, उद्दोगवार, कितने बैगनों की मांग बकाया थी ;

(ख) 16 मई, 1978 से 15 जुलाई, 1978 तक की अवधि के दौरान उद्दोगपतियों को कितने बैगन सम्पादि किये गये थे ; और

(ग) सभा यह सुनिश्चित करते के लिए कि उद्दोगपतियों और व्यापारियों को बैगन सुविधापूर्वक नियमित रूप से और पूरी तरह से उपलब्ध हों, कोई योजना बनवा कार्यक्रम तैयार किया गया है ; यदि हाँ, तो तस्वीरनी ज्वारा क्या है ?

रेल संस्थानमें राज्य नंगी (भी तित नारायण) :

(क) से (ग). 16 मई, से 15 जुलाई, 1978 तक की अवधि के दौरान उत्सवित इंटर्नों पर उद्दोग-वार जादे गये माल-दिव्यों की संख्या

और 15-7-1978 को तका 31-7-78 को रह किए गये भाग पदों सहित बकाया भाग पदों की संख्या अनुकूल 'क' के रूप में संलग्न विवरण में दी गई है ।

स्पष्टतया कुछ बस्तुओं के लिए भाग पद बहुत बड़ा-बड़ा कर देते रखते हैं जैसा कि इस तथ्य से प्रकल्प होता है कि जब मालदिव्यों की संख्या बड़ा ही गई तब भारी मात्रा में मांग पद रह कर दिये गये ।

मालदिव्यों की संख्या मांग पदों की बड़ीबड़ी और प्राप्तिकाता के बनातार की जाती है और अनुकूल 'क' में बतायी गई विवरित से यह स्पष्ट है कि बैगन बाक नेटों के बास्तव को छोड़ कर मांगों को संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा रहा है । बाक-तेलों की अविकाश मांगों के बलब्द स्टेनल पूर्वान्तर सीमा रेलवे पर स्थित है और इसके पार प्रधित बनियालें बस्तुओं के संबंधन के लिए भारी मांग रहती है इसलिए उनके संबंधन को कटे द्वारा विनियमित किया जाता है । इस बस्तु के संबंधन को यथा सम्बद्ध बनाये रखने के लिए रेल प्रशासन द्वारा सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

विवरण

उद्दोग	16 मई, से 15 जुलाई, 1978 तक की अवधि में सदान	बकाया मांग पद		16-7-78 से 31-7-78 तक की अवधि में निरसन
		15-7-78 को	31-7-78 को	
सीमेट	4810	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
रसायनिक उद्दोग	1385	65	100	15
चाक बिट्टी	482	1761	13	1614
साबुन परचर	14	22	21	—
चूना परचर	3650	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
सेलीय नमक	11	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
गैर-सेलीय नमक	8	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
तेल	405	1153	1848	42
बत्त	81	222	7	222
सई की जाठे	214	3	कोई नहीं	कोई नहीं
जनता के लिए अनाज	31	3	1	कोई नहीं
बिनीला	11	34	3	34
प्याज	279	766	40	673
भींसा	8	15	43	कोई नहीं

सम्पत्ति के अधिकार पर स्थान पर भाजीविका का अधिकार

4915. श्रोता रामजी तिहः क्या जिति, न्याय और कल्पकी कार्य मंडी यह बताने की हुपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता पार्टी के बुनाव धोणा पर में यह वायदा किया गया था कि मूल अधिकारों की सूची में सम्पत्ति के अधिकार पर स्थान पर भाजीविका का अधिकार रखा जाएगा ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में मरकार ने ग्रन्थ नक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या मरकार भाजीविका का अधिकार देने के पक्ष में नहीं है ; और यदि हाँ, तो क्या यह वायदे से मुकुलना नहीं है ; और

(घ) यदि भाजीविका का अधिकार नहीं दिया जाना तो रोजगार यांत्री योजना ध्वना बेरोजगारी भ्रमा योजना के बारे में मरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कल्पकी कार्य मंडी (श्री नाति शूष्मन) : (क) जनता पार्टी के निर्वर्तन धोणा-पर में यह बचन दिया गया था कि सम्पत्ति को मूल अधिकारों की सूची में निकाल दिया जाएगा और उनकी वज्रांक काम के अधिकार की पुष्टि की जाएगी ।

(ख) मूल अधिकार के हाथ में सम्पत्ति के अधिकार को मंडिवान (पैतलीसवा संशोधन) विधेयक, 1978 द्वारा निकाल देने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) मरकार का विवार है कि काम के और बेरोजगारी राहने के अधिकार को मूल अधिकार के हाथ में समिलत करने का उचित प्रयत्न उस प्रक्रम पर पहुंचने के बाद होगा जब बेरोजगारी की समस्या को अनियादी तीर पर हल कर दिया गया हो और कूछ यादें से ही लोग बेरोजगार रह जाएं जो बेरोजगारी रहत पाने के हकदार होंगे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सभी व्यक्तियों को लाभप्रद नियोजन देने के लिए उचित परिस्थितियाँ और नीति तैयार की जा रही हैं ।

Setting up of a Polyester Filament Yarn Plant at Devas

4916. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Mafatlal Group have submitted any proposals to Government for setting up a Polyester Filament Yarn Plant at Devas involving an outlay of Rs. 25 crores or so; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes, Sir. The proposal is for manufacture of Polyester Filament Yarn as well as Polyester Fibre.

(b) The proposal is under consideration in the Government.

Memo from All India Scheduled Castes and Scheduled Tribes Association

4917. SHRI SHIV SAMPATI RAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister had received a Memorandum from All India Scheduled Castes and Scheduled Tribes Railway Employees' Association on 5th May, 1978 embodying a demand for recognition to the Association;

(b) whether Government have considered that demand; and

(c) if so, the decision thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) A memorandum submitted to the Prime Minister listing a series of demands including a demand for recognition of the All India Scheduled Castes and Scheduled Tribes Railway Employees' Association has been received.

(b) and (c). In accordance with the policy of the Government, no Association formed by the employees on the basis of any caste, tribe or religious demarcations can be granted formal recognition.

कोरबा में कोवले पर आधारित उर्वरक संयंक की स्थापना

4918. श्री भारत तिहः बोहान :

श्री सुवेंक तिहः :

श्री गोविंद राम मिरी :

क्या ऐडेलियम, रत्नालन तथा उर्वरक अंडो यह बताने की हुपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कोरबा नामक स्थान पर कोवले पर आधारित उर्वरक संयंक की स्थापना की जा रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि कोयता उत्तरव्य न होने पर भी संयंक में उर्वरक का उत्पादन होता रहेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रस्ताव पर अब विवार किया जायेगा तथा इसे कियान्वित करने के लिए कार्यवाही की जायेगी ?

(भीत्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक भंडी (भीत्रोलियम नम्बर बहुगुणा) : (क) कार्यालयितन के लिए हाल में नियम गये कायल पर आधारित उर्वरक प्रायोजनाओं में से कोरवा एक है। साथों की काठिनार्थी के कारण 1974 के मध्य में यह प्रायोजना धीमी कर दी गई थी। बाद में यह नियम किया गया था कि इस प्रायोजना का और कार्यालयितन तथा कोयले फोटो स्टाक पर आधारित प्रतिरिक्षित धनता की स्थापना पर केवल तभी विचार किया जायेगा जब ताकतर और रामारुड़ा में निर्माणाधीन कोयले पर आधारित प्लाटों के बालू होने पर अनुभव प्राप्त हो जाये। रामारुड़म और तालकर प्रायोजनाओं के 1979 के आरम्भ में बालू हो जाने की आशा है।

(ब) और (ग). कोयले पर आधारित उर्वरक प्लाट द्वारे फोटो स्टाक पर तब तक नहीं चलाये जा सकते जब तक कि उनमें भारी लागत रख बढ़ दैमाने पर संर्णाधन न किया जावे। कोरवा में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता के विचार में उपर्युक्त वैकल्पिक फोटो स्टाक की व्यवस्था करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती।

Location of Fertilizer Plant in Maharashtra

4920. SHRI D. B. PATHIL: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he has laid a precondition for approval of Thal-Vaishet as a site for the proposed Fertilizer Plant to be located in Maharashtra State that the Government of Maharashtra should agree to the proposed stage-five expansion of the Fertilizer Factory at Turkhe (Bombay);

(b) whether it is a fact that the Bombay Corporation has objected to the expansion on the ground of air-pollution; and

(c) what is the reaction of the Government of Maharashtra to the above-mentioned condition?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) :

(a) No, Sir.

(b) and (c). The issue of a 'No objection certificate' for the Trombay IV & V Expansion schemes is under the consideration of the Bombay Municipal Corporation.

फेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक भंडी

4920. श्रा० महाराष्ट्र प्रिय लिह शास्त्र : क्या रेल मर्गी यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे थोर्ड के निवेश पर पूर्वोत्तर रेलवे में फर्क्कावाद—बाहुबलीपुर मालानी बाड़ गेज लाइन का संरचना कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ब) यदि हाँ, तो डग बारे में मध्य नव्य क्या है और इस लाइन के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य भंडी (श्री शिव नारायण) :

(क) गो हाँ।

(ब) प्रग्नावित लाइन, जो 154 कि० मी० लम्बी होगी और जिस पर 33 करोंड़ रुपये खर्च आने का अनुमति है, से प्रतिफल घाटिवाला होगा। मर्वेलियम रिपोर्ट के विनाशरुद्धक जानकी की जा रही है। इस लाइन के निर्माण के बारे में थोर्ड के निवेश वेस के पिछड़े खेतों में नई लाइनों के निर्माण के लिए निश्चियों की उपलब्धता पर निम्नरंक रोगें :

कुकिंग गेस के निश्चय

4921. श्रा० महाराष्ट्र प्रिय लिह शास्त्र : क्या फेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक भंडी यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को कुकिंग गेस के बड़े निश्चय मिले हैं;

(ब) यदि हाँ, तो इसमें कुकिंग गेस की कमी को किस हद तक इसे किया जा सकता है; और

(ग) क्या उपर्युक्त विनाश प्रणाली को मंवधा-जनक बनाने तेजु सरकार का विचार नई ग्रांजियों देने का है और यदि हाँ, तो इसके विषय बया मानवज्ञ अपनाया जाएगा?

फेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक भंडी (भीत्रोलियम नम्बर बहुगुणा) : (क) मध्यदूर गेस और प्राकृतिक गेस से विनाशित होने के बाद तरल पेट्रोलियम गेस (काना पकाने की गेस) उपलब्ध होगी। बक्स हाई से प्राकृतिक तरल के साथ एसो-मिएटिड गेस उपलब्ध है। दिल्ली बसीन से प्राकृतिक गेस सम्पाद्ध करने का प्रस्ताव है। विक्षण के बाद लगभग 150,000 मी० दन प्रतिवर्ष तरल पेट्रोलियम गेस उपलब्ध होगी।

(ब) विक्षण होने के बाद और मध्य गोधन शास्त्र और कोयाली ए सी सी यनिट के आरम्भ होने के बाद तरल पेट्रोलियम गेस की उपलब्धता वर्ष 1980-81 के बाद बल्ल बढ़ाविं में ही 100 प्रतिशत बढ़ जायेगी।

(ग) उक्त तरल पेट्रोलियम गेस के विषय ना के लिए तेल कम्पनियां प्राकृतिक एजेंसियों की स्था की करने के लिए कदम उठायेंगी। अर्थात् सरकार

नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को 25 प्रतिशत एजेंसियों दी जाती है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत और शेष वाणिज्यिक महत्व को ध्यान में रख कर दी जाती है, वास्तविक उपभोक्त सहकारी सोसाइटियों और एशो-इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन को शामिकता दी गई है।

उर्वरकों का आयात

4922. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या देंडोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 में विदेशों से कितनी मात्रा में रसायनिक उर्वरकों का आयात किया गया ;

(ख) राज्यवार कितने एकमात्र एजेंटों को वितरण के लिए इन उर्वरकों की सप्लाई की गई ; और

(ग) क्या सरकार का विचार गत वर्ष आयात किए गए उर्वरकों की तुलना में इस वर्ष अधिक उर्वरकों का आयात करने का तथा इनकी बढ़ती वृद्धि मात्र तथा इनके वितरण में कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार एक मात्र एजेंटों की संख्या में वृद्धि करने का है ?

देंडोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमबती नन्दन बहुणा) : (क) 1977-78 के दौरान (वास्तविक पहुंच के आधार पर) रसायन, उर्वरकों की 2873855 मी० टन मात्रा का सरकार द्वारा आयात किया गया था।

(ख) स्वदेशी उत्पादन से उपलब्ध मात्रा तथा हृषि की आवश्यकताओं के बीच अन्तर को पूरा करते के लिए आयातित उर्वरक राज्य सरकारों को प्राप्ति किये जाते हैं। बदले में राज्य सरकारों द्वारा उर्वरकों को पुनः आवंटन भी करती हैं। आयातित उर्वरकों का राज्यों में वितरण करने के लिए भारत सरकार ने कोई ऐजेंट नियुक्त नहीं किये हैं। परन्तु कुछ मामलों में राज्य सरकार इन वितरण तथा नियोजित उर्वरकों को पुनः आवंटन भी करती हैं। आयातित उर्वरकों का राज्यों में वितरण करने के लिए भारत सरकार ने कोई ऐजेंट नियुक्त नहीं किये हैं।

(ग) यह जानकारी देना जनहित में नहीं है।

शाखा लाइन का विस्तार किया जाना

4923. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी शाखा लाइनों का छठी पंचवर्षीय योजना में विस्तार करने का प्रस्ताव है, और क्या इसके बारे में सर्वेक्षण कार्य को अन्तिम रूप दिया जा सका है ; और

(ख) यदि हां, तो उन शाखा लाइनों के नाम क्या हैं, जिन पर कार्य शुरू हो चुका है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विस्तार कीये जाने वाली शाखा लाइनों की सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) 1978-79 में निम्नलिखित तीन नई रेल लाइनों का निर्माण आरम्भ किया गया है।

(i) आप्ता से रोहा।

(ii) नडियाद-कापड़वज लाइन का आमान विरवतं और मोडासा तक उसका विस्तार।

(iii) कल्याणी से कल्याणी टाउन शिप तक।

Investigations into allegations against the Managing Director of Tin Plate Company

4924. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to Unstarred Question No. 9685 on the 9th May, 1978 regarding 'Salary and Perquisites of Managing Director of Tinplate Company' and state:

(a) whether the allegation has been investigated into since then; and

(b) if so, the finding thereof and action taken thereon ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) Taking into consideration the findings of the Inspection under Section 209A of the Companies Act, 1956, the proposal of the company for the re-appointment of Shri Arun Chakravorty as Managing Director has not been approved and the decision has been communicated to the company.

Private Employment without Government permission

4925. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3597 on the 13th December, 1977, regarding mal-practices indulged in by Shri L. S. Darbari, Director, Vigilance, Ministry of Commerce and State:

(a) the action taken or proposed to be taken against Shri L. S. Darbari for taking up consultancy work without Government permission in violation of the provisions of the Civil Services Regulations;

(b) the Ministry which sanctioned his pension; the amount thereof and the substantive post held by him at the time of retirement;

(c) whether he is aware that Shri Darbari has also taken up consultancy work with a larger industrial house and is running a concern named L.S. Darbari and Associates, 10 Pault Marg, New Delhi; if so, whether he obtained Government permission in this case or not; and

(d) whether he would place on the Table of the House a copy of the application submitted by him in this behalf and Government's letter granting him permission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) (a) As already stated in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 3597 answered on 13th December, 1977, Shri L. S. Darbari had not sought prior permission of the Government to take up part time consultancy work with M/s. Vaishali International Private Limited. Shri Darbari has in his reply stated that taking up consultancy work does not attract Government's instructions on commercial employment, adding further that permission may be granted if the Government decides otherwise. This is under examination in consultation with the Department of Personnel & Administrative Reforms.

(b) Shri Darbari, prior to his retirement held the post of DIG/Police on substantive basis in the C.B.I., who have sanctioned a pension of Rs. 948/- p.m.

(c) Shri Darbari has intimated that he has set up his own legal consultancy service titled "L.S. Darbari Associates, A-157, New Friends Colony, New Delhi-110014." No formal request for Government's permission has been made by him in this behalf.

(d) Does not arise in view of answer to (c) above.

U.S. Lawyer engaged by the former Prime Minister

4926. **SHRI JYOTIRMOY BOSU:** Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether one Mr. William Sheffield; a U.S. Lawyer has been engaged by the former Prime Minister Shrimati Indira Gandhi to look after her legal affairs;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether the Government has enquired into the source wherein this U.S. Legal expert is being paid by Shrimati Gandhi in dollars?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) It is understood that Mr. William Sheffield, a U.S. lawyer, had volunteered to render legal assistance to Mrs. Gandhi, the former Prime Minister, in the cases pending against her in the court of Chief Metropolitan Magistrate, Delhi, without any remuneration. He had not formally appeared for her in any of the Court cases.

(b) and (c). Do not arise.

Acquisition of Assets of Heilgers sub-Group

4927. **SHRI JYOTIRMOY BOSU:** Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Shri Pran Prashad's family acquired the Heilgers sub-group with assets of over Rs. 10 crores as family property following on the 1972 bifurcation of Birds Heilgers group of which he was the Chairman;

(b) if so, whether the inquiry conducted by Shri Salil Gupta (of Gupta Ghosh and Chowdhury Chartered Accountants) as an inspector on behalf of the Company Law Board had found the 1972 transactions as "irregular"; and

(c) if so, what are the details thereof and action taken thereon?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) to (c). Shri Salil Kumar Gupta one of the Inspectors appointed under section 237(b) of Companies Act, 1956 to investigate into the affairs of the companies belonging to Bird & Heilgers group, has in his interim report on M/s. Bird & Co. Ltd. mentioned an irregularity at the management of the saying trust by Shri Pran Prashad and Shri K. L. Dua, erstwhile directors of M/s. Bird and Co. Ltd. and trustees of the fund to the detriment of interest of saying trust and with a view to give benefit to Shri Pran Prashad and his family members, through purchase and sale of shares from/to the family members of Shri Pran Prashad and from trusts in which he was interested, at arbitrary prices during bifurcation in 1972. The final report of the Inspector is awaited.

This and other points brought out in the report are under examination. After completion of the same, the matter will be considered by the Company Law Board for such action as may be considered necessary.

सरकारी खेत में कारखाने तथा अन्य प्रतिष्ठान

4928. श्री सुभाष प्राह्लाद : क्या विधि, न्याय और कानूनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मरकारी धनत के अन्वर्गत कुन कितने कारखाने, निगम और अन्य प्रतिष्ठान हैं; और

(ख) उनमें गत एक वर्ष के दौरान किन-किन व्यक्तियों को चेतावनी, निदेशक प्रादि के रूप में नियुक्त किया गया ।

विषि, व्याध और कम्पनी कार्य मंडली (प्री शास्त्र
भूषण) : (क) कम्पनी प्राधिनियम की पाठा 617
में व्याध परिवर्तित मरकारी कम्पनिया, मार्केटिंग
दोंहों का एक प्रमुख धंग है। देख में 31-11-1978
तक 155 मरकारी कम्पनियों का वर्णन हो। इनमें
में 159 ऐसी कम्पनियां थीं जिनके सम्बूर्ण प्रधान
वटूसंस्थक श्रेष्ठ केन्द्रीय मरकार रहे हैं। 548
ऐसी कम्पनियां थीं जिनके सम्पूर्ण प्रधान वटूसंस्थक
तथा राज्य मरकारों के थे, जबकि दोनी 38 कम्पनियां
यों जिनके बटौरीय मरकार व राज्य मरकारों द्वारा
मिलार, बहुमंसक हिस्से धारण किये गए हैं। ये ।
इनके वर्गीकरण कुछ मार्गिक नियम तथा रिसापीय
उपकार हैं, जो यांत्रिकी दोंहों के भाग हैं। परन्तु
कमानी प्राधिनियम की सीमान्तर नहीं पाठे।
मत इनके बारे में सबसे उपराक्ष नहीं है।

(ब) केंद्रीय सरकार की कानूनियों तथा सांविधिक नियमों के प्रधान तथा प्रबन्ध निदेशकों की नियन्त्रण, मन्त्रनिधन प्रणालीक मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा आप वित्तिक इटप्राइवेज नियमों व वित्तिक इटप्राइवेज व्यवस्था बांध से प्राप्त नियकारिणीय व वित्तिक इटप्राइवेज द्वारा की जाती है। 28 मई, 1972 में 23 बृंद, 1978 की प्रधान के मध्य, केंद्रीय सरकार की कानूनियों तथा सांविधिक नियमों में प्रधान तथा प्रबन्ध निदेशकों के रूप में नियन्त्रण किए गए तथा द्वारा आप वित्तिक इटप्राइवेज द्वारा नियमों में जो नाम, विवरण पद्धति में दिये गए हैं, जो सभा पटन पर रखा गया है। [प्रधानलय में रखा गया है। रेकिये संलग्न एव. लो.- 2735/78]

स्टीम, डीजल और इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियों की संख्या

4929. श्री सुभाष अग्रहारा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टीम, डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेनों की पृथक पदक संख्या कितनी है;

(ब) इन रेलग, दृश्यों में से प्रत्येक रेलगाड़ी पर प्रति किलोमीटर कितना अध्य किया जाता है :

(ग) क्या सरकार कम से कम लागत-व्यय वाली प्रणाली से सभी रेलगाड़ियों को चलाने के लिए प्रयास कर रही है ; और

(क) यदि हाँ, तो चालू वर्ष के दौरान इस दिला मे क्या प्रगति होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण):

(क) माप, दीजल और विद्युती कार्यण द्वारा वासित गाड़ियों की पृथक-पृथक संख्या बहलताना संभव नहीं है क्योंकि बहलती गाड़ियां, छंडों में उपयनव्यवस्था कारण-प्रकृति और विद्युत के लिए उपयोगिता के प्राप्तार्थ पर, दो भिन्न व्याधिक प्रकार के करणों से बहलती हैं। लेकिन, 1976-77 के दौरान विभिन्न कारण-प्रकृतिकों के प्रभाव भारतीय रेलों पर साथी (ग्रन्थपत्रगारीय) एवं माल गाड़ी किलोमीटर नीचे निम्न ग्रन्थार्थ ये:

(गाड़ी किलोमोटर
दम लाख में)

	सवारी	माल	जोड़
भाप	166	58	224
दीजल	48	118	166
विजली	29	49	78

(ब) इन गाड़ियों पर किये गये शिशिर व्यय के कर्पंण-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ). किसी लंड विवेष पर करण्येत
का सम्भालन प्रथमा भग्नशा होता, खण्ड पर यातायातो
के घटनाएँ, उस प्रतिक्रिया के भग्नशार के भग्नशार का करण्य
उपयुक्त होता, प्रतिक्रिया के लिए अपेक्षित करने
निचेवा आदि बातें पर निर्भर करता है। इन वार्ताओं
को दृष्टिगत रखते हुए रेल प्रशासन मन्त्रविभिन्न व्यष्टि
पर समर्थ करणं को व्यवस्था करने के लिए प्रवर्तन
शोधे जाते हैं।

Total haulage of Passengers and Goods

4930. SHRI DHARAMA VIR VASISHT : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total haulage of passengers and goods year-wise in 1975, 1976 and 1977;

(b) the availability of total number of locomotives and coaches in the same period year-wise, separately for passengers and goods;

(c) any conspicuous trends in (a) and (b): if so, with reasons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Statistics are maintained for financial year and not for calendar year. Total number of passengers and tonnes of goods originating during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 are given below:

	1974-75	1975-76	1976-77
Number of passengers originating (in millions)	2,429.4	2,945.2	3,300.3

Tonnes of goods originating (in millions) 196.7 223.3 239.1

(b) Number of Locomotives, Passenger carriages and Wagons as on 31st March is as under:

	As on 31st March		
	1975	1976	1977
Locomotives	11,113	11,095	11,010
Passenger carriages	28,254	28,526	28,516
Wagons	377,448	381,497	384,190

(c) There is no conspicuous trend.

Registrar of the Court of Judicial Commissioner

4931. SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a person is qualified to be appointed as a registrar of the court of Judicial Commissioner if he has not attended any law college;

(b) whether it is a fact that the Registrar of the court of the Judicial Commissioner of Goa, Daman and Diu has not attended any law college but still holds a law degree; and

(c) whether the Government propose to hold an enquiry in the matter; and if not, the reasons for same?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) to (c). The Government of Goa, Daman and Diu have intimated that the present Registrar of the Court of Judicial Commissioner passed the IInd LL.B. (Old) Examination held by the Karnataka University in October, 1968 as an ex-candidate. They had asked for details of his attendance in the Law College but these had not been furnished by the University. The Judicial Commissioner, Goa, Daman and Diu has intimated that law degree is not prescribed as an essential qualification for the post of Registrar in that Court, and that the question of Government taking action against the Registrar does not arise.

Confirmation of Temporary Officers

4932. PROF. R. K. AMIN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state whether he will ensure that his directives to the Railway Board to confirm all the remaining temporary officers this year is implemented as there is already abnormal delay in confirming these officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): Yes. Action in this respect has already been initiated.

Railways' participation in Exhibition arranged by AICC

4933. SHRI BHAGAT RAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) is it a fact that Indian Railways took part in the exhibitions arranged by All India Congress Party or any other agency or an individual on the eve of Session of All Indian Congress Committee or to propagate 20 point programme of former Prime Minister of India during Congress regime;

(b) if so, the total number of exhibitions in which railways and its production units took part; information may be submitted separately for each railway or production unit with names of occasions or sessions at which these exhibitions were held;

(c) cost of stores utilized for the construction of pavilions or stalls installed at the aforesaid exhibitions; and

(d) cost of materials should be submitted in the following break-up—

(i) cost of material issued from store depots;

(2) cost of material drawn from the floor or workshops or from its petty stores depots;

(3) cost of material utilised from the stocks held by Inspectors of works, electric foreman, head train examiners and other subordinates of the railways?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) to (d). A statement is laid on the Table of the House. [Placed in library. See No. LT-2736/76].

Out of nine Zonal Railways, three Production Units and other Railway Administrations, only four Zonal Railways viz., Northern, Northeast Frontier, Eastern and South Eastern, actively participated in 10 exhibitions. Other Zonal Railways, Production Units and the Research Designs and Standards Organisation assisted these our Railways by way of sending models and other exhibits from their existing stock which did not involve any additional expenditure.

Upgradation of posts of X-Ray Technicians

4934. SHRI PIJOO CHAND VERMA:

SHRI SUBHASH AHUJA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there are rules framed by competent authority to upgrade and downgrade the posts of X-Ray Technicians in various Railway Hospitals, specially, the sub-divisional hospital, Amritsar and Divisional Hospital, Lalgarh, Bikaner;

(b) if there are such rules, what are these;

(c) if there are no such rules, the reasons therefor and how the upgradation and downgradation is done; and

(d) whether the exposure of X-Ray films at Bikaner is four times more than at Amritsar; what are the causes of downgrading the post of X-Ray Technician at Bikaner and upgrading the post of X-Ray Technician at Amritsar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (d). The nature of work being done by the incumbents of the two grades (Rs. 260—400 and Rs. 330—560) of X-Ray Technicians is identical. The higher

grade posts are provided to improve promotional prospects and the incumbents of the posts are transferred from one post to the other on administrative grounds.

Central Railway Buildings in Kalyan

4935. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Ministry of Finance by its letter No. 477-P/65 dated 29th March, 1967—fixed quantum and laid procedure and intimated to all local bodies in respect of payment of service charges of Central Government properties;

(b) whether it is also a fact that the Central Railway have 54 buildings built after 1-4-37 in the city limits of Kalyan Municipality of Thana District (Maharashtra) but their service charges for the period of last fourteen years amounting to the tune of Rs. 3,80,216 have not been paid to the said Municipal Council even after repeated reminders; and

(c) if so, the reasons thereof and when the said amount shall be paid to the Municipal Council?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) and (c). The 54 buildings in question include some constructed before 1-4-37. It was for the first time in July, 1977 that the Kalyan Municipal Council preferred a claim of Rs. 3,80,216 relating to service charges due from 1-4-54. Since the claim pertains to such a long period, it is being scrutinised, and payments will be made as soon as the relevant points are settled.

Mercy appeal of X-Ray Technicians

4936. SHRI PHOOI CHAND VERMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Minister of State in the Ministry of Railways had accepted the mercy appeal of the X-Ray Technicians working in the low pay scale on the Northern Railway on the 3rd October, 1977 and directed the Director of Establishment of the Railway Board to implement the order and the D.E. Railway Board wrote a D.O. letter to the Additional C.P.O. Northern Railway on 15/16 October, 1978 but the C.P.O. (Additional) and C.M.O. (Medical) Northern Railway did not comply with the orders issued in this regard;

(b) whether orders were again given before the G.M. Northern Railway and

Medical Officer (BKN) in the X-Ray Cell of Medical Department, Bikaner on the 1st May, 1978 (Back to ASR) but they ignored the orders; and

(c) the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) The matter relates to one X-Ray technician who was transferred from Amritsar to Bikaner as a result of a Vigilance case. His transfer was stayed under D.O. letter of 16th October, 1977 (not 1978) but the stay order was subsequently cancelled on 30th December, 1977.

(b) No such orders had been given.

(c) Does not arise.

मध्य प्रदेश में एक पोली प्रोपोलीन फिल्म फैब्रिटरी को स्थापना के लिए आवश्यकता का जारी किया जाना

4937. श्री राधाकृष्णन : क्या देहोलियम, रसायन और उर्वरक मंडी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पोली प्रोपोलीन फिल्म फैब्रिटरी की स्थापना करने के लिए आवश्यकता जारी करने देने सरकार को कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो यह कब प्राप्त हुआ है, और किस माध्यम से प्राप्त हुआ है ;

(ख) आवश्यकता की करने में विनाश के कारण है जबकि इस बारे में गोजय सरकार सहयोग करने वाली सम्भावा के साथ करार करने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ग) यह आवश्यकता कब जारी किये जाने की संभावना है ;

देहोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंडी (श्री हेमती नाथन भट्टुगुण) : (क) से (ग), जी हाँ। विद्युतीय प्रेड के बायोकार्यालयी आर्सिलिंग्ड पोली प्रोपोलीन फिल्म तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम लिं. से एक आवश्यक पत्र जारी करने से सम्बन्धित एक पत्र प्राप्त हुआ था और सं. 9387/77/शाई एल दिनांक 9-12-1977 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। आवेदन पत्र पर विचार किया गया और इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि इस मद के लिए पर्याप्त कमता के उत्पादन के लिए लाइसेंस पहले ही दे दिया गया था।

मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल में इस मामले पर पुनः विचार करने के लिए आवेदन किया है। मामला समीक्षाओं की इच्छा

स्थाई कर्मचारियों का चयन

4938. श्री कूल चन्द बर्मा : क्या रेल मंडी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत माह उत्तर रेलवे अस्पताल में सफाई कर्मचारियों के चयन में और 1977 में एकस-रे तकनीशियन के पद को बीकानेर से अमृतसर रेलवे अस्पताल में अन्वरित करने के मामले में सम्बन्धित व्यक्तियों से कवित पूर्ण सी गई थी ;

(ख) क्या जोधपुर रेलवे अस्पताल से एक एकस-रे तकनीशियन का अमृतसर तबा दला किया जा रहा है क्योंकि भर्ती करने वाले कर्मचारी को छुस दी गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो इस पर रोक लगाने के लिए रेलवे विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो रेलवे अस्पताल, अमृतसर में एकस-रे तकनीशियन के पद का दर्जा बढ़ाने के कारण है और उसे बीकानेर अस्पताल में तबादला करने के कारण है जबकि अमृतसर में कार्यवाहर बीकानेर के कार्यवाहर की आवेदन कम है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंडी (श्री गिर नारायण) :

(क) और (ख), विभागीय बाटों में निर्धारित स्वास्थ्य निरीकांकों के 25% पांच को बढ़ाने के लिए उत्तर रेलवे ने मार्च 1978 में एक प्रवरण किया था। राज्यस्व निरीकांकों पर प्रवरण में ग्राम-एकस-रे तकनीशियन के पद भी बीकानेर में अमृतसर रेलवे अस्पताल में अन्वरित करने के बारे में चुन का कोई मामला रेलवे के नोटिस में नहीं आयी है। इस बारे में नियुक्त कर्मचार द्वारा विवरण मांगने की कोई जिकायत नहीं हुई है।

(ग) प्रण नहीं उठता।

(घ) अमृतसर में 260—430 रु. (सं. ३० बै.०) के पेंड में काम करने वाले एक एकस-रे तकनीशियन को प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित करना था। उत्तर रेलवे के किसी भी अस्पताल में 260—430 रु. (सं. ३० बै.०) पेंड में एकस-रे तकनीशियन को अमृतसर से बाहर स्थानान्तरित करने के लिए उसके पद के साथ बीकानेर स्थानान्तरित करना या गया था और बाले में बीकानेर के एकस-रे तकनीशियन का पद, जिसके पदधारी ने संयोगवत् अपनी तैनाती अमृतसर में कराने की इच्छा अस्वित की थी, अमृतसर अन्वरित कर दिया गया।

12.00 hrs.

**RE. SHORT NOTICE QUESTION
ON REPORTED MURDER OF TWO
CHILDREN IN DELHI**

श्री वंशवर लाल गुप्त (विस्तीर्ण सदर) : उपायक भावोदय, दो बच्चों का कल हुया है, उनकी डैंडी मिली है, मैंने इस बारे में माटे नोटिंग भवेश्वन दिया है, मैं जानना चाहूँगा कि उम्रका क्या हुया ? यह हमारे लिए और मारे मदन के लिए बहुत बड़ी बात है, उसकी इन्वेष्यायरी होनी चाहिए ।

SHRI VASANT SATHE (Akola) : I am sure the whole House and yourself will feel shocked and grieved to hear the shocking and sad news regarding the two young children, one a girl, Gita age 17, and the other, a boy, Master Sanjay, age 15, children of Shri M. M. Chopra, Captain in the Navy, who were kidnapped day before yesterday while they were trying to go from their home in Naval officers' Colony Enclave to the Yuva Vani Programme at 6 p.m. in the A.I.R. They were kidnapped, and today's morning news is, I got it confirmed from the Home Ministry's office, that these young children, unfortunate children, were found murdered with multiple stab wounds and their bodies were left at Ring Road. I do not have words. What is the fault of these young children ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I would like to tell you one thing. A short notice question has been given notice of by Mr. Kanwarlal Gupta and I am admitting it. Tomorrow we will have a full discussion on it.

SHRI VASANT SATHE : Let the Government, let the whole House, convey our deep sense of shock and sorrow to the bereaved family. This is the least that we can do. The whole nation is shocked. I am sure every hon. Member in this House is shocked. When this Short Notice Question comes, Government will give a detailed reply, that is a different matter, and it will be considered as a law and order problem, but at present I feel we have to express, and the whole House has to associate itself in expressing, this total shock that we feel at this ghastly tragedy.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yes, it is very shocking. I think the whole House will associate itself.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : I wish, on behalf of the Government, to associate ourselves with the feeling of shock and

grief that the hon. Member has given expression to. This is a very serious matter which involves innocent children, and certainly Government will leave no stone unturned to look into the whole case and see that the culprits are brought to book. Meanwhile, we share the grief and sorrow and shock that he has expressed, and the feelings of the House may kindly be conveyed to the bereaved family.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think the whole House associates itself.

श्री राम अवधेश सिंह (विकासगंज) : उपायक भावोदय, एक निवेदन है,

उपायक भावोदय : श्री राम अवधेश सिंह जी आप जरा बैठ जाइये ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैंने नियम 144 के तहत नोटिंग दिया है कि काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट पर बहम कराई जाए और उनको लागू कराया जाये । उस सम्बन्ध में 26 प्रादीपियों ने लिखकर दिया है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Ram Awad Singh, you came to the chamber and I have told you to give a notice under rule 377. But you have come here and persisted in raising it in the House. Please take your seat. Do not get up like this impromptu. I will not allow it. Please take your seat.

श्री राम अवधेश सिंह : इस बारे में हाउस को बताया जाये और इस पर बहम कराई जाये ।

SHRI JYOTIRMOY ROSU (Diamond Harbour) : Sir, I want to say....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let me make some announcements.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I will not take half a minute.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please resume your seats.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : It is about the communal riots in Hyderabad.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have given notice about it. I will look into it.

12.06 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST (i) EDITOR, THE NATIONAL HERALD AND (ii) SHRI SOMJIBHAI DAMOR, M.P.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri K.P. Unnikrishnan had given a notice of question of privilege on the 14th August, 1978 against the Editor, *The National Herald*, New Delhi, for alleged "gross distortion and wilful misrepresentation" of certain proceedings of Lok Sabha of the 12th August, 1978, and casting "aspersions" on their "conduct as Members in the House" in a news report published in its issue dated the 13th August, 1978, under the caption "Major Tactical Reverse".

The Editor, *The National Herald*, who was asked to state what he might have to say in the matter, in his reply dated the 19th August, 1978, has stated *inter alia*, as follows:

"Our reporter has explained that in his attempt to give the gist of the tumultuous proceedings of the day in an abbreviated form, unintentional errors had crept into the report. He has further stated that it was farthest from his mind while reporting the proceedings to misquote any member or misrepresent any party's view point. We express regret and offer our unqualified apology for the erroneous reporting and request that the notice of breach of privilege against *The National Herald* is not pressed."

In view of the regret and unqualified apology tendered by the Editor, *The National Herald*, if the House agrees, the matter need not be pursued. The Editor of *The National Herald*, may, however, be asked to publish the necessary correction and his apology prominently in the next issue of the newspaper.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Pandit D. N. Tiwari, M.P., Chairman, House Committee, had given a notice of question of privilege on 3rd August, 1978, against Shri Somjibhai Damor, M.P. for making certain unfounded allegations against him in the House on the 31st July, 1978 and also in a letter addressed by him (Shri Somjibhai Damor) to the Speaker on that date, regarding allotment of houses to the Members belonging to the Scheduled Tribes.

Shri Somjibhai Damor was requested to furnish his comments on the matter and either to substantiate the allegations made by him or to express regret. Shri Somjibhai Damor in his reply dated the 23rd August, 1978, has stated:

**Violent Clashes in 212
Vishakhapatnam (CA)**

"In this regard, I express my unqualified regrets to you and also to Chairman of the House Committee."

In view of the unqualified regrets expressed by Shri Somjibhai Damor, if the House agrees, the matter may be treated as closed.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

12.10 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 26th August, 1978, agreed without any amendment to the Delhi Police Bill, 1978, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 24th August, 1978." —

12.11 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED VIOLENT CLASHES INVOLVING NAVAL PERSONNEL, WORKERS OF HINDUSTAN SHIPYARD AND BUS WORKERS

श्री विजय कुमार मलहोत्रा (दिल्ली): उपरायक महोत्तम, मैं शवित्रनीय लोकमहल के निम्नलिखित विषय की ओर गह मंडी का ध्यान दिलाता हूँ और प्रारंभना करता हूँ कि वह इस बारे में एक बहुत अचूक विषय है:—

"विशाखापत्नम में नौसेना कर्मचारियों तथा हिन्दुस्तान शिप्यार्ड के कर्मचारियों द्वारा बस कर्मचारियों के बीच हुई हिंसा मठभेड़, जिस में पांच अवित्त मारे गये, से उत्पन्न विषय का समाचार"।

पूर्ण मंत्रालय में राज्य मंडी (श्री अधिकारी शाम मंडल) : बहुदार, गवर्नर को विशाखापत्नम में 26 और 27 अगस्त, 1978 को हुई अप्राप्तकालीन हुमारियां पटनालां विनके परिणामस्वरूप तीन अवित्तियों की जाने गई, पर बहुत दुख हुआ है। सरकार इस विषय में राज्य प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

26 अगस्त को काफी शाम को नौसेना के कर्मचारियों तथा हिन्दुस्तान शिप्यार्ड के निवासियों, जो एक बस में यात्रा कर रहे थे, के बीच कहा मुनी हो गई। हिन्दुस्तान शिप्यार्ड के ध्यान

कामगारों को इसकी जानकारी हुई। बाद में बस बस बापत आ रही थी तो नौसेना के कम्बिचारी बस के कंडक्टर को नौसेना के कार्यालय पर ले गए, उसे रोके रखा, और जिपयार्ड के उस कामगार को पहचानने के लिए कहा जिससे कहा-नुनी हुई थी। इस बीच निटी बस के कामगारों को कंडक्टर की इस नजरबन्दी का पता चल गया और ये महालक्ष्मी चिपेटर के निकट एक ही गांग और उन्होंने अपने साथी को बचाने के लिए नौसेना के कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश की परन्तु राज्य पुलिस ने उनको रोक दिया। बाद में नौसेना के कम्बिचारियों ने कंडक्टर को पुलिस को सौप दिया।

26 अगस्त को कासी भास के समय नौसेना के कुछ कम्बिचारियों नाया बस कामगारों और बाद में हिन्दुस्तान जिपयार्ड के कुछ कम्बिचारियों में एक मठभंग हुई। इनके परिणामस्वरूप भराजकता, हिंदा और प्रागजनी की कई घटनाएँ हुईं। जिपयार्ड के कामगारों, बस कंडक्टरों, जनता के कुछ अधिकारियों तथा नौसेना के कम्बिचारियों के बीच पथराव हुआ जिसमें कुछ प्रदीनिक नायिक, नौसेना कम्बिचारी, तथा राज्य पुलिस के कम्बिचारियों को भी चांचा आई। घटना में एक निटी बस और नौसेना के ट्रक को आग लगा दी गई। स्थिति पर काढ़ पा लिया गया।

27 अगस्त की मुहूर की नौसेना के हाथ वीटी आफिसर श्री एन० बी० भट्ट, का बब पिलोटी रात की बारातों के भौके के निकट मिला। जब उसकी मृत्यु का समाचार नौसेना कम्बिचारियों को वित्त तो उनके से कुछ बहुत झोपड़ियां हो गए तथा भराजकता हिंदा तथा प्रागजनी फिर से नौसेना के कम्बिचारियों, हिन्दुस्तान जिपयार्ड के कम्बिचारियों तथा अन्य के बीच भड़क उठी। एक बिनेमाहाल, एक पूजा का स्थान, कुछ आवासीय मकानों तथा कुछ बाहों को जला दिया गया। हिन्दुस्तान जिपयार्ड के एक कम्बिचारी श्री कातीदाम को गंभीर पुलां पाई जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। एक और 19 वर्षीय लड़के (सिविलयन) की मृत्यु का भी समाचार मिला है।

स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित लोगों में 27 अगस्त को शाम 5 बजे से कफ्यू लगा दिया है तथा तब से 28 अगस्त की शाम तक कोई घटनायें नहीं हुई हैं। सामान्य विनियम, नौसेना नाया स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों की गतिविधियों में समन्वय करने के लिए एक संयुक्त नियन्त्रणकाल की स्थापना की गई है। राज्य सरकार ने नगर में शांति और अव्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं। नौसेना के प्रधिकारी भी शांति बहाल करने के लिए राज्य सरकार की सहायता करने के लिए उपाय कर रहे हैं।

मैं सदत से तथा सदन के माध्यम से विशाखापत्नम के लोगों के सभी बांगों से शांति और सदृश्यान्वयना बनाये रखने तथा सामान्य स्थिति का बातावरण पुनः स्थापित करने के लिए हार्दिक शपील कहना।

श्री विजय कुमार बलहोका : उपायम, महोदय विशाखापत्नम के मलकापुरम् जिपयार्ड के लोगों में जो हिस्क घटनाएँ हुई हैं जो काफी दुखदायी हैं। उन घटनाओं में विवेच रूप से जिन लोगों की मृत्यु हुई हैं उन में एक विद्यार्थी है जो बहां पर जिपयार्ड भें गेट के रूप में प्राया हुआ था जिसका इस लड़ाई से और इन घटनाओं से कोई तालुक नहीं था। या एक नैवेल आफिसर की लाज अपले दिन रात को ज्ञालियों में प्राप्त हुई और तीसरे रस्ते लाले अवित का भी ऐसा लगता है कि घटनाएँ से कोई तालुक नहीं था। इस कारण से जो घटनाएँ वहां पर बट्टी हैं उन में कुछ बारताव तत्व बाद में वापसी हुए, इस के बारे में कोई सन्देश दिखाई नहीं देता। इस के साथ जुड़े हुए जो दूसरे सबाल हैं उन की ओर में मंत्री महोदय का व्यापाराकारित कलां बाहिर है कि यह कोई वैटन सिक्के यवधानापत्रक का हो ऐसी बात नहीं है, हिंदावाद में जो घटना हुई है, उस से पहले भराजकता में जो घटनाएँ हुई और उस से पहले अन्य स्थानों पर भी जो हिस्क घटनाएँ उड़ रही हैं और तनाव पैदा हो रहा है इस के पीछे कोई वैटन है या नहीं, इस को देखने की ज़रूरत है। मैं यह तो नहीं कहता कि ये घटनाएँ कोई प्री-मैट्टेंड भी या पहले से लात की हुई थीं। परन्तु एक छोटी सी घटना होती है, उस के बाद भ्राताकाल वह घटना बहुत उड़ रूप ब्लाइर कर लेती है। इसके बारे में यह जो एक साइकोलापी बन गई है देख के बावजूद, इसको केन्द्रीय प्रशासन और प्राविधिक सरकार इन सदन को बिल कर के देखने और इस को रोकने की सकत ज़रूरत है। प्रभर ऐसा न हुआ तो इस के कारण देश में यह जो बातावरण आ रहा है कि ला एण्ड मार्बर तहसीलहूँ हो रहा है, कानून और अवधान या नहीं रह गई है इस के कारण बहुत ही बीमत रूप में पैदा हो रहा है। मैं चाहांगा कि प्रधान मंत्री जी सभी समय भूतियों के साथ बैठ कर इस पर विचार करें और इस के देखे कि इस में किसी तरह की राजनीति नहीं आयी जाहिए और इन सारे मालामालों को विस तरह से हल किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे जहर हैं जो यह चाहते हैं इस बात को सामिल किया जाएँ और इस बात का बड़े जोर से प्रभाव करने को कोशिश उन सी तरकी दियी जाएँ एवं जेनरेजेंस के बावजूद ला एड मार्बर की स्थिति बहुत ठीक थी, अच्छी भी भौतिक एवं जेनरेजेंस बांगों कि हट गई इस के कारण देश में हर रोज समाचारपत्रों में ऐसी खबरें आ रही हैं, परन्तु बहुत से ऐसे स्थान भी हैं जहां कांपेस का या कांपेस (भाई) का शासन है तो उन सभी को मिला कर ला एन्ड मार्बर की प्राविलम के लिए कोई सक्त कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी यहां पर जिक्र किया गया कि दिल्ली के दो बांगों का कल कर दिया गया। इसमें एक बात निकलती है कि जो कानून लोड़ने वाले गुड़ और भराती तत्व हैं उनके सभी में कहाँ हैं प्रकार की भावना न था जाये कि देश में ला एड मार्बर की स्थिति कमज़ोर होती जा रही है।

इसीलिए मैं इस बात पर बहुत बल देना चाहता

[श्री विजय कुमार मलहोत्रा]

हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इस सारे सवाल को देखना चाहिए। आज सभी प्रदेशों में इस तरह की घटनायें बढ़ रही हैं।

दूसरी बात यह है कि यह जो घटना हुई है इसके सम्बन्ध में नैवी के बाइस एडमिरल, सुपरिनेंटेंडेंट पुलिस और शिपयार्ड के प्रबन्धक—तीनों ने अलग अलग घटनायें बताई हैं। आज देश में बहुत जगहों पर वी एस एफ, सी आर पी, मिलिट्री, पब्लिक अंडरटेकिंग स्थित है वहां पर इनमें तालमेल के लिए कोई ऐसी एथारिटी होनी चाहिए जोकि सबके साथ मिलकर काम कर सके और कहीं पर अगर किसी प्रकार की कठिनाई होती है, कोई तनातनी का बातावरण पैदा होता है तो उसका नियाकरण किया जा सके। ऐसी जगह जहां पर नैवी के सेंटर हैं सेट्रल गवर्नरमेंट और मिलिट्री के आफिस हैं उसके, सम्बन्ध में कोई ऐसा नियंत्रण होना चाहिए कि जिसके अन्दर में वे पूरी तरह से काम करेंगे। अगर कहीं पर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए कौन सी कामन एथारिटी होती जो मिलकर सारे मामले को निपटा सके। अन्यथा तालमेल बनाने में समय लगता है। नैवी के कमाण्डर को और शिपयार्ड के प्रबन्धकों को अपने आदिमियों को सम्मालने में 24 घंटे लगे। जो लोकल बस कर्मचारी ये उनको भी सम्मालने में समय लगा। इसलिए कोई ऐसी एथारिटी होनी चाहिए जो सभी को कन्ट्रोल कर सके, सभी का आपस में कॉन्टैक्ट हो सके और एक दूसरे के विपरीत कोई काम न कर सके—इसको देखने की जरूरत है। इस मामले को देखने के लिए और आगे फूंचर के लिए कोई ऐसी इंक्वायरी वहां पर हो ताकि आगे कभी भी ऐसी घटनायें न घट सकें।

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, जिन भावनाओं को व्यक्त किया गया है, मैं उनके साथ हूं। विधि और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का या हिस्सा करने का जो भाव है उस पर काबू पाना चाहिए और उसके लिए माननीय सदस्यों ने जो मुक्काब दिए हैं मुख्य मंत्रियों तथा विरोध पक्ष के नेताओं से मिलकर बात करने के लिए तो हम चाहते हैं ऐसा बातावरण होना चाहिए कि कहीं पर अगर कोई छोटी घटना हो तो उससे इस तरह की हिंसक वारदातें न बढ़ें। इस तरह का बातावरण हमें बनाना चाहिए।

यहां पर जो घटना हुई है उसमें कोई पैटर्न है ऐसा तो नहीं दीख रहा है। आपस में कुछ कहना मुश्की हो गई और उसके बाद बात बढ़ गई। स्थिति को काबू में लाने के लिए उपाय किए गए यद्यपि माननीय सदस्यों ने जैसा कहा कि और भी अच्छे उपाय किए जा सकते थे।

इंक्वायरी की जो बात माननीय सदस्य ने कही है तो एक मैजिस्ट्रीरियल इंक्वायरी का एलान राज्य सरकार ने किया है और अभी सबसे ज़रूरी बात

तो यह है कि शांति और व्यवस्था स्थापित हो और आपस में सद्भाव पैदा हो। यह सबसे पहली आवश्यकता है। यह पहला काम हो जाता है तो बाद में राज्य सरकार से इस बारे में भी बातचीत की जा सकती है।

SHRI JANARDHANA POOJARY (Mangalore): Growing violence in the public life of the country is a serious matter of concern. An atmosphere of violence and lawlessness has gripped the entire country.

You know our defence personnel and particularly, the Naval personnel are to safeguard the coast and also to safeguard public lives and property of the country. I have got high regard for our defence forces. But to-day what had happened in Vizag is this.

In fact, to-day, our naval personnel have taken the law into their own hands which is deplorable and no peace-loving citizens of this country can tolerate it. You know there are atrocities on harijans, weaker sections, poor workers, minorities and it has become the order of the day. What has happened in Vizag on the night of the 26th and how the incident has started. The Minister concerned has not given us a correct picture as to how the incident has started. The incident had started in this way. Two naval personnel got into the bus in a drunken state, that is, under the influence of alcohol. Then, after entering the bus, some workers of the Hindustan Shipyard got into it. The poor chaps, the poor workers, simply crawled under the feet of the navy men. These navy personnel got angry and there was an altercation. Immediately these naval personnel started beating these workers. These workers got down from the bus; they went to the Shipyard and narrated the incident to their colleagues. The colleagues came back. When the bus was returning at the Naval Sena Dock these people waylaid the bus and removed the bus crew and took them to the workers' quarter of the shipyard and they confined them wrongfully.

At the time when the bus crew were in the quarters the bus crew got collected in strength and they demanded the release of their crew members. At that time there was a clash as a result of which a Petty Naval Officer was killed. In the meantime some naval officers were injured and 8 workers were also injured. Next day once again the fighting erupted. The dead body of the petty naval officer was found by them near the bush in the naval colony. At that time these people went on a rampage and they took law into their own hands and even went to the extent of setting fire to the Cinema

Hall and also to the shipyard staff quarters. At that time what happened was this. In the clash one worker, by name, Kalidas was murdered and another nineteen year old boy was also murdered. When the naval people opened fire on the Gurdwara, at that time these people died. Not only that. Public property was also set on fire. This is the position. Can the Members of this honourable House join me in deprecating and deplored the acts of the naval personnel? What is happening to-day? The atmosphere of violence and lawlessness had gripped the entire nation to-day. You heard what Mr. Sathe has just now stated. Now I will come to the main point. What is the reason?

MR. DEPUTY-SPEAKER : You should have come to the main point long before.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Please excuse me. I will come to that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are making here a speech. Actually you should ask for a clarification. Please ask for the clarification.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Please excuse me. Now why it is happening? There is no full-fledged Home Minister in the country. For the last so many months we did not have two Cabinet Ministers and six State Ministers. What is the Prime Minister doing? He is concentrating the powers to himself. He is not prepared to give the powers. That is why there is a bottleneck in the administration. That is why what I submit is this. Is the Prime Minister going to appoint a Home Minister in this country? There is no discipline in their party because there is crisis and there is no time for these people to find time for running the administration effectively. Under these circumstances, may I know from the Prime Minister when is he going to appoint the Home Minister for this country? (Interruptions)

Secondly, whether he is going to appoint a High Court judge to go into these allegations?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI JANARDHANA POOJARY: I am concluding. Sir, people in this country have started feeling that there is no safety for their lives today and as such, I request the Prime Minister to take immediate action, otherwise tomorrow your government will be thrown out by the people. (Interruptions)

भी अधिक सात मंडल : जो रिपोर्ट हमने दी है वह आन्ध्र सरकार द्वारा भेजी गयी है।

भी उपरेक्षण (वेबरिया) : माननीय उपायकारी, जो बढ़ता बढ़ता है, वह बहुत ही जरूरीका है। इस में भी कोई शक नहीं है कि जिस राज्य में यह बढ़ता बढ़ता, वहाँ की राज्य सरकार इस बढ़ता को मुक्त दर्शक की तरह देखती रही। इस से उसकी कायदारी प्रकट होती है।

मुझे तो इस सम्बन्ध में एक तर भिन्ना है। यह तार राकोटी इवररमा का है जिसके पाति राकोटी कालिदास पकड़ कर के ले जाए गये। वहाँ नेवल स्टाफ के डायर मारे गये और जीक आफ नेवल कमांड की हाजिरी में उनको पूरी तरह कुचल दिया गया। आज भी वहाँ पर इस तरह की अव्यवस्था की भावना है और लोग वहाँ कार्पूर लगा होने पर भी डर रहे हैं। आप कि उनका जोन मुर्शिदान रह सकता या नहीं। यह जो तार हमारे पास आया है, मंत्री जी के पास भी पहुंचा होगा।

मैं अब दोनों मतवाल करना चाहता हूं, क्योंकि जनराई पुजारी जी को तरह मैं फालतू लैवरर देने के लिए लो बड़ा नहीं हूँपाहुँ। माननीय मंत्री जी ने अपने वयान में कहा है कि जब वे बस यात्रा कर रहे थे तब उनका आकिर के कमचारी पकड़ कर के आगे यहाँ ले गए। क्या मंत्री जी भेजे राय से सहमत होंगे कि अगर वे बग कमचारियों को पकड़ कर के नहीं ले जाते कि बताएँ कि किस से तुम्हारी कहाँ-मूर्नी हुई है तो उनको पूरी प्रतिक्रिया नहीं हुई होगी? मंत्री जी पहली बात तो यह बताये कि मही मायनों में बगा वे इस तरीजे पर पहुंचे कि वे धिये हुए थे और बिना मुकाम तक पहुंचे रासों में ही मल हो गए थे और उन्होंने धाने अधिकारी का दुरपयाग किया? क्या इसे मंत्री जी जूदा बड़ा घटना को पढ़े, क्या आपने दुर्ल राज्य सरकार को आदेश दिया या राय से कि हाइ कोर्ट के जज के स्तर पर इस की न्यायिक जांच बितायी जाए? अब भी इस में क्यों देर की जा रही है?

रोड बेज के, शिपयार्ड के और नो सेना के कम्ब-चारा प्राप्त में नहैत है और इसके लिए मल्होत्रा जी ने भी कहा और मंत्री ने उनका जवाब भी दिया, इस सम्बन्ध में मुझे याद है कि जब हम लोग जेल में थे तो बगरा में भी मारा-मारी हुई थी और कोई किसी को पकड़ के ले गए थे और उन्होंने पूरा आगरा शहर घेर लिया था। उस समय मोहनरमा का राज था या उनके पिताजी का राज था। हम सोग उस समय जेल में थे और हमने अबबारों में पढ़ा था। ऐसी बदलाएँ जो अबबर बाहरी में हो जाया करती हैं। क्या मंत्री जी ऐसे बहरों के जहाँ पर कि पविलियन बाइररेक्टियम के कमचारी भी-कोई अधिकारी काल करते हैं, कोई लायज़ आफिस या कोधारिडिनेशन कमटी बनाने की अवस्था करती ताकि जब ऐसे मार्के था जाएं तो दुर्ल तायाराही की जाए अब्दोक विभाग के आदेशों से ही यह लीक होने वाला नहीं है।

[श्री उद्धैन]

प्रब मे नंदी जी से दोनों सवाल करना
चाहता हूँ ।

हाई कोर्ट के जज की घट्टाखता मे जांच कमेटी
विठाने मे राज्य सरकार को क्या कठिनाई है यह
मे आप से जानना चाहता हूँ ।

मे यह भी जानना चाहता हूँ कि कोर्साइनेजन
कमेटी क्या नहीं बनाई जाती है? परिवक घट्ट-
टेकिंग के, नंदी के कमंचारी या दूसरे जो लोग
वहाँ रहते हैं उनको इस तरह कोर्साइनेजन
कमेटी क्या नहीं बनाई गई है, यह भी मे आप से
जानना चाहता हूँ ।

नेवल प्राक्टिशर ईस्टर्न कमांड के साथने काली-
दाम को मारा गया, इस ग्रामय का जो तार आया
है, इसके बारे मे आपके पास कोई जानकारी है
प्रोर यदि है तो क्या साप वह नदन को देंगे?

श्री उपरिक लाल मंडल : जांच का सारेंग हो
चुका है। जांच के बाद जो भी माननीय नदन्य
कह रहे हैं उसकी जानकारी दे दी जाएंगी (व्यवधान)
माननीय नदन्य जो कुछ भी कह रहे हैं उसकी
मे नम्रता है। उनका कहना है कि जुड़िशल
इनकार्याली होनी चाहिए। लेकिन हर बात मे जुड़िशल
इनकार्याली हो यह जहरी नहीं है। पहले मैनिंग्टटियन
इनकार्याली हो रही है। जैसा आपने कहा है पहली
ग्रामयकाना—यह है कि बहो तांत्रिक व्यवस्था स्थापित
हो, ग्राम मे गदधार हो। इनकार्याली को जाने के
बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

रक्त नंदी (श्री जानकीबन राम) : अभी प्रातः-
काल ईंग्ल सेंटरी का, नंदीना प्रधान को, मने
यह आदेश दिया है कि प्राप्त सरकार से बात करके
विवाकापत्रम मे वहाँ और नदीना कमेटी को
स्थापना को जाए जो नंदीना के लोगों की, हिन्दू-
स्तान विषयाए के लोगों की, बम, कमंचारियों की
और नारीलों के नेताओं की हो जो सबसे
पहले हर नद नम्बुताओं मे सभायत करने
का प्रयत्न करे प्रीर यह लेखतो गहे कि कोई
तनाव हो तो उस बबत उमके लिए काशर कदम
उठाएं।

SHRI VASANT SATHE (Akola) : I want to thank the Defence Minister for the very salutary measures which have been taken because this is a matter which cannot be treated either in an emotional manner or even lightly. It is a very sensitive issue. I can understand things when there are clashes between communities, civilians, in various fields; these incidents themselves are of serious nature. But it is altogether a different matter if there is clash between armed personnel and civilian personnel. That is the seriousness and that is why the delicacy also. I would not like to go into the details, it is no use doing that. The right thing for us to see now is only to see that the whole situation is brought under control and necessary atmosphere created.

I would like to say one thing. You have issued orders, as have appeared in the Press, asking the personnel to remain bound to barracks. One disturbing thing which came out in the newspapers was that the naval personnel could draw arms from the armoury on 27th morning. Sir, on the 26th this incident took place; curfew was imposed; everything was all right; everything was brought under control. Then it is reported that on 27th morning at 11 A.M. they could draw arms from the armoury. You know the seriousness of this because, if armed personnel could get arms from the armoury, then, it becomes a very dangerous thing; anything can happen. Therefore kindly go into this. There may be provocation or whatever it is. The whole committee will now go into it. We should see that in future no such incidents are repeated. There is need for some directions. I believe you will of course do it. But it is my humble suggestion that some strict direction must also be given that the officer concerned or Officer-commanding of the Area must see that these personnel have no access to the arms in the armoury. That must be done.

I hope, you will kindly consider it.

श्री जानकीबन राम : माहादय, मे जानकीबन कर
आज की मिति मे यह कहना उचित नहीं ममझना कि
जिन लोगों से यह घटना बढ़ गई, क्योंकि वह काम तो
इनकार्याली मैनिंग्टट का होगा, उम को देखना है।
यह बात जारी है कि जब इस तरह की कमिशन (उचित)
किसी स्थान पर हो जाती है, तो नंदी के प्रामनेना प्राप्ति
की सुरक्षा के लिये कुछ लोगों को आमं (हथियार)
दिये जाते हैं और यहाँ पर भी आमं (हथियार) दिये
गये हैं। जो हमें जानकारी मिली वहाँ को मिलिल मध्य-
कारियों ने कहा था कि नंदी के लोगों को मरके रखना
चाहिये समझता है। उन्होंने महायता हमको आवश्यक है।
लेकिन उस के बाद से यहाँ से यह आदेश दे दिया गया
है कि जिन लोगों को हथियार निरात आवश्यक
नहीं हों उनके पास से हथियार से लिये जायें, प्रीर
से लिये गये हैं।

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah) : Sir, what about the question of relief to the families of those who have been killed? This is very important. I have already handed over the telegram which I have received from the wife of the killed person; she has asked for relief. These families must be given immediate relief.

SHRI JAGJIVAN RAM : I will see that some immediate relief is given to the families of all those who have fallen victim in this.

12.37 hrs.

ESTIMATES COMMITTEE**TWENTY-SECOND REPORT AND MINUTES**

श्री लक्ष्माल (बिजोरे) : उपायकार्य मंत्रालय, में ग्रामको प्रनामन से प्राक्कलन समिति का निम्ननिविष्ट प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-मारांग प्रनामन करना है :

- (1) वित्त मंत्रालय—प्रनामांकों की मार्गे (सामान्य) —कार्य—मारांगों का पुनरीकाश—पर 22 बीं प्रतिवेदन ।
- (2) उपर्युक्त प्रतिवेदन से संबंधित समिति की वैठाकों के कार्यवाही मारांग ।

12.37½ hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE**EIGHTY-THIRD, EIGHTY-SIXTH AND NINETIETH REPORTS**

SHRI P. V. NARASIMHA RAO : (Hammond) : I beg to present the following Reports of the Public Accounts Committee :

(1) Eighty-third Report on action taken by Government on the recommendations contained in the Tenth Report on Export of Engineering Goods relating to the Ministry of Commerce.

(2) Eighty-sixth Report on paragraph 37 of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1975-76, Union Government (Railways) on Unauthorised Occupation of Railway Land.

(3) Ninetieth Report on action taken by Government on the recommendations contained in the Sixteenth Report on Fifth International Film Festival relating to the Ministry of Information and Broadcasting.

12.38 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377**(i) REPORTED RESEARCH INTO THERMO-NUCLEAR FUSION.**

SHRI D. D. DESAI (Kaira) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to bring to the notice of this august House an event that happened at the Oak Ridge National Laboratory, Princeton, U.S.A. which has the potential to remove poverty from the entire face of the earth where all sources of energy like firewood, coal, oil, hydro and uranium are getting exhausted while

the demand for them is growing at a fast rate. On August 1, a team of physicists led by Dr. Melvin Gottlieb, Director of the Plasma Physics Division of the Laboratory, heated up a mixture of heavy hydrogen atoms to the incredible temperature of 60 million degrees Centigrade—that is 10,000 times the temperature on the surface of the Sun—which, helped set off the fusion of these hydrogen nuclei to form helium and in the process release 180 times the energy used in achieving this temperature. Such controlled reaction once started can go on for ever—and without external stimuli. The raw material—heavy hydrogen—is available in plenty in sea water. One litre of sea water could provide energy equivalent of 300 litres of high grade gasoline. It is said that the break-through came much earlier than anticipated and that 'thermo-nuclear fusion under controlled conditions will become a reality in another decade'.

Because of the promise this break-through holds, of plenty of energy cheap and from inexhaustible source (sea water) and also because the process does not produce problems of pollution from residual radiation, it would be the Aladdin's lamp we have all been hoping for to provide cheap and plentiful energy to mankind in any part of the world. But a top U.S. scientist says : "This is the most difficult technological development ever undertaken by man for non-military purposes. It is too big for any country to do alone." For instance, the U.S. scientists in this experiment used an equipment devised by the Russians.

The need for international cooperation in research to make this dream of cheap and plentiful energy a reality early opens for us an opportunity to focus international attention on this one problem. India has scientists of calibre, so too many other nations in the world. The research on this is open to all. Therefore, I am sure this House will join me in requesting the Government that it takes the lead and proposes through an appeal international cooperative research on quickly transforming what is now a laboratory success into a great commercial venture to help the poor and the wretched of this world to see a brave new world of plenty within our life time.

(ii) NEED FOR EOUR-LANING OF ROAD BETWEEN PANVEL AND DEHU ROAD

SHRI S. R. DAMANI a (Sholapur) : Sir, the Bombay-Pune Road, National High Way No. 4, is a very important road and carries very heavy traffic, about 4300 vehicles per day, from Bombay towards Bangalore, Madras and Hyderabad. The Maharashtra Government

[Shri S. R. Damani]

suggested four-laning of this road even in the Fourth Plan period at a cost of Rs. 17.5 crores. The portion between Khopoli and Lonawala is particularly hazardous, zig-zag and steep-graded and a large number of accidents and breakdowns are daily occurrences; and hundreds of passengers are killed monthly. The Government of India approved the realignment of this portion as far back as March 1973. But implementation was not forthcoming. As a first step, the State Government proposed, to the Government of India to construct a two-lane carriage way that an estimated cost of just Rs. 3 crores. Considering the very heavy traffic on this National Highway, I suggest that (a) the work is of four-laning the road between Panel and Dahu Road; (b) realignment with a two-lane carriage way between Khopoli and Lonawala and (c) the construction of westerly diversion outside Pune City, can brook no further delay and the Government of India should take immediate action to implement these works.

श्री फिरोजी प्रसाद (बांसगांव): उपाय्यक भारतीय, मेरे पक्ष व्यवस्था का प्रबन्ध उठाना चाहता है।

उपाय्यक बहोदय : व्यवस्था यह है?

श्री फिरोजी प्रसाद : आप मूल लेखिये। अभी कुछ बदल दिनट पाएं थे यो राम व्यवस्था सिंधु ने काका कालेकर की रिपोर्ट पर बहस के लिए कहा था। मैंने भी उस पर लिख कर दिया है। जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि काका कालेकर की रिपोर्ट को लागू करेंगे।

उपाय्यक बहोदय : यह व्यवस्था का प्रबन्ध नहीं है, किसी भवय किसी ने कुछ कह दिया और आप इस तरह से उस के लिये रुक्ख हो जायेंगे, यह ठीक नहीं है।

Now Mr. Raj Narain.

(iii) REPORTED SELECTION OF AIRCRAFT FOR INDIAN AIR FORCE.

श्री राज नारायण (गय बरेली): श्रीमन्, मदन को तो ज्ञात ही है कि हमारी वायु सेना को अपने कुछ पुराने विमानों के बदल नये जहाज खरीदने की मद्दत जरूरत है। इसके लिये कार्रकार ने कई कंपनियों द्वारा बनाई दी। पिछले सैंचयन में हमारे विरुद्ध सदस्य श्री व्याप नदन मिश्र ने बालाल उड़ाया था कि विदेशी पत्रिकाओं में हलता है कि विमान को हम बना लें हैं, तबा उमके लिए कुछ कमीशन भी बांट देंगे। हम यह समझते हैं कि नीता तय करने के पहले इस विचार पर सवाल में प्रकाश डाला जायेगा।

यह पुरानी बहर व्याप ठीक नहीं थी, पर वह दिन पहले बम्बई के एक साताहिंक ममतावार पर ने बताया कि कास ने एक अच्छे प्रस्ताव को ढुकराया

गया है। कास के प्रस्ताव भी ने हमारे बहाव मंडी को पेरित जाने का निश्चय भी दिया था। विमान सूची से हमें यह भी जात हुआ है कि कास की विमान जगत में वाली कम्पनी, औ० की० मा०, के व्यापार ने घपने नये प्रस्ताव में कहा है कि उन की निराज एक—। कोई यह बही दीर्घी, तो साथ ही साथ उन के बदले नये विमान निराज 2000 को भी ऐसे संकेते भी देंगे। यहां यहां बातें। इस प्रस्ताव को अपनी मायता देते हुए उनकी सरकार ने भी लिखा था, पर इसका जबाब हम ने देर से और विना व्यापकता दिखाते हुए लिखा—इसका जबाब देर से दिया।

मात्र ही नाम विदेशी पत्रिकाओं में पता चला कि प्रमरोका बाह रहा है कि हमें विमान हवाई जहाज स्वीडेन में न मिले। सुनने में बात है कि सरकारी कम्पनी के जाग्मार विमान खरीदाराओं बाही है, जिन को यार पाप मान के बाद येरोप की वाय सेनाओं की सर्विस से हट जायेगा, मारी बहुपुराने दायर का है।

यह भी यह विनाजनक बात है कि काम के प्रियांत्र तथा स्वीडेन के विमान के ओल होते हुए भी ब्रायार विमान को ही लेने का निश्चय किया जा रहा है। बहर यह भी है कि इस में भारी कमीशन बदले की सामान्यता है। गोपनीयों हो रही है, लेकिन कोई जानकारी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में यह बात मार्ग देख के लिये बहुत ही ग्राही और विनाजनक है। एकली बात तो यह है कि देश के लिए यह बहुत व्यापक है कि वायु सेना के बीच ताक पुराने विमानों के बदले नये तरह के विमान हम बही दीर्घी, जो कि हमारी वायरात्रों को करीब बीमां साल तक पूरा करते रहे। पर इस के लिए हमें एक विमान के लिए नहीं रुक सकते जो कि अभी किडाइन ही किया जा रहा है, क्योंकि हमारे आवायाम के देश बहुत ही विवितातों और नये तरह के विमान तथा नियोजन खरीद रहे हैं, जिस से हम पाप बार हो सकते हैं। इसलिये हमें जी इस नये तरह के विमान की भी व्यापकता की भी व्यापकता है। मेरे ऐसे होने चाहिए कि उनके नये माडेन को ही हम बाब में आसानी से खरीद सकें तथा भारत में भी बना सकें।

हमारी बात यह है कि एक तरफ में तो सुपर पावर का दबाव पड़ रहा है कि नये तरह के विमान हमें न मिलें और दूसरी ओर सरकार के भीतर का एक "प्रैटर थ्रॅप" या "कॉकन" बाह रहा है कि एक पुराने विमान को हम बही दीर्घी। गोपनीयों ही रहा है, इसका कारण कानूना व्यापक है। सरकार से आपहूँ है कि उनके नये कानूनों से सवाल को अवश्य करायें।

श्रीमन्, मुझे कहने का भौका दिया जाये कि यह देश तबा यह सवाल इस बीते को जूप-चाप न देंगे, जिस में हमारे देश तबा इस भी वायसेना को एक पुराने देश का विमान दिया जा रहा है, जिस पर पलियां का 1500 करोड़ रुपयों का लब्ज है। जब कि और भी अच्छे विमान हमें लिन चाहते हैं। सरकार इस बात पर अपनी जिम्मेदारी हीत भी न बरामोंगे, जिसमें हमें किसी भी प्रकार

वाल लिया जाये कि हम बच्चे परीक्षित, लें लियातों की जगह पुराने लियात करीदें, तब बैचने वालों का वाला बाल में लिया जाए तब वह उन के नये लियात को हम करीदें, जो कि अभी सावित भी न लिया जाए हो । हवारा वाला लियात ऐसा होता चाहिए जो कि वह जुला ही और जिन की जुलिया सावित हो जाए हो । इस बात पर हम विषय में देख की हाजिर देखने को लैयार नहीं हैं ।

श्री लक्ष्मणलाल लिया (लेपेतराल) : मैं एक बात की सफाई देते हैं। मानवीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं ने पिछले बार में यह कहा था कि कर्मीजन बाटी नहीं । मैं ने ऐसा नहीं कहा था । मैंने कहा था कि कर्मीजन बाटी नहीं की परिपाटी है और यद्य पर्यावरण बाटी जाती है तो कर्मीजन राज्य को जाए, किसी व्यक्षित के हाथ न लगे ।

(iv) PUBLIC SCHOOL SYSTEM)

SHRI RAJ KRISHNA DAWN (Burdwan) : Sir, under rule 377, I mention the following matter of urgent public importance.

The coaching system in private schools is creating a gap within the society and day by day the gap is widening between the common men and the affluent. As has been seen, every person of privileged class is anxious to get his kid admitted in a private school by paying huge sums which are demanded in the guise of donations. While our leaders make loud promises for Indianisation, they are absolutely keeping their eyes and ears closed as to how the brains of innocent children are being washed. Instead of making them proud of their heritage, they are made to feel that their culture and way of living in Europe. The typical system adopted by these private schools imparts a perverted culture and makes middle-class sahibs intellectually subservient to half-digested ideas of the middle-class west. Therefore, it is very necessary to go into the details of the functioning of such schools and to determine precisely what kind of a person is created by such institutions. This is a subject which has aroused many suspicions in the minds of the public in general about the way these schools are in operation within the country. They demand higher fees and expect the boys to be better dressed and the medium in all subjects in English. Thereby they create communities of the affluent elites. By destroying their own roots of origin, the boys are alienated from their own people, and remain so far the rest of their life.

It is precisely to avoid the turning out of alienated and rootless young men

that 'parents in developed countries have shunned the ideas of public schools system. Yet in India where we need consciously to promote integration, the State continues to tolerate and assist special schools, which turn out potential brown sahibs. It has gone so far as to maintain such schools by direct funding and patronising such a system. It is the time that we should seriously think of discarding such a system which is cutting at the very root of integration and making our children subverters of their own culture and heritage. Although the Centre has not been able to feel the pulse and has realised the extent of damage which such private schools are doing to the nation. Perhaps primarily this is the reason that they have already adopted a unanimous resolution in Delhi Metropolitan Council where they have suggested doing away with the Public School Education System to bring uniformity in the standard of education and have recommended that such schools should be brought at par with those of the Government of Government-aided schools.

It is strongly felt that the Centre should move fast in scrapping out the system of public school education so as to bring an end to corrupt practices by the management of these public institutions throughout India.

(v) REPORTED DEATHS AND HEAVY LOSSES DUE TO RAIN IN HIMACHAL PRADESH.

SHRI DURGA CHAND (Kangra) : I am thankful to the Chair for having permitted me to raise this matter of urgent public importance under rule 377....

This year, Himachal Pradesh has faced heavy and incessant rains causing death of 141 persons. Hundreds of cattle have perished, thousands of houses have collapsed, standing crops have been destroyed and there is heavy erosion of fertile lands, damage to roads, culverts and bridges by landslides, particularly in Kangra, Chamba, Mandi, Bilaspur, Hamirpur and Solan District. The total loss as per reports amounts to several crores of rupees. This is too much for a backward State to bear such a heavy loss on account of natural calamities.

There is an urgent need to provide adequate funds from the Central Exchequer for relief measures in the worst affected regions in the State and to send a Central Study Team to make an on the spot assessment of the havoc wrought by the heavy rains in this State and the damage caused by the earthquake shocks in the Dharamsala area (District Kangra).

12.56 hrs.

PRESS COUNCIL BILL—contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We now take up further consideration of the following motion moved by Shri L.K. Advani on the 24th August, 1978, namely :

"That the Bill to establish a Press Council for the purpose of preserving the freedom of the Press and of maintaining and improving the standards of newspapers and news agencies in India, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Shri Venkataraman to continue.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : About the telephone system in Calcutta, I have given notice.

MR. DEPUTY-SPEAKER : A hundred notices are there, including yours.

श्री राज नारायण (राज बरेनी) : मैंने एक नियम आसे करता है कि प्रधार कोंसे के हैं 31 तारीख को रिटार्न हो रहे हैं। सरकार इस पर एक बयान याहां पर दें। इस में दूसरी की सुरक्षा का तबाल है।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) : It is an urgent matter which is going to be decided by the 31st. This matter has to be brought up before the House before that date and the expert committee report has also to be placed on the Table of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have called Shri Venkataraman to continue his speech on the Press Council Bill.

SHRI R. VENKATARAMAN (Madras South) : I was saying last evening that the public have a right to independent and objective news and fair comment. One of the factors which militates against an objective presentation of news is the self-interest of the newspaper proprietors, and the self-interest is brought about by other extraneous interests like business which the proprietors of the newspapers have. Therefore, all over the world, wherever there is a free press, there has been an agitation for diversification of the ownership of the newspapers and for controlling the monopolistic tendencies in the press.

The Press Council Act of 1965 stated in section 12A that the object was :

"to study the developments which may tend towards monopoly or concentration of ownership of newspapers and news agencies, including a study of the ownership or financial structure of newspapers or news agencies, and if necessary to suggest remedies therefor."

12.59 hrs.

[SHRI AMITABH KRISHNA IN THE Chair]

The hon. Minister, while introducing the Bill here, said that he had more or less faithfully carried out the provisions of the old Act, and he mentioned only one or two deviations, but he omitted to mention this very serious deviation which he has made in the Bill now before the House.

If you refer to Clause 13(i) relating to monopolies, the power of the Press Council under the Bill before the House is :

"to concern itself with developments such as concentration of or other aspects of ownership of newspapers and news agencies which may affect the independence of the press";.

13.00 hrs.

I want you to kindly look at the difference in the language. In the old Act, the Press Council was authorised to study and make recommendations for the avoidance of monopoly and concentration. In the new Bill before the House, the Press Council is asked only to concern itself with developments such as concentration. I have looked into some of the judicial dictionaries of Words and Phrases and I have found that there is no judicial definition of the word "concern" as a transitive verb. There is a definition in the dictionaries where it is a noun that "concern" means anxiety. In certain cases where there are contracts and a person is said to be a "concerned" with the contract, it shows the interest of the person in the contract. But "to concern itself" would only mean, according to the Oxford Dictionary, to interest oneself in or about the matter.

So, don't you see the great difference between the power of the old Press Council to study the monopolistic tendencies and the concentration of power and to make recommendations and of the Press Council under the present Bill, which shall concern itself, that is, interest itself? Sir, I am making this point because if the Press Council tomorrow takes up any issue of concentration of, or monopolistic tendencies in, the press, the press concerned will go and move the Supreme Court and say that it is beyond the jurisdiction of the Press Council, because it has no power to study, as it was in the original Act, it has no power to make recommendations, as was the position in the original Act, but it can only concern itself, that is to say, interest itself; it will be interested in knowing who is the owner and what is the extent of his holding; nothing more. I do not know why the hon. Minister thought it necessary to deviate from the old section, when he has *ad idem* adopted them in respect of all the other

clauses. It amounts to weakening of the powers of the Press Council. Unless the Government wanted to be soft towards some press barons, there is no other justification whatsoever for changing the clause, as it stood in the Act of 1905, into this almost anaemic clause, saying that it shall concern itself.

I shall briefly refer to the position in England. There the Press Council shall have the power to report publicly on developments that may tend towards greater concentration or monopoly in the press, including changes in ownership, control, and growth of press undertakings and too publish statistical information relating thereto. The British people believe that public opinion is a far greater check against abuse than any legislation. Therefore, the British people have provided that if statistical information regarding the ownership of newspapers is published widely, then it will give rise to an opinion in the country, both against the tendency towards growth of monopoly as well as against the concentration in a few hands. Therefore, they have relied upon public opinion, rather than legislation, as a check.

But, what do we do here? We follow, neither the British pattern, in which we will create public opinion by publishing all the information regarding the ownership and control of the press, nor do we follow a pattern which was adopted in the last Press Council Act, in which the Press Council was specifically given the powers to study the growth of monopolistic tendencies and to make recommendations therefor. Today, in my opinion, the Press Council cannot make any recommendations with regard to the concentration of power and monopolistic tendencies in the press with the clause as it stands.

As you know, in the interpretation of statutes, if there was a previous statute and that statute had been amended or changed, then the interpretation of the new statute is that the Parliament did not want an old law to continue and they enacted a new law, different from what the original law was. Therefore, the point really is, if you want that the Press Council should have the power to study, then you must adopt either the clause which was in the original Act or you must adopt the clause which the Press Council in England has. If you do not adopt these two things, the fact that there is a clause saying that the Press Council "shall concern itself" is mere verbiage and will have no effect and no value.

जी निम्नलिखित जीवं (सिवनी) : समापत्ति महोन्नप्य, मैं इस विवेद्य के सामने के लिए अंग्रेजी भी की जावाहाद देताहूँ। जहाँ तक जैसा का सावाल है,

प्रेस की वृद्धता फिल्सी प्रकार से नकारी नहीं का उकाती। यह लोर्ड स्टेट कहताही है। यह अपने जाते में बहुत अधिकारी, बहुत बलवाही है। कभी कभी वे भी यहाँ देता है कि अधिक भी यह यह लोर्ड देते हैं कि इस के साथ कोई भी सावध दिक्कत नहीं दिया जाएगा तो अब चूप हो कर बैठ जाते हैं और यद्यकि उन का यह सावध इस में नहीं आता। यह भी अपने जाते में ऐसे की अधिकता का परिचयापक है। लेकिन यहाँ जानित होती है वहाँ बलित के साथ साथ लंबम की भी बहुत सावधकता होती है। यह दो बलितदो जानने सामने आयी हों, एक बलित ब्रैस की ओर ब्रैस भी देता विस के पास पैसा हो और इसी सरकार की बलित तो इन दोनों बलितदों के बीच में बहुत सावध की भी बहुत सावधकता होती है। इस संतुष्टम में इस बात की भी सावधकता होती है कि जनमानस इस के कारण पीड़ित न हो।

समाचारों के बारे में बहुत प्रभावशाली दंड से कहा जाता है कि समाचार क्या है? यह लूटा आदमी को काटता है तो समाचार नहीं बतता, लेकिन यदि आदमी कुते को काट जाता है तो समाचार बन जाता है। कई बार समाचार-पत्रों में इसने सततनीचें चीजें पाती हैं कि जनमानस को बदल पूछते करने में से बहुत सावधकता होती है। इसनिए जो पहले सेंस में नहीं बलिक सेंसेविलतमें ज्ञाना विवाद सद्वाते हैं, उनकी भी रोक बाय की सावधकता है। लेकिन यह रोकबाय किंचि कानून न होकर वे [प्रधान मंत्री को द्वारा अनुकूलित करें।

भाजकल पीत पलकारिता बहुत बड़ती चली जाती है। बहुत से पीत पद तो अनुभात और आलंकारिक भाषा में इस काफर लिप्त रहते हैं कि उनकी इस प्रवृत्ति पर धूकुम की सावधकता है। लेकिन प्रैस की स्वतंत्रता का गतान छोटा जाए, उन के भ्रष्टाकारों का धरखाल हो। प्रैस भी अपनी स्वतंत्रता का दुखप्रयोग न करे, अपनी भ्रष्टाकारों का दुखप्रयोग न करे। इसनिए इस सम्बन्ध में इस प्रैस काउंसिल विल को ठीक ढंग से लाने की चेष्टा की गयी है। बहुत विवाद जाता था पहले कि इसका गठन किस प्रकार से हो। कुछ लोगों का मत था कि प्राप्त के स्वार पर एक काउंसिल होती चाहिए। लेकिन अन्ततोत्तरता विवाद विवरणों के बाद जो तथ्य सामने आए उन में पहले के सेसद सरस्यों की समिति की जो लिकारिया भी उस के अपर भी एक सुझाव यहाँ पर आया कि तीन व्यक्तियों का दैनन्दिन और वह एक चैयरमैन को बनोनीत करे। मैं समझता हूँ कि इस से एक योग्य समाप्ति, निष्पक्ष समाप्ति और कमेंट समाप्ति प्रैस काउंसिल को प्राप्त हो दी सकता।

ममी तक वही प्रेस जानी होती भी जिसके सम्बन्धी जीवी जानी वर्ग से होता था कि अपने भारत में प्रभावशाली नहीं थी। जेलीय भाषाओं की उस में अध्यहेतुना होती थी। अब जेलीय भाषाओं, को, उन के सम्बन्धों को और न कोले ल सम्बन्धों को बलिक अब जीवी पद करारों को भी उस में प्रतिनिधित्व देकर इस को बाल्टव में एक प्रतिनिधित्व दें।

बतावे की चेष्टा की गई है। इस में बतावी प्रकाश तात्पर होते हैं, समाचार तात्पर होते हैं, संचालक भी जो विविहैत हैं तब की तीव्र बतावी वेब बाटा जाया है, बड़े बाध्यक और लोटे, उनमें से दो दो रखे गए हैं, तात्पर एवंती का एक विविहैत व्यवस्थित विषय जान रहता है ऐसे तीन और तात्पर पांच, इस प्रकार से जो इसका गठन है उस गठन में इस बात की चेष्टा की गई है कि सभी प्रकाश के साथ और सभी रिपोर्टर के साथ इस में प्रतिविवृत्ति प्राप्त कर सके ताकि उत्तराधितनिविक्षण सूचना रूप से विकलित हो सके और वह एक स्टैंडर्ड, एक कोड आफ कंडक्ट भी बना सके पर्याप्तार्गों के लिए। इस बारे में बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत होना चाहिए अब यह नहीं। कुछ लोग बाहर से कि विविहैत स्वतंत्रता तब को प्रदान की जाए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो स्तर पीत पद कारिता का पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है और जैसा मैंने कहा सेसलन-विषय की जो एक प्रवृत्ति रहती है उस के कारण एक कोड आफ कंडक्ट का होना बहुत आवश्यक है।

इन सभी दृष्टियों से इस के बितने प्राप्तियां किए गए हैं, बहुत संतुलित ढंग से किए गए हैं और उस के लिए मैं मरी महोदय को बधाई देता हूँ कि उन्होंने श्री परिवेद्य की तुलसीपाता का प्रयाप्त किया है जिस को प्राप्तिकाल में जब दर्दस्ती श्रीम का गता थांड कर समाप्त कर दिया गया था।

SHRI C. K. CHANDRAPPA (Cunninghame) : I support this Bill. But, while supporting the Bill, I would like to make a few observations.

First of all we are not discussing the Press Council Bill in a vacuum. There is a background. We had a Press Council according to a parliamentary statute and that was working in this country for more than 10 years and then it was scrapped. But it is useful for us to know or for us to look back what happened during the operation of that Press Council in the country. We had succeeded in fulfilling the objectives for which the Press Council was made. Why I am saying so is because I have gone through this Bill and all that which is said is laudable. It is like a good ornament but whether it is going to serve the purpose for which it is being enacted, I have my own doubts.

First of all, the Bill says that this is to help newspapers and news agencies to maintain their independence. For making the Press independent this enactment is being brought forward. But is it possible really in the situation as we have it in our country to-day? Because the important newspapers in the country are owned by industrial houses. That is why the question of diffusion of ownership and delinking the press from the industrial

houses becomes a major issue. When we speak of the press freedom. So long as it is not a reality. You have expressed yourself for the delinking of the press from the industrial houses. So long that is not done. I cannot visualise that we will have a free press.

Sometimes some accident may occur and due to political reasons, the industrialist may take a stand; that is laudable. But that is an accident. Here Shri Venkatraman pointed out that thing. When you speak of the concern that the Press Council should have about the pattern of ownership, you do not seem to have gone further in that. There I would like to disagree with Mr. Venkataraman also.

According to him, he wanted to study the pattern of ownership. Earlier the Press Council was making recommendations to Government from time to time. But, what happened to the recommendations that they have made? You know that nothing was implemented. In a society like this, where press is part of an industrial house—if the press, by and large, is run by the industrial house—it will not serve the purpose of creating a free and independent press in our country. Take the industrial houses. They run not only the press but also the hospitals. There are temples run by them; there are social welfare organisations and there are schools, colleges and everything as also newspaper. It is one of the status symbols for an industrial house to have a temple—Lakshmi Narain Temple by Birla. (Interruptions). You may not know that ever God is being sold in retail and wholesale. That is the problem.

So, my point is this. In a Bill like this, you are not going to make much headway unless you have a political will to diffuse the ownership of the newspapers and delink it from the business house; I am sure, you—not the minister but the Janata Party Government—will not be able to do that.

Coming to another aspect of the matter, recently, I was very much amazed to know about the P.T.I. I think it is now a part of the Non-aligned News Pool. We now have got rid of the Samachar. We wanted to make the news agency more independent. Look at it as to how they reported the Non-aligned Conference of the Foreign Ministers which took place in Belgrade. That was one of the most distorted version. Even the press in U.S. and in U.K. reported that much more fairly. What was said about the role of Cuba in Africa? Here the monopoly press of the industrial house and their masters, the imperialists, wanted to depict Cuba as an aggressor in Africa. That was done in most unashamed manner. And you want to call it an independent news agency. It is not possible. These limitations you will have when you enact

this legislation. Even then it is good that at least we speak about press freedom and about the necessity of the independence of a press.

As I said at the beginning, I extend my support. I have of course moved my amendments specifically to improve the legislation further. If the Minister accepts my amendment to the legislation regarding the monopoly houses, the ownership of the press and having more representations of the journalists, I will be very happy about it.

When I move my amendments at that time I shall refer to them.

बी औल ब्रकात स्वामी (बहराइच) : समापनि महोदय, मैं इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूँ और मंत्री महोदय को ब्राह्मणाद देता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक को हासी सीधे में पारित करने के लिये हम को प्रबोधर दिया। मैं इस बिल से इसको महत्वपूर्ण मानता हूँ कि हमारे पास नेपाल से विद्यालय प्रकट किया है। प्रजातांत्र के लिये यह नियात प्रावस्यक है कि उस में मनुष्यों की दारी स्वतंत्र रहे, प्रेस, मन वज्र पर पूरी स्वतंत्रता के साथ मौलिक और लैखिक कृप में विचार करने और प्रकट करने की स्वतंत्रता रही चाहिए। यह स्टेटप्रियं है, तानाउणही है, बाहे लिसी भी कृप में है, उनको प्रैस की स्वतंत्रता की प्रावस्यकता नहीं है, अन्तिम भी। बाहे यह एक भारतीय की विदेटप्रिय हो या स्टेट की विदेटप्रिय हो, जैसे ब्राह्मण और रिया में प्रैस की स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं है। यही मोरोमली और विग हाउसेज की बात आप कर रहे हैं, परन्तु वह मनुष्यों के विद्यार्थी और स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं है। आगे स्वतंत्रता पूर्णक और प्रबोधर अवसर कर दे तो बड़े बड़े स्टाइलिस्ट और विस्टोरियम जैसे भी बाल दिये गये, आप यहाँ स्वतंत्रता के लिए गए होंगे।

SHRI :C. K. CHANDRAPPAN : Do you seriously believe it or because you just want to score a point that is why you are saying all that?

MR. CHAIRMAN : Let there be no interruptions otherwise, Mr. Tyagi, you will lose your time.

बी औल ब्रकात स्वामी : मैं इसीलिये कहता हूँ कि प्रगर प्रैस की स्वतंत्रता रही है तो प्रजातांत्र मुरक्कित रहता है। 19 महीने की समापनिलाइन स्थिति के द्वारा प्रैस पर सैंसदराजप लगाया गया और प्रैस देश की वास्तविक स्थिति को सरकार के सामने नहीं रख सका, इसीलिये सरकार दोषेरे में भी और उसको विनाश का मुंह देखना पड़ा। प्रैस का महत्वपूर्ण कार्य मह भी है कि वह जनता और सरकार का मार्गदर्शन करे। इसके लिये भी उसकी स्वतंत्रता की प्रावस्यकता है।

मैं इसीलिये भी इस विधेयक का समर्थन करता हूँ कि आपने किसी तरह से प्रैस की स्वतंत्रता के

लिये प्रैस कार्डिसिल की स्वाप्नता भी है। यही इसका लक्ष्य है। मैं बताता चाहता हूँ कि वैस की स्वतंत्रता के 3 लक्ष हैं लोग, लालू और जय। भाज सारांशवर्ष के किसी तो समाचार-पत्र इससे नुस्खा है? बहु समाचार-पत्र इन लोगों कालों से नुस्खा है विनाश व्यक्ति गत क्षम में एक पारमी मार्गदर्शक है, समाज जो विग हाउसेज और नेपालनेपाल की स्टोरेट पर रहे हैं या विदेशी धन के बाहार पर वहाँ जन रहे हैं, वह स्वतंत्र नहीं है और आपकी प्रैस कार्डिसिल के द्वारा स्वतंत्र नहीं है और आपकी प्रैस कार्डिसिल जो जनकाल से जनता को स्वतंत्र विचार प्रिल सके? यह तो और पर जो स्वतंत्र रूप से जनते वाले कुछ समाचार-पत्र हैं, जोकि व्यक्तिगत हैं, उन के सामने भी बाहा सा प्रबोधन है और वह है विजापन का। इन्हे 19 महीने की समापनिलाइन स्थिति में देखा है कि सरकार ने उनका गला घोटने के लिये प्रपती विजापन नीति को देता कहा बना दिया लिये तो उन को सरकारी विजापन न विल सके। उसका परिणाम वह हुआ कि दिल्ली में भी ऐसे समाचार-पत्र, "बी ब्रिजिंग" भावित जो स्वतंत्र विचार व्यक्त करते हैं, वह समाप्त हो गये।

इस में प्रैस कार्डिसिल विल में वह द्वारा कही भी नहीं है कि सरकार की विजापन नीति में वह होगा कि कोई भी सरकार आये वह नियात नीति के द्वारा सभी को बनने विजापन देंगी, प्रकाशित नहीं कर सकेंगी, ऐसा प्रगर इस बिल में ही तो टीक रहेगा।

बर्देमान विजापन नीति के अन्तर्गत समाचार-पत्रों को विजापन उनकी सकलेतन के प्रावश्यक पर दिये जाते हैं। जिन समाचार पत्रों के पास ज्ञाना धन है, जिन्हें विग हाउसेज चलाते हैं, मल्टी-नेशनलज जिनके पीछे हैं, विदेशी ताकतें जिनके पीछे हैं, यह स्वामाधिक है कि उनकी सकलेतन ज्ञाना होगी। लेकिन जिन समाचार पत्रों की पीछे हैं, जो व्यक्तिगत समाचार पत्र हैं, उनकी सकलेतन कम होती है और इस लिए उन्हें विजापन नहीं मिलते हैं, जो सार जिक्र विजापन उन्हें को मिलते हैं, जो प्रैस की स्वतंत्रता का गला घोटते हैं, जिन ने द्वारा व्यक्ति और स्वतंत्र कृप से समाचार नहीं दिये जाते हैं। यदि सरकार की इच्छा है कि प्रैस स्वतंत्र रहे, तो उसे इस बारे में आवश्यक प्रावधान करना चाहिए।

प्रैस कार्डिसिल को यह भी व्यक्तिकर दिया जाना चाहिये कि कोई समाचार-पत्र जाहे लिसी व्यक्तिगत मालिक का हो, किसी विग हाउस का हो या मल्टी-नेशनल का हो, उस के सम्पादक की कलम पर कोई प्रतिबंध न लगाया जा सके। शो बर्डीज ने कुछ लिखा, तो विग हाउस ने उन्हें निकाल दिया। प्रैस कार्डिसिल को यह व्यक्तिकर करने का प्रयत्न होता चाहिए कि प्रगर कोई सम्पादक लिसी विग विजापन की नीति के बिलाक सम्पादकीय नियता है, या विचार व्यक्त करता है, तो उस के बिलाक कोई कार्यशाही न की जा सके, उसकी रोडी-रोडी पर

कोई बतार न पाये। भाज विचारित यह है कि सम्बादक और पत्र-प्रतिनिधि वर्ग वार्षिकों की नियां दो देख कर ही समाचार बताते हैं।

प्रैस कॉमिशन के अधिकारों में एक महत्वपूर्ण बात सम्बिल होने से यह गई है। राष्ट्रीय एकता की समाचार-पत्र वार्षिक भारत और उत्तर भारत, हिन्दी और अंग्रेजी, हिन्दी और अंग्रेजी के नाम पर भावनामें उत्पादने की कोशिश करते हैं, ताकि इस देश की एकता न रुके पाये। प्रैस कॉमिशन को इस बारे में समर्पित अवस्था करन का अधिकार भी होना होना चाहिए।

प्रैस कॉमिशन के अधिकार में यह भी हो कि समाचारपत्र में समाचार या तो उपर और अपर लिये, तो वह पूर्ण होना चाहिए, एकांशी नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि कई समाचार पत्रों में अपूरे या तोड़-परोड़ कर लिये जाते हैं। वे समाचार पत्र का उतना ही बंध प्रकाशित करते हैं, जिस से उन के विचार का समर्पन होता है। जो हिस्सा उनके प्रपञ्च को सर्व करता है, केवल उनना ही हिस्सा—जपने यत्पत्र का हिस्सा है—कई समाचार पत्रों में छपता है, जिस से जनता आत्मा में रुकी है। जो समाचार पत्र पूरा समाचार नहीं देते हैं, वे प्रैस कॉमिशन को उन के विचार कार्यवाही करने का अधिकार होना चाहिए, ताकि पूरा समाचार जनता के सामने पाये।

यह विशेष लाने के लिए वै मंत्री भद्रोली को बध्यवाद देता हूँ और सामग्री भी बध्यवाद देता हूँ कि आप ने युवा लोगों के लिए लक्ष्य दिया।

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Kolkata): Madam, Chairman, while welcoming major portion of the Press Council Bill, as proposed in this House, I would like to make some observations and suggestions.

Madam, 'Freedom of the Press' is a must, Here, from this Press Council Bill, we see that this will be mainly controlled by the Central Government and there are too many restrictions for controlling the Press Council. The Press Council should really be an independent body under whose purview even, radios, televisions, all newspapers, journals and the whole mass media should come in. In England there has been legislation even in 1977, that is, last year in this regard. This is also the case in the U.S.A. Radios and televisions are under the control of their Press Council. Here it is said regarding the objects that it shall preserve the freedom of the press and maintain and improve the standards of newspapers and news agencies in India. I wish to submit that all journals, radios and televisions should come within the purview of this Press Council. In the past, there were certain restrictions.

But if there are certain restrictions even now, if there are controlling factors, under which they are to be brought up, the Press Council cannot act freely. The Press Council should be given wide powers to see that the freedom of the press is achieved in real terms.

Then, the freedom of the press will not be there if there is individual ownership of newspapers. By individual ownership, I mean, certain newspapers are owned by Goenkas, Bangurs etc. and other privated limited companies. This is also to be considered as individual ownership. The Press Council should be empowered to see that the individual ownership of the newspaper is done away with. The Press Commission of U.K. has been given wide powers and we should see that the Press Council in India is empowered fully to achieve these objectives.

Sir, as we know, the Press Council in India was suspended some time back; that was very unfortunate for all of us and the nation. When this Bill is again before the House, it should have been brought in a comprehensive way and the Press Council should have full autonomy in all its administrative and other matters and should have ample powers to work freely. The Government of India should not interfere in their affairs and should not impose limits on them that they will go upto this limit and not beyond that. They should be given suitable powers so that they are able to achieve the objectives enumerated in the Bill that is being enacted.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, as it is, the objectives of this Bill are very limited and the scope of this Bill is very small; the hon. Minister will bear me out. The objectives are only to improve the standards of newspapers and news agencies in India. The objectives should be to improve, to enlarge the newspaper industry as a whole, and bring about the required improvements in the working of the mass media, so that they can reach the people in an objective manner. The mass media would include the television and broadcasting and as I said, these should also come under the purview of the Press Council. If this is not done, we would be able to achieve only partial freedom of the press and not full freedom.

As I said earlier, the Press Council should be fully empowered to do away with the private ownership of the newspaper. Where there is private ownership of any particular newspaper, the editors and reporters cannot give vent to their views freely and fearlessly. It is, therefore very essential that every effort should be made to do away with the private ownership and that should be one of the objectives of the Press Council.

I have got many other things to say, but I shall speak at the time of discussion on my amendments. With these words, I conclude.

बा० राजकीय लिह (भागलपुर) : मतभागिता, महोदय, प्रेस कौसिल का जा बिल यहां पर उपस्थित किया गया है, यह हमारे भवी जी का सोचायाम है कि संसद में स्वतंत्रता के सम्बन्ध में जिन्हे विवेक की उनको उपस्थित करने का उद्देश थी अपराध ग्रातंत्र गया है। प्रजातंत्र के प्रति तामाज, इसों ने कहा है :

"Loss of liberty to mind is worse than death. Death is not the greatest calamity. There are still more terrible calamities for the brave ones who, if need be, are prepared to lay down their lives for the noble cause of freedom and liberty".

यह हमारा सीधाया है कि आज की माननीय भवी जी के प्रयत्न से प्रेस परिवद का नुनज्ञम हो रहा है। जिस प्रकार वे 1977 में भारतवर्ष में स्वतंत्रता का नुनज्ञम हुआ उसी प्रकार 11 वर्षों के बाद और 19 महीने की इमरजेंसी के बाद प्रेस परिवद का नुनज्ञम हुआ है। प्रेस की आजाइना के लिए यद्यपि हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री नेहरू जी ने बहुत कहु कहा था, लेकिन किर भी उनको प्रेस कानूनकानेवाल मंटर ऐक बनाना पका था। यह हमारा सीधाया है कि माननीय भवी जी के प्रेस प्राक्षेपित्वन नैठर प्रेस की निर्देश कर रहिए हैं। यद्यपि नेहरू जी ने कहा था :

"I would rather have a completely free Press with all the dangers involved in the wrong use of freedom than a suppressed or regulated Press."

लेकिन उनको भी प्रेस पर कुछ आजाइने उपस्थित करनी पड़ी जी और हाल आजाइने स्वतंत्र की आज भव ने स्वतंत्रता के लिए बोल रहे हैं उनको युक्तार मुस्त हाताता है कि कल तक ये प्रेस की नुसारों का सर्वानन्द कर रहे हैं जो आज आज की स्वतंत्रता का सर्वानन्द कर रहे हैं। पर दूर ते ही तकी लेकिन दुर्दृष्ट आये—इतना ही कहा।

वास्तव में आज को प्रेस का स्वतंत्रता इन बत्तें है उनको भी देखने की जरूरत है तभी प्रेस की स्वतंत्रता एह सकती है। आज इनियर लैवेज के लेखों 23, 5 परसेट हैं। नेटोरीलिटन रिटायर, कलकत्ता, लख्नौ, यात्रा भ्रम लिंगी में 31, 2 परसेट है और एक आज से कोर्ट की आवाही के बो टाउन ही उनमें 11, 3 परसेट हैं। तो यह बात की है कि आज में रखना होगा कि सेक्यूरिटी-नैत जो है वह कोइ इन्हाँ इन्हाँ के लिए है, प्रधान वेट है इसनिए अब तक सेक्यूरिटी-नैतों की स्वतंत्रता के साथ आरत की जरूरत की स्वतंत्रता की जाहा जाये तो यह स्कूलर इन्वेलेट्स को साथ करना होगा यान्हों में जो करोड़ी गोरीब लोग हैं उनके लिए सेक्यूरिटी-नैतों की स्वतंत्रता शून्यवेत है।

इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत ये तो परिवद के गठन के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं लेकिन यान नेहे की आवायकता है कि यहीं इसके लिए उसको सतानिरेक्षा की होना चाहिए और स्वामित्वनिरेक्षा भी होना चाहिए। सतानिरेक्षा करने के लिए संबूद्ध प्रबन्ध सतीति ने जो रिपोर्ट थी है वह उसको सरकार के बाहरीत नहीं है। यह भी पीर मह एक बहुत बड़ी बात है। यान देखेंगे कि भगवर सरकार भी निरकृत हो जाये तो प्रेस परिवद सरकार के विवाद भी अनुसंधान कर सकती है लेकिन यहां हीता भगवर प्रेस परिवद के विषय को सरकारी कोर्ट से दैवत नहीं होना पड़ता यहां लिया जायेगा—यह मैत्रियिक लियात है। इसलिए प्रेस परिवद भी सतानिरेक्षा करने की जो बात करी गई है पूर्व तो पहला ये तो कौनतों जी या उसके लिए भी रिपोर्ट के पेज 53 पर कहा गया था :

"Press could be free only when the Government keeps away from it, nor is the Press above the law of the land..."

यहें थीक बात है कि प्रेस की यहां के कानून का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है लेकिन सत्ता से ये भी स्वतंत्र होना ही चाहिए। मैं समझता हूँ भगवर संबूद्ध में प्रेस की स्वतंत्रता देना चाहते हैं तो सत्ता से उसको हटाना होया लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता की दूसरी बात भी है कि उसके स्वामित्वनिरेक्षा भी होना चाहिए।

"Press Council would never be able to discipline the Press, unless it was de-linked from Big Business."

भगवर दाटा, विवादी भीर जैन और सरायम्पेटों के लैस बतते रहे तो ये विवादित में प्रेस की स्वतंत्रता का अध्यै बेकार है। इस लिए संबूद्ध में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उसका लाती लियोंके ताप्तात्त्व या स्वामित्वनिरेक्षा भी होना चाहिए।

"A definite danger exists of news being twisted to serve the personal interests of the owners."

इसी लिए यह प्रावस्थक था—प्रेस कीसें ने कहा था—

"If you cannot do anything with the ownership you must do with the management of newspapers."

वह इस पर विग-विजेते वालों का एकाधिकार रहेगा, जो यह प्रेस की स्वतंत्रता के बाल पैकीपतियों के स्वामित्व और उनके निहित स्वालों को पूरा करने के लिए होगा। इसी लिए देरा निकलन है कि यहां आज आज के लिए प्रेस वरियर बनाई गई है वहां जोक्यूरी स्टर पर—जोक्यूरी जात फैल एक देव नहीं है, बल्कि एक महा देव है—सेक्यूरिटी प्रेस कानून बनाई जाये, एक नेतृत्व रविस्टर रखा जाय।

इसी सम्बन्ध में ऐसे एक बीज चीज देखी है—
जिसे संकुल ग्रंथार समिति ने दिया है। हमारे
वासनीय मानवसंकर लाइब्रेरी और दो वर्ष सदस्यों
ने भोट-आजाइसेट दिया है—कोइ धारक कानून
के बारे में। वह कोइ लाइब्रेरी कानून बीज है?
हम समझते हैं कि जो सरकारी की वापी के उपायक
है—उन को स्वयं बनाने विद्युत के साथ-साथ कर्तव्य
के लिए आवार-नहिंता बनानी चाहिए, हमें उन पर
कोई चीज लादी नहीं चाहिए....

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

डा० राजीव लिख : मैं एक मिनट और
लेना चाहूंगा—स्लाइ 14 (1) में—

Decision of Press Council beyond courts.

MR. CHAIRMAN : You have given notice for an amendment. You can speak on your amendment. Please conclude your general remarks.

डा० राजीव लिख : इस लिए मैं एक बीज
कहना चाहता हूँ—

Decision of Press Council Beyond courts.

मैं समझता हूँ—यह बहलत है। ब्रेस कीमिंग भी
ताजागाही के दास्ते पर या सकती है, इसलिए
उस का आवालन को छार करन नहीं होना चाहिए।
भारी हाल में अमरीका के एक प्रोफेसर आये थे—
एक लेखिकार हमारा पा—“Judiciary can save
the Press”. उन्होंने कहा था है—“The
judiciary can provide “salvation”
for the Indian Press from Governmental
Pressure.”

इसलिए मैं समझता हूँ—माननीय भंडी जी
का यह कहना कि ब्रेस कीमिंग के लिए कोइ का
दबावाव करन का दिया जाय, मैं समझता हूँ—यह
कोई नहीं होगा।

इन वाक्यों के साथ मैं इस विदेशक का हृदय
से स्वागत करता हूँ।

भी राज कुल (भरतपुर) : माननीय
सभापति जी, जो विदेशक ब्रेस की स्वतन्त्रता, ब्रेस
के स्तर को लंबा करने के लिए लाया था है, मैं
उसका स्वागत करता हूँ।

लेफिन, सचावपति जी, सचाव यह है कि
हम ब्रेस के स्तर को लंबा रखना चाहते हैं ही भीर
हमारी यह स्वतन्त्रता भी सुरक्षित रहे—इस का
प्रयत्न भी करता चाहते हैं। लेफिन जो समाज की
बहालान चिना है और जो समाज की बहालान देना
है—उनका दिलेक्षण ब्रेस पर हो—यह कोई रोक
नहीं सकता है। साज स्वतन्त्रता का लंबे लंबा
है? अगर स्वतन्त्रता का लंबे करता करता करता

हस्तलेप करता नहीं है, तो मैं बहलता हूँ—यह
बातों निर्वाचित सरकार है। आविर लखार बनाता
की निर्वाचित सरकार है और सरकार का भी
मपना कुछ दृष्टिकोण होता है। स्वतन्त्रता का
लंबे केवल इतना हीता चाहिए कि जो हमारे नीति
निवेशक तिकाल है, उन के लिए ब्रेस भावर
कोई काम करे तो उन की स्वतन्त्रता का हुनर मानें।
जिस राज्य की कल्पना हुन न हो तो, वैसे समाजवादी
राज्य—मैं समझता हूँ—सजा समाजवादी राज्य की
कल्पना के लियाकाल भावर ब्रेस बाल्यर करता है,
उसके लियाकाल प्रबाल करता है—उस का समर्वन
करे या न करे, यह दृती बात है—लेकिन जो
हमारे नीतिक सिद्धान्त है, नीतिक साम्बन्धों हैं,
यदि उन के लियाकाल ब्रेस काम करता है, तो इस के
लिए हमें निर्वाचित स्वयं से कोइ धारक कानून बनाना
चाहिए और हम उसके लियाकाल नहीं हैं। स्वतन्त्रता
का लंबे यह कोई नहीं हो सकता है—अतीव स्वतन्त्रता
या भौंर बनन की स्वतन्त्रता। स्वतन्त्रता
का एक सीमित लंबे होता है। उस के सीमित
लंबे में जिस तरह हिन्दुस्तान का नागरिक या संसार
का नागरिक अपने भाषप को उपलब्ध करता है, उसी
दृष्टि से वह अपने स्तर को बना सकता है।

आज सब से बड़ा सवाल यह है कि हमारे
ब्रेस की स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि हिन्दु
स्तान का बड़ा ब्रेस हिन्दुस्तान के पूर्णपत्रियों के हाथ में
ही भीर जो ब्रेस-पूर्णपत्रियों के हित में रहेंगे, बह धूंजावाद
के लियाकाल लंबे कर सकेंगा—यह कभी भी समझ
नहीं हो सकता है। इसलिए आज सब से बड़ा सवाल
हमारे देश के सामने यह है कि हम पूर्णपत्रियों और
वह बरातों के इस देश के स्वामित्व के तुलने से दूर
करे? भीर मैं समझता हूँ कि इस ब्रेस पूर्णपत्र
के बारे में या ब्रेस के सम्पूर्ण मामले पर भी मैं
सरकार इस दृष्टि से विचार नहीं कर रही है।
असली विचारलौंग प्रश्न तो यह है कि यदि हम ने
समाजवादी समाज की कल्पना की है, समाजवाद
राज्य की कल्पना की है तो हमारा हर कानून, हमारा
हर वरण, हमारा हर कानून उस विद्या को सम्मुख
करते बातों हीना चाहिए, उस विद्या को मजबूत
करते बातों हीना चाहिए। ब्रेस-पूर्णपत्र विदेशक में
इस की कोई स्वतन्त्रता नहीं है, बर्यांकिं
इस समझता के अधिकांश सदस्य कामल हैं।

सभापति नहोवदा, एक बात कही नहीं कि
ब्रेस सोम और लालच के मुक्त रहना चाहिए। यह
यह की जीवी इस समाज में लंबव है जहाँ अधिकारित
दृष्टि है? जब तक दृष्टि का साक्षर्य बना देंगा
हुमियों में उस से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए
बरण इस बात की है कि अगर हम इस सारे ब्रेस
को स्वतन्त्र करना चाहते हैं, तो इसके स्वामित्व
पर की हमें विचार करता होगा।

हमारे देश में एक बड़ा संकट पीली पत्रकारिता
का है। यह पीली पत्रकारिता भर्ती पत्री है। इस
के दो-तीन कानून हैं। एक तो यह है कि जो लोटे
पत्र हैं उनकी प्रार्थिक विद्यि अत्यधिक बालव है।

इसलिए वे पीली पत्रकारिता के रास्ते पर जाते हैं। भूमि की बहुत पत्रकार भी यह है, राजनीतिक कार्यकर्ता भी यह है, इसलिए मैं उस से पाठ्यांगा कि वे वह समाचार पत्रों की बाजारे छोटे छोटे पत्रों को, सेलीय पत्रों को भजवृत्त करने की कोशिश करें। लेकिं पीली पत्रकारिता की तरफ छोटे पत्र ही जाते हैं।

एक सामाजिक संघर्ष में वर्चा की जा चुकी है विद्यालय के सामने में है। क्या प्रेस सरकार पर वारित नहीं है? सरकार पर तो वह आविष्ट रहेंगे? लेकिं सामाजिक संघर्ष में वर्चा की भावना की प्राप्ति रहेंगी? सामाजिक महाविद्या, मैं सामना दूँ कि लीन-बार तरह की तानाकाही होती है। वाह वह वह लीनिक तानाकाही हो, जाहे वह सामनों से तानाक नाही हो, वाह वह एक लीनिक तानाकाही हो। इस तरह की तानाकाहियों में प्रेस कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता है। जिन लोकतालिकों में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्ष है वहाँ भी प्रेस की स्वतंत्रता का वर्ष है जो लोकों के पत्र में प्रचार जो कि नहीं होता चाहिए। वहाँ भी लोकों के पत्र में बातावरण बनाता जाता है। इसलिए ऐसी स्वतंत्रता पर बहुत लगाना चाहिए। प्रेस परिषद् में जो कंफरेंट की जाती गई है, मैं उसका समर्पण करता हूँ। उस में विषय की सम्पत्ति दी गई थी, उसको भी देखा गया है। प्रेस परिषद् को कुछ कंफरेंट बनाना चाहिए जिस से पीली लोकतालिकों को नियन्त्रणात्मकता दी जाए। प्रेस को लोकतालिकों के विद्युत प्रचार करना चाहिए, कमज़ोर और दूसरी बागों के हित में प्रचार करना चाहिए और स्टेट पालिसी का प्रचार करना चाहिए। हमारे प्रेस का यही दृष्टिकोण होना चाहिए।

सरकार जैसी होगी, जैसा ही समस्या पर होग। लेकिं हम बर्तनाम में बात करते हैं। बर्तनाम में जो हालाई सरकार है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसका समर्पण हिन्दूस्तान के पत्र करें। यह आज का वर्ष है, यह आज की वर्षता है, इस से हमें बेकार नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता की स्वतंत्रता बात कर के एक प्रकार का संकट प्रेस बड़ा कर दे, इसकी छूट बेच को नहीं दी जा सकती है।

ग्रन्थ में समाप्ति जी मैं पाठ्यांगा कि हमारी कोशिश एक दृष्टिकोण होनी चाहिए। हालांकि हिन्दी और अंग्रेजी के नाम पर विवाद बड़ा किया जाता है। अभी सामाजिक सदस्य भी बहु सुहावं बोल रहे हैं। उन्हें अंग्रेजी में बोलने में कठ हो रहा था। क्या आनन्द आनन्द याज्ञ वे अंग्रेजी में बोलने के बाजाये बोलते। इसलिए हमारी यह कोशिश होनी चाहिए, हमारा यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम लोकतालिकों को मजबूत करें, तेलग को, बंगला को, भस्त्रियों को भजवृत्त करें लेकिन जैसी की समाजात करें। यह हालाई प्रेस कंफरेंट की भी सीती बाही चाहिए यानीकि विवेकी जाता से सामनावाद और कैपिटलिज्म पतनपता है। जहाँ जोक जाता होगी, वहाँ जीकंपत जाएंगे होगा। जहाँ जीकंपत जाएंगे होगा वहाँ जनवाद भजवृत्त होगा। जैसी जाता की बात करना, मैं

समझता हूँ कि यह एक बंध है, एक बहुत बड़ा बंध है। इसलिए हमारे बेस की कोशिश बहली जाहिए कि वह विवेकी जाता की बात से बदल दो। जैसे जी प्राप्ती जाता लोक जाता हो सकती है। इस लोक जाता को भोलालान देने के लिए और लोक जाती जाता को समाज करने के लिए वहि प्रेस परिषद् को कोई विकल्पितनेवाला भी करना पड़े तो कला चाहिए और जो लीनीय जाताएं हैं उनको भजवृत्त करने के लिए, उनका प्रबार-भस्तर बड़ाने के लिए, उने पूरी मदद करनी चाहिए।

इन बहुओं के साथ, जो प्रेस परिषद् विवेक जाया गया है और जिस सीमित उद्देश्य से जाया गया है, उसका मैं समर्पण करता हूँ।

MR. CHAIRMAN : I should like to put this point to the hon. Members. According to the time allotted for this Bill, I have to call the Minister now. But there are as many as 12 speakers, still remaining to be called (*Interruptions*).... Normally such extension of time at this stage of the session is referred to the Business Advisory Committee. In view of the importance of the Bill.

AN HON. MEMBER : The time should be extended.

MR. CHAIRMAN : If you hear me patiently, it will be helpful. We have got one hour remaining for the Bill. I would request the members to co-operate when we come to the clause by clause. Meanwhile I would like to know whether the House wishes to extend the time.

बीजटी बलबीर सिंह (होमियास्पुर) : एक बंदा बड़ा किया जाए।

SEVERAL HON. MEMBERS : One hour more may be given.

MR. CHAIRMAN : I want to make one thing quite clear. Members will have to co-operate in this matter and that is that there will be only five minutes for each speaker. And, therefore, when I ring the bell, I would request the speaker would request the speaker not to say—one minute or two minutes more. When I ring the bell, kindly start concluding and do not force me to ring the bell a second time.

So, Minister will reply after one hour.

बीजटी बलबीरी (भिवानी) : जो प्रेस काउंसिल विल येता किया गया है, इसका मैं समर्पण करती हूँ। इस काउंसिल में जिन लोगों को रोका गया है उन में नामों के दरमे जो लोग हैं जैसे जां रामजी सिंह ने कहा है उनके लिए कोई गुणालासा नहीं रखी गई है। इनका बहुत बड़ा लैबलन है। उस में

[भीमारी बनावटी]

उनके नुमाइंदे जा सकते थे। वे जाव के सोरों की बात नहीं सकते थे। पंचायती की तरफ है पहुंच तिले लोग या सतहे थे, उनके नुमाइंदे जा सकते थे, फार्मर एसेविएशन से नुमाइंदे पा सकते थे। इस तरफ आपको व्याप देना चाहिए।

जीता कहा गया है आज वेस में बर्ट टाइप आफ औरीबाद है। पारिंटिंगियन भी दैनिकतांकों में बसर में रहते हैं। हमारे यहां यांगों में एक कहावत है जूह आए तो आज रामायण। हम बुद्ध तो चाहे तें और उनके प्रभाव में रहे और वह कहे कि एस्टीटर उनके प्रभावित होते हैं तो यह ठीक नहीं है। जिस देश में इकोनोमिक सिस्टमरिटी न हो वहां वे प्रभावित तो होते ही। हम लोग भी होते हैं। इसलिए हम उनको क्या दोष देते हैं? उन में बहुत बहुत कोण चाही हैं। यहां यांग भी होते हैं। उनका सब से पहला बैक भेरे पास चुनाव में आया तो उनको परसनली की उपचार कर तक वही नहीं दे सकी है और न ही उन्होंने यहां से भी चीज़ की इकड़ी ही रखी है। मैं यसकी हूँ कि जो रिप्रिजेंटिव आपने जैनेश्वरी के रखे हैं उनके स्वान पर वैसा कारेसपीडेंट के बदल से चुनाव करा कर रखे जाएं, सीनियर प्रेस कारेसपीडेंट में से चुनाव करा कर रखे जाएं और उनके नुमाइंदे एस्टीटज़ के समाजी भी चाहें तो वैसा कारेसिल व्यापा भवित हो सकती है।

टी० बी० और रेडियो को भी मैं समाचारदारों के अलग नहीं कर सकती हूँ। वहां पर भी कुछ सीक्योड भी भीमीपोरी ही नहीं है। बंदा आज बंदा चले जाते हैं और सौ सदा भी यार जाते हैं। जिस देश में इकोनोमिक सिस्टमरिटी न हो वहां कुछ भोंगों की जोनोपोरी रहे यह बड़ी आपत्तिजनक बात है। मूले इस पर बड़ा यारी एतराज है। किस तरह से कुछ योंगों को वहां चुनाव जाता है, जिसे उपर्याम्भ माल देने के लिए चुनाव जाता है, विक्रिकर लैक्षन के लोंगोंकी चुनाव जाता है, ऐनाइज किया जाता है, इसकी तरह मैं आपको आना चाहिए। हारेरे नदीव वेस में इस तरह भी जात नहीं चाहिए। सभी तरह के लोंगों को वहां चुनाव जाना चाहिए। डरर नींवे के लोंगों को चुनाव जाना चाहिए। बहिं जै तो कहुँगी कि जो नदीव सोने हैं या जो बनाएस्यायद लड़के हैं उन के उनको चुना कर नदीव बचाएं बचाएं जाएं तो कम से कम उनको इतना तो लिलें। जो पहले से एस्यायद हैं उनको रेडियो और टी० बी० पर चुनाने से कोई लाभ नहीं है। बनाएस्यायद को चुनाएंगे तो कम से कम उनको यहांने में 250 लड़के हो लिलेंगे। कुछ इनप्लूएंट लोंगों की बलियां हैं, उनका जी बलिया हो सके तिर्क इसलिए उनके वहां चुनाव जाता है। और उनके परिवार के लोंगों को इसीलिए लोग जाता है ताकि उनका भी बहुल आपका भीर उनका बच्चे भी भी निकल सकेंगे। जो इस तरह के लोंगों को फैटोनाइज किया जाता है इसके में बहुत लिलाफ है।

रेडियो और टी० बी० पर बंड विलाव और प्रूत परतों के भरे नाटक बिलाये जाते हैं, जब कि इस देश में भारतीयवाद वहां से ही हो। वहां इस तरह के नाटक नहीं दिलाये जाने चाहिए। कई बार तो इसने ड्रामे नाटक होते हैं कि व्यक्ति उनको देखते देखते डर जाते हैं। ऐस बाते भाई यहां मुनते हुएं, ऐस्टोलार्जी को बात है सब से को भाटा है, तो यह इमरजेंसी से भाना यह दुई क्योंकि इनका कस्तर नहीं वा, यह कोई बात लाप नहीं सकते थे। इसलिये मैं भारतीय कल्पी वैस कार्डिनल में जो लोग हुएं उनके भीर वैस वांगों से भी कि भी विकापन देते हैं तो लिलान के भी प्रभाव होता है। इसलिये विकापन के लिये एक कमटी हीनी चाहिए, जो नियम रीवाइज बचावार हों जाए वह कहीं से भी देश के किसी हिस्से से निकलते हैं, उन सब को एक सा विकापन लिलाना चाहिए। बलि होना तो यह चाहिए कि लिला संस्कृत कम हो उसको ज्यादा नव फर करी चाहिए। कुछ लग दो योटा ले कर ही वा जाते हैं, इस तरफ व्याप देना चाहिए। याका है मंडी भवोदय देरी बातों पर व्याप देने।

चौबीसी बल्लीर लिह (हीमियारपुर) : समाचरित महोदया, मैं आपको ज्ञानवान देता हूँ और यही महोदय को युद्धारेकाव देता हूँ कि यह वैस कार्डिनल लिह जाये है। वैस बचाव हो जाव और उसकी किसी ताकत है यह लारी चुनिया को जाए है। बचावीका में जो सबसे ज्यादा गोटे के रूपे भेसीकें बचा जा उसको वैस से करने कर दिया एक काढर गेट स्टैंडल पर। एक मासूमी भी बात है। मासूमी देने इसलिये कही है कि यहां हिन्दुस्तान में उससे 10 युगा ज्यादा स्टैंडल हुए लेकिन जिसी ने बचाव तक नहीं उठाई।

MR. CHAIRMAN : I would request hon. members not to interrupt speakers. They have only five minutes. Be fair to them,

चौबीसी बल्लीर लिह : डा० बल्लीर प्रकल्प कह रहे हैं कि कै और युकांड। कौपें जाले और भोर नमाहे हैं, उब ली सारी बटी एकी खुनी में नीमी, बल्लीर जल कर जाव या चुनाव जूलनी होती है। इरिया यांगी के राज्य में वैस कारेसेट / चुनियारी कारिटेट और कलोजील भी लगिलें बहुत। वह कल्पते कि आपोबीजन इमरिट से जाक कर के खत कर सकते हैं ऐसे नहीं। मैं मासूमी ज्यानों में चुनिया बचावार कल्पिलिट यांगी के छपते वे 1940 तक देरे लिह में उत्तरे रहे। जब इसी बचावी चीजुलत भार बल नहीं तो हमारा और इसकी नाता दृढ़ा। तो मैं बहुल चाहिए हूँ जैसे जावाव ही तक वह जाना है। लेकिन जावाव जीते होंगे जब करोबरी इस वैस को जानी जाते हैं। यही बी, बार नहीं जी बात है इसी देश में बहुत ज्यादा बारोंका भारकार ने फैलाया लिलाफ किया जाना है 40 परसेट है। अल्पकर लैम्बर में जाया कि नहीं पता नहीं।

लेकिन तारे भूल के सदमावेदार प्रेस बाले लाठी ले कर पीछे पढ़ देये कि जनता पाटी टटो चाहिये और रोब यहाँ उस ढंग से प्रवाह किया गया ।

14.00 बटे

हम जो यह कहते हैं कि प्रेस आवाद है, तो यह आवाद कहाँ है । करोड़पति लोग इसके बताने वाले हैं, किसी के पीछे लिखा है, किसी के पीछे टाटा है, और गोपनका है । आवाद प्रेस इस तरह से कैसे बल बताता है । प्रेस काउन्सिल इस तरह के प्रधानार्थ दे कि ये सदमावेदारों के बायूल से छुट सकें, एडिटर लोग उनके इतारों पर न बन मँके । प्रेस के कौरस्टीडेंट और रिपोर्टरिंग इन्वेस्टिगेशन के लिये कुछ करिये । आज ये लोग आवाद नहीं हैं, इनको ऐसे के लिये किसी का मंहूं देखा नहीं है । इनके लिये कोई ऐसा कानून बनाया नहीं है । इनके लिये कोई ऐसा कानून बनाया है ।

आज हम लोग जो इस हाउस में बोलते हैं उसके बारे में भी यह है कि बगर अवाद वालों को नवाप करते के लिये चले आये तो बगर मुर्दों में आयें, भगर प्रेस बालों को नवाप करने नहीं आये तो बगर एक लाइन में आयें और वह यह भी इस ढंग से आयें कि बलबोर लिह आलसी स्टोक । मैंने यहा॒ प्राइवेट कहा है या यह नहीं कहा है, वह अवाद में नहीं आयेगा । मैं चाहूँगा कि जो प्रेस है वह आवाद हों और इन पर सदमावेदारों को बलवा दाया होगा चाहिये । जो एडिटर, कौरस्टीडेंट और रिपोर्टरिंग हैं, उनकी लिये भी कोई इतजाम करिये, कानून बनाये उनकी उनको पूरा दिया जिसके लिये भी कोई रोक न मँके । आती प्रेस काउन्सिल बताने से कुछ नहीं होगा । इस में कोई आरा ऐसी नहीं है जिसके उन नामों को प्रोटेक्शन दिया जाए । इस तरह से प्रेस आवाद नहीं हो सकेगा ।

प्रेस आवादिल एक जो आप बता रहे हैं, उसमें बूलाजिमों के लिये, बलास । और बलास-4 और जो बर्टी में आकर देपर सलाह करते हैं, जोटे-जोटे बचपनी जीविका के लिये यह बलवा करते हैं, उनके लिये भी कोई इतजाम करिये तभी यह प्रेस आवाद हो सके ।

नामों को लिखने की पूरी आवादी हो और उन पर किसी का बालव न हो, वह बचपनी बर्टी से बचपनी बाल लिख सकें, यह बल तक नहीं होगा, तो जो भेज काउन्सिल विल आपने बनाया है, इनका कोई फायदा नहीं होगा । आप वह बाल पूरी की पूरी इसमें रखें, ताकि प्रेस आवाद हो सके और इस देव की आवादी की भावना पूरी हो सके ।

SHRI AMRUT KASAR (Panaji) : I support this Bill and congratulate the Minister for bringing forward this Bill. But at the same time, I am surprised that this Government has taken 17 months to come with this Bill.

When I read the Press Council Act, 1965 and the present Bill, I find to my surprise that there is no difference between the two except the composition of the Council and the sequence of the sections or clauses of the Bill. Anyhow, I am happy that the Janata Government have fulfilled another promise by bringing forward this Bill. The freedom of speech which was curbed during the emergency has been restored now. Some of the Members who had been supporting the emergency at that time asked 'where is the freedom of the press'. I do not support their views. Today, there is freedom of speech. In spite of their views, they have been saying that they preserved the freedom of the press. But the freedom of the press is not protected by the big monopoly houses. I feel that the big monopoly houses and big business houses are the outcome of our economic system, and unless this economic system is changed, their hold over the press also will not go.

The hon. Minister said in his speech that the Bill is brought for protecting the press from various onslaughts and encroachments being made either by the Government or by big business houses or by any other sector. The preamble also speaks about the same thing and in the object of the Council the same thing is repeated. There are two parts of this. One is maintaining and improving the standards of newspapers and news agencies in India. For that there are a number of sub-clauses in Clause 13, but for the other namely preserving the freedom of the press, I do not see any sub-clause here in Clause 13. It is only said that the object of the Council shall be to preserve the freedom of the press. Freedom from whom? That is not said. From Government authorities, from private individuals whether that is going to be done or not, that is not clear. And today actually the threat to the freedom of the press is also from Government. Government has also become a big monopolist and capitalist in the present society. The Minister may remember that I gave him concrete examples. Many times Government has used its authority for unilaterally cancelling the advertisements to newspapers. Advertisements are stopped in order to exercise coercion on newspapers. There must be a uniform policy as regards the distribution of advertisements. Unless these things are done how will you assure the freedom of the press from Government authorities also? That is why that should have been cleared in Clause 13 of the Bill.

Clause 13 (i) says :

"to concern itself with developments such as concentration of or other

[Shri Amrut Kasar]

aspects of ownership of newspapers and news agencies which may affect the independence of the Press;"

The same clause was there in the previous Act also. There is no change. So, the question is whether in the incorporation of the same clause, even after the emergency, without some restrictions on the monopoly houses is going to help. If it is going to help, the Minister may explain in what way this will help us.

Again, Clause 14 speaks about the conduct of the newspapers only, but what about the conduct of the Government towards the newspapers? What is the provision made for that in this Bill? That is also not there.

I am happy about the composition of the Council. It has become more representative than the previous provision in the Act of 1965. I have moved some amendments, and I shall speak on them at the appropriate time.

I again support this Bill and congratulate the hon. Minister on the restoration of the freedom of the press.

भी समाजी भावावल नामक (बृजराही) : सभापति मनोदत्त, माननीय मंत्री जी को मैं सम्म्यावद देता हूँ कि उन्होंने प्रेस परिषद् विधेयक पेश कर के स्वतंत्रता का बातावरण प्रत्युत किया है। आप देखें कि समाजाचर पत्रों का काम केवल समाजाचरों का भावावल प्रवान करना ही नहीं है बल्कि मैं मनोदत्त हूँ कि राष्ट्र के सभावल बनाना, समृद्ध बनाना भी और जो शोषण मुक्त बना कर के समाजाचर के भावावल पर एक समाज की रक्षा करना भी उन का काम है भीर इस में यह ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न पर कर सकते हैं।

ममी कई माननीय सदस्यों ने कही थांते सामने रखी। मैं केवल इनका कहना चाहता हूँ कि ममी हमारे समाजाचर पर जो जहरों का बातावरण होता है या उन के कार्यकलाप होते हैं उन को ही सामने रखते हैं, आमीन लेक में जो हमारे गरीब, शोषित भीर पीड़ित मार्झ रहते हैं, उनकी जी कठिनाइयां हैं, उन को वह सामने नहीं रखते भीर यह किस तरह से समाज के ऊंच बन सकते हैं तथा उन की कठिनाइयां किस तरह से हुए हो सकती हैं, इस में वह समान पार्ट भद्रा नहीं करते। मैं चाहता हूँ, जैसे कि केंद्रीय सरकार ने एक निर्णय लिया कि बहु जहरों में ज्वरों जहरी जहरों, बहु बहु भारकानों नहीं जहरों, आमीन लेक में ही हमारा सारा कारोबार होगा, इसी तरह से यह प्रेस परिषद् की इस तरह से निर्भय है, प्रेस के सामने ऐसे सुमाव दे जिस से देहाती जंगल के जो भी कार्यकलाप हैं उन को वह सामने लाएं भीर बहु जो मानव पीड़ित हैं उन्हें उठाने के लिए

यह काम करे। जैसा मैंने निवेदन किया समाजाचर पत्र का काम केवल समाजाचर का आवाग प्रवान करना ही नहीं होना चाहिए बल्कि उस की दूलगामी दृष्टि होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे कुलल सबार भवनाहे भोड़े को बालुक भीर लगान से प्रयत्न काढ़ बैठता है इसी तरह से प्रेस भी चाहे वह मनवाही सरकार हो, वाह भरावाचक तरब हों या समाज-विरोधी तरब हों उन को उपने घंटुल में रख सकता है। तभी एक अच्छे समाज का बातावरण बन सकता है। आपी कुछ भववाचक ऐसी प्रतीक्षित बातें करते हैं, वहा वहा कर थांते लिखते हैं जो समाज के लिए हितर न हो कर दुलगामी हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रेस इस प्रकार काम करे जिस से लोगों में एक अच्छा भावावरण बने। वह स्वतंत्रतावांक भीर सामने के सामने प्रयत्न काम करें। एमजॉसी में भी मैं ने देखा कुछ अच्छावारे को, जैसे "नवी दुर्निया" इन्हीं भीर भर्जन इन्होंने जिस समय एमजॉसी में ज्यावपालिका में न्याय के लिए जाने पर रोक लगी थी उस समय उस का विरोध किया था। मैं ने जैसे थांते के बाव उन के साहस के लिए उन को पढ़ लिया था। मैं चाहता हूँ भववाचक उपने को बेच न दे, अपनी सबतंत्रता काम रखने क्यों कि नामांक भाजाही के लिए वह ज्यादा से ज्यादा समाज के सहायक बन सकते हैं।

इसी तरह से जिस तरह लिटेन में आकाशवाली स्वतंत्र है, उसी तरह यहां भी स्वतंत्र होना चाहिए ताकि देश में एक अच्छा भीर स्वतंत्र बातावरण बन सके, लोग उपना एक नया जीवन बना सकें और हमारा देश समृद्ध हो, देश में एक दाता का बातावरण बने। हमारी समाजावापन इस दिनों में काम करें, ऐसी मैं भासा करता हूँ।

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Madam Chairman, I warmly commend this Bill, because it revives the Press Council, and I hope it also now revitalises this Council, in view of the new improved Bill that we have got before the House today. I congratulate the Minister also because of the fact that the missing loophole in the Emergency Parliament's trio—the Prevention of Publication of Objectionable Matters Act, Feroze Gandhi Act (abolished) and the Press Council Act (abolished), all these three were there, but two of them were repealed and so one of them was missing—he has now completed that trio and for that he deserves congratulations.

Madam Chairman, I was a Member of the Joint Select Committee and I have given a note of dissent. I do not want to elaborate on that again. Precisely because I was a member of the Committee, I do not think I should move amendments and that is why I have not moved any amendments. It would be wrong perhaps for me to say that now after the Select Committee Report, it has

come with betterment or improvement because that would be, in a way, self-praise. But I do say in all humility that the Select Committee gave considerable thought in some quiet moments to the whole Bill in order to make the press not only more free, not only more strong, but, if I may say so, more responsible and more sensible and more serious, particularly in regard to language papers, small papers, district papers, and the Government's responsibility *vis-a-vis* the press in general. I hope, therefore, the new Press Council, when it comes into being, will see to it that the code of conduct about which I am legitimately somewhat nervous, will try and see that the whole thing is built up brick by brick, gradually, and that there is not a *priori* a whole set of disciplinarian points, commandments, "Ten Commandments" as it were, "do this" or "don't do this"; that should not happen, because the pressmen themselves will do it.

Why is a press freedom vital? It is vital for democracy, vital for people, vital for Parliament. Unfortunately, the situation in India today is that, generally speaking, you might say that the freedom of the press situation is rather at a low level. In other words, this deterioration, if at all there is some, is in line with or is a part of the general overall deterioration in the whole country in terms of excellence in various fields. That is why we are suffering in that respect also. In 1954 when the Press Commission was set up for the first time, it recommended the constitution of a Press Council. I am sorry it came as late as 1966 and, again, because of the emergency aberration, it was removed. Therefore, it was an abortive experience, or abortive experiment of the Press Council. I hope and pray that the new Press Council, bearing in mind that experience and encounter, will improve and strengthen the media through the pressmen themselves so that the freedom of the press in general can be preserved.

In India, of course, we must remember that the Press Council is a statutory body unlike what happens in Britain. In the United States there is no Press Council, although I have learnt last week from a Seminar where some of the US pressmen were present, some of them eminent, that they want a Press Council in America as well. That only shows that the pressmen themselves are aware of their own responsibility in the matter of building up and strengthening the freedom of the press.

I would say only one more point and I have done. I am sure the Minister will agree with me when I say that if the Press Council has to function efficiently, then it has to act as an agency for generating what is called accountability of the

press to the community; by accountability of the press to the community I mean not only social accountability but accountability to the community, to the country and to the ideals of a free press; not accountability to the Government and certainly not accountability to the management. Because, if it is accountable to the management or the Government, it will go astray from the normal path of the freedom of the press. It has to be accountable itself, to its own conscience, laid down by the tenets of the free press. Therefore, I would say that this social accountability would imply self-control, self-restraint, self-introspection, self-analysis and self-criticism by the press. I am sure the Press Council can generate this accountability as well.

One final word and I have done. I am sure the Minister has seen and perhaps the House has seen a recent article in *Sunday* of 27th August by Shri Kewal Varma, given as a cover story, entitled "How Editors are Managed".²⁵ Not only editors are managed, even columnists are managed and they are not properly treated, indeed, they are ill-treated by the proprietors on the one hand, and let the Minister not forget it, that on the other hand there are occasions when Government have badly treated the editors and columnists. I have my own experience when I was a columnist of several newspapers in Gujarat. At one point of time they did not like what I wrote, just because the Government at that point of time did not like what I wrote. Therefore, I was asked very quietly to leave.

Take the very recent example of Editor Shri Chalapathi Rao of *National Herald*, who had to go precisely for the same reasons. We all know how a new Editor, who was complaining of being sacked from a Bombay paper has been brought to Delhi. But he forgets that he was brought to Delhi to fill up a post because a Delhi editor was sacked in the same way in which he was sacked in Bombay. These things have happened, but they should not happen.

I will conclude by saying that the responsibility of the press is far greater because it is very powerful. I only hope that the Press Council will act as a sacred temple and as an edifice of freedom which will go into these problems in their entirety with a sense of seriousness and responsibility, because it has to guard its own freedom, namely, the freedom of the press.

जी दुर्विवद (कांगड़ा) : समाप्ति महोदय, मैं याननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रेस कॉमिटी वित्त यहां पर देखा किया। इमरजेंसी के दिनों में जो एक्सेसेज हुई थीर वित्त तात्पर ने नास-नीतिया पर याकूबी लगाई गई तथा हमारे

[भी दृश्यमन]

सोकरं वीरं हमारी भावावी को विस तरह हे वह पूर्णी भी उस को दूर करने के लिए जनता सरकार ने कदम उठाए हैं। मैं समझता हूँ—भावनीय बंडी जी को यह बेय जाता है—कि उन्होंने प्रेस की भावावी को बहास करने के लिये और भावनीदिवा को स्वतंत्र करने के लिये और कदम उठाये हैं, वे सरानीय हैं।

वे भीभावी से कुछ बातें कहता आहता हूँ—स्वाम 5 (भाइटन 2) से आहिर होता है—नामिनेशन भाव ऐचर्टेन—बेघरेन का नामिनेशन कितने भावावाना होती के होगा। इसी तरह से स्वाम 4 भाइटम। मैं “पावर्ट डेस्टर एनी न्यूज़पेर भाव न्यूज़एजेन्टी”—इस में प्रेस कौन्सिल को प्राइवेट दिया गया है कि उन वेब्ज या न्यूज़ एजेन्टों के विभाव का गाइड लाइन्ज या कौड भाव कन्सट के विभाव जावेगी, उन को देन्टर किया जा सकता है।

कल भी बानातावाजा जी ने कहा था—स्वाम 16 में जो यह कहा गया है कि कोर्ट जू पीजी को सेवी कर सकती है—मग नहीं होगा काहिये। जारी कौन्सिल को यह धरिकार नहीं होगा काहिये कि वह की को लेंडी करे। मैं यह बातें करता आहता—भाविर कौन्सिल को भलाने के लिए कफ्स की जकरत पडेंगी, वह दप्ता कहा से आवेगा? घगर कौन्सिल दूर भलाने पीरों वाच बडी ही—इस से अच्छी धोर दप्ता वात हो सकती है। इस लिये मैं देसा भवहूत करता हूँ कि जो प्राइवेट दिया गया है, वह ठीक है। उन्होंने कहा कि सरकार को सारी विभावारी लेंगी काहिये, लेकिन घगर वह स्वाम 17 को पढ़ते तो उन को भालू हो जाता उन में साफ दिया हुआ है कि घगर सरकार अपने भजाने से इस कौन्सिल को भलाने के लिये पैके का प्रबन्ध करेंगी और वह कौन्सिल भी भी उना सकती।

जहां तक प्रेस कौन्सिल विभेयक की दृश्यी प्रावीन्यज्ञ का ताल्लुक है—उन को देख कर वह मानूम होता है कि लाकई वह प्रेस को रेस्युलेट करने के लिये एक बहुत अच्छी प्रयास किया गया है। सेक्रिन मैं भानीय भंडी की के विभाव में लिये एक बात कहना आहता है—लोटे पेपर्स को प्रेस कौन्सिल में जो प्रिजेन्टेशन दिलेगा, उस पर हिट में रखते हुए बहुत छोटे रोजनल धोर लेंदेवज पेपर्स मालकम की तरह से जड़े हो गये हैं—उन को यह प्रेस कौन्सिल कैसे रेस्युलेट कर सकेंगी—यह प्राप्त की वेखना पड़ेगा।

जहां तक ऐचटिजेन्ट की भाव है—इस के स्विटम को भी रेस्युलेट धोर कन्डोल दिला जाना काहिये। यैसो-जर्नलिज्म के अरिये छोटे और बड़े भजावारों में वडा भैक-मैकिंग व्हलता है। वे धरने विष्व पर बहरें भावा कर देते हैं, जिस से सोसायटी पर चढ़ा घासर पहाड़ा है। इस तरक भी भावको घोर करना काहिये।

क्षेरे कुछ निकोंने कहा कि बड़े-बड़े भजावारों की भाव भी घोरताविष्व है—इस को विष्वकरणे

की जरूरत है, उस की तरक भग्न करन उठाने की जरूरत है। मैं भी इस विचारावारा से उपरोक्त हूँ और उम्मीद करता हूँ, प्रेस कौन्सिल इस तरक उठानी घोर भानीय भंडी जी भी भूमालिक करन उठाना बहरी होगा, उठायेंगे।

वैसे भंडी लैबेज और रीजनल पेपर्स का विक किया। वैसे कौन्सिल की एक भारी विभेयारी यह भी हीड़ी कि इन पेपर्स की कठिनाइयों की तरफ गोर करे। ये पेपर्स विस तरह हे बचने भाविहे, उस तरह से आख चल नहीं रहेंगे। विस तरह हे इस भावनीदिवा को गांवों में बेनट्रट करना भाविहे, उस तरह हे हो नहीं पा रहा है। इस के लिये जो हमारी ऐचटिजेन्ट पालिसी है—प्रेस कौन्सिल को उस के बारे में सोचना पड़ेगा।

वे इतना ही कहता हुआ—भंडी जी को अव्यावह देता हूँ और कान्डेचेलेट करना आहता है—उन्होंने एक बहुत प्रक्षण दिल इस ददन में वेल किया है।

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Madam Chairman, I rise to support the Bill. But I have certain observations to make.

The press, particularly in our country, has got a very important and crucial role to play. The freedom of the press has all along been one of our cherished values of life. These cherished values of life have struck deep roots into our national life right from the days of national freedom movement in our country.

In order to understand what is the specific role of the press in our country today, I only want to mention that the press has got the role (1) as an inspirer of the masses, (2) as a teacher of the masses and (3) as the Inspector-General of the governmental activities and policies. To fulfil this very important and the crucial role of the press, the press requires freedom. In actual terms, the freedom of the press means, freedom from proprietorial interference, freedom from the governmental interference and freedom from interference from other conceivable sources. The freedom of the press has also been defined as “the freedom to hold opinions, to receive and to impart information through the printed word without any interference from any public authority”.

The Press Commission itself felt that the freedom of the press must include editorial independence, objectivity of the news presentation and the fairness of comment. I concede that the freedom of the press which was completely extinguished has been restored, by and large, and the proposed legislative measure, I think, can go a long way to fulfil the promise for the restoration of democracy

in our country. But the fight for the freedom of the press is a continuous process. It cannot be, I would say, a gift from the Government, a gift from any authority.

Further, the freedom of the press has wider connotations also. It is an integral and an indivisible part of the democratic rights and civil liberties of our people. Therefore, the fight for the freedom of the press is not only the fight for the press alone but it is also the fight for the preservation of democratic rights and civil liberties of our people. It is true that the press fights for itself alone but equally, I now, it also fights for others. This is the lesson which we have learnt from the trauma of the Emergency. The experience that we have gained is that a monopoly press which gives rise to vested interest is a complete negation of the true values of the freedom of the press.

The money bags which control the press and have a stronghold over the media are a constant threat to the freedom of the press in our country. Here is the most glaring example of the infirmity of the Bill and that is that the Bill is conspicuous in its lack of understanding or lack of concern for this growing threat to the freedom of the press. Since I have not much time at my disposal, I do not want to dilate on the subject. But I would only like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that the common ownership and interlocking of the newspapers have grown in recent days.

According to the information available with me, the common ownership of newspapers account for 81 percent of the circulation of all metropolitan dailies published in our country.....

श्री एस० एस० मावाक (नानदरावर) : मेरा प्यासता का प्रश्न है। कोर्प नहीं है।

MR. CHAIRMAN : When the question of quorum is raised, the bell has to be rung..... Now, there is quorum. You can continue. Please finish in half a minute.

SHRI CHITTA BASU : This particular problem of growing concentration of ownership of the Press has been dealt with by the Press Commission itself and certain recommendations were made. I have come to learn that the Government has set up a committee to take certain steps. May I request the hon. Minister that in the course of his reply he should take the House into confidence as to what steps have so far been taken in the matter of transfer of management of the Press to public trusts, the diffusion of ownership, delinking of the Press from

business-houses, etc. He should tell the House.

SHRI PURNANARAYAN SINHA (Tezpur) : I congratulate our Minister for bringing forward this Bill which has been passed by the other House.

The Bill emphasises what we want our Press to be. Freedom is not required to be qualified by any amount of definition in the body of the Act. Freedom is freedom. There is no guarantee of freedom against the government or anybody and changes have been made in this Bill in order to guarantee freedom.

A Press Council will be constituted with 28 Members. There are 13 Pressmen, 6 from owners or managers of the newspapers, one news agency man, the Chairman and 3 wisemen and five politicians, i.e. the M.Ps. I think this constitutes a good team.....

MR. CHAIRMAN : MPs are also wisemen.

SHRI PURNANARAYAN SINHA : They are. The other point is: This morning I read in one of the local newspapers that the session is being extended. I get *Times of India*, *Hindustan Times* and the *Statesman*. One reported that the session is being extended. I immediately inquired of our Minister if this is correct. He said, 'No, no.' Now if the reporter had only taken little pains to.....

SHRI DINEN BHATTACHARYA : (Serampore) : This is the freedom of the Press.

SHRI PURNANARAYAN SINHA : Sir, I have been reporting from 1934. Even to-day I report for some of the papers including my own paper in my district. There are pitfalls but there is no such lack of responsibility. Mr. Mavalankar wants them to be accountable to the society. But I say not only to the society but to the nation and the world, to the human society at large they should be accountable. The Indian Press should be at least an ideal Press. Here the Reporter could have ascertained the fact from the Minister or his Secretariat whether the House is being extended.....

SHRI DINEN BHATTACHARYA : What is the harm ? It is simply overzealousness.

SHRI PURNANARAYAN SINHA : Publication of it even before the House decides is something wrong.

I have an allegation against the Press. After this Party has come to power, freedom of Press has been guaranteed

[Shri Purnanarayan Sinha]

but the press here, particularly, in Delhi is behaving with some amount of irresponsibility which has resulted in some of the squabbles. Perhaps they want to divide us. That is the idea. Perhaps they have been instigated by some agents from somewhere to drive a wedge between us. I have cited one sample of wrong report that has appeared to-day. They do not try to verify, they publish guess work, their imagination, their own story. I do not expect the Indian Press to be like it is done now in some papers. In section 13, there are so many clauses. I do not find the main thing in any of the clauses 'virtue of the press is truth'. Truth is found nowhere.

MR. CHAIRMAN : You should conclude now.

SHRI PURNANARAYAN SINHA : I have taken three minutes only.

MR. CHAIRMAN : I have got the clock here. You have taken four minutes.

SHRI PURNANARAYAN SINHA : The word truth is not found in any of the clauses that the press should be truthful.

The word 'truth' itself is nowhere there. The question of jute, textile, sugar industrialist monopolising the press is not foreign to my own way of thinking. I understand the sense of responsibility that is to encourage the growth of sense of responsibility. Sub-Clauses (d) (e) and (f) of Clause 13 should have been more elaborately defined. At the same time it is said the Council should not take cognisance of the complaint in the opinion of the Chairman if it is felt there is not sufficient ground for holding an enquiry.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI PURNANARAYAN SINHA : Any responsible reader could find if the press is dabbling in untruth or that is trying to create some political confusion among the people or the party. In that case, the Press Council should take cognisance of it and an enquiry should be started.

With these recommendations I support the Bill. I hope the House will accept them. At the same time, I also want that due representation should be given to small newspapers in the Press Council so that their voice is heard and they could speak for the people for whom the Government speaks a lot, that is, rural people.

SHRI B. C. KAMBLE (Bombay South-Central) : Madam, so far as the provisions which pertain to the public

service and public interest are concerned, I welcome those provisions. But they are only *casual* provisions. However, I would like to plead with the hon. Minister to kindly define broadly what he means by public service or what he means by public interest, so far as the freedom of the press is concerned.

So far as freedom is concerned can there be freedom for the press or for any category of people in India when the material resources of this nation are concentrated in the hands of 20% people? There can hardly be any freedom. In case the hon. Minister is sincere for the freedom of the press, break that chain by which the press is enslaved. There are two chains—one chain is by the capitalists and the other chain is by the Government. Therefore, break that chain. So long he has not broken that chain; it is not possible also. Take the principle of nomination. Press Council is being constituted under the principle of nomination. Do you mean to say that the Press Council, by such a nomination, will be able to preserve the freedom? It is impossible. Therefore, the principle of nomination was discarded long ago in the Constituent Assembly. Do not revive that principle. Accept the principle of direct election. I have suggested certain amendments but I shall not go into them in detail at this stage. But whatever be the conception of the Press Council, if it is by nomination, Parliament has an insignificant place in the Press Council. Therefore, instead, the principle should be like this. I would say that even among the Working Journalists there should be representation on the Press Council. Their representation will never be on the Press Council. That seems to be the provision here.

Looking to the provision about the foreign aid or foreign money or assistance, all must come up before Parliament, even the economy of the press must come up before it. That can at least be done at this stage. The budgets or foreign assistance for which there is a provision, all the details of them must be placed before Parliament. Annually, there should be a report submitted through this Press Council so that there will be a full discussion.

Now, Madam, there is a provision with regard to rates. There is a provision for uniform rates for medium, small and big newspapers. Why do you want same rates? Therefore, I have proposed graded rates. For the small newspapers there should be low rates; for the medium newspapers there should be middle rates and for the big newspapers there should be higher rates.

Lastly, I would like to ask what is the purpose for which this freedom is to be given. You define the purposes for which it is necessary. In that regard, I have given certain amendments. I will conclude by making certain suggestions. Let there be some choice for the public with regard to newspapers. Let there be diffusion of ownership. Let the economies of the Press be brought before the House and let there be relationship between the labour and the management. In case our nation has to go ahead, the Press has to play a big role which it has not so far played and, as such, vast masses of the people are steeped in illiteracy and are below the poverty line. As such, certain portion of blame goes to the Press as it has not played its proper part.

SHRI AJITSINH DABHI (Anand) : Madam Chairman, the Bill seeks to establish the Press Council and thereby to make the law regarding the preservation of freedom of the Press and to improve its standards. The law by itself is not sufficient. It has been shown by experience that many a law are 'flouted with human intelligence and ingenuity despite legislative checks and strict legal provisions. What is more, the attitude of the government goes a long way in the growth of a free Press. I am sorry to say that I have no faith in the sincerity of the present Janata Party government regarding the proposed enactment. The attitude and conduct of the Janata Party government bears testimony to the fact that this government wants not a free press but a coloured press. This government wants to lend it a 'Bhagwa' colour of RSS and Jan Sangh to whom the hon'ble Minister for Information and Broadcasting belongs. Because, Madam Chairman, he has become a minister in the Janata party government by virtue of a quota of ministers given to Jan Sangh in the Janata Government. Immediately after the breaking up of the single news agency, namely the Samachar into four news agencies the Minister and his colleague in RSS, Shri Baleshwar Agarwal, tried to invest 'Bhagwal' colour to Samachar Bharati—an independent progressive news agency—by merging it with the Hindustan Samachar controlled by the RSS. It is well known that the hon'ble Minister had brought pressure on Shri P. C. Gupta, Chairman of the PTI Board and got accommodation in the PTI building for the RSS controlled Hindustan Samachar. Not only that. Last year he had allotted Rs. 8 lakh for each of the four news agencies but for the Hindustan Samachar controlled by the RSS, he gave Rs. 4 lakhs more. Therefore, Madam, I say that the establishment of the Press Council, by itself, does not ensure the independence of a free press. How can

you expect unadulterated news and information by a news agency which is controlled by religiously fanatic people who in fact distributed sweets when the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, was assassinated ? Madam Chairman, it has been recommended by the first Press Commission that the Press should be de-linked from the big industrial houses. Not only that. The hon. Minister, Mr. Advani, while speaking before the conference on the Indian Press and Freedom, last year, stated that the Press should not be in the hands of unregulated forces of market. What he is doing today is exactly to the contrary. His Ministry recommended Rs. 60 lakhs to be paid to the Express Newspaper Group which is controlled by a big multimillionaire jute baron.....

MR. CHAIRMAN : You have taken more time than what is your share. Please conclude.

SHRI AJITSINH DABHI : While the newspapers like the *Patriot* and *Mainstream* were allowed to perish. I say that.....

MR. CHAIRMAN : You are taking a long time. Kindly conclude.

SHRI AJITSINH DABHI : I am just concluding. I say that with the present Minister in charge of Information and Broadcasting, the freedom of the Press is far away. I am just concluding.....

MR. CHAIRMAN : No, no. I am calling the next speaker, Mr. A. K. Roy. Kindly resume your seat.

SHRI AJITSINH DABHI : I am concluding.

MR. CHAIRMAN : No, please. You can speak on the amendments which are standing in your name, Mr. A.K. Roy.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad) : Madam Chairman, this deserted House**

MR. CHAIRMAN : Don't record. Kindly don't make such a remark. It is against the rules. It will not go on record.

SHRI A. K. ROY : and complete boycott by the AIR of the proceedings of this Press Council Bill indicate the real worth of the Bill. It shows either that the people's representatives and all concerned are not interested in the real freedom of the press or there is no genuine element of freedom of the press in this Press Council Bill. There can be only two alternatives to this general apathy all round towards the so-called impressive Press Council Bill with which the Minister has come.

**Not recorded.

[Shri A. K. Roy]

Madam Chairman, you will agree with me that our position has become very difficult, because, we are to choose between genuine slavery and a counterfeit freedom. We don't know what to do. We have seen 19 months of genuine slavery, unadulterated agmark slavery, and now we are having 17 months of counterfeit freedom; that is also regulated, processed, finished and presented. So, Madam Chairman, our position has become very difficult. Previously in that controlled Press, so-called committed Press, we used to read from our jails, stories of Sanjay Gandhi. Today in the so-called uncontrolled and free press we are reading stories of Kanti Desai and nowadays of Suresh or some such chaps; we don't know tomorrow what we will read about and about whom. The voice of the teeming millions, the voice of the working people was choked before and it is being choked even today.

Now, we may see how the Press Council can preserve the freedom of the press. I wonder, how an odd 29 nominated Members can give us freedom. Out of the 29 nominated Members, even if that is a good body, I am afraid, it will be only good for nothing.

Only seven will be from the working journalists and five will be from the two hon. Houses. So, the entire concept of freedom of press is being mortgaged to the good wishes and wishful actions of some press barons or press owners.

Madam, while you are busy with pressing the bell, the Minister has come with an unimpressive Bill in this House. Freedom means freedom from what and freedom for what. Freedom has to be from intimidation, freedom from compulsion, freedom from all sorts of terror and fear. I would like to ask the hon. Minister, can the Press Council Bill provide that freedom to the working journalists, freedom from their owners, freedom from the management? Now, freedom for what? Freedom for venting one's views and facts about the huge agony of the society. Can there be any guarantee for that?

Press in this poor country is not only a means of entertainment, it is an instrument for change, it is an instrument for giving direction to the society. But what is the press today? It is full of scandals; it has become unreadable now-a-days. I was just reading a few lines by Oscar Wilde with regard to the difference between literature and the press. He said that while the press is unreadable, literature is never read and that is the position now.

Sir, the fight for democracy is a long one. It requires not only democratic tongue, but it also requires democratic teeth and this Press Council Bill is devoid

of any democratic teeth. It is simply like the previous one and as I told you, it is only the counterfeit freedom which the Janata Party is offering us instead of the unadulterated slavery from which we have emerged.

MR. CHAIRMAN : I wonder, who will give the Chairman freedom from speakers who exceed their time limit?

The Minister.

मुख्यमंत्री और प्रसारण मंत्री (श्री लाल हुम्मा शाहावाहानी) : सभापति महादया, मैं बहुत आशादी हूँ उन मानवीय सदस्यों का जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है। केवल एक अपवाद को छोड़कर जोकि अभी बोले हुए बकाने से पहले बोले थे, वाली सभी ने, जहाँ तक इस विधेयक का महत्व है, इसका स्वातंत्र्य दिया है। इस विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में टीका-टिप्पणी की गई है लेकिन वह भी सामान्य क्षय के ही। अधिकारियाँ जो भी सामाजिकार्यों और टीका हुई है वह प्रेस के कार्यकारिणों के बारे में हुई है। प्रेस की जो सामाजिक समस्यायें हैं, जिनसे मैं भी परिचित हूँ, उनके बारे में कई विचार व्यवहर किए गए हैं। मैं पहले पहल प्रेस परिषद के बारे में जो टीकाटिप्पणी हुई है, उसके बारे में कुछ संक्षेप में कहूँगा और उसके बाद जो सामान्य चर्चा की गई है प्रेस के बारे में उसका जिनाना मैं संग्रह में उपयुक्त है उसका उत्तर देने की कोंशिश करूँगा।

मध्यस्थ परामर्शदाता जो चीज मालिकर जी ने कही है, यह लीमारा विधेयक है जिसको सामने के बाद हम समझते हैं कि विधायी स्तर पर लेजिस्लेटिव सेवन पर, प्रेस की आजादी के मामलों में इस सरकार ने जो बायदे किए थे वह पूरे हो जायेंगे। प्रेस की आजादी ऐसी नहीं है जो केवल कानून द्वारा पूरी हो जाये।

14:55 hrs.

[SHRI N. K. SHEJWALKAR in the Chair]

इस प्रस्ताव से मैं महसूत हूँ और जिन-जिन लोगों ने इस बात को कहा है—मैं समझता हूँ कि उन्होंने उपयुक्त कहा है। मान सीमित—हम पीनस कोड में कोई अच्छी व्यवस्था करने के बाद कोई यह कहे कि जब तक बेकारी बहस नहीं होती, जब तक लोगों का चरित्र ठीक नहीं होता, तब तक इस कानून का क्या मतलब है? कहने के बाते तो यह बात ठीक है, लेकिन कानून की अपनी एक सीमा रहती है और उस सीमा तक वह अपनी विस्तृति को सुधार सकता है। यह जो लीसर विधेयक "प्रेस परिषद विधेयक" लागा गया, वह एक सीमित सामान्य में प्रेस की आजादी को सुरक्षित करेगा, जिस सीमा तक कि कोई कानून सुरक्षित कर सकता है। दो कानून हम वे पहले पास किये थे—जायद संसद के पहले ही सत्र में "श्रीबंगल आक परिषक्षण आक

आजीवननेवल "मैट्टर्स एक्ट" को रिपील किया था, जीरोज गांधी एक्ट जो पिछो सरकार ने बत्त कर दिया था, उस को इस सरकार ने किर मे रिकाइ दिया ।

इस सम्बन्ध में यहां पर चर्चा हुई—एक प्रयत्न संस्था है—भाइ-एन-एस-०—इन का नाम आप ने सुना होगा—कि का भय रहा है कि हिन्दूस्तान में भी प्रेस कॉर्सिल उसी प्रकार की बननी चाहिए, जैसी इंडिया में है, द्वितीय प्रेस कॉर्सिल की जरूरत नहीं है। इस चर्चा पर विचार शुरू हुआ। मैं यह नहीं बातता या कि मैं इसी तरह से प्रेस कॉर्सिल ज्यो-किं-रों से आऊं। सरकार ते विचार किया था कि यह आठ लाख रुपये द्वारा इस बात की ओरणा कर दें कि हम प्रेस कॉर्सिल किरण से बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रेस कॉर्सिल विचार करने से पहले भक्ता होगा कि प्रकारों से सलाह कर ली जाय, जितने मध्ये ही, उन सब पर चर्चा कर ली जाय।

"Whether it should be a voluntary body, or a statutory body."

15.00 hrs.

एक पहले द्वारा भी है—जिस की शुरू में बहुत चर्चा होती राइ है। शायद प्रेस कमीशन ने जब पहली बार प्रेस परिषद् की सिफारिश की थी, तब से होती राइ है।

"Should the Press Council have teeth, or should it have only the power to censure and admonish and express its opinions?"

एन० पू० जे० ने, बकिंग जनरलिस्ट्स की फैसलेन
ने भी अपने विचार रखे हैं। मुझे निश्चित रूप
से तो याद नहीं है, लेकिन एन०पू०जे० के बारे में
मुझे याद है—उन्होंने बड़े पात्रात्-से यह बात कही
थी कि हम जो प्रेस परिषद बनायें

"We should provide it with teeth. We should not make it a body similar to what was there earlier."

बह में सारे भूते ऐसे थे—जिन पर जब्तीबाई के कोई नियंत्रण नहीं करना चाहता था, परन्तु साथ-साथ विलम्ब भी नहीं करना चाहता था। इस लिये वो ऐसे को बाद भैंसे जिनमें वसकारों के प्रतिनियन्त्रण थे, उन को बुलाया, उनकी कांस्ट्रॉक्शन की, उन से बच्चों की भी भौतिक एक ब्राइक-सेंसेस-मर्क्स की हुआ और वह यह हुआ कि हम को हिन्दुस्तान में एक स्टेंचूटरी बाड़ी चाहिये, बालंटी बाड़ी नहीं। यहाँ पराहिये, जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था की पूरी सामाजिक व्यवस्था बदल दी गयी थी। इसलिये उस पर बड़े-बड़े पल छाये रहे, छोटे बच्चों में विद्यम पद्धों का उसमें कोई स्थान नहीं रहे। स्टेंचूटरी बाड़ी होगी तो उस के जिन्हें अधिकारी करना होगा, वह बालंटी बाड़ी में नहीं हो सकता है। इसलिये प्रेस कौम्भल के द्वारा हम जिस उद्देश्य की प्रूतियाँ करना चाहते हैं, वह स्टेंचूटरी बाड़ी के द्वारा ही हो सकता है। इसलिये आप स्टेंचूटरी बाड़ी बनाना चाहते हैं। वो संस्थाओं को कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं। एक शार्हां-एन-ही० सी० ने मत व्यक्त किया कि हम स्टेंचूटरी बाड़ी के पल में हैं। इस सब बच्चों के बलते बलते सरकार ने एक मत लिया कि एक विदेशी कार्यकारी लाने के बाद उस सदन ने तय किया कि इसको एक प्रबल समिति एक ज्वार्पंत तिवैकूट कमेटी के सुझाव कर दिया जाए। जब टीवी में वह समिति बन गई थी, वह तय हुआ कि मानवता सेवन के पहले दिन रिपोर्ट दी जाए। मूँह याद रखें उस प्रबल समिति की पहली बैठक ही तब मैंने समिति से निवेदन किया था कि यह सामाजिक विनों से लटकाया था यहाँ है, किर से मह प्रबल समिति का पास चीज़ भाइ है, जार बार प्रबल समिति का कार्यकारी बड़ता ही जा रहा है। इस बास्ते मैं निवेदन करांगा कि जो संसद् ने हमें आदेश दिया है उस प्रादेश का पालन करते हीपुर यह सब के, वर्षा भरु के सब के पल दी रखी तैयार हो रहा गया है, किर से मह प्रबल समिति द्वारा हमें इसके लिए वित्ती भी बैठेंगे क्यों न करनी पड़े। जितनी भी बैठकें हमें करती हैं एक महीने में कर लें। मूँह संतोष भीर खड़ी है और मैं धन्यवाद भी देता हूँ प्रबल समिति के सभी सदस्यों की जिन्होंने पूरा सहयोग दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार का एकसंबंधन मांगना न पड़े भीर जिस दिन हम से कहा गया था उस दिन आगे कर हमें विवेष भूल जाएगा। इस बात की मूँह विवेष हो देती है। यहाँ जो पहला विदेशी था वह एक दूषित विदेशी किया था उस में कृष्ण महत्वपूर्ण संबोधनाएँ थीं।

[वी ताल कल्प वारदाती] इस है वाहे थोड़े ही हुए हैं। लेकिन जितने भी हुए हैं सब सर्व सम्मति ने हुए हैं। एक बात से हुए है। एक मुद्रे पर, एक प्रावधान पर मतभेद रहा है जिस के बारे में डाइसेंटिंग नोट भी है। उसका वी उल्लंघन करना यह कोड प्राफ कंडेट का है। वाकी जितने संसोधन ये सब सर्व सम्मति से हुए थे। सब जो उल्लंघन ये सहृदयी। पूरी सम्मति यही थी कि यह जो बाही है उसमें टीप नहीं देने चाहिये। बनातालाला ताहब ने कहा या राय साहब ने कहा कि इससे क्या फायदा होगा, प्रेस परिवद कोई निर्णय देती नहीं थी और उसको कोई मानेगा या नहीं मानेगा तो उसकी क्या अवस्था होगी इत्यादि। बाही हम को ऐसी बनाती चाहिये जिस की बात में उसके कम्पोजिन के कारण बजन हो। ग्राहर प्रेस काउंसिल कहती है कि सरकार ने बजत बात की ही तो मैं समझता हूँ कि सरकार के बास्ते जो आसान बात नहीं होगी, काम से काम कोई भी ऐसोकेटक सरकार उसमें इन्कार नहीं कर सकती है, उसकी बात उसको माननी पड़ेगी। आगे देखें कि हाउस के प्रिवेलेज का बीच होता है तो सबल बीच करने वाले को ग्राहर डमारिंग का बांट देने को उसका कितना बजन होता है, इसको हम जानते हैं। इस प्रकार की संस्था के द्वारा एडमानिंग होना या किसी प्रकार से लैंगर होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, मायूसी बात नहीं होती है।

इलाति पिलाति में एक बात यह कि उस में इस बात का उल्लंघन नहीं था कि प्रेस परिवद सरकार के काम पर भी टीका कर सकती है। कभी भी सरकार के बिलाक कोई मामला जाता था तो एतराज उठाया जाता था। मुझे ट्रिम्प के सम्पादक का मामला याद है। सम्पादक ने प्रेस काउंसिल में हरियाणा सरकार के बिलाक एक मुहा दायर किया था। पटना के सर्वसाइट बखबार ने बिहार सरकार के बिलाक एक मुहा दायर किया था। योनी मामलों में सरकारी बैंकों की तरफ से प्रिलिमिनरी आवैदेकल दृश्या था कि यह प्रेस काउंसिल बिल की बात नहीं लिखा है कि सरकार की बात पर भी टीका बह कर सकता है। ऐसोकेट जनरल ने यह आर्मेंट दिया था कि सरकार की बात पर प्रेस काउंसिल को टीका करने कोई आधिकार नहीं है। प्रेस परिवद ने उनकी इस बात को नहीं माना, पिलाति प्रेस परिवद ने। उसने कहा कि जो रेजिस्ट्रेशन पावर इत्यादि है उनके प्रधान महि निष्पर्यं निकाला जा सकता है कि हम को यह भी आधिकार है कि प्रेस की आजादी पर ग्राहर सरकार कोई आक्रमण करती है, कोई हस्तक्षेप उसके द्वारा होता है तो उस पर भी हम टीका कर सकते हैं। उसके आधार पर उन्होंने की भी। सरकार को लगा कि इम बारे में कोई सन्देह नहीं रहना चाहिये और इनके बारे में प्रावधान कर देना चाहिये कि प्रेस परिवद को आधिकार होगा कि सरकार ग्राहर प्रेस की आजादी में हस्तक्षेप करे तो उसकी प्रावधान कर दिया गया है। और यह प्रावधान करने से स्थिति प्रचली बनी।

ऐसा भी नहीं मानता है कि ऐसे परिवद बह नहीं तो प्रेस की आजादी की गारंटी हो गई। भी तो कह बार कह बकता है कि एक बतारा है सरकार का, दूसरा बतारा है नालिकों का या स्वामित्व के रूप का भीर तीनरा बतारा है ऐक आफ इंटराइटी भीत वि पाट आफ जर्नलिस्ट्स। तीव्रारा बतारा सबसे बड़ा है और इसका कोई भी ऐंटीट्रायुक्ट सम्पर्क्ट्रूट नहीं हो सकता है। और उसके आधार पर तो प्रेस की आजादी का मारा भवन बड़ा रहेगा मुख्य रूप से। यह तो हम केवल सहारा के रहे हैं, जितना दे सके अच्छा होगा।

सब सरकारों ने कहा कि जब तक ग्रोनरिप ऐंटर्न नहीं बदलता, जब तक स्वामित्व का आज का कर नहीं परिवर्तित होता प्रेस की आजादी आरंभित नहीं हो सकती। मैं इस बात से सहमत हूँ। अलवतारा यह बात जकर कहूँगा कि पिछले 20 वर्षों में प्रेस के ग्रोनरिप की बात एक स्लोवेन के रूप में की गई है हमेंसा। प्रियंकन और ईंटीलिंकिं इन बायों का भी गलीजों के रूप में प्रयोग किया गया है इम नाते कि ग्राहर की तरफ के बतारा है सबसे बड़ा, मैं उसको सबसे बड़ा मानता हूँ, ईंटीकि सरकार में सबसे बड़ी मानोली हो गई है, और सरकार से इन्तारा बतारा है उसकी तुलना में नालिकों का बतारा इनका बड़ा नहीं है। उस खतरे से लोगों का व्याप ग्रोनर करने के लिये पिलाति सरकार ने बाट-बाट ईंटीलिंकिं और हिप्पजन की बात कही। जब कि किया कुछ नहीं, एक फदम भी आगे नहीं बड़ी। मैं मानता हूँ कि हिप्पजन बहुत बड़ा मानोली है। ईंटीलिंकिं यादा प्रैस्टिकल है। लेकिन उस दिना में कुछ भी करवा चाहिये था। लेकिन वह नहीं किया। यह थीक है, लेकिन उसकी बर्चा रोड करने से यो भी बोलता था सरकार की ओर से उसकी बर्चा करता था और हमेंसा यह किलाने की कोविल करता था कि ग्राहर बैल के अन्दर प्रेस की आजादी सीरित है तो उसका कारण मालिक है। अली बात कही नहीं करते थे। यह सरकार जब से आयी है, जितने कदम उठाये हैं वह कदम अपनी बायिं कम करने के हैं। One by one we have been shedding the powers of the government. जब से ले कर आज तक, मैं अपने मंत्रालय का चलेकर कर सकता हूँ कि जितने कानून हम लाये हैं तब कानूनों के पास होने के बाद भीरे ताकत कुछ कम है। जिस समय भी मंत्रालय की कुर्सी पर बैठा था तो लगता था कितनी ताकत है जाहे जिसको जो कुछ कर दो। और आज रियां पर है कि मैं अपने बचनों से बंधा हूँ जिसके कारण आज रेडियो पर कई बीजे आती हैं जो मैं पसन्द नहीं हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। चैकि हमारी बहन ने रेडियो की बर्चा की हमारे आज के बाब बहने सुन किया gleaning from the Press.

ऐंटीट्रायुल प्रति दिन देना चाही था। आज ऐंटीट्रायुल कोम भी प्रेस ग्राहर आप देखेंगे तो कहेंगे वह क्लिंग पार्टी के बिलाक है, और वह

देवर हिलन पांडी के लिया है। आज्ञा जीव है, मैं इसके लियाक मही हूँ। मैं बता रहा हूँ कि सारी जीवें ऐसी हैं जिनके कारण लकार ने जगी बांधित स्वेच्छा से कम की है जबोकि हम मानते हैं कि जब तक वह जीवित थे सरकार के हाथ में केन्द्रित है वह जनता तक नहीं आती, जैसे की आजावी वहाँ नहीं रहती, तब तक लोकतंत्र नहीं हो सकता है। ईमानदारी से हम उसमें विश्वास करते हैं।

हमारे कई तदव्यों में आहे जितनी बार चिसी पिटी बात कही थी कि हमने बालेश्वर अध्यात्म और "हिन्दुस्तान समाचार" को पी०टी०आ००० में कोई हथान दियाया। मूळ ताज्जुब होता है, जबोकि मैं कई बार हथाय इस बात का बड़न कर चुका हूँ और पी०टी०आ००० ने कभी उक्तो कमरा दिया ही नहीं। फैस्ट ही नहीं कि कोई कमरा दिया। मैंने जब पता चला एंडी कोई बात चल रही है कि पी०टी०आ००० बाले शायद "हिन्दुस्तान समाचार" को कोई कमरा देने आ रहे हैं, तो पी०टी०आ००० के सम्प्रदायक मुख्य मिले ये भैंसे उनको कहा कि आई बद्या कर रहे हो? अगर आप दे रहे हों, आपके पास कोई जगह है देने की तो "समाचार आर्टी" और "हिन्दुस्तान समाचार" दोनों को जगह है, देना है तो दोनों को दे दो। मैं तो अपनी तरफ से कोणिंग कर रहा हूँ कि बहसं और हाउसिंग मिनिस्टरी उनको दे दे। लेकिन अगर उनको बहसं हाउसिंग विनियोगी नहीं दे सकती है और आपके पास एवेलेबल स्पेस है, देना है तो दोनों को दे, ऐसा न हो कि एक को दे और उनके कारण हमारे कंपर आयोग द्वारा हो। स्वित्र दूसरी है, उसके बारे भी जबोकि हमसे कुछ नहीं लिया गया तो वह पुरानी बात थोड़ाते आयें। (अवधान) उसी प्रकार से मूळ बाद है एक मानवीय समस्य में शायद लूकात लिह का भी उल्लेख किया।

SHRI AJITSINH DABHI (ANAND): The Employees of the P.T.I. had passed a resolution unanimously that accommodation to Hindustan Samachar would endanger the independence of the P.T.I.

SHRI L. K. ADVANI : That I have said officially and I am giving the full facts of it. It did not actually happen, but the moment I came to know that this is the possibility which the P.T.I. people are thinking about, I told them that if you have space and accommodation to provide, give it to both. So far as I am concerned I requested Works and Housing Ministry to give accommodation to both, which the Minister of Works and Housing did give to them. So, that question did not come up at all. But that old bogey of it keeps on being repeated.

जबोकि मैं यह मानता हूँ, कभी-कभी मजबूरी भी समझ सकता हूँ लिपि की, बास दौर वह इस कोने में बैठे हुए लोगों की कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारे साथ में ताकत आये तो वह ताकत का प्रयोग नहीं करेंगे। वह घासंभव बात है।

They perhaps find it impossible to contemplate that a Government or a person who wields such power would be willing voluntarily to shed it. But this is exactly what is being done.

स्वेच्छा से सारी बातें को जा रही हैं। बास-बार अपने हमको कहते हैं कि आटोनामी करेंगे आप, आटोनामी होनी नहीं है। कौन यानेवेट लोड़ती है? मैं मानता हूँ कि आपसान नहीं हैं, मैंने भैंसे लगता है कि काहे के लिये छोड़ देंगे, इतने अधिकार है, हम ठीक कर सकते हैं। अगर छोड़ देंगे तो आपद बराबर हो आयेंगे। अपने जायेंगे। लेकिन ईमानदारी का जो कृप्त है वह है विश्वास, जनता और प्रेस पर विश्वास।

मेरे एक दिन ने कहा कि उनकी आजावी इतनी निर्मली है कि ईररप्रिसिलिटी से सोग लियाने सते हैं अखबार बाले। मैं बड़ी लिम्युता से अपने साथी से कहूँगा कि

Irresponsibility is not a monopoly of the politician.

प्राक्तिक ईररप्रिसिलिटी सब के लिये दिक्कार्ड देती है, ऐसा कोई अंत नहीं है जहाँ दिक्कार्ड न देती है। प्रेस का सेक्रेटर या कोई अखबार ईररप्रिसिलिटी से अव्याहार करता है तो सहज क्षण के हूँसार कोई साथी प्राक्तिकल पांडी में इस तरफ पा उस तरफ कर दे

Press has become irresponsible.

और इसीलिये उस पर बन्धन होना चाहिये, आजावी बाले चाहिये, मैं इस बात को मानता के लिये तेयर नहीं हूँ। (अवधान) लेकिन, कुछ हीता आहिये, इसके लिये ही अवस्था को जा रही है। यह जो प्रेस आयोग है, यह आटोनोमाइजेशन के लिये एक संस्थागत अवस्था है।

It is an institutionalised arrangement for self-discipline.

इसमें वहाँ के लोग बैठेंगे और वह कहेंगे कि यह जो है, यह पीत वकारिता है, लेकिन हम बैठ कर यह कहें, जो चीज हमको पदार्थ नहीं आये कि यह भैंसे जनेतिम है, वह बात ठीक नहीं। वह अधिकार हम भयने पास रखना नहीं आहते। इसीलिये कई लोगों ने विशेष पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन 2, 3 सदस्यों से मैंने सुना कि नामिनेट बाबी है,

This is going to be nominated body! This is not going to be a nominated body. That Government has nothing to do with it absolutely. So far as the personnel of the Press Council are concerned, right:

[Shri L. K. Advani]

from th: Chairman who is to be nominated by a nominating panel comprising of the Lok Sabha Speaker, the Rajya Sabha Chairman and one person elected from among themselves by the members of the Press Council. So, this is the nominating panel who is going to nominate the Chairman. So far as the members of the Council are concerned उनके लिये वर्वदाय की गई है और वह प्राइवेट रूप से ही कि चिर से संविधान नाम देती, हम नाम नहीं देते। ए.पार्टी-एन.डी.सी. नाम देती, लाइनरोफर्म्स नाम देता, बॉकिं जीविलट केरेसेम नाम देती, एन.पू.सी. नाम देती। जो भी संस्थाएं कल्पना एवं तरीका, वार्किंग, वह नाम देती और उसमें भी हम कल्पना कर रहे हैं कि कल्पन में सिस्टम समैक्यता का हो रह जाएगी। इसकी को डिलिक्यन न हो। Not even the Chairman is going to have discretion in picking and choosing.

बह भी नहीं कह सकता है कि इसमें यह अवधित होता चाहिए, या वह अवधित होना चाहिये । हम इस प्रकार की अवधिता कर रख दें कि जूने नहीं लगता है कि लियो को इसे एक नामिनेटेट एवं बह करते का प्रकार है । कम से कम सरकार और में नहीं आती है ।

ज्ञायद श्री बड़नवाला ने को या नेबो लानाने का विद्रोध किया है। वै ममता हूँ कि यह प्रश्नवाला बहुत सोच-विचार कर किया गया है। कहीं नहीं। यीराम भी मन व्यक्त किया है कि अगर सारा वैसा सरकार से आयोग, तो सरकार किसी न किसी दिन—प्राप्त नहीं हो कर—उसके नियंत्रित करें। इस लिए पूरा वैसा सरकार के लिए बाहिर है कि यह व्यवस्था, उसके नियंत्रित करें। एरेंजमेंट इस प्रकार के हों कि सरकार को उसके काम के काम देना पड़े। हम ने वरकार की तरफ से ब्रॉड-इन-एड देने की व्यवस्था की है, क्योंकि कोलिन्स के काम के लिए हम की ज़रूरत है।

लेकिन एक बात ऐसा करना चाहता है कि सरकार का इरादा है कि वित्त पत्र की संरक्षितन पांच हजार के कम है, उसका जीवन वित्तन न देनी पड़े—लेटे पत्र पर इस का बोधी विकल्प न पड़े, और आज वहे पत्र हैं, उन पर विडिड बोक पड़े। संरक्षितन ऐसे ऐसे पांच हजार के लिए उत्तर आये, उन समाचार-पत्रों को विधिक बदल, या इस की प्रतिवर्यकारी, तो इन्हीं विधिक विकल्प नहीं हैं। हिन्दुस्तान में बहुत पत्र हैं। इन लिए बदल तभी से बोडा-बोडा हिस्सा आयेगा, तो प्रेस विविद के प्रति आभ्यन्तरीयता का भाव देवा होगा, जो भेज विविद का संवेदा होगा, और जो भवित्व की विधिवत भावहारा और उसके प्रशासन को बदल देगा।

भाषिकांक माननीय सदस्यों ने योगदानिर्वाचन भट्टने की बात कही है। यह सरकार उसके बारे में जागरूक है, और यही कारण है कि इस सरकार ने भारी निर्णय किया कि सेनेट प्रैस कीरण बनाया जाये—हृष्ट प्रैस कीरण भारत से प्रबलीत बाल को पहले बना था—और उसकी टम्पल आफ रेकरेंस में सब से प्रमुख प्रावधान पह है—

"It will examine the ownership pattern and the financial structure of organs of the press with a view to ensuring editorial independence and professional integrity and readers' right to objective news and views and comments freely expressed."

This is one of the primary objectives why we have set up the second Press Commission.

इस कलीग्राम के अधिकारी भीर उन के साथी लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसे प्रेसीडंसी करना है कि वे सात भर में हमारी भारतीय रिपोर्टेजें दे देंगे, भीर जो दूसरा छन्द्रा हम देखते हैं, उस छन्द्रे के द्वारा ऐसे एक निविदा देता है कि उसका एक प्रकार की व्यवस्था कर सकती है।

बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं, जिन का उल्लेख मैं धाराओं और संशोधनों पर चर्चा के समय करेंगा।

एक मानीय सदस्य ने किया प्रभावार—~~संस्कृते~~—में से बोट करते हुए विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी का नाम ले कर कहा कि प्रधान मंत्री जी को कहते पर इलेक्ट्रोटिप्प औकली के समादाक को बहाते ही से हटाया गया। मैं इसका ऊरादार बंडन बांधा। मैंने प्रधान मंत्री की से भी बात की है, और एक बार मैंने स्वयं इलेक्ट्रोटिप्प औकली के समादाक से भी बात करते का योका मिला। उसके बाद मैं इसका ताक साक्षात् बंडन कर रखा हूँ कि जहां तक सरकार का साक्षात् है, उसमें से से ले कर आप तक, कहते पर भी, इस प्रकार की बात नहीं की है, न डायरेक्ट और न इनडायरेक्ट प्रभाव दाता है। सरकार के हाथ में प्रभाव दातेने का जो सत्ता है वह साक्षात् रहता है, वह यहाँ है जिसका नीति, एवं बटाइजमेंट पालिनी है। और आपको इसकी पिछली नवम्बर महीने से जिससे प्रकार से बनी है, जिन गाइलाइन्स के आधार पर बनी है, उससे पाप में हाथ बंधे हुए हैं। भैरों पाप लाग रोज भाते हैं—बात तौर से इन्हें देखते हैं—और कहते हैं कि इस अवधार में विलमता वा, व्यक्तिकृ हम उस समय सरकार के खिलाफ थे, और आप भी हमारे प्रभावाद को कुछ नहीं बिलता है, या बहुत कम बिलता है। मैं उन को कहता हूँ कि आप को जिसने एवं बटाइजमेंट मिल रहा है, वह या बहुत कम वक्तकीली बाते कीसी अवधार को उत्तेज उत्तेज उत्तेज उत्तेज

मिलता है। वे नहीं बता सकते। अगर वे बता दें, तो मैं उसको तुरन्त रेकिंगर्ड करूँगा।

कुछ लोगों ने कहा है कि अगर सरकारेशन के प्रायार पर विवाहित विवेचनों, तो कैसे काम करेगा। मैं नहीं मानता हूँ कि इसके प्रभाव कोई हूँसी करूँटी हो सकती है। यह सब से प्रमुख और अच्छी करूँटी है।

श्री शोभ प्रकाश श्यामी : तो छांटे पेपर्ज की मदद कैसे होती है?

श्री शाल हृष्ण शाहवाही : अगर इसी प्रकार मदद देनी है, तो जिस पद का सम्मुलेन हूँच भी न हो, उसको सब से ज्यादा एडवरटाइजमेंट मिलेगा। और वात मानसिए।

PROF. P. G. MAVALANKAR : Is it the contention of the Minister that circulation is the only and the most effective criterian? If that is so, I want to remind him of what I read years ago when a British journalist said at that time that "Newspapers with large circulation are like fashionable ladies who are more concerned with their figures than their morals"?

श्री शाल हृष्ण शाहवाही : मावलंकर जी ने मुझे टीक किया है एक प्रकार से कर्यांक में मानता हूँ कि यह एक प्रमुख करूँटी है।

It is one of the criteria and it cannot be the only one. But at the same time, all the other things being equal, the difference only being whether this paper supports my Government or not, I want to make this clear because all other things equal mean that both are political papers, the fact that this paper who supports me and the other paper who does not support me will have nothing to do with the advertisement. Political views and political opposition is totally irrelevant so far as this Government's advertisement policy is concerned.

SHRI KANWAR LAL GUPTA Delhi Sadar) : What about yellow journalism? Will you allow such sensational news in this country?

श्री शाल हृष्ण शाहवाही : मैं इस के बारे में यह कह सकता हूँ कि प्रेस परिषद् के गठन के बाद प्रेस परिषद् के जो निर्णय होंगे एवारट येलो जनरलिस्ट, वह भी रिए बहुत सहायक होंगे क्योंकि वह एडवरटाइजमेंट पालिसी को भी प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि इस में यह जकर है कि अगर कोई बालर या आवासी पेपर है तो उस को एडवरटाइजमेंट नहीं दिया जायेगा। इस में कर्यांटी का साकाल नहीं है। हासारी एडवरटाइजमेंट पालिसी में यह बात हो है कि अगर कोई इस प्रकार के पत्र है तो उन को एडवरटाइजमेंट नहीं दिए जाएंगे।

बहुत से ऐसे पत्र होते हैं जो आगे दिए गए इट पोलिटिकल लगते हैं But they are indulging in all kinds of obscenity and vulgarity. तो उन पत्रों के बारे में भी मैं अपेक्षा करूँगा कि प्रेस परिषद् के निर्णय, उन के दृष्टिकोण मेरे लिए सहायक होंगे इस मामले में भी।

कोड आफ कांडकट के बारे में श्री मावलंकर जी ने कहा। उन्होंने स्वयं भी इस बात को एप्रिलिएट किया कि कोड आफ कांडकट अगर बैठ कर के बनाया जाये एक दो तीन बार पाल ड़: कर के तो उस से संभावना है कि उम को कोड आफ डिसिलिन कर के यज किया जाये, बास कर के क्योंकि एमजेसी के दौरान कोड आफ कांडकट भी बात इस सम्बन्ध में की गई कि सरकार की ओर से एक कोड आफ कांडकट बनाया जाये या ए आइ एन ई एस से बनाया कर उस को लेपिस्लेट किया जाए। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रकारों में उम कोड आफ कांडकट से ही परिवर्तित हो गई। मैं जानता हूँ, मैं इस बात से परिवर्तित हो गई। और इसलिए, मैं इस बात को आफ करना चाहूँगा कि जब इस विधेयक में बिल्ड अप कोड आफ कांडकट भी बात कही गई हो वह बिल्ड अप जानवास कर कर कहा गया है। मैं डाउन नहीं हूँ, फारम्युलेट नहीं हूँ और पिछली प्रेस परिषद् ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि हम जो गेंडर्डिकेशन करेंगे, हम जो केस निर्णय करेंगे, उन का जो केस ला बनेगा वह स्वयं में एक कोड आफ कांडकट बनेगा। उमी को कोड आफ कांडकट माना जायेगा। इस के आगे कुछ नहीं।

श्री बेकटरमन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने मेरे द्वारा इस बात को धारा-दिलाया कि गिर्ल्स प्रेस परिषद् रिप्रेंटेव और उम प्रेस परिषद् रिप्रेंटेव के प्रावधान में परिवर्तित हैं। जो कलात्र 13 का मत्र कलात्र (याद) है उम में यह है:

"To concern itself with developments such as concentration of or other aspects of ownership of newspapers and news agencies which may affect the independence of the press."

मैं यह कहना चाहूँगा कि यह जानवास कर हमने लिया है। पिछलो बार की प्रेस परिषद् में, बाहे उस में मोनोपॉली या और जिती अच्छी अच्छी बात कही गई हो, लेकिन मैं पूछा कि उन्होंने किया क्या उस बारे में और कर सकने की कुछ याजाइश भी ही है क्या? प्रेस परिषद् का काम क्या है? प्रेस परिषद् का काम है इंविडेंस

[श्री लाल हुण ग्राहवाली]

आप ये प्रेस से अपने को कहने करता । प्रेस आधिकार का काम बल्ग है जिस का हम जे उत्तराधिकार कि प्रेस कमीशन को तो इन बेष्य जा कर के शोनरविष पैटन के बारे में, शोनोपलोज के बारे में, कसेंशन आफ शोनरविष के बारे में अपनी रिपोर्ट देती पहुंची और हम के आधार पर बालबल आइटरेंटिव आफ के समने रखता पहुंचता । लेकिन So far as Press Council is concerned, that Press Council is mainly concerned with the freedom of the press. और कोडम आफ ये प्रेस जिस मात्रा में कहने करता आफ शोनरविष डारा कुठित होता है, जहाँ लगता है कि ये आर पेपर इकठ्ठे ही गए, इसीलिए वह कम हो गया तो it has to concern itself with that Concern itself does mean, as you say, interest itself in. And when it has to take interest in this particular matter, it has to express itself. हमने यह बात जानवाल कर इसलिए की है कि हम बाहत हैं कि यह प्रेस पारिषद वास्तव में एक इकैनिट बाही बने और जो काम उसके सुरुद्ध किया गया है उसको बह करे । उसमें मोनोपसी की भी यह बात थी । मैं ममताता हूँ मोनोपसी की जहाँ तक बात है It falls more within the purview of the MRTP. यह उनके प्रावधान में आये, उनके लेख में आये । जिस मात्रा में कोडम आफ प्रेस कुठित होती है उस मात्रा में उनके प्रावधान में आये ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : MRTP is absolutely different. Monopoly is in the sense that a chain of papers is owned by certain businessmen. So, the freedom of the editor comes. He becomes the boss. Then again, there is the question of the monopoly of the editor, and then the question of the freedom of the correspondent comes in. You have been watching that a particular editor during the emergency was behaving in a particular way. The same editor now is behaving in a different way. Prior to the emergency he was behaving in another way. So, freedom of the press means the freedom of the correspondent, the editorial staff and everybody. so, what are you doing to do about it ?

श्री लाल हुण ग्राहवाली : इस मात्रा में सहमत हूँ कि कोडम आफ ये प्रेस की जब हम बचाकरते हैं । It means editorial freedom as well as the climate to maintain the professional integrity of those who work in the press. As I have said, I mean the freedom of the press as opposed to the freedom of the purse. I am not talking in terms of the owners of the press.

तो इस से मैं सहमत हूँ लेकिन मैं बाहत या कि जितने सारे प्रावधान होते हैं, आज्ञेक्ट

में बात कर जो होगा They should be practicable. They should not seem just airy words.

केवल नवद प्राइवेट हो जिसमें करना कुछ न पड़े, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए । प्रेस पारिषद के मामले जो काम रखा जाये वह उनको सब कि एकिटोबल है ।

श्री लाल हुण ग्राहवाली : प्रगत इन बातों के अनुसार प्रेस प्रावधान न करे तो उसके लिए कही भी विधान में नहीं है कि प्रेस के खिलाफ क्या एकिटोबल लिया जायेगा और क्या मजा दी जायेगी ।

श्री लाल हुण ग्राहवाली : इसमें सजा देने का कोई कारण नहीं है । दुनिया भर में प्रेस पारिषद की कलना इस प्रकार की कि सजा नहीं दी जायेगी । प्रगत सजा होती तो कानून के अन्यर्थ होगी । प्रगत कानून का उल्लंघन किया जायेगा तो सजा होती । बगर किसी अलबार ने एक बात लिया दी, हरेस्पानिमिल बात लिया दी I would say it is carelessness, not being particular about being accurate about one's report. मैं जानता हूँ बालकर लेकिन मैं जो प्रमुख अलबार है वह बहुत तरक्की रहते हैं लेकिन के बाद काउंटरके करते हैं और जब तक पूरा विवाद नहीं हो जाता तब तक अलबार नहीं छापेंगे । प्रगत हम में से किसी ने बाटरेंट के सारे काम को कालो किया होगा और ये प्रमिल पृष्ठक लिखी गई है उसका पढ़ा होगा तो देखा होगा, यद्यपि जो बात कह रहे थे वह गही थी लेकिन कहीं बारीकी में दीया था गया तो फिर उनको कितना प्रबलानप होगा, एडिटर को कितनी प्रेरणानी होती थी और कितना एम्परेंट होता था । मोटे तौर पर ये बात कह रहे हैं कि वह सही है लेकिन अलबार में, डिटेंस में हमारी पढ़ बात गलत क्यों निकली— इस बात की उल्लंघनता होती थी । मैं सबक्षता हूँ हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे प्रबलानप हैं जो बहुत सावधानी रखते हैं और इसीलिए उनका बहुत है । प्रगत एक प्रबलानप ने लिखा है, उसका साइड प्राइविकल है तो लोग कहते हैं कि कलाने ने लिखा है इसके बाहर कुछ होता । लिखा लैंगरी के यह आटिकल नहीं लिखा गया होगा । यह केबिनिटी तरफ देवलप होती है जबकि प्रबलानप स्वयं सतर्क ही, जागरूक ही और टच के बारे में, सच्चाय और इमानदारी के बारे में वह सावधान रहे । मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेस पारिषद लिखियक पारित होने के बाद ऐसी अलबार हो जायेगी कि एक तरफ तो आत्मानुकासन का अतिरिक्त लिल जायेगा और दूसरी तरफ प्रेस की आजादी पर, जहाँ से भी आक्रमण होगा, जहाँ से भी हस्तक्षेप होगा, वह बाहें सरकार की ओर से हो या मानवांक की ओर से हो या किसी भी तरफ से हो, एकदृष्टिक्षम से तरफ से हो उस पर दोक लगेगी । इस उम्मीद के साथ मैं इस विवेदक को सबन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ ।

SHRI B. K. NAIR : Clause 14 of the Bill provides for punishment—warning, admonishing, censuring and all that. All these actions are aimed at journalists, editors and other parties. Do you conceive of any action on the part of the owner of the newspaper which may call for censure or any other punishment for the offence committed by him, who is a very prominent constituent of the Press Council? Does the owner come under this Act for punishment for any of his actions?

SHRI L. K. ADVANI : Why not? He is not free from...

SHRI B. K. NAIR : He is not free? He is above all these? There is no censuring, no admonition or no other punishment for him? Does he not commit any offence?

SHRI L. K. ADVANI : If you see clause 14, it is stated :

"Where on receipt of a complaint made to it or otherwise, the Council has reason to believe that a newspaper or a news agency...."

It does not mean the editor, it may mean the manager, it may mean the owner. It depends upon the Council's assessment or the appraisal of the case as to who is at fault and then he will be censured.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will you take the representatives of the readers on the Press Council? This is very important because you have to educate the people.

SHRI L. K. ADVANI : Mr. Chairman, this point was made by Mr. Kanwar Lal Gupta at the outset. I may point out that in India we do not have associations of readers as such. But the lay members of this Council which include all the five Members of Parliament, the representatives of the various councils, academies, the Sahitya Akademy or the U.G.C.—all these are supposed to be there as representatives of the readership. Their capacity to be there is as reader. Incidentally I may mention that five of us, Members of Parliament, are there on the Council and I would be very happy if by convention one of the Members of Parliament nominated to the Council is a trade unionist. I would be very happy about it. This is something that was suggested in the Joint Select Committee and there I said that I would certainly like to express a wish in the House when I reply to the debate because it will be for the Speaker to nominate or the Chairman to nominate. If this happens by convention, it would ensure that a large section of the workers in the country are represented.

SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN (Deogarh) : Mr. Chairman, the hon. Minister just now said that papers having a circulation of less than 3000 will be free from the payment of subscription. But this is not provided in the Bill.

SHRI L. K. ADVANI : I will explain this when we deal with clauses. We now come to the clauses because there are amendments on them.

MR. CHAIRMAN : Now, I put the motion for consideration of the Bill to the vote of the House.

The question is :

"That the Bill to establish a Press Council for the purpose of preserving the freedom of the press and of maintaining and improving the standards of newspapers and news agencies in India, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up clause by clause and amendments thereto. First of all we shall take up clause 2. There is one amendment, amendment No. 130 by Shri C. K. Chandrappan and Shri K.A. Rajan.

Clause 2 (Definitions)

SHRI K. A. RAJAN : Sir, I move:

Page, 2 line 3,—

after "working journalist" insert—
"and other newspaper employees".
(130)

MR. CHAIRMAN : I now put amendment No. 130 to the vote of the House.

The question is:

Page 2, line 3,—

after "working journalist" insert—
"and other newspaper employees".
(130)

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is : "That clause 2 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 5 (Composition of the council)

SHRI BHUSAHEB THORAT : I beg to move :

[Shri Bhausaheb Thorat]

Page 2, line 19,—

for "twenty-eight" substitute "thirty"
(1)

Page 3,—

after line 10, insert—

"(f) two shall be members belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, each nominated by the President of India;" (2)

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : I beg to move :

Page 3,—

after line 10, insert—

"(f) one shall be nominated in accordance with such procedure as may be prescribed from among persons who send news to newspapers (correspondents):" (45)

SHRI A. K. ROY : I beg to move :

Page 2, line 21,—

after "nominated" insert—

"from the panel of three persons suggested by other members of the Council" (60)

Page 2, line 28,—

for "thirteen" substitute "eighteen"
(61)

Page 2, line 28,—

for "nominated" substitute "elected"
(62)

Page 2, line 30,—

(i) for "six" substitute "three".

(ii) for "seven" substitute "fifteen"
(63)

Page 2, line 34,—

for "three and four" substitute
"two and eight" (64)

Page 2, line 34,—

for "six" substitute "three" (65)

Page 2, line 35,—

for "nominated" substitute "elected"
(66)

Page 2, line 40,—

for "nominated" substitute "elected"
(67)

Page 3, line 4,—

for "Bar Council of India" substitute
"Indian Science Congress" (68)

Page 3, line 6,—

(i) for "five" substitute "three"
(ii) for "three" substitute "two" (69)

Page 3, line 8,—

for "two" substitute "one" (70)

Page 3, line 10,—

add at the end—

"who are not members of any other Committee of the Parliament" (71)

Page 3, line 14,—

for "nominations" substitute
"elections" (72)

Page 3, line 15,—

for "nominated" substitute "elected"
(73)

Page 3, line 23,—

for "fifteen thousand" substitute
"ten thousand" (74)

Page 3, line 26,—

for "fifteen thousand" substitute
"ten thousand" (75)

Page 3,—

for lines 27 to 38 substitute—

"(4) Before making any nomination of Chairman under sub-section (2), the members of the Council shall be elected by secret ballot as per the provisions laid down in sub-section (3) under the supervision of the Election Commission in accordance with the existing law". (76)

Page 3, lines 39 and 40,—

for "nominated" substitute "elected"
(77)

SHRI AJITSINH DABHI : I beg to move :

Page 3, line 41,—

for "fifty" substitute "seventy-five"
(89)

Page 3, line 29,—

for "fifty" substitute "seventy-five"
(90)

SHRI ANANT DAVE : I beg to move :—

Page 2, line 20,—

add at the end—

"and one member of every State Legislative Assembly nominated by the Speaker of the Assembly who shall not come within the meaning of section 24 of this Act and who shall simply assist the Council and protect the interest of small newspapers of his State" (98)

SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move :—

Page 3, line 31,—

for "panels of names comprising twice the number"

substitute "the required number of names" (103)

Page 3,—

after line 17, insert—

"Provided also that in case nominations under clause (a) and clause (b) do not include any member from any one or more of the languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution, such additional number shall be nominated so as to secure members from all such languages," (149)

Page 3,—

after line 38, insert—

"(4A) Before making any nominations under the third proviso to sub-section (3), the Central Government shall, in the prescribed manner, invite names of the required number of members to be nominated from such associations of persons as may be notified in this behalf by the Central Government." (150)

SHRI B.C. KAMBLE : I beg to move :—

Pages 2 and 3,—

for lines 27 to 42 and 1 to 47, respectively, substitute—

"(3) of the other members—

(a) fifteen shall be elected from amongst the working journalists including editors; the persons who own or carry on the business of

management of newspapers, big medium or small newspapers, those managing news agencies, by electoral college of members of the above mentioned bodies;

(b) ten shall be elected from amongst the members of the House of the People;

(c) five shall be elected from amongst the members of the Council of States.

(4) The Election Commission shall be entrusted with the preparation and conduct of and superintendence of these elections as may be prescribed by the Government.

(5) Central Government shall notify the names of persons elected under sub-sections (3) and (4) in the Official Gazette and the same shall take effect from the date of notification." (109)

SHRI R. VENKATARAMAN : I beg to move :—

Page 2, line 10,—

after "Chairman" insert—

"who is or has been a Judge of a High Court or Supreme Court" (120)

SHRI K. A. RAJAN : I beg to move :—

Page 2, line 19,—

for "twenty-eight" substitute "thirty-two" (131)

Page 2, line 28,—

for "thirteen" substitute "fifteen" (132)

Page 2, line 30,—

for "seven" substitute "nine" (133)

Page 2,—

after line 39, insert—

"(bb) two shall be nominated in accordance with such procedure, as may be prescribed, from among the other newspaper employees;" (134)

Page 2, line 41,—

for "who manage" substitute—

"who are working in" (135)

SHRI YASHWANT BOROLE : I beg to move :—

Page 2, line 26,—

add at the end—

"and the Committee, as far as possible shall, nominate a person as Chairman having judicial background." (137)

SHRI BHAUSAHEB THORAT (Pandharpur) : Mr. Chairman, Sir, I have suggested two amendment to Clause 5 and in those amendments, I have suggested that the Press Council should consist of a Chairman and thirty other Members in order to accommodate two Members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is my suggestion.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput) : I have given notice of amendments No. 8 and 9, which are identical with amendment Nos. 1 and 2. I have also given notice of an amendment to clause 13 i.e., my amendment No. 10 and here I would like to refer to the same. I will read out that amendment.

"Page 6—

after line 35, insert—

"(1) to encourage the newspapers, news agencies and journalists to undertake the greater responsibility for the upliftment of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and economically backward classes by highlighting the true and correct socio-economic and cultural conditions in national and regional papers."

If the hon. Minister is not agreeable to amendment Nos. 1 and 2, I would request him to make at least a provision in clause 13, so that the Press Council can deal with the matter.

श्री सर्वजी नारायण नाथक : मेरा संघोदन मह है कि जो दीस सदस्य रखे जाएं उन में संवादवातामां के प्रतिनिधियों को भी रखा जाए। संवादवाता समाचारपत्रों के महत्वपूर्ण दंग होते हैं और वे संवाद एवं करके भेजते हैं और इस काम में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसलिए प्रेस कार्डिनल में इनके भी प्रतिनिधि होने चाहिए, यही मेरा सुझाव है।

SHRI A.K. ROY : Mr. Chairman, Sir, as I already said sometime back, the freedom of the press means, freedom of the pen, freedom from the purse and freedom for the people. No freedom is

possible otherwise if the body which will give freedom is not democratically constituted. So, this Clause 5 is very important as it is concerned with the making up of that body.

Any democratic body is formed from the bottom, from below. Any autocratic body is formed from the top. Any type of oligarchy is formed from the top. The whole body has been formed from the top. Somebody is nominating the Chairman; somebody is nominating the members and somebody is nominating others. I have proposed that first the members of the council will be elected from different categories, as I have explained. Then, that Council will propose a panel of three names from amongst whom the Chairman will be elected. There will be one representative on behalf of the Speaker of the House of the People which is an elected body; one representative on behalf of the Chairman of the Council of States which is also an elected body and third one will be on behalf of the members of the Council. So, the panel of three will be an elected body. The Chairman will be elected from the panel of three names which would be suggested by the members of the Council and which would be an elected body. In this way, I think, we can have a truly democratic body to bring or to enforce democracy in the press.

As regards the membership also, you will find that the members nominated from amongst working journalists are in a minority. Under the present Press Council Bill, only seven members will be taken from working journalists and five Members of Parliament, three from the Lok Sabha and two from the Rajya Sabha. These people will have direct concern with the people outside. I have proposed that out of 29 members of the Council, the majority of members should be from working journalists, that is, 15 members should be elected from amongst working journalists; two members from the Lok Sabha and one member from the Rajya Sabha, three from the editors; three from the management, etc. But the majority in the Press Council should remain in the hands of working journalists if we want to give freedom to the press, freedom of the pen, freedom from the purse and freedom for the people.

I have suggested that we must give a scientific orientation to the society. And that is what is needed most. We do not want much of litigants. We have got enough lawyers both within the Parliament and also in the politics outside, in our Cabinet and in every sphere of our life. We have got enough lawyers everywhere. It is becoming a lawyer's paradise. And I believe they are interested in increasing the

arena, in increasing the power of the courts and to curtail the power of the Parliament. That is why I have suggested that at least let the Press Council be free from these lawyers. Yea, you can have one member from the University Grants Commission. He will be an academician. The one from the Sahitya Academy will be a good litterateur. Then with respect to one member from the Bar Council of India, instead of the Bar Council directly or indirectly dominating everywhere, I suggested let one member be from the Indian Science Congress so that in the Press, in the Television and in the Radio a scientific outlook is correctly projected as the hon. lady Member was telling that now-a-days radio and television is preaching superstition.

What I am pressing on our Minister is: let him beware of the Bar Council. We should take precaution. Otherwise, they will enter and you will be out. So, I have suggested that instead of the Bar Council, have one member from the Indian Science Congress so that you can project a scientific outlook both in the Press as also in other spheres.

Another thing is: I have put certain limitations on the members who would be from the Rajya Sabha and the Lok Sabha and who will be selected from the Bar Council. As in the society outside, there should be one man, one job, at least within the Parliament. Here you will find that many of our members are busy with so many jobs and many of our members are sitting idle like me in the back benches, doing nothing and not even getting a chance to speak. At least let the principle of one man, one job be applicable within this House so that members who are members of other bodies would not be taken into this Press Council. The membership of the Press Council will have nothing to do with other spheres—there I have said, 'No'. Only those members who are not members of any other bodies will be eligible to become a member of the Press Council. We are talking of diffusion of ownership and distribution of facilities. In this way, at least within the Parliament, let us distribute the facilities. That is why I have said that members who are already members of other committees like Estimates Committee, Public Accounts Committee or Public Undertakings Committee, this committee or that committee would be debarred from becoming a member of the Press Council.

Regarding nomination I have said that the members of the Press Council will be elected from different organisations through a secret ballot and with the help of the general election laws and under the guidance of the Election Commission. That also I have said because the very idea

of nomination is incompatible with the spirit of democracy we want.

SHRI AJITSINH DABHI (Anand): Mr. Chairman, Sir, I feel that in view of the report of the Newspaper Economy Enquiry Committee of 1975, and observations made therein, the definition of newspaper given in the Bill should be amended.

I will actually quote the words of this Committee wherein it has been stated that :

"Small newspapers may exist simply for the purpose of acquiring of newsprint allocations depending on the revenue on the blackmarket sales of the quota or a part of the quota."

So, in order to ensure that this mischief regarding the newspaper quota may not continue, the definition clause should be amended. Instead of 50,000, 75,000 should be there.

MR. CHAIRMAN : Mr. Anant Dave. He does not want to say anything. He was there at that time. Shri Banatwalla.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Sir, I have moved three amendments. My first amendment is with respect to the manner in which the Council will be composed. It is strange that the Bill has a partial or a hesitant approach to the principle of election. When nominations will be required to be made under Clause 5, sub-clause 3(a) and (b), names will be invited from the relevant associations. But these associations will be called upon to suggest twice the number that is sought to be nominated and then, out of this panel, nomination of persons is required to be made.

If we read sub-clause (4) to Clause 5, in the first instance, we find that the wording is very vague. It is clear that in the case of first nomination, the Central Government will call for the names from the relevant associations. It is also clear that in case of subsequent nominations, the retiring Chairman of the Council will call for the names from the relevant association.

It is, however, not clear from the wording of this sub-clause (4) as to whether it is the retiring Chairman in the subsequent cases who alone is going to sit in judgment and select the final persons from the panel suggested by the relevant association. I submit that this method will not be proper. It is necessary that the principle of election should have a fair and full place. There is no reason why associations should be called upon to elect twice the number required to be nominated. Then, somebody else has to sit and to name them out of that panel that has been elected by this Association. This, I say, is a partial

[Shri G. M. Banatwalla]

approach, a hesitant approach, towards the principle of election. It should go.

Therefore, my amendment seeks to provide that the relevant association should elect the number required to be nominated and those elected by the relevant association should be nominated on the Press Council.

MR. CHAIRMAN : Mr. Banatwalla, do you want more time or you will finish with a sentence or two?

SHRI G. M. BANATWALLA : I am still to speak on two more amendments.

MR. CHAIRMAN : Then you may continue your speech on a later date when it is taken up.

16.00 hrs.

MOTION RE. INCREASING PLAY OF MONEY POWER IN ELECTIONS

MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up Mr. Unnikrishnan's motion.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara) : Sir, I beg to move:

"That this House is of the opinion that increasing play of money power in elections pose grave threat to the future of Parliamentary Democracy as evidenced by the recent revelations of collection of huge election funds by some important persons including Ministers and those who are in proximity to high offices of power and decision making."

Sir, I rise to move this motion with great sorrow and anger and also with deep concern because in recent months and weeks this country has gone through many traumatic experiences which come across the history of nations on very few occasions. But this country went through a crisis of confidence in ability to run its democratic institutions which the people of India had earned for themselves through their national struggle under the leadership of Mahatma Gandhi and Jawahar Lal Nehru.

Now, Sir, I am deeply worried not only about the troubled present but also about the future. Sir, you are probably familiar with a term, in Greek terminology they call it 'Catharsis'. Has this country and its democratic institutions come to this moment of catharsis. We have lived through these experiences—as I have noted—and we thought in March 1977 at a moment of decisive intervention by dumb millions that things would be set right. A new order was born, it was announced from house tops by Jayaprakash Narayan, by Moraji Desai, by Chandra Shekhar

and even though it was a conglomerate which had come into power they went to Rajghat to seek inspiration.

As I recall, one other vow which was taken was to cleanse the public life and to fight corruption. A man, who, we thought was an apostle of the new regime, an apostle of fearlessness, took over as Prime Minister of this country. He had a long and distinguished record as a fighter in the freedom movement, long record of administrative experience in various capacities. But what we thought he had more than all these was certain moral fibre. He claims to be the disciple of Mahatma Gandhi and he has been associated with him. We had a Home Minister who is absent today—the then Home Minister—who repeatedly told this House that we shall not rest till corruption is totally knocked out and destroyed. We thought, here was a new crusader. Commissions were set up. Cases were filed against what was known and what was publicised as criminal activities of the previous Prime Minister, the caucus around her. And the list did not end there. It was extended in an act of megalomania to many others. I recall that one of those cases was the way the congress party collected its election funds or funds in general. We had expressed the hope on our side that at last a new nation would emerge out of this with its moral fibre strengthened.

But, Sir, today where are we? The Indian National Congress did not accept the political base of the Janata party or its thrust and attitudes to various national and international questions and many other policies that were proclaimed. But we said this. I recall the Resolution of the AICC in May 1977 that we shall not shield corruption, we want to cleanse public life. If we are guilty, through legal means, pronounce us as guilty and punish us. This was the attitude that we took. We hoped that the long awaited reform of elections would come. We hoped that the campaign against corruption in high places will be taken to its logical end. We hoped that the wheel would have turned a full circle. Today the wheel has again turned.

This conglomerate which took over is in shambles. Its Titans are locked up in a grim battle, not over policies and principles, but over positions of power, over chairs as Raj Narain was fond of saying. He once called Charan Singh, Chair Singh. The Chair Singh is again active. The entire moral worth and credibility of this conglomerate, as Babu Jagjivan Ram has called it, is in shambles. It is eroded. The hopes and the dreams and the aspirations of the people of this country who fought for you and who thought that distortions will be corrected, are shattered today. Why should this country traverse this path,

this trajectory? That is my concern today, Sir. Sometime ago there was what is known as a correspondence between the Prime Minister and the then Home Minister Mr. Charan Singh. It was reported in the press that the allegations treated in these letters may not be specific but the thrust of the correspondence was that things have to be enquired into that a belief, strong belief or conviction is there in high places that corruption has entered the *sanctum sanctorum*. It is very unfortunate that we should be discussing this issue and this Parliament should be concerned day in and day out with these issues, which I will say, are peripheral issues. We are discussing this issue, which is important for our functioning, but this House has no time to discuss basic questions of our economic life, economic policy. I would say that this Government and the Prime Minister are responsible for the situation, for having brought this House to this situation, because the opposition in a parliamentary democracy has a function to perform. The attitude of high and mighty that the Prime Minister took and his Party took has forced the opposition into this position, which is not very natural position, not very important from the long-term perspective of the country, but you have compelled us to take this position.

After this correspondence, Shri Virendera Kapur of Indian Express brought out a story—I will come to other stories later—that Shri Madhu Limaye, General Secretary of the Janata Party—I do not know whether he has resigned or is still there—has said that Rs. eighty lakhs or more were collected by Shri Kanti Desai towards the election funds of the Party. Shri C. B. Gupta, the treasurer of Janata Party, said that it was not Rs. eighty lakhs, but Rs. ninety lakhs and I had said that it was neither Rs. eighty lakhs nor Rs. ninety lakhs, but it could be anywhere around Rs. one and a half crores. Shri Madhu Limaye later took a position that he would neither deny nor confirm it. He has not denied it, all that he would say that he would neither deny nor confirm it. This revelation is of crucial significance.

In March 1977 and later in June 1977, when elections were held to the State Assemblies, Shri K. Santhanam, who was the Chairman of the first Committee for Electoral Reforms, who had been exercised over these things as a patriot for a long time....

AN. HON. MEMBER : That Committee was concerned with elimination of corruption.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : charged the Janata Party with extorting money by using unfair means. The reply came from the Party Chairman, Shri Chandra Shekhar, that they had never asked

any of their Ministers to collect money and Shri C. B. Gupta, treasurer of Janata Party said that they had not asked any one, only authorised persons were collecting the funds. Mark the word 'authorised'. This was on May 24, 1977. He said: "Only authorized persons." When he was asked to disclose as to who were these authorized persons, he said that 'it was an internal affair of his party.'

I do not want to take the position to-day that parliamentary democracy, our institutions and the electoral system or the party structures that we have inherited due to historical circumstances, can be run without money. I am not taking that position at all. And these were some of the debates that we had in the past in the Congress organization itself. But the basic question is not only one which concerns the immediate present, but also one which concerns the future. Immediately we are confronted with a party which, having come to power, having taken a pledge at the *Samadhi* of Mahatma Gandhi and entered the portals of power, is now in shambles. Not only that; its moral worth and credibility have been eroded. It is not merely a question of collecting election funds. It is the means which have been used in collecting these funds, as well as the nexus between administrative actions and collection of these funds, as also collections by unauthorised persons, which breeds corruption in the whole system. There lies the crux of the matter.

As I said earlier, Commissions of enquiry have been set up and many, including Mr. P. C. Sethi who was treasurer of our party, are still facing similar charges. I do not want to go into details, because some of them are *sub judice*. This is the time when this House should assert itself, to guide us, because the party which came to power on the same platform, after a prolonged agitation in Bihar and Gujarat—which, according to Jayaprakash Narain centred around the theme of corruption in high places—is in such a state that its moral worth has further deteriorated. So, in an environment like this, it is time that this House intervenes effectively and decisively, no matter who is involved, and says: "We shall not go back to the situation where we came from." It is in this spirit that I look to this Motion to-day.

When allegations are made, the obvious reaction should be that one cannot judge oneself. That is the basis of our functioning or the basis of any kind of functioning. I do not want to call it juristic; it is basic, simple, commonsense.

What are these allegations? I shall take one allegation, *viz.* that Mr. Kanti Desai collected Rs. 80 lakhs or Rs. 90 lakhs: figures are not that relevant, but the fact

remains that — it is admitted that large sections of people in this country believe that — he collected not only funds, but also that it has not been fully accounted for. The question is also whether he had the permission, because he is in close proximity to the highest centre of decision-making in this country. Mr. Morarji Desai has gone on record as saying that he (Mr. Kanti Desai) terminated his business connections as early as in 1964. On 30th July 1968, in reply to Mr. Umanath and Mr. Madhu Limaye he told this House — and I quote — "Let him know that my son has given up business from the year 1964, and not now." But subsequently it was known that he continued in this business. So, possibly it could be that because he was involved in that business in the past and had been in the business contact, the Janata Party decided to make use of his good offices. But the trouble here is that he is not a nobody. I do not dispute his right as a citizen or a political worker; if he wants to enter into politics and remain in politics, I do not dispute it at all nor do I say that the Party should not collect funds.

But, as I said, his activities have bred corruption; his activities have led to what Justice Shah called "Deviation from established administrative procedure" for which the people are being arraigned. It means subverting the established administrative procedure and misuse of authority. This is the crux of the problem.

Now I am happy that the Finance Minister is here. I do not want to go into lot of things because there are lot of things to be talked about what is going on in his Ministry from March 1977 to this day. But I only want to mention a few things. You are aware of the situation of the Central Board of Direct Taxes. Mr. Kanti Desai, one fine morning, last year, landed in Calcutta. A group of businessmen met him and lobbied the case of Mr. I. P. Gupta and said that he should be appointed as the Chairman of the CBDT. I am told, a substantial amount of Rs. 50 lakhs was donated to Janata Party's fund as a *quid pro quo* for making Mr. I. P. Gupta as the Chairman of the CBDT.

Now, Mr. Kanti Desai, as an experienced businessman who keeps his words, had to promote his candidature when the post of Chairman fell vacant. The appointment is of the rank of the Additional Secretary to the Government of India and governs the rules made by this House, according to the Central Board Act of 1953. The order of seniority for this post was: (1) Mr. Kailash Narain, (2) Mr. I. P. Gupta and (3) Mr. Kuruvilla for reasons I have explained. The choice of Mr. Kanti Desai fell on Mr. I. P. Gupta. But the Central Vigilance Commissioner was investigating certain serious allegations against Mr.

Gupta. The Finance Secretary approached the Central Commissioner Mr. Pimpukar who refused to submit to the pliant demands of the messengers and couriers of Mr. Kanti Desai. Mr. Kailash Narain was overruled for Janata Party's political views; and the Finance Secretary then suggested and the Finance Minister and the Minister of State endorsed it on the file that Mr. Kuruvilla be considered. The Prime Minister was away in Kashmir. But Mr. Kanti Desai did not stop, conscious as he was of his commitment to his friends who were pressing him. After this again the Finance Secretary was sent to C.V.C. — All this can be checked up — to revise its opinion about Mr. Gupta but he refused to do so. The dates of his meeting also are important.

MR. CHAIRMAN : Two hours time had been allotted; you can take half an hour; you have already taken 25 minutes. You have to look at the watch also.

AN HON. MEMBER : Time will be extended.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : There were other members. I shall cut short my observations because there are many other kisans also — members like Mr. Srinivasan, Avtar Singh etc. on the Board. Mr. Badami for whom I have personally high regard and I hold him in great esteem, who was in charge of forfeited property was brought in. When it went to the Appointments Committee of the Cabinet he was not a member of the Board. According to the Gazette of India January 1, 1964 notification of the ministry of finance rule No. 3, it says: The Central Government may by notification in the Official Gazette appoint one of the members to be chairman. I do not think the Appointments Committee was told about this. He was appointed straightforward, asked simultaneously to become a member and then take over as chairman. CBDT and settlement commissions have been important arenas of Kanti Desai's operations. I want an enquiry; I challenge this government to conduct an enquiry; how many settlements have been effected since April 1977 till October 1977 and then from November 1977 to June 1978? How many violations were there? Clause 245 (d) of the Income-tax Act of 1961 says: sub-section 1, proviso (3) of 245: Provided further that an application shall not be proceeded with under this sub-section if the commissioner objects to the application, being proceeded with on the ground that concealment of particulars of income on the part of the applicant or perpetration of a fraud by him evading any tax or other sums chargeable or assessable under income-tax has been established or is likely to be established before any income-tax authority.

section 30 the Official Secrets Act. Please. How many fraud cases have been settled? There are clear implications. I do not want to mention names because of shortness of time. How many cases have been decided against the clear cut advice of the Commissioners, particularly in Bombay circle and in Ahmedabad circle. I do not want on this occasion to refer to some firms—because that is outside the scope—with which the Finance Minister was earlier connected or firms with which the Secretary to the Prime Minister, Mr. Shankar was connected. That is outside the scope, I presume. What I want to know is: tell us the donors to the Janata Party election funds; give us the accounts; then tell us—the House and the country are entitled to know—how they have been favoured by the income-tax and CBDT and settlement commissions.

MR. CHAIRMAN: Your half an hour is over. You know the total time is two hours.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: I have to tell you more.

MR. CHAIRMAN: You must finish in five minutes.

SHRI VINODBHAI B. SHETH (Jamnagar): Ultimately he is going to prove that Janata Members are not interfering in the day to day affairs of the government.

How much of it was in black money?

MR. CHAIRMAN: How much of time do you expect me to give you?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: I will take at least 15 minutes more.

MR. CHAIRMAN: How is it possible? Out of two hours if you take 45 minutes, then what about others?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Time may kindly be extended.

In regard to settlement of income tax and wealth tax, what about penalty and prosecution and in how many cases was the interest waived? This is one question. How much was it in black?

On this question of appointment Mr. Morarji Desai, who happens to be the Prime Minister now, once recalled the advice that he gave to the then Governor of Bombay in 1939—Sir Roger Lunley who had approached the then Revenue Minister with the request that somebody be appointed for some minor post. Mr. Desai asked him how dare you ask me to do this. I am not going to do it. But, unfortunately, when Kanti proposes, things are different. Now, I do not want to go into various questions like Polyester Filament Yarn, C.P.M.O., and how they are connec-

ted. But I must tell you something of which I have the privilege to bring about, regarding Hindujas Bros. A very important question has arisen out of this. That is not the question of 11 million dollars, which I have brought before the House and the Prime Minister's Secretariat, I allege, was requesting the President of India to get invited for the banquet, latest on this last trip of Mr. Kanti Desai or the Prime Minister's trip. Hindujas were consorting with him in Hotel Beauvivage in Geneva. It has been the scene for money collections—unauthorised collections in foreign exchange. Not merely Hindujas, there are chibas in Westbury in London. How much was collected in the last trip i.e. in 1977? Janata Party and the Government of India, do they know how much has been collected not merely through their independent contacts, not in Indian currency but in foreign exchange?

Now, what is relevant is, I refer to the Central Vigilance Commissioner's latest Report, wherein there is a very interesting case regarding Hindujas Bros. An Indo-Iranian firm produces a film called 'Subhadra aur Sham' and without the knowledge of the Information and Broadcasting Ministry and Customs Finance Department was brought to India. It was changed and was made a film. This happened during Sanjay Gandhi's days. But the point is the officials were proceeded against as a result of C.B.I. enquiry, not the Hindujas. To this day no prosecution has been launched.

Now I refer to the Hindu Report of July 24, 1978, Heading—P.M. Tops Slush Payment. What was the payment of \$ 450 million? What was this contract of \$ 450 million? Was it the same that Kanti discussed with Hindujas in Hotel Beauvivage, we want to know? That is an access. The source is these corrupt links. Now, investigations were held in another case—Boeing purchases regarding Maneckji. The two serious things to which I want to draw your attention are these. On 30th September, 1977, in spite of his friend Shri Kanti Desai being in a position of power and influence, he had to be charge-sheeted because it was linked with other VIPs of the former regime. In the FIR submitted to Mr. Kotwal, the Additional Chief Metropolitan Magistrate of Bombay, under section 56 of FERA of 1973, two lines of enquiry were to be pursued. One was that Commandant-General Maneckji and his younger brother, Kekoo used part of the money to promote the sale of Boeing aircraft by bribing Cabinet Ministers and highly-placed Government officials. The second was that Mr. Kekoo Maneckji received unauthorised information of a secret nature relating to the development and acquisition of defence aircraft and stores in our country, which is punishable under Section 3

[Shri K.P. Unnikrishnan]

of the Official Secrets Act. Please refer to page 84 of the CBI report for 1977 placed on the Table of the House, where what I have read out has been substantiated. I would like to know what has happened. The moment the investigation reached the point of Kanti-Shankar axis, the investigation was stopped and has found itself in a blind ally! How much money has come through, Mr. Haridas Mundhra should be able to tell us. He is another new friend. I do not want to go into all these details. It does not end there. The kiss of Janata misrule and corruption that they are breeding in this country, all in the name of election funds, does not end here. There was the question of impounding of passports in April, 1977. I would like to know how the passports of Mr. Raunaq Singh of Raunaq International were returned. Who was lawyer Juneja who approached the close relatives of the then Home Minister and get it out for a consideration? Mr. Charan Singh has always been very vehement on the issue of corruption. Speaking in this House on 13th July, 1977 he said:

"Corruption is prevailing from top to bottom. Political leaders and Ministers are not also free from it. The moral fibre in this country has completely collapsed." But he allowed his son-in-law that is the tragedy of this country what do you do with them?—to interfere in the cases of impounding of passports of criminals and racketeers who abound in this country? Armed racketeers are now around because we are considering the purchase of DPSA and Mr. Kanti Desai cannot deny that he met the racketeers Chibber Brothers in Westbury Hotel in London. I am making that charge.

I do not see the former Health Minister here unfortunately. He should have been here. We are entitled to know from him how much money was collected by his Special Assistant, Mr. Chitrangad Singh. It is a very amusing story, the collections made by his Special Assistant.

Mr. CHAIRMAN : You should conclude now.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : Before I conclude I would like to say something about this Mr. Chitra Angad Singh.

श्रीमती बलबीर तिह (होमियास्पर) : यह बाये तेजा वही नहीं था, को जिससे हांदरा नहीं लिक कोइ निला था ?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN :

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस जूलाई में हीटल बुरवाज, जेनेवा में शंकर साहब और कांति देसाई जिससे मिले थे, वही थमे तेजा ।

Mr. Raj Narain had a very colourful Private Secretary or Special Assistant known as Mr. Chitra Angad Singh. It is rumoured that an enquiry is going on. Ms. Chitra Angad Singh was not merely colourful but he also understood the requirements of political finance of his mentor and his group. He used many ordinary and extraordinary means. One of them is very amusing. There were three Persian carpets belonging to a VIP which on a fine March morning of 1977 found its way to Vishwayatan Yogashram. Swami Dharendra Brahmachari tried to take them out but by that time, he had come under surveillance. So, they got stuck there at Vishwayatan Yogashram. Mr. Raj Narain appointed an Administrator of this Ashram a man called Chhatrasal Singh from UP who had nothing to do with yoga but every thing to do with Chitra Angad Singh. One fine morning, all the carpets including these carpetworth lakhs of rupees, *kambals*, mattresses, lock, stock and barrel were removed from the Ashram. Many have been returned but not these expensive carpets.

The whole question is one of standards. We had set up certain standards in this country because Mr. K. D. Malavia's Personal Assistant was found having collected Rs. 10000/- An inquiry commission was set up. It was scrutinised. An inquiry was held by a Supreme Court Judge. He resigned. These were the standards we had set for ourselves in this country. Now, Sir, I want the Prime Minister to be remembered in this country, remembered by posterity not as a father who showed infirmity at a crucial moment of his own life and the life of this country, but I want him to be remembered, as I said, as an apostle of fearlessness who came from Raj Ghat, went to define certain standards of public conduct to strengthen the moral fibre of this country. This is what is lacking today. I recall what he told this House on 9-12-74. This is what power corrupts. I quote :

"I hope the Prime Minister will realise it if not today some day, it will have to be realised."

I hope, Morarji Bhai will not abdicate his commitment. I hope, he will not abdicate his position of responsibility or what he owes to this country which has put him where he is. I have not said this out of a perverse love. I have not said this out of personal prejudiced. But if you want to cleanse the system, you will have to. And about this I shall come back in my reply.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That this House is of the opinion that increasing play of money power in elections pose grave

threat to the future of Parliamentary Democracy as evidenced by the recent revelations of collection of huge election funds by some important persons including Ministers and those who are in proximity to high offices of power and decision making."

Now, amendments will have to be moved.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN (Seoni) : I beg to move :

'That in the motion,—

after "evidenced" insert—

"since the elections of 1971 and" (1)

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : I beg to move :

'That in the motion,—

add at the end—

"and recommends to the Government to bring forward expeditiously legislation by which all political parties in the country should be registered under the Registration of Societies Act, 1960 (as amended up-to-date) and should maintain accounts of all their receipts revealing their sources and expenditure supported by stamped vouchers and publish annually a statement of receipts and expenditures duly audited and certified by a chartered accountant which should be published in the Gazette of the Government of India." (2)

SHRI SHANKAR DEV (Bidar) : I beg to move :

'That in the motion,—

after "Parliamentary Democracy"

insert—

"and to the highest Indian traditions and culture." (3)

MR. CHAIRMAN : Mr. Kamath.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoskangababu) : I had given notice of a substitute motion. I do not know why it is shown as an amendment. Is it permissible or not as a substitute motion?

MR. CHAIRMAN : You can only move an amendment.

SHRI HARI VISHNU KAMATH : I gave notice of a substitute motion.

MR. CHAIRMAN : Office informs me that it will be in the form of an amendment itself to substitute that.

SHRI HARI VISHNU KAMATH : I have no objection. I beg to move :

'That in the motion,—

add at the end—

"and expresses its grave concern over the fact that the electoral process as well as public life in India which was badly polluted and vitiated by an unholy alliance of political power and money power during the decadent decade, 1967-77, with the steep erosion of ethical standards and moral values, threatened to distort democracy into a plutocracy deform 'Janatantra' into 'Dhanatantra' and recognizes the imperative need to reverse those morbid trends and is convinced that for the purpose the formulation of a voluntary code of conduct by all political parties is essential and urges the Government to initiate, without delay, comprehensive measures with a view to cleansing public life in general and purifying the electoral process in particular." (4)

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : I beg to move :

'That in the motion,—

for "as evidenced by the recent revelations of collection of huge election funds by some important persons including Ministers and those who are in proximity to high offices of power and decision making."

substitute—

"and directs the Government to refer the matter to the Chief Justice of India to ascertain whether there is a *prima facie* case for a thorough probe under the Commissions of Inquiry Act, and further directs the Government to bring suitable legislation before the House to ban collection of election funds from business houses by any body." (5)

श्री हरी शंकर राय (गाजीपुर) : मान्यवर, प्राव दसव के सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत है वह एक बड़े गम्भीर प्राव से संबंधित है। जो मेरे विल इसको मूल करने वाले हैं वे मूल में तो लोक यह लोकिन भ्रम में उहांने इस विवर को लोक कर दी ही लकड़ी दीह लगाई जिस पर मैं आता नहीं चाहता। वह प्राव बहुत पुराने समय से चला।

[वी औरी शंकर राय]

या रहा है कि नंगी और सरकार में जो लोग हैं उनके पाय का प्रयोग चाहा बहुत करते हैं कैसे नहीं होगा और यह जो नहीं है वह किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित है करे—इसका प्रयोग बहुत पहले से हुआ है। सन् 1960 में उस प्रकार की बात आई थी लेकिन पैरो नेहरू ने इसका विरोध किया था और बन्दा लेने की बात उन्होंने रखी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 1969 में बन्दा लेने के अपने जो पारदी लगायी गई तब हमारे विद्रोह का पारदी लगाने का भलब यह था कि आप बूक बन्दा न लिया आये। इसके दो नतीजे निकले। एक नतीजा तो यह निकला कि अलैक मनी आने लगा और दूसरा नतीजा यह निकला कि पारदीयों का भलब देना बन्द हो बग्यांक अलैकमनी जो आती थी अपना हिंसा बन्द देने के लिए वे बजार नहीं थे। मैं कामें की परम्परायों को भी भी जानता हूँ क्योंकि हम कोई दूर के नहीं हैं, हमारा भी लिया रहा है। जबसे बन्द बैन हुआ तब से रसीद में रुपया न आ करके अलैकमनी पालिटिक्स प्रारंभ हो गई हमारे उन्नीकूलन और उन्हका मालब वेर बन्दवानदों की बात में नहीं करता, मैं क्षयियों की बात नहीं करता चाहता, मैं साधारण कांग्रेसमें की बात करता हूँ कि उनसे अलैकमनी पालिटिक्स जब हो गई। उसमें अलैकमनी को प्रभाव आने लगा और वह बन पड़ा। एप्रिल 8-10 यात्रा, 1969 के बाद की जो कांग्रेस रही है, उनके आकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन यहीं मेरे मानवों जो आकड़े हैं इनमें अगर किसी ने बन्दा लिया तो भेरा बयाल है कि दम प्रतिदंत में उम साय न कांग्रेस के लोगों ने बन्दा लिया। कर्क यह था कि कांग्रेस में कई प्रकार के लोग थे—कुछ प्रगतिशील वे और कुछ प्रतिक्रियादारी थे। मैं इस समस्या में कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन प्रगतिशील भी ग्रामिया जो की जाती है—

A progressive is a man who can digest money from Russia. A reactionary is a man who can digest money from the dollar area. A dynamic person is one who can digest money from both places most effectively. And there were dynamic people, they conducted the whole country's finances and elections.

इस प्रस्ताव में एक जट जो लिखा है, हम चाहते हैं उम पर बहस हो लेकिन नित ने प्रस्ताव को पर्वट कर दिया। उन्होंने कहा रेलवेजन्स नहीं है। वी उन्नीकूलन को भव भालूम हुआ है कि प्रभावशाली लोग बन्दा इकट्ठा किये करते हैं। इससे पहले इनको यह जान मालूम नहीं थी। बच्चाओं बाहबल ने स्वप्न में भी नहीं देखा कि बन्दा भी लिया जाता है। यह हिंसन विद्रोह द्वारा देखा जाता है कि इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी और बच्चाओं साहब सारा बन्दा हिंसन बस्ती से ले आते हैं और तारे देख में बाट देते हैं। इस प्रकार से सर्व समाजम चलता था। मैं इसके लिए कोई सब्द कहा

नहीं चाहता, एक तो इंसर्ट युक आदी होता है, हिंसा का बद्द बच्चा नहीं होता, “हायादर” अनपालेमेट्री ही जायेगा। आप ऐसे कि जित साहब के साथ बन्दा लेने की परम्परा का विरोध करते हैं।

कट्टम बाती जो बात है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारी उसमें आपेट करते हैं। भेरा बयाल है और यिक को उम लेत में बड़ी जानकारी है क्योंकि उमका हम बजाब नहीं है मकते हैं। उन का कट्टम से ज्यादा ताल्लुक है, इसलिये वह जानते होंगे, . . .

वी औरी शंकर राय : (बैरकुर) : इनकम टैक्स की बात है।

वी औरी शंकर राय : इनकम टैक्स के बारे में भी मूल जानकारी नहीं है, कांकिंक मैं नाम का भारी हूँ। इनकम टैक्स आसिमर कीन है, मैं नहीं जानता। लेकिन एक का तो सम्बन्ध करता है, बड़े प्रादरशीय है। लेकिन किनने आदरशीय है या किनने धूपिय है—मैं नहीं जानता और जान भी नहीं जानता हूँ—क्योंकि मैं प्रोतेस्वित भी नहीं हूँ और डाक्युमेंट भी नहीं हूँ—इस निये नहीं जान सकता हूँ।

मैं नियेन कर रहा था—प्राज मदन के सामने जो बम्बीर प्रवन विचाराये हैं—जैविक्लैन से यह प्रवन नहीं बदलेगी, एक्सेप्यैन्ज से यह प्रवन नहीं बदलेगी। कालिनबाई ने बन्दा माया, जनता पार्टी ने बन्दा माया, सरकार में जो लोग हैं उन्होंने बन्दा माया, राजनारायण जो ने बन्दा माया लेते हैं जो बड़े ने यान करने वाले लोग हैं—मैं अपने विरोधी दलों के मिलों में और बाय नोर से माठे मालब से कहना चाहता हूँ—प्राज की मालजी को भी बड़े से नफरत है, तो मैं इस बन्दे से नफरत करने वालों से कहना चाहता हूँ—एक बाय वैट कर इस पर विचार करें, याने जीने पर हाथ रख कर विचार करें—इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है? इस समस्या का समाधान एक्सेप्यैन्ज से नहीं होगा। यह कहना जानत है कि नई रेलवेजन्स हूँ हैं। मैं बाये में नफरत करते बाले मिलों से कहना चाहता हूँ—यह परम्परा प्रारंभिक काल से है, जब के कांग्रेस पावर में आई, बन्दा मांगती रही। कर्क निक इतना है—सी ० बी ० याना जैसे जो पुराने रिएक्यूनरी गोड़ी रहे हैं, वे रखी दे कर बन्दा लिया तेरी भी जीकरत ही नहीं रही।

मैं आप के जरिये अपने मिलों से कहना चाहता हूँ—इस पर गल्लीरा से विचार करते के लिये बैठिये—बाजार में लग जायगा, इन्हा काफी नहीं हैं। रिहूजा बौद्धि के बारे में बच्चाओं साहब से पूछिये। वह विदेश मंडी और जित मंडी रह चुके हैं—प्राज उन को जाहू के साथ कहना चाहिये कि उन का ब्लैकहार क्या था। मिसिंग गोड़ी उस को अकेले डैक्स महीं किया

करती थी, उन को भी इस की ओरी-बहुत जानकारी बरबर होती

वी सोमव रात्र : प्रूफ लाइवे ।

वी ओरी शंकर राय : प्रूफ की बया जकरत है, यह कोई भ्राता नहीं है। मैं तो भले भ्रातीयों के लिये यह बात कह रहा हूँ—जो उम की महसून कहने के लिये तैयार है। यह कह देने से कि इन्होंने बन्दा बमूल किया, उन्होंने बन्दा बमूल किया, इस से बात नहीं बढ़ती। आप ने भ्रातीयों में एक भी ऐसा सुझाव नहीं दिया कि इन को एक भी किया जाय। बन्दा बमूल कहना कोई नई बात नहीं है, यह प्रवृत्ति भ्रातीयों से ही ही थी। जब हमारा नारायण भ्रातीयों बल रहा था, तब भी देश के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय भ्रातीयों में भ्राता दे कर हमारी महायात्रा ले, लेकिन उम सभ्य पारार उन के पास नहीं थीं। इन्होंने बन्दा करनाकार का भ्राता नहीं पढ़ा। उम के बाद प० ज्वाहर लाल नेहरू के जयने में भी प्रतीकृति बन्दा देते थे, इन्दिरा गांधी के जयने में, चूंकि वह प्रगतिशील और ब्राह्मण की, इस लिये वह आकाश तक चला गया। मैं इसपें उधर बैठे हुए मिथ्यों से कहना चाहता हूँ—उन्होंने आपने सभ्य में इस परम्परा की बड़ा बीजनस्त रूप दिया। सभापति महाराष्ट्र, १९७७ में जब पालियामेंट के 'बन्दा बृहं मैं विद्वान' के मात्र बन्दा हुए—हमारी पार्टी के पायं पक्ष गणया भी देने के लिये नहीं था। लोगों ने बदा बैकर हम को चुनाव नक्या था। मैं यह नहीं कहता कि इधर सब समाजी बैठे हुए हैं या वह बदा नहीं लेंगे। लेकिन मैं अपने भाई उन्नीश्वरन और ब्राह्मण मारवाड़ से कहना चाहता हूँ—एक ब्राह्मणम् इत्यत्वं कीजिये कि किस तरह मैं इस सभ्यता का समाधान होगा। लेकिन मैं इस सभ्यता का समाधान नहीं ही सकता।

1969 में आपने नेशनलेशन बनाया, नेशन उम नेशनलेशन से आपने लैंबनी को व्यापार मुक्त कर दिया, और भ्राताजी का रैमा शाजमानिक कफ्ट में आपने लगा। मैं एक दुर्गानी इंडेंट पढ़ रहा था—उसमें लिखा था—

The Government of the people, by the industrialists and for the industrialists.

ऐसा आपने उम सभ्य किया। मेरे पास सभ्य नहीं है, मैं आपकी तरह से युक्त बक्ता नहीं हूँ—जहाँ मैं आपको बतलाता कि किस प्रकार से कोईम सरकार ने एम एस टी सी के द्वारा कार्ट-भायरन का दाय बढ़ा कर चिन-किन कट्टीज से टन्डा भ्रातीयों से कर चिदेशी बैंकों में जमा किया। मेरी नाम लेने की आदत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ—जो लोग भ्रातीयों में थे—उनका किनारा दाया चिदेशी बैंकों में जमा है। रिकार्ड चिल्स-विलियम कर इन बातों की बतलाता है। मैं एकसेजेन नहीं कहता चाहता हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ—धर्म सभ्यता में इस सभ्यता की सभ्यता की ओर मैं—तब तो इसका समाधान निकल सकता है, लेकिन यह उनका उद्देश्य कानिन भारी का नाम

लेना है, तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन साठे माहूर भ्रातों का मालम होता, आपके यही उमांशकर शीघ्रत पहुँचे बदा इक्ट्रो लिया करते हैं। वहले भ्राता के ट्रेजरर हुए और फिर देश के। हमारे भ्राता एक नेशनल हेरिड भ्रवार है। इसमें मैंकी इनकी मरी जेनेट होती रहती है। भ्रवार में भ्राता लैंकिंट उमकी विस्तिव बनती रही। व्यक्तिनांत रूप से कहने से नहीं, पोलिटिक्स के नाम पर, लैंक भ्राता मांग करते नेशनल हेरिड को सीधा यारा जोकि एक परिवार की सम्पत्ति है। उमकी भ्राता यारा। मैं जानता हूँ कि भ्राता भी, जो लोग यह जनत में या पारक में नहीं हैं—इन्हें दम हजार लघ्ये महीना छाँचे करते हैं। उनमें बहुत से पालियामेंट के भ्रवार भी हैं। कहाँ से यह नव भ्राता है? ये सब बातें किस भीज को साक्षित करती हैं?

आप प्रधान भ्राती मोरारजी देसाई पर हमला करिये लेकिन भीमे के घर में रहने वाले लोग ऐसा हमला न करें। आप भ्रातर करना चाहते हैं तो इस दृष्टि से करो कि योई सुझाव द्वारा जिससे यह लोग भ्रवार कर, बैठ कर बात करें। आप प्रधान भ्राती जी से, भ्रियों से बात करिये। मैं बहुतों कि चद्वाण माहूर बात करें। भ्रातर भाव लोग नहीं जानते कि हिन्दुओं भ्रवार से क्या है। यह उग्रान भ्रविमन में रहने वालों को भ्राताजी की है, यह उम बदा बैठ करते हैं।

मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव को लाकर इस मदन का इस तरह में तुलयांग नहीं हाना चाहिए कि कोई भ्रातीयों कोई भ्राता चिकायत करने के लिए, जिसका नेशनल भ्रविमन से इसका दुर्लभ्यांग है। मैं आपने कहना चाहता हूँ कि आपको कोई चिकायत है तो इस मदन में भ्राती दोनों के लोग मिल कर बैठें और विचार करें कि वैसे इस देश के चरित्र को बदला रखना है, जैसे इस देश में चंदे ने राजनीति बनाई और बात कर चौरी, कहा नक उसकी भ्राताजी करना है। इस पर मिल कर नव लोग सीधे सजते हैं। यह भी एक दूसरे को गाली-गाली बैठकर नहीं सोची जा सकती है।

मानवाद, हमारे दो टीचर्स थे। एक वह विदान थे और दूसरे कुछ कम पढ़े लिये थे। दूसरे टीचर जब इन्विहान होता तो नकल करने वाले लड़कों के पढ़े लिया करते थे। उनमें हमारे विदान टीचर कहा करते थे कि तुम उच्चपन में जम्मर नकल करते होंगे तभी नकलियों को पहचान जाते जहो। इसलिए हमारे ये भ्राती भी जानते हैं कि कहाँ कहाँ से बन्दा भ्राता है, कहाँ कहाँ है। इसके बात हैं मैं इनके बाने ब्रियामाद बात को भी भ्रातों से हिचकाता हूँ क्योंकि इनको सब मालूम है कि कौन कहाँ कहाँ नाजुक भीका है। ये वहले से नाजुक भ्रातों को जानते हैं। इसलिए मैं आपके भ्रतों हूँ कि आप इस पर बैठकर विचार कीजिए, और सुझाव दीजिए। यह काम कानून बनाने से

[भी गीरी बंकर राय]

होता है तो वह बताएं। यह वेस 62 करोड़ का है। वेश में काति भाई के अतिरिक्त क्या हर किसी को बंदा मानने से नफरत है? आविर आप क्या कहता चाहते हैं। बाट इ मूँ बाट दूँ इम्प्रेशनों भी? मैं कहता हूँ कि इस सारे मामले पर बैठ कर विचार कीजिए कि कैसे इस समस्या को हल किया जाए। इस प्रस्ताव का एक हिस्सा अपनी पराकाष्ठा पर चला गया है। जब बच्छां साहब मंत्रिमंडल में वे तब भी रिविलेंस हुए हैं। इसलिए यह कहता कि पंजीयितयों से पैसा लिया गया, इन बात को जानद और उन्नीकृत जी उन्होंने जानते जितना कि भी बच्छां साहब जानते हैं। इसलिए मैं कहता चाहता हूँ कि सभी लोगों के लोग भीठें, एक कालेंसर, एक एप्लेस्ट्रिडिंग पर बायें कि किस तरह से सार्वजनिक जीवन में एक परम्परा कायम की जाय, भैयार निश्चित रूप में कायम किये जायें। बाली गाली देने से तो वह नहीं होगा। आप इसके लिए भैयार लिया भी कीरिए। यह मैं किसी को बिल्ड करने के लिए नहीं कह रहा है। मैं इसलिए कहता चाहता हूँ कि यदि आप समस्या का समाधान करता चाहते हैं तो बैठ करें इसका हल हुँ, वह बहर निकलेंगा।

भी बहलन लाठे (ध्रुवोला) : सभापति महोदय, मैं गीरीबार राय जी से सहमत हूँ जो अभी उन्होंने बात कही। यह जो प्रस्ताव मेरे मिल भी उन्नीकृत जी ने यहाँ पर रखा है, इस प्रस्ताव से जो सबाल उन्होंने उठाया है, उसका हल इस तरह से निकल सकता है यह बात भी समझ में नहीं आयी। (व्यवहार) आपकी आयी ही तो बताएं। मैं गीरीबार जी से सहमत हूँ। इसलिए कि अन्य इकठ्ठा हो रहा है और वही पारदर्शक राय ही समस्या है और उससे बहरा दौड़ा हुआ है। मैं प्रभावित करती है और बड़े लोग जो सत्ता में हैं हमें उन्हें ज्यादा सहभवित होती है तो यह बात ही आपके लिए रहेगा। और जो सत्ता में रहेगा स्वामित्व है अन्य उसी के बाल जाएगा और सत्ता में न रहे तो उसके पास बन्दा नहीं आएगा, यह भी स्वामित्व बात है। प्राज तत्त्व में नहीं रहे इसलिए जिकायत ही तो बात अलग है। लेकिन सबाल जैसे राय जी मैं कहा, यह है कि इसकी बुनियाद में हमें जाना होगा। बुनियादी बात के लिए आप क्या करता चाहते हैं? कोई नया सिस्टम निकालने वाले हैं? जर्मनी में जैसे है कि गवर्नरेंट सारा इलेक्शन का करती है वैसे होगा? क्या ऐसा सिस्टम आप सुना रहे हैं? मैं समझता हूँ कि यह वह ही नहीं सकता है। जब तक हम देख में जो आधिक लाज है, जो आधिक व्यवस्था है, जो पूंजीबाद पर आधारित है उसको रहते काला बाल बैहिसब बड़ता जा रहा है... (व्यवहार) लाल पगड़ी लोगों की समझ आएगी यह बात। वह समाजवादी है। हमारे लोगों रहे हैं और वह इस बात को जानते हैं। जितनी पूंजी जगा होती जाती है वह लोगों से हाल में, वे की मेहरूत के लियित हुई पूंजी वह

बन लोगों के हाथ में एकवित हो तो वहाँ काला बन भी रहता होता है। ऐसी पर्यावरणस्था में आप आहे कुछ कर ले तो कुछ नहीं हो सकता। कोन्ड्रेट अच तत्ता होगी तो उसका उपयोग या डुप्पेयोग राजनीति के बाने के लिए कंट्रोल में लाने के लिए किया ही जाएगा। यह हलीकत है, यह बस्तुविचित है। आप और हम इसकी बहलने के लिए भाज भी तैयार नहीं हैं। जो ईस्टार्ड इटरेटर है उनको खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। अन्याय सताने पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है। होता क्या है? हम आपकी और आप हमारी टोपी उठानने की लोकियत करते हैं। हम काति भाई का गालियां दे देते हैं और आप संजय को गालियां दे देते हैं। यह क्या है। 27-00 hrs.

भी गीरी बंकर राय (बैरकपुर) : दोनों में मेलजाल हो गया।

भी बहलन लाठे : यही बात बलेगी और इसमें आपको मनोरोग है मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने याह कमीशन बैठाया। साठ कैसिस सबज गायी पर बलाए। तेल कैसिस इंदिरा जी पर बलाए, मिस्सूरी बाल पावर, कुरुक्षेत्र इन हाल हालीकम। पर जब द्वारे का बेटा हो तो बराबर, घपना बेटा हो तो ललवा। उसके नाम से बोली भव, वह दूध का बुना हुआ है, साफ है, वह कोई बदबलन नहीं है, उसकी बात न करा, वह कुरुक्षेत्र नहीं करता है, जैसे किन द्वारे में सभी बुरायां हैं। इससे आपका निपटना नहीं। मैं आपके पूछता चाहता हूँ कि क्या आपने इस पर गम्भीराता से विचार किया है?

17-03 hrs.

[Dr. SUHILA NAYAR in the Chair]

धर्म व्यवस्था के बारे में कोई बोलत है या? आप और हम किसी को भी जाप उठानी पुरस्त नहीं है। जब से आप सत्ता में पाए हैं मुझे बालाएं कमी ऐसी बच्ची, कमी ऐसी बेटा हुई है कि बद्यादी परिवर्तन आंचे में हम कैसे लाए और आप हमें जूलीती दें कि बलिये बुनियादी परिवर्तन लाना है, ये जो ईस्टार्ड इटरेटर हैं। कैरिकलिंग क जो गढ़ है, जो कान कर बैठ गए हैं सीने पर इस देश के इनको खत्म करना है, जलो यह हमारा प्रोताग्राम है जिसको बेलंज समझना चाहिये और आपको इस प्रोताग्राम को जलाएं। कोई बात हुई है? इस बात पर बच्चा नहीं होगी। इस पर आपको भी कहत नहीं है क्योंकि आप उन्हें बलना नहीं लगा सकते। बैटेड इटरेटर है, 20 हवार करोड़ लाख मनी जिनके कब्जे में हैं और वह भी दो, तीन हजार लोगों के हाथ में हो तो वह किसे इस देश में नहीं बरीद दकते हैं? सारी टोप अम्बूलोकेशी उनसे मिली हुई है। आप बताएं जीने पर हाथ रख कर कोई मेहर पालियामें कह दे क्या एक एमो १० का चुनाव 35,000 रु. में होता है? नहीं। किर कही से आता है वैसा जो साल, साल बाल बच्चे होता है, वह वैसा कहा से आता है वही भाला है जो काति भाई से जाना किया। उनको जो 80-

लाल ८० मिसां, आपने तो सूचेनिवार कलेक्शन जो कांग्रेस का हुआ, उस सम्बन्ध में १८० लोगों के नाम आपने लियाये और उस पर कांग्रेसी भी की, नोटिस दिये गये कलेक्शनों को । ८० लाल जिस लोगों से आया उनकी भी लिस्ट दे दी गयी, और उनके ऊपर भी नोटिस दी जिये । लेकिन नहीं देंगे आप, क्योंकि सी० की० गुप्ता साहब कहते हैं कि उसने मुझे दूर हिसाब दे दिया है । और जो पार्टी के लोग हैं उन्हें बत्ता कलेक्शन भी किया लेकिन कोई हिसाब नहीं दिया । यह गुप्ता जी कह रहे थे । आब इनसे पूछिये कि उन्होंने ८० लाल क० बिना बोली रखे, के कल प्रधान यात्रा के पुल हांगे के नामे, इन्डिटा किया तो तो भी संभव है मानवीय पटनायक या मानवीय एच० एस० परंपरा इनको लिताना मिला होगा ? उनका हिसाब कोई बतायेंगा पर, वह बात भी नहीं होगी । मैं आपसे कहता हूँ कि यह से गम्भीरता से विचार कीजिये ।

हमारे कामत साहब को जाह कमीजन पर बोलते समय उनको एक ही बात मार्गीम है कि किस तरह मेरे जरिये हनत इंदिरा गांधी और उनके खानदान का किया जाय जिससे उनकी आत्मा संतुष्ट हो । हमारे बाकी के भी लोग हैं । आपको याद होगा कि उन्होंने हमस्टी इम्प्टी लियरिक मुराई भी....

भी हरि विष्णु कामत (होमगावाद) : वह रेकांड पर है, टेप पर है ।

यो बत्तन साठे : एक रिमरिक में भी इनको सुनाना चाहता हूँ आपके बारे में, गौरीलंकर राय के बारे में :

मम जूठमलानी गौरी लाल, गौरीलंकर और हंवर लाल, और आई० सी० एस० हरि, आई० सी० एस० हरि विष्णु कामत,

Some joath malani, Gauri, Lal, ICS Hari with much sound and fury; Signifying nothing.

Indira Gandhi they wanted to bury : Now they fret and fume in impotent rage at her renewed success and glory.

भी हरि विष्णु कामत : जबा नहीं ठीक ।

SHRI VASANT SATHE : Now, to revert to the subject under discussion, it is said that Kantibhai has nothing to do with politics, he is only a Private Secretary looking after his aged father. What does Kantibhai have to say about this ? A German correspondent interviewed him and this is how the interview goes on.

The correspondent asks : "Well, how do you serve your father ?".

Kantibhai : "Well, you see my father is very old and he needs to depend upon some one for decision-making."

Correspondent : "surely, he can consult his Cabinet colleagues."

Kantibhai : "Yes, he consults them and they give their opinion. But I usually advise him on which opinion to take."

So, Madam Chairman, Kantibhai has no role at all !

इस्पत और बाल बाली (दी बोज पटनायक) यह कहां से पढ़ रहे हों ?

भा बत्तन साठे : German Magazine कांती भाई रोल अदा नहीं करते वह तो केवल अबूल कुमार की तरह पिता की सेवा में लगे हैं । मैं आपसे कहता हूँ कि कोई दूष का बला नहीं है, कोई यह नहीं कहे कि holier than thou आप तो खांसी करतान के पुले हैं, मुझे की जो बुनियादी बात है, मैं आपको माफ़त कह तो बत्तन का हत लिकाला जा सकता है । नहीं तो वह तो हम रखे हैं कि अच्छा मौका है, तू-तू, मैं-मैं हो रही है । जूतां पैंजार में लगे हैं भी जब बत्तना आयेंगा तो बत्तन के लिये हमारे पास आयेंगे । वह जानते हैं, हंस रहे हैं, आपका मर्जीत जड़ा रहे हैं ।

आप एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं । आप इस भावाना से मत देखिए, राजनीति वह रही है, पटरी पर से फिर से उतर रही है ।

Our whole national debate is getting derailed on non-issues. Believe me, the biggest non-issue was Indira-baiting. Now it is coming home. It has started against each other in the Janata Party itself. This cancer will grow. I beg of you, I beg of my friends through you, Madam Chairman, to consider this issue in this larger perspective and gravity and approach it with that basic approach of removing the system which corrupts and which corrupts all individuals. And as long as that system prevails you cannot undo corruption by just passing this resolution or some law. Thank you very much for giving me this opportunity.

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah) : Madam Chairman, though the resolution expresses concern in the future of parliamentary democracy by the increasing role of money in elections but mainly the discussion is centering round charges of corruption against Kanti Desai. These two aspects I want to deal with separately.

I do not blame them because they are out to utilise every occasion to discredit the Janata Government and the Janata Party and to take maximum political advantage of it. My accusation is against the Janata Party and the government and Mr. Morarji Desai himself because the Prime Minister should not have given any scope. Wherever any charge of corruption

[Shri Samar Mukherjee]

comes and when it comes in a concrete form, he should have faced it with some form of inquiry. If, without that, the Prime Minister comes to defend the son, it links up the old tradition. Here a tradition has developed that sons and daughters of Prime Ministers and Chief Ministers have become the real reasons of the exist of the Prime Ministers and Chief Ministers from the scene of political life.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Trivandrum) : That is why Bengal has always chosen the bachelors.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Now is the time for the Janata Party Government, the Janata Party as well as the Prime Minister to defend their image before the public life. They should come forward to have a probe on every case wherever any concrete charge of corruption comes and, if that charge is proved, the Prime Minister and the Government should take proper steps and fully dissociate with those actions and defend the integrity, honesty, purity of the party and the position the Prime Minister is holding. When again and again this type of complaints and charges come, they should be met with proper enquiries otherwise the entire attention of the House and the whole country will be engaged and diverted into those issues and only this will be a common talk before the public, while the government gave no time, no attention, to the basic problems of the people. Only these issues are getting primacy. That is why we told in the past also that whenever the question of the letters came up, we had told the Prime Minister to lay the letters on the table. Let the public see what is there in the letters. If there are charges, that should be subjected to be probed. Now, it has been declared by the Prime Minister that if there is a concrete charge and if any Member is prepared to give it in writing, 'I am prepared to forward it to the Judge of the Supreme Court.' I would urge upon the friends here to give them in writing and offer to the Prime Minister the scope to test this declaration. Let him forward that to a Supreme Court judge and let it be probed. (*Interruptions*)

SHRI SAUGATA ROY: Whether it applies to the foreign transactions also?

SHRI SAMAR MUKHERJEE: That the judge will decide.

Madam, Chairman, whenever the friends bring these charges, they pose themselves as if they are the real fighters against corruptions. Look at their own background. They must be self-critical; they must be honest.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: The less said the better.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Before starting accusing others, their attention should be drawn to the issue of Blitz, last year, April 16. The whole headline is: 'Congress Looted Crores from State Bank'. It is alleged—I am reading,

'It is alleged, for example, that Varadachary personally carried Rs. 9 crores in tin boxes to Malda, from where former Banking Minister was contesting the Lok Sabha elections....

Shri Dinesh Joarder is here. He defeated Shri Pranab Mukerjee.

'.....as well as Rae Bareli and Amethi, Indira and Sanjay Gandhi's constituencies, and supervised the cash handouts to voters.'

SHRI C. M. STEPHEN (IDUKKI): Shah Commission was there.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: No please be self-critical. Don't absolve yourself of the responsibility. You never raised your voice against this type of corruption. (*Interruptions*)

My accusation is that you never raised your voice against corruption. Now you become the critics of corruption. (*Interruption*): Lakhs are spent on posters.

I quote:

"Two of the premier financing units, the State Bank of India and the LIC, were horribly muddled in a Mafia-like operation. Dissenting officials were sacked or transferred and the compliant were given undue promotions and extensions.

After State Bank Chairman Talwar was briskly edged out of the job, his successor T. R. Varadachary was forced to pull crores out of the Bank's funds to finance the Ruling party's election campaigns.

Insiders claim the money was collected from the banks' customers who were given generous overdrafts and forced to part with a substantial percentage of it on pain of withdrawal of all facilities in future. In the process the bank's till was severely drained.

To get an extension of service, Chairman Varadachary was further compelled to please the Banking Minister by giving huge advances to certain parties. In some cases the advances were handed over even before processing the documents, and in other cases before the signing of the agreements."

After the election were over they tried to regularise these in bad debts. There are other details also but I am not going into them. I simply want to draw the attention of the hon'ble Members who have now brought these accusations—I am not opposed to bringing accusations—if they are sincerely interested in fighting corruption then they must start from their own self. (Interruptions)

SHRI C. M. STEPHEN : Let us begin with the four CPI (M) Ministers against whom corruption charges were established by Commission of Enquiry instituted against them. (Interruptions)

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Madam Chairman, I support Mr. Sathe in one respect that this very system—under which we are living—is based on exploitation and for thirty years of Congress rule the rich have become richer and the poor have become poorer and there has been concentration of money and growth of monopoly houses. For this you cannot accuse Janata party government. But we accuse the Janata party government that they are pursuing the same policy. There has been no basic change in the policy of the Janata party government. Money is being concentrated in the hands of the few. What does the Directive Principle in the Constitution say? It says that disparity should be reduced. But what is there is in actual practice. The rich are becoming richer and the poor are becoming poorer. The disparity is growing day by day. Only last month the Reserve Bank reports revealed that the monopoly houses have earned nearly 50 per cent more profit in the years 1972 to 1975. The monopoly houses know that this government is providing through their policies the scope for earnings huge profit and, as such, they are interested to keep this government in power. They know so long as this government is in power their profit earning scope will remain intact. As the people at large are being exploited and so their discontent is growing day by day. These monopoly houses know that it is becoming more and more difficult for the ruling party to get support and face the elections. That is why people must be influenced by money power, by using casteism, communalism and various other fraudulent methods.

Day by day, capitalism is faced with crisis. Day by day, money is concentrated in the hands of a few. Day by day these people's movements are growing. More and more, these big capitalist houses and the exploiting classes are bound to purchase the ministers and use them, and use their money power for influencing the voters. This is inevitable in this system. That is why, when you

talk of removing corruption, we must keep this in mind. The Government has changed. But the State machinery has not changed. The entire bureaucracy is there. You can change one officer from one department to another department. But he is bred in this atmosphere, where everybody has been forced to be corrupt. If any honest officer is there, he has to face punishment. By becoming honest, by refusing to become corrupt, he is pressurised, he is transferred or he is demoted. They are forced to become corrupt and they become part and parcel of the ruling machinery. That is why in this atmosphere you cannot expect that the entire administration will be free from corruption. That is why I say that higher political consciousness is necessary and the entire people must be aroused to fight corruption. The consciousness of the people must be roused against corruption to curb the possibility of corruption spreading in other spheres. The level of the political consciousness of the people must be aroused higher. They must get the feeling that money cannot corrupt the people. The people of West Bengal have exhibited their political consciousness. They have correctly selected as to which party they should support; they have found out which are the parties which are the agents of the big business houses and who are the agents of the exploiters. They have proved that money cannot influence them, money cannot purchase votes. Although the bourgeois parties spent lakhs and lakhs of rupees, they found that their candidate had been defeated and the Left forces had won. The glaring example of West Bengal is there. Lakhs and lakhs of rupees were spent, but the people in the villages knew to whom they should vote. In the villages landlords spent huge amounts of money. But the peasantry has been intelligent enough. They decided "we will get the money, but we will vote for our own selected candidates. Those who wanted to influence the voters with money see that even after spending so much money their candidates had been defeated. Then they will refuse to spend money in those areas in future.

So, what I say is that the people's consciousness must be roused. People's cooperation must be enlisted to fight this system and to change this system. People's organisations must be organised and developed. Without this, there is no way out.

The Janata Party Government, in order to keep their image, must come forward and order probe whenever there is any concrete charge of corruption, particularly if those corruption charges are in connection with any relation of any Minister—

[Shri Samar Mukherjee]

or in case of any relation of any Prime Minister. Otherwise, with the experience of 31 years, people automatically take it for granted that, even after the Prime Minister denying it, that man is linked with corruption. That impression you cannot remove from their mind. If there is a probe, that probe can prove that certain charges are baseless. If it is proved that the charges are valid, then the strictest punishment must be awarded to them. Then the image of the Prime Minister will become more heightened in the eyes of the people. Then only he will be a capable of leading this Government and the people of the country to fight corruption. Then only his words will carry weight with the people. Otherwise, his words will never carry weight with the people. That is why we are insisting that corruption must be fought ruthlessly. The Janata Party has given pledges to the people before elections that they will fight corruption upto the last. So, I demand that they must come forward with this proposal: Whenever there is any corruption charge against any Minister or any relative of a Minister, they must immediately order a probe. They must place before the country the results of such a probe. That alone will heighten the image of the Janata Government. Otherwise, looking at the way you are fighting among yourselves, you will also have to face the same future which the Congress had to face. That is why I give you a most serious warning that you must re-think and remodel and reorient your entire method of functioning.

With these words, Madam Chairman, I would tell the House that the question of fighting corruption should be taken up seriously and due weightage must be given to the various points made by me.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Mr. Chairman, after hearing the mutual recrimination from both sides and after so many stinking skeletons have come out of the cupboard, I think, no persuasion would be required on my part for the House to accept a very constructive suggestion which I have put forward in the shape of my amendment. In my amendment, I have said:

***add at the end—**

'and recommends to the Government to bring forward expeditiously legislation by which all political parties in the country should be registered under the Registration of Societies Act, 1860 (as amended up-to-date) and should maintain accounts of all their receipts revealing their sources and expenditure supported by stamped vouchers and publish annually a statement of receipts and expenditures duly audited and

certified by a chartered accountant which should be published in the Gazette of the Government of India."

There would be no two opinions that it is a matter of great concern that these are undemocratic intrusions which have been susceptible to pernicious influences. It is said that in some countries power flows through the barrel of the gun, but in this country, we know that power flows through money bags during elections. The poverty and ignorance of the voters are fully exploited. After the elections, they start engineering defections, indulging in political horse trading and in forming minority Governments. In my thirty years of active political life in every case, I know that while submitting my election expenses return, I have submitted a false return. I admit this myself and it must be true in the case of every Member in this House.

Money and politics are two sides of the same coin in this country. In last September, the Government released a list of 180 companies, who had paid Rs. one lakh and above for advertisements in the souvenirs of the political party then in power. We would also like to know the quantum of money collected from the various sources, along with the sources, by the present ruling party in this country. Money and politics have always had a adulterous relationship; it is illegal and exciting. Despite various pious statements full of morality, politicians do take money from rich people and from the various companies, and in return they promise them favours. Most of the money flows from the unaccounted black money and this money is syphoned to the coffers of the political parties in a very clandestine way and under the table. In this House, there has been a debate in the past how the CIA and KGB money has played its role in patronising the various political parties having clandestine relationship either with CIA or KGB.

In this regard, I take this opportunity to quote a few lines from the latest book "Rescue Democracy from Money-Power" by Shri Rajagopalachari. It is a compilation of the various articles written by late Rajaji in "Swarajya". And the Foreword to this book has been written by no less a person than Shri Jayaprakash Narain; and JP says:

"One who weighed every word he uttered or wrote, Rajaji was a relentless campaigner for rescuing our democracy from the corrosive influence of money-power and its evil brood. As I went through his collected writings on the subject, I could not help admiring his

far-sightedness, absolute sincerity, depth and courage of conviction and total devotion to national welfare.

No truth gains currency when it is first propounded and no prophet has been spared of initial calumny and dispragement. Similar was the fate of Rajaji when he set face sternly against the conventional politics of election-winning and pursuit of self and power. At the time when Rajaji wrote these articles, they did not evoke the response they deserved. This was perhaps due to the then prevalent all-pervasive charisma of Pandit Nehru and the blinding force of unshied power and the all-round subservience and sycophancy it generates.

But to-day, both Jawaharlalji and Rajaji have left the scene. The nation itself has just regained its freedom from despotic rule, about the advent of which Rajaji had clear forebodings and of which he had given ample, timely and unambiguous warnings. Against this setting, today his writings acquire a new dimension and significance and call for fresh in-depth study.

His words are words of wisdom. If the plant of parliamentary democracy is not merely to survive but thrive on our soil, it is imperative to create a corruption-free and congenial climate for it till the top roots go deep into the soil." And then he mentions how it is essential that politics in this country should be freed from the influence of money. I had, in this regard, tabled a non-official Bill identical to the amendments which I have given here; and in this regard, I sent a copy of it to some persons who had taken interest in this matter. And Mr. K. Santhanam who presided over the Anti-Corruption Committee has written to me thus:

Mylapore, Madras
6-2-78

"Dear Shri P. K. Deo,

Thank you for the copies of the two Bills sought to be introduced by you in the Lok Sabha. Both of them are important. I would however like that in the Bill for Registration of Political Parties and Publication of their accounts, you had provided for the maintenance of members' list and the constitution of the party, including the executive authorities and procedure for changing the Constitution. You may table amendments for the purpose.

I wish you success in your brave attempt. With kind regards,

Yours sincerely,
K. Santhanam".

Similarly, many messages have come from all over the country. I do not want to take the time of the House; but if the Government and the Opposition are anxious to have a permanent solution to this problem of corruption and to root it out from the body politic of the country, I think they should gladly accept the amendments I have suggested to the Motion so ably moved by my friend Mr. Unnikrishnan.

श्री राज नारायणः (राय बरेसी) : मैं एक परसनल स्टेमेंट देना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN: देखिये, राज नारायण जी, Direction 115C says:

"No member shall be permitted to make a statement by way of personal explanation under rule 357 unless a copy thereof has been submitted in writing by the member to the Speaker sufficiently in advance and the Speaker has approved it. Words, phrases and expressions which are not in the statement approved by the Speaker, if spoken, shall not form part of the proceedings of the House."

मैं तो बहाँ भी नहीं। उडीकूलान साहून ने कुछ कहा, ऐसा धापको बताया गया। उनके कहने के बाद धापको भगवर परसनल एक्सप्लेनेशन देना है तो बोहो तो लिख कर भेज दें कि क्या एक्सप्लेनेशन देना है। उनके बाद धापको अवसर मिल जाएगा।

धापकी बलवान तिथः प्रेसीडेंट है कि जब कोई बोला है उसके बाद जिस के बारे में कहा गया है उसने परसनल एक्सप्लेनेशन दिया है।

श्री राज नारायणः मैं जानता हूँ क्या नियम है। अब तक के कावेशन के बिल्कुल विवद धापकी बात है। मैं चुनून इस सदन में कई बार परसनल एक्सप्लेनेशन दें चुका हूँ। कल ही जब उपाय्यर बैठे हुए थे तो एक विषय धाया था जिस में उन्होंने नमूने अधिकारण लाईकीरण करने को कहा था— और मैं उसका मोका दिया था। मैंने स्पष्टीकरण दिया था। स्पष्टीकरण ने भी कई बार दिया है। सभी को दिया है। जो चीज हैंज इन दी धाइ धाफ दी हाउस एमिटेटसी उसका एक्सप्लेनेशन उसी समय दिया जाता है। भगवर कोई चीज ऐसी हो जो बाहर की हो किसी लेख पर धारित हो उसके बारे में लिख कर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ आमने सामने की बात है। उडीकूलान साहून मिले हैं उन्होंने बताया है, दूसरों ने भी बताया है कि उन्होंने यह कहा है। मैंने कोरिन जा कर भी चिलांग सिंह को कोन दिया है। मैंने उन से भी भी उडीकूल से बात की है—

SHRI K. GOPAL (Karur): I am on a point of order. Mr. Unnikrishnan,

[Shri K. Gopal]

in his speech, nowhere has he mentioned about Mr. Raj Narain; he only mentioned about his Private Secretary. Members cannot come before this House on behalf of their Private Secretaries.

श्री राज नारायण : मैं इतना ही कह देना चाहता हूँ कि श्री वितांगन निज भार विकासलन सोगायम के जो डायरेक्टर हैं वे भी इत्यतासल सिंह जी उन्होंने कहा है कि जिस मदद्य ने वह कहा कि यहाँ से कारपेट्स जे जाये गए हैं वह विकृत्य प्रभाव है, निरापार है, देवनियाद है, भूत है और अपरोध है कि आ कर लाग बृक को देक नहीं कि क्या सामान गया है और क्या नहीं गया है।

मैं समझता था कि हमारे मित्र मजबूत हैं और विता इत्यतायरी किए हुए, आज किए हुए अच्छी तरह से किसी बात को बोलेंगे नहीं। मैं इनकी चांद पर कहना चाहता हूँ कि इस तरह से अन्यत आगाय लगाना बहुत प्रशंसनीय है। जो आदमी सदन में महीने है उसके लिये इस तरह से आगे लगाना संवेदनीय प्रशंसनी के लिएरात है।

मन मर्लान तन मून्दर ऐसे।
विष रम भरा कनक घट जैसे ॥

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Bada-gara): Do not pretend. He pretends to be an angel.

MR. CHAIRMAN: I must say that it is not right.

श्री राज नारायण : मैं कह निवार कर भी देंगा। प्रब तो ही ही गया है।

सचावति भ्रष्टोदय : यहर आप यहाँ बैठे होते और कोई मानोनीय मदद्य बोलता, और आप तुरन्त उठ कर एकलोकेन्द्रीय हो जाते होंगे या मानकरी थी। अब तो कृतिमीर्मी हो गई है। वह कहते हैं कि आपका नाम ही नहीं लिया गया है, आपके लिए कठ कहा ही नहीं गया। ऐसी परिस्थिति में उचित यही होगा कि जो भी कहा गया है उसके बारे में आप स्मीकर को लिख कर दें। जो उन्होंने कहा है वह रिकार्ड में आ गया है। आप वह लिख कर दें तो उसको देख कर आपकी स्मीकर माहजन द्वारा नहीं मानकर है।

श्री राज नारायण : आपने जो कहना था मैंने कह दिया है। आपकी आज गिरोधार्य करता है। कल जो आप ने कहा है मैं लिख कर देंगा। आज जितना कहना था मैंने कह दिया है।

मन मर्लान तन मून्दर ऐसे।
विष रम भरा कनक घट जैसे ॥

SHRI KRISHAN KANT (CHANDIGARH): Mr. Chirn, I am thankful

to you that after all you thought of calling me. There is a general practice that one Member from the Opposition and one from the Ruling Party should speak. But, this time, probably the rule was changed to accommodate the Opposition.

I am grateful to the mover of the Resolution that he tried to raise the level of the debate by changing the motion from individual corruption to the general approach to the problems of power politics and money politics.

The Resolution says :

"This House is of the opinion that increasing play of money power in elections pose grave threat to the future of Parliamentary Democracy as evidenced by the recent revelations of collection..."

The first part really points to the malady. What is to be sorted out has been mentioned by Mr. Unnikrishnan. But, he confined himself to citing a few cases, and did not attack the problem as a whole. He refers to the recent weeks and months. What about the present and what about the future? This is not a new thing. When Dr. Rajendra Prasad retired as President, he gave a valedictory address in the Central Hall. In that he referred to the money power and he said that money power was taking over, was taking hold of politics in India and unless something was done about that, the elections would become a farce and ultimately power will go into the hands of those who have money power as well as physical power. Babu Purushottam Das Tandon addressed the Lok Sabha and he referred to the danger of money power taking over the politics in India. So, it is not a new thing. We have not learnt the lessons. While Mr. Unnikrishnan was speaking, I was expecting that he would refer to the perspective, to the whole problem and say how things could be solved. It was refreshing to hear Shri Unnikrishnan, and I hope, he will not mind if I refer to the AICC meeting. I wrote a letter against black money power and I pointed out how black money was taking over, how black economy was leading to black politics. I am referring to what was happening in the Congress and then some friends challenged me.(Interruptions). I do not want to name any friends. It was done first in the Delhi AICC and secondly, the same question was referred to in the Gandhinagar session. When I said that some delegates had told me that the price of sugar was increased because we took money from the sugar barons, thirty-two Members of the Congress Party spoke against me as if I was talking blasphemy. It is refreshing to note now, I will be glad if he joins in the crusade for the total

eradication of black money and black money power. There is nexus between black money and black politicians, black bureaucrats and the black businessmen. Unless that nexus is broken nothing can be broken. And that starts, as he said, from the election processes. We have to examine whether by merely attacking black money and black politicians we can eradicate the whole nexus and really remove the black money from the country. Kindly analyse the situation. At that time in the Congress Party I was referring to certain figures and I wrote three articles in the *Hindustan Times* on black money power and electoral reforms. I had calculated this on the basis of my Haryana experience, a Lok Sabha constituency and 9 assembly constituencies. If you give two jeeps in every constituency, it means 18 jeeps; one jeep for the candidate and one jeep for the election agent—that comes to 20 jeeps. The rate of hiring a jeep is Rs. 150 per day; it means Rs. 3000 per day for 20 jeeps. If you calculate petrol at the rate of Rs. 100 per jeep, it means the expenditure is 2000; the total is 5000. For thirty days the expenditure is Rs. 1.5 lakhs. That is the minimum. There is no black money involved; there is no corruption, nothing. Secondly, if we leave out the slips that you give, if you send them by post to each candidate, by 25 paise covers, it means 1.25 lakh for 5 lakh candidates. The total is Rs. 2.75 lakhs. I remember that when I read these two figures in the Congress, Shri V. B. Raju who was the General Secretary said that it cost a rupee per voter, it cost Rs. 5 lakhs. Are we not playing false to ourselves by putting it at 10,000 and 25,000. Even the Tarkunde Committee which J. P. had appointed referred to 35,000 and 50,000. Why deceive ourselves? Because we are deceiving ourselves, we are not true to the economy or true to the polity. If you want to remove it, some fundamental cure has to be done. Mr. Sathe spoke and criticised that the Janata Party has done this or that. He did not refer how the political system was utilised by Mrs. Gandhi in 1977. Rs. 9 crores worth advertisements were taken for the souvenir; most of them were not published. How was the administrative machinery utilised

TBE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAEE) : They saved paper.

SHRI KRISHAN KANT : They made the Company Law Board issue a certificate that advertisements will not be considered as political donations. Secondly, they made the Central Board of Revenue to issue a certificate that all the advertisement expenses should be allowed as deductions in the income tax. The list of donors to the Congress funds was seized on the Baroda Rayon and was

handed over by the investigating authority to Shri Mehta which was given to Shri Pranab Mukherjee and which went to Smt. Gandhi. I would like to know from Shri Patel whether the list has come or not? Is it still there?

Mr. Sathe was talking of those things, I am not talking of those things which are irrelevant.

Vimat Lal Commission is sitting there, looking to the excesses. It was given out on the basis of evidence that each candidate of Legislative Assembly was given a lakh or a lakh and a half. If that is the situation for an Assembly candidate—lakh or lakh and a half, which was given out by Vimat Lal Commission, then what about the Lok Sabha candidate? Unless we have a big thrust on the whole system of election, nothing is possible. I may like to reiterate those suggestions which I had given in 1974 and 1975 and had talked to Shri Jaya Prakash Narayan also. I said that the Tarkunde Commission recommendations will not do. What is happening to-day? The four curses of elections are—

1. Caste and community.
2. Communalism and religion.
3. Money.
4. Gunda power, muscle power which they contribute and these gundas survive according to Mahatma Gandhi only on the protection of politicians.

If politician has to be purified, if politician has to be ennobled, then the basic attack has to be on the methods of election.

How can we make people based politics and not money politics? I had given two or three suggestions. May I urge the Government to consider that the elections should be held only after giving a notice of a week, not three weeks or four weeks. There is not office of the political parties in the villages, towns, talukas or anywhere. Any political party which has worked for a period of five years will be able to face election within a period of seven days and before one month no vehicle should be allowed. The workers of the political party which have worked for whole five years will go immediately and voting will be held. This has to be done if you want people based politics rather than money based politics. Secondly, if we want people based politics and the political parties to work then let us not have any inhibition on donations to political parties, whether by individuals or by companies and all of that, like Germany should be given income tax deduction, because we want to have the political system on the basis

[Shri Krishan Kant]

political parties. Let us not dupe ourselves by closing the Company relations and we start the same donations in a much bigger amount under the table.

All the accounts of the political parties must be audited annually, not only the election account. If that is done, it will become easier to cleanse the politics. Black money starts from bad politics. If black economy has to be given a goby....

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : Time is coming. I have to move for extension of time. I have to do it. This is time to do it.

I move for extension of time.

MR. CHAIRMAN : What is the wish of the House ? Two hours are nearly over.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : Four hours.

SEVERAL HON. MEMBERS : Four hours.

MR. CHAIRMAN : The House may sit till 7 O'clock and this will continue till 7 O'clock.

SEVERAL HON. MEMBERS : No, till 8 O'clock.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : Not later than 7 O'clock.

MR. CHAIRMAN : Not later than 7 O'clock. Is it the wish of the House that this debate be continued till 7 O'clock ?

HON. MEMBERS : Yes. (Interruptions).

MR. CHAIRMAN : I have understood that the House wants to discuss this till 7 O'clock.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : We can discuss it till 7 and continue it tomorrow.

MR. CHAIRMAN : It is for the House to decide. Probably it is for the Minister of Parliamentary Affairs to say whether he wants this to be concluded today ?

SHRI RAVINDRA VARMA : Yes ; this will be concluded today. The Business Advisory Committee had recommended 2 hours. But in view of the demand, one hour more may be given. More than that we are not willing today.

MR. CHAIRMAN : May I request hon. members not to waste time on this ? Let everyone be brief and to the point. Let us try and see how much we can get through by 7 O'clock. Mr. Krishan Kant, please wind up.

SHRI KRISHAN KANT : Madam Indira Gandhi had institutionalised black money politics. I do not want to refer to instances, as Mr. Unnikrishnan has done, how files in the Commerce Ministry were sold for getting licences or how certain money that certain companies wanted to give were refused because she suspected that they were giving money to other parties also. She wanted to completely institutionalise the whole political system for herself.

What I am referring now is to the political malaise and how it is to be checked. I would like that this present debate should not end up having one against this man or that man or against this company or that company, but lift up the whole thing so that a situation is created where all political parties in this House will sit together and evolve a system where you can have clean politics, pure politics, on the basis of which this democratic system was evolved, according to the dream of Gandhiji. Only then, we shall be able to buildup a system which will be a system of cleaner economy for the people and cleaner economy for the society.

MR. CHAIRMAN : Shri Chandrapan :

SHRI A. BALA PAJANOR (Pondicherry) : What is the procedure you are following ?

MR. CHAIRMAN : I am calling the different groups one by one.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : You have to call two members from this side and one from the opposition.

SHRI A. BALA PAJANOR : Even among the opposition parties, she is not following the order.

MR. CHAIRMAN : You sent your name much later.

SHRI A. BALA PAJANOR : That does not matter. You have to go according to the order.

MR. CHAIRMAN : All right. If you want to speak first, you may speak. Shri Pajanor.

1800 hrs.

SHRI A. BALA PAJANOR (Pondicherry) : Madam Chairman, as

usually mentioned by Members of Parliament when they rise to speak that they are happy to participate in the discussion, I am not happy to participate in this discussion for the simple reason that it is about a sad affair. Secondly, I am happy to speak after Mr. Krishan Kant because he has pointed out a very important matter. It is more like a privilege issue that we always take in this House. Without any party barrier, it is to be discussed.

I was happy to see in the beginning when Mr. Unnikrishnan moved his motion. If you read the motion there are four particular points, to which he has referred. This House is in agreement with him about the money power in elections posing grave threat to the future of parliamentary democracy as evidenced by the recent revelations of collection of huge election funds by some important persons including Ministers and those who are in proximity to high offices of power and decision making.

Madam, I am not going to restrict myself to the people who have collected money in the recent past because when I go through the Indian history as far as collection of money is concerned, it is very much embedded. If you see the history of 30 years, I think, even 50 hours are not enough for this Parliament to mention the names of those people who were concerned with this. If my revered friend, Mr. Unnikrishnan has the occasion to go to the Library, he can collect the cuttings of the papers and find out this starting from the days of Mr. Nijalingappa.

श्री बला पाजनोर (उड़ीज़न) : काला धन दाके पास नहीं होता तो तीस साल तक ये काहिस के लोग नहीं टिकते।

SHRI A. BALA PAJANOR : I can understand Mr. Kachawai. It is a matter of deep concern for every one of us. Mr. Sathe and many other Members also mentioned this and they were concerned about it. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please continue. You have only ten minutes like everybody else.

SHRI A. BALA PAJANOR : It is a matter where we have to take serious note of. Since the Chairman is restricting my time, I take you to the *Asian Drama* by great Gunnar Myrdal. If you want to ask about my party, even before Lok Nayak J.P. Narayan, my Party leader and the present Chief Minister of Tamil Nadu rose against corruption within the Party. He is much against this. I do not think any person can come forward and say publicly that we are for corrup-

tion and for money power. But I want to put it very clearly that our Party has established to this country that without money also we can come to power. When our great leader, late Anna, started the Party, we were penniless and we were the party representing the poor and common people of this country. We fought against the great Congress which had big money bags, in those days. In one of the brilliant speeches in Tamil which I cannot correctly translate here, Anna said that we would make you one of the biggest money bags and the greatest industrialists of this country who sit on the top towers of this country and who come down to the common man's feet. That is our greatest achievement. We are not bothered about the number of seats that we are going to get in the Legislative Assembly. And that happened also. In 1967, the present Janata Party tried to dislodge the Congress Party but they could dislodge it in 1977. But they could not come to Tamil Nadu or Pondicherry because of the simple reason that we do not believe in money; we believe in the common people of this country. This is what I want to ask on this occasion. This money is collected for what reason? —to conduct elections as has been explained by many hon. Members. This money is utilised as explained by Santhanam Committee as speed money, to speed up the matters for which they are lobbying. I am sorry to say that it is said about Members of Parliament also that some of them are being purchased by these money bags. That was mentioned in a very clever manner, in a covered manner by Shri Krishan Kant. There are certain lobbies—sugar lobby, jute lobby. They are able to purchase Members of Parliament, Legislators to influence and direct the process to be followed up. Not only here but they are able to do it with bureaucrats also. That is the weakness of the democratic system in this country. So, if we are going to find out a solution—it is interesting to have an academic exercise in this House by means of a motion by saying that we all condemn and this House takes serious note of it. And this resolution states that, The next moment we go in for it and only collect funds. But I see that there is a difference between the present and the past. From the ruling benches, whenever they speak, they refer to the past 27 years, but there is only one difference, because you are decentralised. Like four or five parties, in a decentralised manner, you are collecting, while it was centralised in the past. But the same offence is being committed in the same manner. So, don't distinguish between the present and the past.

As far as we are concerned, we are much against corruption. It is we who

[Shri A. Bala Pajanor]

started saying that corruption must go out of politics because otherwise it is impossible for the common man to come to the top. We make the commonest man the Mayor of Madras for the first time. Prior to that it was the prerogative of the rich class only to occupy the first chair of the city of Madras. Many other cities have subsequently followed it. We made a third rate fellow, according to the present-day politics the first citizen of the city of Madras, but instead of taking a lesson from that, you try conveniently to say that you will abolish donations by companies, you will amend the law etc. So many legislations have come, but nothing has happened.

As time is short, I will just read out certain passages so that they may go on record. If you take the report given by Gunnar Myrdal when the *ana* yeses the poverty of nations, especially in Southeast Asia, he says:

"When considering the prospects of reform in countries where corruption is so embedded in institutional and attitudinal remnants of traditional society and where almost everything that happens increases incentives and opportunities for personal gain, the public outcry against corruption must be regarded as a constructive force. This holds true even when this reaction is basically only the envy of people who themselves would not hesitate to engage in corrupt practices had they a chance, and even though the common awareness of corruption is apt to spread cynicism. As those people who can benefit personally from corrupt practices are a tiny minority, the public outcry against corruption should support a government intent on serious reforms. What the people—and the outside observer—generally demand is punishment of the offenders. Resentment stems especially from the belief that ministers and high officials go unpunished."

I think that is the main outcry now.

I am well aware of the fact that there is a lot of character assassination. I am in agreement with the Prime Minister when he says that whenever he is in power, they talk about these things, and the moment he is not in power they stop talking about them. If they were sincere, they would have taken it up even earlier. This is character assassination and so I am not prepared to associate myself with it.

But if you take corruption in general, see what the Santhanam Committee has said. You read the report. It has been there for such a long time. I do not know why the previous Government did not take note of it, and I cannot understand

stand why the present Government is also not taking note of it. Please permit me to read this passage at least:

"It is believed that the procedures and practices in the working of Government offices are cumbersome and dilatory. The anxiety to avoid delay has encouraged the growth of dishonest practices like the system of speed money. 'Speed money' is reported to have become a fairly common type of corrupt practice particularly in matters relating to grant of licenses, permits, etc. Generally, the bribe giver does not wish, in these cases, to get anything done unlawfully, but wants to speed up the process of the movement of files and communications relating to decisions. Certain sections of the staff concerned are reported to have got into the habit of not doing anything in the matter till they are suitably persuaded. It was stated by a Secretary that even after an order had been passed, the fact of the passing of such order is not communicated to the person concerned and the order itself is kept back till the unfortunate applicant has paid appropriate gratification to the subordinate concerned. Besides being a most objectionable corrupt practice, this custom of speed money has become one of the most serious causes of delay and inefficiency."

This is the crux of the problem. You require money to speed up the files, to get decisions you require money. The quantum of money is the only consideration whether it is Rs. 10 or Rs. 10 lakhs or Rs. 10 crores. I am not referring to any particular person or Minister of the past or the present. For a poor man, to part with Rs. 10 may be something; for a rich man, to part with Rs. 10 lakhs may be something. The Finance Minister deals with crores of rupees. So, this is a very serious matter. This House should take it up as a matter of privilege, but sometimes we do not take up even matters of privilege in the proper spirit. But if you take up the matter, I am sure we can get out of it. I am happy that Mr. Unnikrishnan and Mr. Vayalar Ravi have brought this motion in this House so that the country will know that we are also serious about it and the country will be grateful to us and will keep us in this House without sending us out if we are sincere about it and execute it.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad) : Chairman Madam, I move an amendment, rather a substitute motion to the motion mentioned in the Order Paper, listed as amendment No. 4. My amendment to the motion is as follows:

"The House expresses its grave concern over the fact that the electoral

process as well as public life in India which was badly polluted and vitiated by an unholy alliance of political power and money power during the decadent decade, 1967-76, with its steep erosion of ethical standards and moral values, threatened to distort democracy into a plutocracy, deform 'Janata' into 'Dhanatantra', recognises the imperative need to reverse those morbid trends, is convinced that for the purpose the formulation of a voluntary code of conduct by all political parties is essential and urges the Government to initiate, without delay, comprehensive measures with a view to cleansing public life in general and purifying the electoral process in particular."

This, Chairman Madam, I submit is a major amendment in substance and I would crave the indulgence of the House and yours too, to speak at some length, but not at great length.

MR. CHAIRMAN : I am afraid I can't give you more than 10 minutes and you have taken three minutes already in reading your amendment.

SHRI HARI VISHNU KAMATH : I have to read it. If I don't read it, how can I convince the House ? You make it 15 minutes.

SHRI SHANKAR DEV : Madam Chairman, our Party Members are also there to speak.

MR. CHAIRMAN: Please continue Mr. Kamath.

SHRI HARI VISHNU KAMATH : Now, Chairman Madam, I am sorry to say that though my friend, Mr. Unnikishan, has brought a motion of some importance before the House, yet the main thrust of his argument was with regard to collection of election funds recently, and particularly he mentioned the name of Shri Kanti Desai. I am afraid that Shri Kanti Desai has occupied more of parliamentary time during this Session than perhaps any other single person in the country. Both the Houses together, the Rajya Sabha and the Lok Sabha, have taken more time in discussing Shri Kanti Desai's activities at various places than they have in discussing any other person in this House. It should not have been so because the hon. Speaker, when the issue was raised in the House last Tuesday, a week ago, gave a clear ruling. I am sorry that has been overlooked in this discussion. The Speaker said :

"The collection of funds for political purposes by those in power as well as those near the seat of power is likely to give rise to suspicion that there might have been misuse of official power or position. This is a political question.

Solution to such issues must be found either by enacting necessary laws or by developing appropriate conventions. This is not a matter for me."

Nor was it a matter for an adjournment motion.

Madam Chairman, I have followed the line laid down by the Speaker and, as suggested, the Government must come forward without delay to enact measures for cleansing public life in general and purifying the electoral processes in particular.

My hon friend, Shri Sathg, he has again fled. On the 12th of this month, earlier, he had fled. He makes, I suppose, a good job of it. Because, he himself said once—it was his own words—once a coward, always a coward. He said it last time, and he follows to the letter and also to the spirit, his own words. Now he is, if I may say so, a beknighted knight, in shoddy armour, of Her Extinguished Majesty, and he is not present here. Both he and his leader are absent. Though his leader has been given the status of the Leader of the Opposition, *de jure* Leader of the Opposition, more often than not *de facto* he is a misleader of the opposition. And the second in command, as I have already said, has made it a profession or vocation of fleeting the battle-field at the nick of time. He did it once and he has done it again. It is for him to consider, to decide, to mend his ways.

Now I do not wish to go into all the lurid details not merely of the elections, but of every form of corruption, because corruption is a hydra-headed monster, which has been indulged in by the Congress Governments for over 30 years. There is a saying in Hindi or Urdu, I hope I am right in saying it,

ती सी चूड़े खाय बिस्तरी हज़ को चली ।

That applies in totality, entirely to our friends of the Opposition.

In 1971 and in 1977, and in the previous four years 1967 to 1971 during the famous or notorious era of Ayaram and Gayarams, money had to be found to finance the buying and selling on the exchange of the Legislatures at the Centre and the States; I do not know I do not wish to go into it, but money was found for that also. Be that as it may, in 1971, I remember, because some of the Congress candidates in Maharashtra and Madhya Pradesh had told me personally, that each of them, many of them, had received at least Rs. 2 lakhs to 3 lakhs. Out of that, some of the more enterprising once kept something for the rainy day, and did not utilise it, use it for election purposes.

[Shri Hari Vishnu Kamath]

They did not mind losing and some of them lost. They used it perhaps for their own other purpose. In 1977 also the same thing happened. And the money found for these elections, perhaps rained from heaven. According to some of the members of the opposition only money collected by the Janata Party and Janata Party agents came from some fishy sources, but all the money that came for the Congress Party candidates for the elections in 1971 and 1977 must have come from God himself, rained like manna from heaven. He need not go into how the money was collected.

My hon. colleague, now a Minister here, a former party colleague, Mr. Dandavate,—I was not in Parliament then in the fifth Lok Sabha, I believe, he made a charge against one of the Congress Leaders saying that money was collected by that leader, who was then a Minister of the Government, but was not accounted for and only a very small portion was paid to the Congress Party, and the rest was retained by him and Shri Dandavate challenged the Government on the floor of the House to institute an inquiry. No, inquiry was instituted, only that Minister was not included in the Cabinet and he was made a Governor and sent to one of the States.

You are very well aware and the House is very well aware as to how and in what manner money from the nationalised banks, some of the nationalised banks was siphoned off for Maruti Ltd. I believe some of it has come in the Shah Commission's Report, more could be said, much more could be written about this. But since you are ringing the bell, I do not think I can continue for long. But I wish to refer to one or two salient points before I conclude, I have to conclude. Otherwise, I had a number of points, and I could have gone into all this at some length to prove that democracy was distorted into a plutocracy during those years and now if there is anything at all, it is a hangover from the past, from those years, from thirty years. Hangovers cannot be cured, cannot be got rid of so soon. (Interruptions).

SHRI A. C. GEORGE : Hangover cannot be passed on to somebody else.

SHRI HARI VISHNU KAMATH : There is a saying that

कराव का नसा उत्तर जाता है लेकिन सत्ता का नसा चढ़ा जाता है धौर से कर दूँता है।

That is what happened to them. Now they are coming in the House with stories about the collection of funds by an individual or two or three individuals. As a matter of fact, the statements attributed to certain

persons—Shri C.B. Gupta's name was mentioned here—they have been contradicted, denied and not authenticated, how they could be relied upon in this House as matters materially valid enough or good enough for a motion of this kind, I do not know. But, or course, I may make it clear that I do not hold any brief for anybody who is accused of corruption.

The Prime Minister has told the House plainly, he has told the country, the nation that if any specific charge is made against anyone, it will be referred to a Supreme Court Judge. My friend, Mr. Unnikrishnan referred to that. In the olden days, in the Third Lok Sabha when you, Madam Chairman, were also a Member of that Lok Sabha, the then Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru referred to a Supreme Court Judge a specific charge made by the party to which I had then the honour to belong, the Praja Socialist Party, my colleague Shri Surendra Nath Dwivedi and myself, we brought home a charge and we have a specific instance about an entry in the documents, in the account books of Mr. Serajuddin of Calcutta, we gave that and that was then referred to Mr. S.K. Das of Supreme Court informally; the report was not placed before the House, but Shri Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister asked the Minister to quit the Cabinet. Who took him back into the Cabinet? His daughter, Shrimati Indira Gandhi. The daughter, whose father had expelled him from the Cabinet, that daughter took him back into her Cabinet. That is the sort of example they have set.

One word more and I have done. My hon. friend, Mr. Sather, referring to my criticism of "Her Extinguished Majesty" on earlier occasions.

AN HON. MEMBER : Extinguished.

SHRI A.K. ROY : Who was the Minister, involved in that affair

SHRI HARI VISHNU KAMATH : Pandit Keshv Dev Malaviya was involved in that Serajuddin affair. He was expelled; he was asked to quit the Cabinet after the inquiry.

So, I would also ask my hon. friend, Mr. Unnikrishnan and his colleagues, the parties in his Opposition, to bring forward such specific instances. Then, I am sure the Government will not fight shy. The Government will be really prepared to refer those specific charges for an inquiry.

As regards the Motion as it stands, nobody will have any quarrel with that. What does it say? It says, "increasing play of money power" is detrimental to parliamentary democracy. Is there any

question about that ? The play of money power is detrimental to the growth of a healthy parliamentary democracy.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI HARI VISHNU KAMATH : I am concluding. Please don't be impatient. I appeal to you to have a little more patience. We have patiently borne the Congress Government's misrule for 30 years. Now, atleast for a few minutes more you can bear with me.

What is the operative part of the Motion ? Please read it. I do hope, you have read it. Are you reading it just now ? What does it say ? It says :

"increasing play of money power in elections pose grave threat to the future of Parliamentary Democracy..."

MR. CHAIRMAN : You have read it once. Why do you want to read it again ?

SHRI HARI VISHNU KAMATH : It says "increasing play of money power." It has been increasing, not now, and it went to a climax in 1971 and 1977. From the year 1977, the year of peaceful revolution, it has been showing a downward trend. As far as possible, we must eradicate this evil. I am sure, the House will agree with me that, human nature being what it is, all over the world, not India alone, there are many hues and colours of corruption, and corruption of many kinds, of all kinds, cannot be totally eradicated not only in India but anywhere in the world. All that you can do is to minimise it, as far as it lies in human power. To that, our Government is committed; to that, our party is committed.

Before I sit down, I would once again ask the absent mover—his deputies and colleagues are here—and I would ask them: they have not asked for an inquiry. An inquiry was asked for by Mr. Sathé on that day on which he fled. That does not arise now. I would ask them to make a concrete issue of this and not to leave it in vacuo, in the air. It says, "grave threat to the future or Parliamentary Democracy" and it, later on, says, "as evidence by the recent revelations". Have they made any demand or request for an inquiry into this matter ? No. They are silent on that point.

I am sorry to say, this is an important motion, without any legs to stand upon, without any heart, without any head, without anything at all—it is a lifeless motion; it is a still-born motion. Therefore, I would like them to make it a live motion, a concrete motion, so that it can

be brought home to the Government. Otherwise, there is no alternative before the House but to accept my motion which I have moved already asking the Government, all political parties, that you I and all of us sit together and accept a code of conduct. That is my fervent appeal to all Parties. Let us evolve a voluntary code of conduct. *Achar Sanhita* so that all Parties may honour that code of conduct and the Government should come forward with measures to cleanse the public life in general and purify the electoral process in particular.

MR. CHAIRMAN : Mr. Chandra-ppan.

श्री विनम्र सम्बद्ध बैठक : सभापति महोदय, जिनके संशोधन हैं, उनको बोलने का समय मिलेगा क्या ? कुछ तो बोलिये, हाँ या नहीं ।

श्री सर्वर बेब : हमने जो प्रमेयमेंट्स दिये हैं, तो मुक्त योग को चाहत मिलेगा या नहीं ?

MR. CHAIRMAN : Mr. Chandra-ppan.

If you do no interrupt, we will accommodate two more speakers.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (Cannanore) : I am very happy that this motion gives us an opportunity to discuss the political corruption in our country. But I am sorry I cannot share the views expressed by some of our distinguished colleagues including Shri Krishan Kant who said that we should discuss it in a very academic fashion and that we should go to a higher plane. I cannot float with them in that higher plane because we are discussing this motion in the House in a definite context.

The Janata Party which came to power a few months ago in the year of revolution, as it was put by my esteemed friend, Shri H.V. Kamath, came with the slogan, 'We will remove corruption from public life.' That was one of your main slogans. And, to-day, we are witnessing a strange spectacle. It is not only kantibhai Desai but the father, Morarji Bhai Desai himself and the whole Janata Party have proved to be more corrupt than any administration we ever had. (Interruptions)

श्री मुक्त योग कालावाय : जनता पार्टी ने सब को कर्ट दिया है, इन शब्दों को निकाला जाये ।

सभापति महोदय : देखिये, माप बैठ जाइये, जब आप बोलें, आप अपनी तरफ से उनको जवाब दे दीजिये । यह उनका ग्रसिकार है, जो उनके मन में है वह बोलें । यह कोई जन-पालियामेंटरी नहीं है ।

[सभापति महोदय]

बो पापके मन में है, बब पाप बचाव में, तब कह में। इस तरह से इन्हरेट न करो। इस तरह से कैसे काम हो सकता है?

SHRI C.K. CHANDRAPPAH : I do not know why they are shouting. Perhaps the shoe pinches. If the shoe pinches, then those who feel the pain of it, may get up....

MR. CHAIRMAN : Proceed with your speech. Do not waste your time.

SHRI C.K. CHANDRAPPAH : Please call the House to order. How can I speak in this way?

I am telling out of certain facts. There are certain facts to prove that. We in this House heard about it.

श्री चंद्रपाप : पापके दात जाने के पार हैं, दिलाने के पार हैं।

SHRI C.K. CHANDRAPPAH : I can shout better than you. You are a little bit older than me.

We have heard about Kantibhai Desai and his money collection. Not that I said it. The Treasurer of the Janata Party said that he authorised him to collect Rs. 90 lakhs. Not a matter of joke. He did not deny it.

When the whole world said that the Party is corrupt and the Prime Minister's name is in mud, an after-thought dawned on him and then he denied. We heard it from your leader, Shri Madhu Limaye, Secretary of the Janata Party who wrote that letter saying Rs. 90 lakhs but when he was asked in the Central Hall 'Do you confirm or deny?' he did not have the guts to say that 'I don't deny or confirm it'. (Interruptions) No more shoutings will help.

SHRI VAYALAR RAVI : Please keep quiet.

SHRI C.K. CHANDRAPPAH : What does it mean?

SHRI VAYALAR RAVI : If the Congress is corrupt, you are also corrupt.

SHRI A.K. ROY : They are corrupt, they are corrupt—we are not corrupt.

SHRI C.K. CHANDRAPPAH : Madam, Chairman, they are not allowing me. That time should not be counted against me.

What was the period in which these collections were made. What was they amount collected? They came in power after the last general election and the Assembly Elections. In three month's

time, Rs. 90 lakhs of rupees in ninety days Rs. 90 lakhs. For them one lakh does not matter. But it is on record. Here is the proceedings of the Rajya Sabha where one of the former ministers, who died—he became the President—the late Shri Fakhruddin Ali Ahmed is answering question No. 3812 on 19th August, 1968, gave certain figures of collection. (Interruptions) Why are you getting so much excited (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : May I request you all to let him proceed? Please continue, Mr. Chandrappan.

SHRI C.K. CHANDRAPPAH : Madam, it says that within the period from 1st March 1962 to 20th February 1963 they compiled the figures, the money given by various companies to political parties, accounted money—unaccounted money is not included. It says :

"The Congress Party received Rs. 2,05,22,798."

The Congress stood very good. They were Number 1. Then came Shri H.M. Patel's party, the Swatantra Party at that time—

"Rs. 46 lakhs." (Interruptions)

Why are you reducing it to Rs. 20 lakhs. I am reading:

"46,02,563/-; then came Praja Socialist Party with Rs. 66,000/-."

Like that it goes on. What I am saying is (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please continue.

SHRI C.K. CHANDRAPPAH : How can I continue if so many people are interrupting me?

MR. CHAIRMAN : Do not take any notice of it. You continue your speech

SHRI C.K. CHANDRAPPAH : I am continuing. I am trying not to listen to them (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please let him proceed. Don't waste the time of the House.

SHRI C.K. CHANDRAPPAH : The point which I am emphasising is that there is a corrupt system. I agree with those who said that a capitalist system is corrupt. The Leader of the Janata Party or Lok Nayak said that he would wipe out the corruption. The people changed their place. When they were sitting there, these Congress people, when they were sitting there, they could collect Rs. 2 crores very easily. And to-day

when the Janata Party is sitting there wearing the garbs of angels trying to flutter the Heaven, they could also collect and they even broke all the records. This is what I said. It is not the only story of this country (*Instructions*). They collected Rs. 90 lakhs in 90 days. Madam, then comes the father. As a person, I do not like that our Prime Minister is known as the corrupt Prime Minister. This is not something to be proud of for any nation. But the Prime Minister is sitting silent. On his face we are asking everyday 'Did you write that letter?' Even to-day Shri H.M. Patel said that he wrote that letter to the Andhra Pradesh Chief Minister successively from Shri Vengal Rao to Dr. Chenna Reddy, asking for exempting the former Raja—Raja of Challappalli of 2,000 acres of land. So, the father is not better.

Madam Chairman, corruption is there. It is not a new thing. From 1961 onwards the country was worried about political corruption. In 1952 elections, 1957 elections, 1967 elections and in 1971 elections the capitalists were very clever. They knew whom they should butter. Here, with your permission, Madam Chairman I would like to quote a portion of what Mr. Tata said in his affidavit in a court in Bombay. In this case one of the share-holders of the Tata company had questioned the right of Tata company to change their Article of Association to enable them to donate Rs. 10 lakhs to Congress Party. He challenged it in a Bombay court and then Mr. Tata gave a very interesting affidavit in the court. He said that it was in the interest of the company that I gave donation. The share-holder said that my interest is not looked after by giving Rs. 10 lakhs. Mr. Tata said that you do not live in this world. It was to safeguard your interest and to promote your interest and to enhance your profit that we are giving money to this party. And today these people are sitting on this side. I do not say that they are absolutely useless. But for practical purposes for Indian monopoly houses they are second in the list whereas Janata party is at the top and they will get anything. It is only a question of stretching their hand.

AN HON. MEMBER : Are they not stretching?

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : They are. Otherwise how would you explain a man, who is not even a public man, who is only a businessman, Shri Kanti-bhai Desai, can collect Rs. 90 lakhs in 90 days. It is because he is the son of the Prime Minister and he is living with the Prime Minister and he is the one—according to everybody—who advises the Prime Minister on important matters. So,

he has a price and the Indian capitalists are ready to pay that price and that is what is happening.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : While concluding, I must say that I am sorry I could not make the Janata benches so happy but I must tell the House one thing that those who came sixteen months ago—in the year of revolution—chanting a song about anti-corruption today we are seeing them sinking in the mire of corruption. They are standing in the dock in the other House. Let us not forget that. The other House is equally a part of Indian parliamentary democracy. It has put the Janata party in the dock. (*Interruptions*)

It has asked them to appoint a parliamentary committee or a commission to probe into the corruption charges. It is a matter of shame that our Prime Minister went and said : You give in writing, if you have a definite allegation. I will send it to a judge. It is much bigger than what Indira Gandhi did when she flouted the Allahabad High Court judgement.

Then, Madam, it was expedient ..

MR. CHAIRMAN : Please resume your seat. I have called Shri Kanwar Lal Gupta.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : It was then expedient for Mrs. Indira Gandhi to say 'I don't care for the Allahabad Judgment ; the people are with me.' But today what happens ?

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Madam Chairman, by flouting the decision of the other House, Mr. Morarji Desai and his Government today stands in the dock of the people. If you want to remove poverty, to the extent it is possible under the present system, you have to bring about radical electoral reforms and there should be proportional representation.

MR. CHAIRMAN : How can it go on like this, if you take so much time ? How will others get time ?

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Madam, I have not taken so much time as some others have taken. There should be radical electoral reforms and proportional representation. Part of the essential part of the election expenditure should be borne by the State itself as was suggested by Shri Vajpayee when he was sitting here in the opposition. If that proposal is accepted, to the extent possible in our system today, we may succeed in

[Shri C.K. Chandrappan]

rooting out corruption; but, so long as capitalism remains, corruption is also bound to remain in the body-politic of this country. Thank you.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN : How will you manage? It is already 6.50' Mr. Unnikrishnan has to reply.

MR. CHAIRMAN : We will conclude by 7 O'clock today, and continue for one hour at 3.30 p.m. tomorrow, in which one or two speeches can be made and the Minister will reply and then Mr. Unnikrishnan will reply. It is not possible to extend the House after 7.00 p.m. today according to the hon. Minister.

श्री चैरर लाल मूर्त्ति : Please extend it up to 7.05 so that I may get sufficient time.

समाप्ति महोदय, जिस समस्या की तरफ उन्नीकृतन जी ने व्याप दिलाया है वह समस्या बही जटिल है। इस देश में चुनावों में पैसे का कितना प्रभाव होता है, इस चीज की ओर उन्होंने व्याप दिलाया है। मैं समझता हूँ इसमें किसी पार्टी का सबाल नहीं है। मैं पृथ्वी का चाहता हूँ कि यहाँ पर जिनी भी पार्टियाँ हैं, वहाँ इस तरफ की या उस तरफ की प्रभाव इनमें से कौन भी पार्टी कोई पार्टी है जो यह कानून के द्वारा चुनाव में अल्प मरी का इस्तेमाल नहीं किया? मैं इमानदारी के साथ कहता चाहता हूँ कि वहाँ कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, नार्किनस्ट पार्टी हो या कोई भी दूसरी पार्टी हो, या कोई पार्टी पार्टी नहीं है जो कह कर उसमें काले छान का प्रयोग नहीं किया। इसलिए मैं कहता चाहता हूँ कि यह कोई पार्टी का सबाल नहीं है, यह सबाल यारे देख देता है और उसी स्तर पर इसको सुनाक्षण कराता है। मेरा कहना है कि लेकर चारत का भी सबाल नहीं है, जिनी भी डिवोटेटक फांटीज हैं तभी मैं पैसे का प्रभाव चुनावों पर होता है। प्रमरीका में, ईस्टैड में, जर्मनी में, सभी जगह पर इसका प्रभाव होता है। लेकिन यारे का चारत चूंकि गरीब देश है इसलिए यहाँ पर इसका प्रभाव व्यापा होता है। लेकिन मैं यह नहीं मानता हूँ कि केवल पैसे से चुनाव जीता जाता, जो इन्दिरा जी की हार करी नहीं होती। इन्दिरा जी के पास जितना पैसा था, उस के मुकाबले में जनता पार्टी जब पैसा भी नहीं हुई थी, उस समय कितनी जोर से उस की विजय हुई—इन का अर्थ है कि केवल पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता, उस के लिये जनता की सपोर्ट भी जारिये, प्रोत्तम भी जारिये, दूसरी जीजे भी जारिये। लेकिन मैं इस बात की जोर जनता हूँ—कि हमारे गरीब देश में पैसे का प्रभाव बहुत रहा है। जब से, 1947 से लेकर आज तक हमारे लोग इस के लिये कोशिश करते रहे। उन्होंने कम्युनिज के कानून पारम्परी साराँ ताकि वे डोनेशन न दे सकें, लेकिन जिनी शोरिया आज तक की गई, जिस का प्रभाव उन्होंने

ही बहुत है। जितना प्रभाव काले छान का चुनाव के ऊपर पहुँचे था, आज उस से कई बहुत व्यापा है, क्योंकि यह क्या होता है—वे जितने बड़े-बड़े बिंग-बिजनेस-हाउसेज हैं, इन की कम्पनियाँ ऐसा नहीं हैं जो सकती हैं, तब उस से कहा जाता है कि अच्छर-हिंटेविल दे दीजिये और इस तरह से अच्छर-हिंटेविल करोड़ों व्यापा इकट्ठा किया जाता है। उन का भी कर्ट किया जाता है, और अपने आप को भी कर्ट किया जाता है, पार्टी को भी भी कर्ट किया जाता है, वर्कर्स को भी कर्ट किया जाता है और चरित का हूँन होता है।

इस लिये मैं कहूँगा—मंदी महोदय, आप ने जापनी ला में जो प्रावधान किया है कि कोई भी कंपनी पैसा नहीं दे सकती, इस के कानून दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। मेरा सुझाव है कि इस पर दोबारा विचार कीजिये, इस का रीकॉर्ड डर कीजिये, इसको ईकेंड-वाट दीजिये और उस में एक बैंकमेम लिमिट लागू कर दीजिये कि कोई 30 हजार या 50 हजार लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। लेकिन जो हार्ड-रिंटेविल वैसा है, उस का प्रातीक्ष्यन बोना चाहिये। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह चीज संभव नहीं है—जब तक परिवक्त-पार्टीनाम और पार्टिं-टीकम पार्टीज का अपना को-ऑफ-काउन्सल न हो। जब तक हम लोग न्यू लीक नहीं होंगे, तब तक इन्डस्ट्रीलिमिटेट को दोप देने से कठु नहीं होगा। उन को तो लाइमेंस लेना है, ले तो आते ही रहें और जैसा बनाएँन साबल ने भी कहा—जो पैसा टाटा ने दिया, उस के कर्म गृह ज्यादा उम ने ले लिया—वे तो वैसा है कि कानून उठायेंगे ही। इस लिये मेरा कहना है—जब तक कोड-प्राकालन्डवट पोलिटीकल पार्टीज अपने लिये नहीं बनायेगी, जब तक जनता में पोलिटीकल कानूनन नहीं होंगी, तब तक इस समस्या का निवारण नहीं हो सकता है। यह बीमारी बड़े रही है और तेजी से बढ़ रही है।

इस लिये मेरा सुझाव है—पोलिटीकल पार्टी बैठ कर तय करें कि लिमिट-जाहे स्टेट के मिनिस्टर हीं या सेन्टर के मिनिस्टर हीं—कोई भी हों, उन को पार्टी के लिये बता इकट्ठा नहीं करना चाहिये। इस तरह का नियम बनाना चाहिये लेकिन यदि परिवक्त सालफ को स्वल्प करना है, यदि आप आवश्यक भी यह कोई भी दैसा पैसा नहीं है कि परिवक्त-मैन के ऊपर लोंगों का विवात बना रहे हों, मैं यह बत सब के लिये कह रहा हूँ। मैं कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन यदि परिवक्त सालफ को स्वल्प करना है, यदि आप आवश्यक हैं कि परिवक्त-मैन के ऊपर लोंगों का विवात बना रहे हों तो यह जरूरी है कि कोई भी मंदी पार्टी के लिये या किसी के लिये भी दैसा इकट्ठा न करे। मैं यह जानता हूँ—पार्टी के नाम से दैसा पार्टी के लिये भी इकट्ठा होता है और अपने लिये भी इकट्ठा होता है।

दूसरी ओर, मैं जबाब नहीं देना चाहता—
ममी भेरे पाई बोल कर खले गये—हम ने स्लोगन
लगाया था। ठीक है, हम ने जबकर स्लोगन लगाया
था—परिवक लाइक में प्योरिटी लगायें। मैं पुछता
चाहता हूँ—किस ने वह स्लोगन नहीं लगाया
था, क्या आप चाहते हैं कि परिवक लाइक में
प्योरिटी नहीं रहती चाहिए? अगर सचमुच में
हस्तांतरे में यह ब्याल है कि हम कर्ट हो
नके हैं, तो जनता को हमें हटा देना चाहिए—
इस में कोई दो रायें नहीं हैं, लेकिन प्रधान मंत्री
जी ने स्पष्ट कह दिया है—मेरे परिवार के ऊपर
या बरत सिंह जी के परिवार के ऊपर—आप तो
उडीक्षण जी ने राजनारायण जी के बारे में
भी कहा है, मैं उन को भी उस में शामिल करता
हूँ—या कोई और हो, जिसी के लिए आप वह
लिखित प्रमाण के साथ लिख कर दें तो एकवारी
होती रहिये। कोई है, इसमें हो, उधर से ही
प्रगत कोई लिख कर के स्टीमिंग कार्जिंग दिये जाते हैं
तो उसकी इंकारायी भी फ़ास्टिस से हो। मैं समझता
हूँ कि इसके पासे कोई गुंजाश नहीं है। इस
तरह से आप पोलिटिकल कंसीट्यूशन से कुछ भी
कहते रहिये, राष्ट्र सभा के द्वारा गुंजाश
में गहरा गहरा गुंजाश है इस सब को चीफ अस्टिस
पर स्लोट दीजिए। किसी बारे में भी यहाँ बोलने
का जो हमारा प्रांतिकार है, उसका मिमियज नहीं
होना चाहिए। प्राप बाहर बोलिये, लिख कर
दीजिए ताकि दूध का दूध प्रोट पानी का पारी
सामने आ जाए।

सभापति भटोदया, मेरा एक कंक्रीट मुझाव
है कि इनेक्षन काफ़ीनोंसग का सारा सिरटम रिष्यू
होगा चाहिए। एक गोरी भारती आज चुनाव
नहीं लड़ सकता है, पालियामेंट का मेंबर नहीं
बन सकता है। मेरा मुझाव है इस के लिए एक
पालियामेंट की कमेटी बनायी जाए।

The entire system of financing the election should be reviewed; and that should be done by a parliamentary committee.

वह कमेटी इस पर विचार करे और सारी
वारों पर विचार कर के वह अपनी रिपोर्ट मदन
के सामने रखे। कोई वह कंक्रीट प्रोजेक्शन सदन
के सामने देता करे।

दूसरी ओर सरकार को यह भी सोचना
चाहिए कि जो खर्च इनेक्षन में होना है उसका
कुल हिस्सा वह बदलित करे। जब तक यह नहीं
होता, तब तक मैं नहीं समझता कि कोई भी काम
ठीक हो सकता है या इसका प्रभाव कम हो
सकता है।

सभापति भटोदया, एक स्टेट्यूटरी प्रोविजन
बनाया गया था कि दिल्ली में पालियामेंट का मेंबर
दस हजार रुपये, जिसी दूसरी जगह 40, 35
हजार रुपये खर्च कर सकेगा। मैं समझता हूँ
कि इसका रीकॉन्ट्रोल करना चाहिए। यह नहीं कि
इस खर्च की बड़ा कर दुनाव कर दिया जाए या

तिपुा कर दिया जाए। लेकिन मैं यह कहना
चाहता हूँ कि यह इतना भ्रष्ट कर दिया जाए
जिससे कि इसका ठीक ठीक हिसाब दिया जा सके
मैं कहता हूँ कि यहाँ एक भी आदमी ऐसा नहीं है
जिसने कि भवता इलेक्षन रिटर्न ठोक से भ्रष्ट
हो। क्रोम टाप टू बोटम कोई भी ऐसा नहीं
मिलेगा। मैंने बारंग इलेक्षन के तिलित्से में एक
याचिका दी भी भीर मेरी याचिका पर फ़ीसा होने
के बाद ध्रीमती इंदिरा भारी मे कानून को ही बदल दाला।
यह कह दिया कि पार्टी खर्च करे, बेटा खर्च करे,
बाप खर्च करे, वह उसमें शामिल नहीं माना जाएगा।
कैंपेनिंग जो खर्च करता, वही माना जाएगा।
लेकिन दस हजार रुपये में पालियामेंट का इलेक्षन
नहीं हो सकता है। इसके लिए कोई संतोषजनक हल
निकाला जाना चाहिए। अगर हाँ यह नहीं
निकालते हैं तो दस प्रावधान को ही बदल देना
चाहिए। पालियामेंट में बारंग से हल्ले ही हुआरे
चर्चित का हनन हो जाता है, हमसे भूत बुलवाया
जाता है। यह नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई
रास्ता निकाला जाना चाहिए। इसके बारे में सर-
कार ध्यान दें।

सभापति महोदया, मैं पोलिटिकल पार्टीज के
प्राइट के बारे में एक विवाह लाया था। उस
समय मामने कहा था कि पार्टीज के भ्राउंट का भी
प्राइट होता। अब तक कास्टीट्यूशन में पोलि-
टिकल पार्टी नाम की जीव नहीं है। अब
एप्टी फ़िकेशन विल के कारण से वह भी कास्टी-
ट्यूशन में भा रही है। इसलिए पोलिटिकल पार्टीज के
भ्राउंटस पर भी कंडोल होना चाहिए।
अगर पांच हजार रुपए से अधिका किसी को दिया
जाता है तो उसका नाम जनता के सामने भारी
चाहिए। उस पार्टी का अकाउंट भी प्राइट
कर के जनता के सामने रखा जाना चाहिए कि नितने
उसे पैसा दिया, उसने किसको पैसा दिया? कामय
साहब ने जैसा कि कहा कि पार्टी बाले खुद पार्टी
का पैसा वह जाता है। इससे वह जीव भी नहीं
होपी और सब को पत लग जाएगा। अगर प्राइट
होगा तो यह जीव पता लगेगा कि किस अकाउंट
से पांच हजार रुपया आया, उसका नाम के पता
भी सामने आ जाएगा। जो नहीं देता है उस
पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। इस
प्रकार का प्रावधान कर दिया जाना चाहिए।

19:00 hrs.

मैं इसको सीधा करपान का सवाल बनाना
नहीं चाहता। केवल चुनाव में करपान का सवाल
बनाना चाहता हूँ। जनरल करपान का सवाल
हस्तों में नहीं बनाना चाहता। मेरे पास यहूँ
से इस्टीत्स है कि जिसको यहाँ रखा जा सकता है।
बहुत गडबडी हूँ है कि जिसको भ्रामी तक पकड़ा नहीं
गया है। लोगों के पास इंदिरा भारी का रुपया है
जो पकड़ा नहीं गया है। उसमें कमजोरी हमारी
सरकार की है। मैंने वित्त मंत्री को एक पत्र भी
लिखा है। एक यूनिवर्सिटी का लड़का है उसके
नाम से डेक्क करोड़ रुपया जमा हुआ पोस्टल
सेविंग एकाउंट में। मेरे पास पत्र भी है जिसको मैं
पढ़ देता हूँ।

[श्री कंवर लाल गुप्ता]

"There are also a few suspicious deposits like those in the name of a Delhi student amounting to about Rs. 1.35 crores. It is evident that the student concerned did not have the means to make the deposits. Even if he had the resources, it is inconceivable that he could have deposited large funds in the post office for just a day or two."

This is dated 28th February, 1978 written by the Minister of State for Finance.

यह जो पैसा है इसके बारे में मैंने शोबारा पत्र लिखा है और कहा है कि इसकी इकायायी की जहरत है । मिनिस्टर याक स्टेट कह रहे हैं कि जहरत नहीं है । मैंने वित्त मंत्री को लिखा है कि इकायायी की जहरत है । उनका उत्तर नहीं पाया । इस तरह का एक घकार्ट नहीं है । एक साल में 24 करोड़ रुपया हरियाणा के पोस्ट घाकिसिस में जमा हुआ है, एक ही हफ्ते में और एक ही हफ्ते में निकाल लिया गया है ।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : Who is the student?

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I do not know. He is a student from Haryana.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

श्री कंवर लाल गुप्ता : यह बेनामी नामों से है । मेरा कहना यह है कि यह सब पोस्टिकल रूप से है । वित्त मंत्री जो मेरे पक्के का बच्ची तक लोई उत्तर नहीं दिया है । मैं कहना चाहता हूँ कि इसकायायी की जहरत है । मिनिस्टर याक स्टेट ने कहा है कि नहीं है । इनकायायी होनी चाहिये कि याकिर रुपया कहा गया, किस का है । इस सब के बास्ते मिल जुल कर एक पालियामेटरी कमेटी हमें बनानी चाहिये जो इस सारे प्रावस्त्रम की तह में जाए । तभी यह समस्या हल हो सकती है ।

इन पदों के साथ मैं प्रपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

19.05 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 30, 1978/ Bhadra 8, 1900 (Saka).